



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936

No. 223]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

रक्षोपाय महानिदेशालय
सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

विषय : भारत में पीएक्स-13 या 6 पीपीडी (रबड़ रसायनों) के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16 और नियम 18 के साथ पठित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(4) के उपबंधों के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा – अंतिम जांच परिणाम – के संबंध में।

स.का.नि. 293(अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

क. प्रक्रिया

1. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात् "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष (1) मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड, मुंबई द्वारा भारत में रबड़ रसायनों एन 1,3 – डाइमथायल ब्यूटाइल-एन" फिनायलीनडायामाइन जिसे पीएक्स-13 या 6-पीपीडी के रूप में भी (और इस याचिका में उसी तरह उल्लिखित) जाना जाता है के आयातों पर मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात् रक्षोपाय शुल्क के विस्तार करने के लिए रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा करने एवं उसका विस्तार करने के लिए एक आवेदनपत्र यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया कि पीएक्स-13 या 6 पीपीडी (रबड़ रसायनों) के संबंधित आयात भारत में पीएक्स-13 या 6 पीपीडी (रबड़ रसायनों) के घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति का कारण बन रहे हैं या गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर रहे हैं। भारत में पीएक्स-13 या 6 पीपीडी (रबड़ रसायनों) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा करने के लिए रक्षोपाय जांच शुरुआत नोटिस 29 अगस्त, 2013 को जारी किया गया था और वह दिनांक 29 अगस्त, 2013 की जीएसआर 583(ई) के तहत उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 29 अगस्त, 2013 की जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति केंद्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, निर्यातकर्ता देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतवासों/उच्चायुक्तों के माध्यम से तथा निम्नलिखित सूचीबद्ध सभी हितबद्ध पक्षकारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार प्रेषित की गई :

2क. निर्यातकर्ता**1. चाइना सनसाइन कैमिकल होल्डिंग्स लिमिटेड**

चाइन बिजनेस एंटेप्रस, शान्जियान शान्डांग प्रांत के दक्षिणपूर्व में चार किलोमीटर, पोस्टल कोड 274300, चीन जनवादी

2. शान्डांग यान्गू हुआताई कैमिकल कंपनी लिमिटेड, सं. 217, संबंधी वेस्ट रोड, यांगू काउन्टी, पोस्ट कोड : 252300**3. डांगयिंग बो चेन कैमिकल कंपनी लिमिटेड**

डा वांग, डांगयिंग, शान्डांग प्राविन्स इकनामिक एंड टेक्नालोजिकल डिवलपमेंट जोन

4. नान्जिंग कैमिकल प्लांट (एनसीपी) पता : 560 हियान रोड, नान्जिंग, चीन, पोस्टकोड : 210038**5. हिनान कैलुन कैमिकल कंपनी लिमिटेड, 25 जीफांग रोड, नार्थ, हुआक्सियान काउन्टी, हिनान, चीन****6. डालियान रीकोन केम कंपनी, लिमिटेड, 1/10एफ, चाइना बैंक प्लाजा, नं. 15 रेनमिन रोड, डालियान, चीन-116001****7. हीबेई हाउफेन कैमिकल ग्रुप 19, चांगजिंग रोड, क्विंग लियांग डियान टाउन, वुमी काउन्टी, हीबेई प्राविन्स, चीन****8. यिजिंग डांगफेंग फिन्स कैमिकल, 201 रेमाइन रोड, फेन्शुई टाउन, यिजिंग जियांगशु चीन****9. सोलुटिया इंक (विश्व मुख्यालय) 575, मैरीविले सेंटर डा., सेंट लुइस एम ओ 63141, यूनाइटेड स्टेट्स****10. इस्लो ए एस, एडमिनिस्ट्रेटिव्ना बुडोवा ईव, सी 1236, साला, 92703 स्लोवाकिया****11. कुम्हो पालीकेम कंपनी, लिमिटेड, 20वां तल, कुम्हो आशियाना मैन टावर #115 सिन्मुन्नो 1-जीए, जोगनो-गु, सिओल कोरिया****12. जियान्सु साइनोकेम टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड, संघाई आपरेशन सेंटर, 22 एफ, योंगडा इंटरनेशनल टावर, सं. 2277 लांगयांग रोड, पुडांग न्यू एरिया संघाई-201204, जीन जन. गण.****13. चांगडे डिंगयुआन कैमिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, डांगफेंग ग्राम, नान्पिंग टाउनशिप, वुलिंग जिला, चांगडे, हुनान, चीन****14. जिनान रून्क्वान कैमिकल कंपनी, लिमिटेड हेंगचेंग बिल्डिंग, सं. 288, जिंगसी रोड, जिनान, शान्डांग, चीन****15. झेजियांग योग्जिया कैमिकल प्लांट, पता : डोंग-ओउ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट (ओउबेई तृतीय पुल) वेन्झोऊ चीन, जिय कोड : 325105****16. रोंगचेंग कैमिकल जनरल फैक्टरी कंपनी, लिमिटेड रोंगन रोड, रोंगचेंग सिटी, शान्डांग प्रांत, 264300, चीन****17. झेन्जियांग संख्या 2 कैमिकल फैक्टरी, झेन्जियांग कैमिकल डिवलपमेंट एरिया, जियान्ही, झेन्जियांग सिटी, जियांग्सु प्राविन्स, चीन****18. शेन्झेन हुआरेन इंडस्ट्रियल कंपनी, सूट सं. 1103-1108, डियान्जिंग बिल्डिंग, 2 गुजी उन्न रोड लुओहु जिला, शेन्झेन सिटी, चीन****19. झेजिना युइकिंग अल्ट्राफाइन पाउडर्स एंड कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, शांगबुटोऊ इंडस्ट्रियल एरिया, क्विंगजियान, यूएक्विंग झेजियांग, चीन****20. लैनक्सेस एन वी जर्मनी, 51369 लिबरकुसेन जर्मनी****21. फ्लोक्सिस एन वी बेल्जियम पार्क साइन्टिफिक – फ्लेमिंग रूई लेड बर्नियात, 3बी-1348 लौवेन – ला – न्यूवे बेल्जियम****22. मैसर्स कुम्हो पेट्रो कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, निर्यातक, कोरिया गणराज्य****23. मैसर्स ईस्टमेन कैमिकल कंपनी, पी.ओ. बॉक्स 511, किंग्सपोर्ट, टेन्नेसी****3 ख. आयातक****1. सिएट लिमिटेड, आरपीजी हाउस, 463, डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400030****2. अपोलो टायर्स लिमिटेड, छठा तल, चेरुपुष्पम बिल्डिंग, पन्मुगम रोड कोच्चि-682031****3. एम आर एफ लिमिटेड, चेन्नई 124 ग्रीम्स रोड, चेन्नई-600006****4. पोद्दार टायर्स लिमिटेड, जीटी रोड, जुगियाना लुधियाना-141420**

5. दि रबड़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्लॉट संख्या सी-44 रोड संख्या - 28 वाग्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट, थाणे (मुंबई) 400604
6. जे के इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 7, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कोलकाता-700001
7. बिरला टायर्स, बिरला बिल्डिंग, 7वां तल, 9/1 आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001
8. मैट्रो टायर्स लिमिटेड, मैट्रो टावर, सी-49, सेक्टर 62, नोएडा-201301, भारत
9. रालसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जे 38, उद्योग नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली-41 (भारत)
10. मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड 65 अटलांटा, नरीमन प्वाइंट, मुंबई

4 ग. भारतीय उत्पादक

1. मैसर्स एन ओ सी आई एल लिमिटेड, सी-37, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, पावनी गांव, नवी मुंबई (घरेलू उद्योग)
2. लैन्क्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लैन्क्सेस हाउस, प्लॉट सं. ए 162-164 रोड संख्या 27, एम आई डी सी, वाग्ले एस्टेट थाणे (पश्चिम)-400604, महाराष्ट्र
3. पी एम सी रबड़ कैमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 103, जीटी रोड वेस्ट, डाकघर रिसरा-712248
4. मर्केस लिमिटेड, ग्रोव सेंटर, 44 डिवलपमेंट प्लॉट कलामेसरी, कोचीन-683109 केरल, भारत

5 घ. ज्ञात प्रयोक्ता एसोसिएशन

1. आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, पीएचडी हाउस, चौथा तल, सिरी फोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एशियन गेम्स विलेज के सामने, नई दिल्ली
2. दि आल इंडिया रबड़ एसोसिएशन (ए आई आर आई ए) 601, प्रमुख प्लाजा, बी. विंग, 485 कार्डिनल ग्रेसियस रोड, अपोजिट प्राक्टर एंड गैम्बल चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400099

5 ड. निर्यातक राष्ट्र/प्रतिनिधिमंडल/राजदूतावास

1. भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल
2. भारत में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल
3. चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास, 50-घ, शांति पथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
4. फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का राजदूतावास सं. 6/50 जी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
5. कोरिया गणराज्य का राजदूतावास, 6, चंद्र गुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-21
6. संयुक्त राज्य का राजदूतावास, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
7. स्लोवाकिया का राजदूतावास, 50 एम, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
8. बेल्जियम का राजदूतावास, 50 एम, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21

5.1 उपर्युक्त निर्यातकों में से 3 निर्यातक ऐसे थे जिनके यहां जांच शुरूआत नोटिस नहीं भेजा जा सका और यह नोटिस इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि उनका पता सही नहीं है, यह निर्यातक निम्नलिखित हैं:

- (i) मैसर्स नानविंग कैमिकल प्लांट (एनसीपी) पता : 560 हेयान रोड नान्जिंग चीन, पोस्टकोड : 210038
- (ii) मैसर्स झेजियांग योंगिवया कैमिकल प्लांट पता : डांग ओऊ औद्योगिक जिला (ओबेई तृतीय ब्रिज) वेन्झोऊ, चीन, जिप कोड : 325105
- (iii) मैसर्स झेनजियांग नं. 2 कैमिकल फैक्टरी, झेनजियांग कैमिकल डिवलपमेंट एरिया जियान्ही, झेनजियांग सिटी, जियांग्सु प्रांत, चीन

6. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों पर जाकर आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी विचारों पर समुचित निर्णय लेने के लिए विचार किया गया। अभिप्राप्त या प्राप्त अगोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

8. दिनांक 19.12.2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सार्वजनिक सुनवाई के लिए दिनांक 03.12.2013 को नोटिस किया गया था। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों की सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम 6 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लिखित प्रस्तुतिकरण फाइल करें। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रत्युक्ति, यदि कोई हो, दर्ज करने का अवसर प्रदान किया गया। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अभिव्यक्त सभी विचारों की, चाहे वे लिखित प्रस्तुतिकरण हों या प्रत्युक्तियां, जांच की गई और समुचित निर्णय लेते वक्त उनको ध्यान में रखा गया।

9. **संक्षिप्त इतिवृत्त :** मैसर्स एन ओ सी आई एल लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में रबड़ रसायनों एन-1, 3-डाइमिथायल ब्यूटाइल एन फिनायलीनडायामाइन जिसे पीएक्स-13 या 6 पीपीडी के नाम से भी (और इस याचिका में उसी रूप में उल्लिखित) जाना जाता है, के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया कि पीएक्स-13 या 6 पीपीडी के संबंधित आयात भारत में पीएक्स-13 या 6 पीपीडी के घरेलू उत्पादों के लिए गंभीर क्षति का कारण बन रहे हैं या गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर रहें और इस आवेदनपत्र के आधार पर महानिदेशक (रक्षोपाय) ने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत एक जांच प्रारंभ की थी। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 की सभी अपेक्षाएं तत्रैव पूरी होती हैं, इसलिए पीएक्स-13 या 6 पीपीडी के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 के जांच शुरुआत अधिसूचना, जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित कराया गया था, के तहत जांच प्रारंभ की गई। त्वरित जांच आयोजित करने के पश्चात दिनांक 06 जून, 2011 को अंतिम जांच परिणाम जारी किया गया। केंद्रीय सरकार ने महानिदेशक रक्षोपाय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 83/2011-सीमाशुल्क (एसजी) के तहत उपर्युक्त रबड़ रसायनों के आयातों पर दिनांक 30-08-2011 से दिनांक 29.08.2012 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए, संदेय पाटनरोधी शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत की दर से निर्णयक रक्षोपाय शुल्क और द्वितीय वर्ष दिनांक 30.08.2012 से दिनांक 29.08.2013 तक के लिए संदेय पाटनरोधी शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत की दर से निर्णयक रक्षोपाय शुल्क उदग्रहित किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है रक्षोपाय शुल्क दिनांक 29 अगस्त, 2013 तक प्रभावी था। तथापि, वर्तमान आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा दो वर्षों की अन्य अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाने/उसमें संवृद्धि करने के लिए इस प्रयोजनार्थ दायर किया गया है कि घरेलू उद्योग अपनी अतिजीविता के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सके।

10. पक्षकारों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के समान हैं। इन पर उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है।

11. जांच शुरुआत के पश्चात किए गए निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक सुनवाई से पहले प्राप्त हुए :

क. मैक्सिको की सरकार : मैक्सिको द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि उनकी प्रशुल्क सूचना प्रणाली के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस उत्पाद के मैक्सिको द्वारा भारत को जनवरी, 2009 से जून, 2013 के बीच कोई निर्यात नहीं किया गया। विश्व व्यापार संघ के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार मैक्सिको डब्ल्यूटीओ का एक विकासशील देश सदस्य है और उसने इस प्रक्रिया से व्युत्पन्न किसी भी रक्षोपाय शुल्क के अनुप्रयोग से मैक्सिको के उत्पाद आयातों का अपवर्जन किए जाने के संबंध में विचार करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है।

ख. यूरोपीय आयोग :

1. आयोग ने इस समीक्षा जांच को प्रारंभ किए जाने का विरोध किया है जिसमें कई गंभीर प्रकार्यात्मक कमियां हैं और पीएक्स-13 के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क इस स्तर पर विधिक रूप से संभव नहीं होगा।

2. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 9.2 के उपबंधों के अंतर्गत भारत को इस मामले में मूल शुल्क की समाप्ति के दो वर्षों के पश्चात अर्थात् अगस्त, 2015 से पहले रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, इस जांच को समाप्त करें और यह सम्पुष्टि करें कि शुल्क समाप्त हो गया है।

3. आवेदकों ने दावा किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है, वास्तव में, रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात घरेलू उद्योग की विक्री में थोड़ी सी वृद्धि हुई और तत्स्थानी बाजार हिस्सा संगत रूप से स्थिर बना रहा जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों को लाभ हुआ और उनका बाजार हिस्सा जो वर्ष 2009 में 8 प्रतिशत था दो गुना बढ़कर वर्ष 2013 में 16 प्रतिशत हो गया जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग आयातों के अलावा अन्य कारणों से भी समस्याओं का सामना कर रहा है।

4. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 7.4 के अनुसार, यदि शुल्क का समय विस्तार किया जाता है तो वह शुरुआती अवधि की समाप्ति पर जितने प्रतिबंधात्मक थे उससे अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं हो सकते हैं और वे उदारीकृत होकर लागू रहने चाहिए।

ग. लैनक्सेस

एक घरेलू उत्पादक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि गुजरात के झगड़िया स्थित लैनक्सेस का संयंत्र एक बहुउद्देशीय संयंत्र है और रक्षोपाय शुल्क के अभाव में वे हमेशा इसको उस उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए करते थे जिससे उन्हें सर्वोच्च मूल्यवर्धन मिलता था। किसी तरह का रक्षोपाय शुल्क इस इष्टतमीकरण को बाधित करेगा और तद्वारा भारत में सृजित मूल्य को कम करेगा।

घ. कोरिया गणराज्य की सरकार

1. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (रक्षोपाय शुल्क की कालावधि एवं समीक्षा) के अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत सरकार द्वारा एक समीक्षा प्रारंभ किए जाने के साधन में विस्तार किए जाने के बजाय उसके पुनः अनुप्रयोग के रूप में माना जाना चाहिए।
2. ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो अनंतिम उपाय या रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत समीक्षा के संबंध में निर्धारण में भूतलक्षी प्रभाव को विनियमित करता हो क्योंकि रक्षोपाय साधन की प्रकृति यह है कि वह विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत आपवादिक तौर पर अधिरोपित किया जाता है।
3. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.5 के अनुसार अनुप्रयोग की अवधि कम से कम दो वर्षों की है। अतः भारत सरकार द्वारा समीक्षा एवं विस्तार के संबंध में चल रही जांच को या तो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
4. डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 में उल्लेख है कि रक्षोपाय साधन का "विस्तार इस शर्त पर किया जा सकता है कि आयातकर्ता सदस्यों के सक्षम प्राधिकारियों ने अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 में निर्धारित कार्यप्रणाली की सम्पुष्टता में यह निश्चय किया हो कि गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका समाधान निकालने के लिए रक्षोपाय शुल्क को जारी रखना आवश्यक है और यह कि इस आशय के साक्ष्य हो कि उद्योग को समायोजन करना पड़ रहा है।" इस संबंध में करार के अनुच्छेद 2.1 में उपबंध है कि आयातों में घरेलू उत्पाद के समग्र रूप में या संगत रूप में वृद्धि होनी चाहिए जो कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए आधारभूत शर्त है। पीएक्स-13 में रक्षोपाय जांच की शुरुआत के नोटिस में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार इस उत्पाद के आयातों में वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके या वह गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर सके।
5. यह नोट किया जाना चाहिए कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की मूल भावना "ढांचागत समायोजन की महत्ता को पहचानने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के बजाय उसमें श्री वृद्धि करने की जरूरत है।" जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस पहलू का सत्यापन किया जाना चाहिए कि क्या जब रक्षोपाय शुल्क लागू था उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा ढांचागत समायोजन करने के सदभावी प्रयास किए गए। पीएक्स-13 के रक्षोपाय जांच के जांच शुरुआत नोटिस में दिखाए गए क्षमता उपयोग इंडेक्स और प्रतिदिन उत्पादकता इंडेक्स के अनुसार ढांचागत समायोजन करने के प्रयासों में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने की अवधि के दौरान भी ढांचागत समायोजन करने में निरंतर कमी आई है।
6. अगस्त, 2011 में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में इस उत्पाद की कीमतों में वृद्धि हो गई और इसके बदले में टायर उत्पादकों (अंतिम प्रयोक्ता) की प्रतिस्पर्धात्मकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्हें इसकी खरीद उच्चतर कीमतों पर करनी पड़ी। यदि रक्षोपाय शुल्क को बढ़ा दिया जाता है तो इसका अधोप्रवाही उद्योगों और उपभोक्ताओं पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
7. इसलिए रक्षोपाय शुल्क की पुनरीक्षा करने और उसका संवर्धन करने की जांच की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत नहीं है और इस जांच को या तो तत्काल प्रभाव से या अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए बिना समाप्त कर दिया जाए।

ड. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी कोरिया

1. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत परिकल्पित रक्षोपाय साधन की कालावधि और समीक्षा के लिए संधार के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क को इसकी अवधि समाप्त होने से पहले बढ़ाया जा सकता है, न कि उसके पश्चात/रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 7.2 तभी लागू होता है जब रक्षोपाय शुल्क को बिना अंतराल के जारी रखना हो और रक्षोपाय करार का अनुरोध 7.5 तभी लागू होता है जब रक्षोपाय शुल्क एक अंतराल के उपरांत, न्यूनतम दो वर्षों के अंतराल के अधीन, "एक बार पुनः" या "फिर से नए ढंग से लागू" किया जाए।
2. वर्तमान मामले में, रक्षोपाय शुल्क 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गया है। जांच शुरुआत करने की तारीख रक्षोपाय जांच के लिए अपरिणामी है। रक्षोपाय शुल्क संबंधी विधिक प्रावधान और रक्षोपाय करार में शुल्क के भूतलक्षी उदग्रहण का प्रावधान नहीं है। किसी शुल्क या भूतलक्षी प्रभाव से उदग्रहण केवल तभी संभव है जब यह अधिकार संविधि में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो। इसलिए पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण उस पिछली तारीख से "संबंधित" नहीं किया जा सकता है जिस तारीख को विगत में प्रभावी शुल्क समाप्त हुआ था। अतः, इस मामले में, चूंकि शुल्क फिर से शुरू होगा या उस अवधि की समाप्ति के पश्चात लागू होगा जिसके लिए पूर्व में लगाया गया शुल्क प्रभावी था, इसलिए यह शुल्क को "एक बार पुनः" अर्थात् रक्षोपाय शुल्क के नए सिरे से उदग्रहण के रूप में होगा और इस कारण अनुच्छेद 7.5 में उल्लिखित निषेध लागू होगा। पुनः यह उल्लेख किया गया है कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए महानिदेशक रक्षोपाय को रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय 29 अगस्त, 2013 से पहले ले लिया जाना चाहिए था, जिसका आशय यह है कि रक्षोपाय जांच करने और रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय 29 अगस्त, 2013 से पहले ले लिया जाना चाहिए था।

आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक के आवेदन पत्र में गलत सूचना और उसके परिणामस्वरूप समीक्षा की शुरुआत गलत है।

3. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने मूल जांच के लिए दिए गए अपने आवेदनपत्र में निम्नलिखित समायोजन योजना प्रस्तुत की थी :

"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा *** एमटी रबड़ रसायन तथा मध्यवर्तियों, जिनमें पीएक्स-13 एक उत्पाद के रूप में शामिल है, का उत्पादन करने का है। इस संयंत्र में कुल *** रुपए के अनुमानित व्यय पर *** एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग *** करोड़ रुपए है जो क्रियान्वयन के स्तर पर है। कंपनी को आशा है कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में प्रारंभ हो जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता में लगभग तीन वर्षों के दौरान पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो जाएगा। अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं और पीएक्स-13 निर्यातों की तुलना में आयातों में और मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र की संवर्धित क्षमता देश में पीएक्स-13 की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।"

4. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में अपनी पूर्व उल्लिखित समायोजन योजना को ही दोहराया है :

"प्रार्थी पुनः उल्लेखन करते हैं कि "एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा *** एमटी रबड़ रसायन तथा मध्यवर्तियों, जिनमें पीएक्स-13 एक उत्पाद के रूप में शामिल है, का उत्पादन करने का है। इस संयंत्र में कुल *** रुपए के अनुमानित व्यय पर *** एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग *** करोड़ रुपए है जो क्रियान्वयन के स्तर पर है। कंपनी को आशा है कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में प्रारंभ हो जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता में लगभग तीन वर्षों के दौरान पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो जाएगा। अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं और पीएक्स-13 निर्यातों की तुलना में आयातों में और मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र की संवर्धित क्षमता देश में पीएक्स-13 की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।"

5. यह निदेशक रक्षोपाय ने अपने दिनांक 6 जून, 2011 के अंतिम जांच परिणाम में इस समायोजन योजना के लिए निम्नलिखित नोट किया है :-

6. "34. भारतीय उत्पादकों ने एक समायोजन योजना बनाई है जो (क) उत्पाद लागत, (ख) मौजूदा उत्पादन क्षमता का और अधिक उपयोग, (ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार पर प्रकाश डालती है।

35. प्रार्थी उद्योग अर्थात् एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा की स्थापना करने जा रहा है जिसमें कंपनी का इरादा *** करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से *** एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने का है। यह उल्लेख किया गया कि यह परियोजना मार्च, 2012 में शुरू हुई और अप्रैल, 2012 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया है। किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्य का विवरण देते हुए एक चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है और यह प्रमाणित किया गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अप्रैल, 2012 से उत्पादन शुरू हो जाएगा।"

7. आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान आवेदनपत्र में दावा किया कि उन्होंने मूल जांच के लिए अपने आवेदनपत्र में समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया था :

"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 10,000 एमटी मध्यवर्तियों का उत्पादन करने का है। इस संयंत्र में पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त 10000 एमटी मध्यवर्तियों का 250 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से किए जाने की क्षमता होगी।कंपनी को वित्त वर्ष 2013 में कभी भी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र तीन वर्षों की अवधि में अपनी इष्टतम क्षमता के लिए पूर्णतया प्रचालनात्मक होगी।"

8. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने अपने वर्तमान आवेदनपत्र में पुनः निम्नलिखित दावा किया है :

"चूंकि कंपनी ने दाहेज संयंत्र में 4 एडीपीए का विनिर्माण करना पहले ही प्रारंभ कर दिया है, इसलिए प्रार्थी ने आयात प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त उपाय किया है।

3. प्रार्थी ने दाहेज में 4 एडीपीए का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। संयंत्र के मुताबिक, यह ही एकमात्र उत्पादन होगा जिसका प्रार्थी दाहेज में उत्पादन होगा। यह संयंत्र केवल पीएक्स-13 (अर्थात्4 एडीपीए) के लिए है, जिसका अनन्य रूप से पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(ड.) घरेलू उद्योग ने दाहेज संयंत्र में नवम्बर, 2012 से उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है।"

9. आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग ने अनिवार्य प्रकटन के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज को निम्नवत अधिसूचित किया।

दाहेज में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत कंपनी अपडेट 15:43 एनओसीआईएल ने बीएसई को यह सूचित किया कि कंपनी ने गुजरात राज्य के भड़ौच जिले में दाहेज स्थित अपने एक नवीन हरित क्षेत्र संयंत्र में उत्पादन का सफल परीक्षण पूरा करने के पश्चात, 07 मार्च, 2013 से रबड़ रसायनों का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

10. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक में अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित घोषणा की है :

निदेशक मंडल 1. कंपनी का नाम दिनांक 14 सितम्बर, 2007 से नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर एनओसीआईएल लिमिटेड कर दिया गया।
वित्तीय परिणाम

कारपोरेट अभिशासन 2. कंपनी को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी ने गुजरात राज्य के भड़ौच जिले में शेयरधारिता पैटर्न दाहेज स्थित अपने एक नवीन हरित क्षेत्र संयंत्र में उत्पादन का सफल परीक्षण पूरा करने के घोषणाएं पश्चात, 07 मार्च, 2013 से खड़ रसायनों का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

11. महानिदेशक रक्षोपाय ने समीक्षा के लिए जांच शुरूआत नोटिस में निम्नलिखित उल्लेख किया है :

समायोजन योजना : प्रार्थी ने विचाराधीन उत्पाद के मध्यवर्ती का विनिर्माण करने के लिए लगभग 10000 एमटीएस का एक नया संयंत्र दाहेज में स्थापित किया है जिसने, ऐसा उल्लेख किया गया है कि नवम्बर, 2012 से उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रदान कराए गए रिकार्ड के अनुसार वे एक परीक्षण उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद के उपान्तिम स्तरीय उत्पाद/मध्यवर्तियों अर्थात् 4 एडीपीए का विनिर्माण कर रहे हैं और उन्होंने शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए समीक्षा के प्रयोजनार्थ अपनी समायोजन योजना के रूप में इस नए संयंत्र का उल्लेख किया है।

12 अब, आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने दावा किया है कि उसने मूल जांच के समय इससे भिन्न दावा किया था अर्थात् आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक अपने दाहेज संयंत्र में 4 एडीपीए का उत्पादन करेगा (जिसे आवेदन से उद्धृत किए गए पोर्शन से देखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महानिदेशक रक्षोपाय इस तथ्य की जांच करें और यह निश्चय करें कि आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक का मूल जांच के लिए दिए गए अपने आवेदन पत्र में क्या दावा था।

13 दूसरा, आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि और अधिदेशित प्रकटन के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज को (स्टाक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अंतर्गत) यह अधिसूचित किया है कि दाहेज संयंत्र ने 07 मार्च, 2013 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। यह आवेदनपत्र 31 जुलाई, 2013 को दायर किया गया (यद्यपि यह सही नहीं है, यह इस प्रस्तुतिकरण में अन्यत्र सिद्ध हो चुका है)। आवेदन पत्र के पृष्ठ 27 पर यह दावा किया गया है कि उत्पादन नवम्बर, 2012 में प्रारंभ हुआ। जांच शुरूआत नोटिस में भी यह उल्लेख किया गया कि दाहेज संयंत्र ने नवम्बर, 2012 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था, जब कि आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने एक अन्य सांविधिक प्राधिकारी के समक्ष यह दावा किया है कि दाहेज संयंत्र ने 7 मार्च, 2013 को उत्पादन प्रारंभ किया, इस तरह उनके आवेदनपत्र में एक दूसरे के विपरीत दावे किए गए हैं और जांच शुरूआत नोटिस अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए धोखा है। महानिदेशक, रक्षोपाय से अनुरोध है कि वे इस तथ्य की जांच करें।

14. तीसरे, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या दाहेज संयंत्र के प्रचालन से पीएक्स-13 की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। यह नोट किया जा सकता है कि इसकी क्षमता 8500 एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने की है, जैसाकि जांच शुरूआत नोटिस में उल्लेख किया गया है।

समायोजन योजना का अनुपालन न करना

15. रक्षोपाय नियमावली के नियम 18(1) (i) में यह अपेक्षा की जाती है कि घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा करने के लिए आवेदन करते समय सकारात्मक रूप से समायोजन के साक्ष्य प्रदान करेगा। आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादक ने मूल जांच के लिए आवेदनपत्र में और वर्तमान समीक्षा के लिए आवेदनपत्र में असंगत दावे प्रदान कराए हैं। जांच शुरूआत नोटिस में उल्लेख किया गया है कि आवेदक घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता 8500 एमटी है। आवेदन पत्र में आवेदक घरेलू उत्पादक ने कहीं भी इस बात का दावा नहीं किया है कि पीएक्स-13 के उत्पादन करने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

16. मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में नोट किए गए तथा वर्तमान याचिका में भरोसाकृत समायोजन योजना में भारी अंतर है। इनका उल्लेख निम्नवत किया गया है :

क्र.सं.	मद	अंतिम जांच परिणामों तथा इससे पहले की याचिका में नोट किया गया समायोजन योजना	वह समायोजन योजना जिस पर इस याचिका में भरोसा किया गया
1	दाहेज संयंत्र में विनिर्मित किया जाने वाला उत्पाद	पीएक्स-13 या 6 पीपीडी	4 एपीडीए (वास्तविक रूप में विनिर्मित)
2	समय-सीमा (दाहेज संयंत्र)	मार्च 2012 से प्रारंभ हो रहा उत्पादन अप्रैल, 2012 से	वित्त वर्ष 2013 में कभी भी प्रारंभ (याचिका का पृष्ठ 24) अगस्त, 2012 तक प्रारंभ (वार्षिक रिपोर्ट, 2011-12) नवम्बर, 2012 तक परीक्षण उत्पादन (याचिका का पृष्ठ 27) वास्तविक शुरूआत 7 मार्च, 2013 (वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012-2013)

17. उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि आवेदक गलत आंकड़े प्रदान कर रहा है और उसने महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष विभिन्न अवसरों पर गलत तथा प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दाहेज संयंत्र में संबद्ध वस्तु का न ही विनिर्माण किया है जैसा कि मूल जांच के समय मूल समायोजन योजना में प्रस्ताव किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने समायोजन के लिए एक वर्ष तक सकारात्मक कदम उठाने में विलंब कर दी है जिसके लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विलंब आयातों के कारण हुआ (जब कि मुख्य कारण बिजली की कम आपूर्ति है)।

18. चूंकि आवेदक मूल जांच में किए गए प्रस्ताव के अनुरूप समायोजन के लिए कोई भी सकारात्मक प्रयास करने में असफल रहा है, इसलिए वह रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 का आश्रय नहीं ले सकता है। महानिदेशक रक्षोपाय ने थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा संबंधी अपने अंतिम जांच परिणाम में दिनांक 7 जून, 2013 को यह धारित किया कि रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग का अनुरोध जिससे कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयारी करने का कुछ अवसर मिल जाएगा का आशय यह होगा कि उन्हें सकारात्मक समायोजन के लिए प्रयास अभी भी प्रारंभ करने होंगे। महानिदेशक रक्षोपाय ने उस मामले में रक्षोपाय शुरू बढ़ाने के अनुरोध को यह धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि घरेलू उद्योग ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रदान कराने में असफल रहा है कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी तरह, इस मामले में, घरेलू उद्योग समायोजन हेतु सकारात्मक कदम उठाने के लिए समय विस्तार की मांग कर रहा है जो यह दर्शाता है कि वे मूल समायोजन योजना के अनुसार समायोजन के लिए कोई भी सकारात्मक उपाय करने में असफल रहे हैं। उपर्युक्त मामले में महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा निर्धारित किए गए विधि शास्त्र के अनुसार रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने के लिए किए गए ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जिसमें सकारात्मक समायोजन के लिए साक्ष्य का अभाव हो। अतः, इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19. उपर्युक्त के मद्देनजर, महानिदेशक रक्षोपाय से अनुरोध है कि वे इस जांच को समाप्त कर दें क्योंकि घरेलू उद्योग मूल जांच में यथा प्रस्तावित समायोजन के लिए सकारात्मक प्रयास करने में असफल रहा है जो रक्षोपाय नियमावली के नियम 18(1)(i) का उल्लंघन है। अतः, रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किए जाने के लिए घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए और इस जांच को अविलंब समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

जांच का प्रमाण : आयातों के कारण गंभीर क्षति प्राप्त करने की अपेक्षा

20. नियम 18(3) नियम 8 के उल्लेख नहीं कर रहा है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बेशी अतिरिक्त विधिक उपबंधों का अधिनियमन होगा। नियम 18(1)(i) में रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की केवल तभी सिफारिश करने का उपबंध है जब रक्षोपाय शुल्क, "गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने" के लिए आवश्यक हो। किसी ऐसी समस्या का समाधान करना जो मौजूद ही न हो समक्ष से परे और तार्किक रूप से असंभव है। किसी वस्तु का उपचार या निवारण तभी संभव है जब पहले यह निश्चित हो जाए कि वह वस्तु मौजूद है। इसलिए इस आशय का कोई भी निर्धारण करने से पहले कि गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका उपचार करने के लिए रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता आवश्यक है, यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या ऐसी गंभीर क्षति मौजूद है।

21. इसके अतिरिक्त, नियम 5 और 11 के साथ पठित नियम 18 महानिदेशक रक्षोपाय से यह अपेक्षा करता है कि वह गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती की अवस्थिति का निर्धारण करें और अपने अंतिम जांच परिणाम में संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करें। जब किसी समीक्षा में रक्षोपाय नियम स्पष्टतः गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए और कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए स्पष्टतः अधिदेशित करते हों तो आवेदकों का इसके विपरीत किसी तर्क का विधिक आधार निराधार हो जाता है।

22. इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8(ख)(1) केंद्रीय सरकार को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति केवल उन मामलों में प्रदान करती है जहां संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। या गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर रहे हैं।

23. समीक्षा में शुल्क की निरंतरता रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 के अनुरूप होना अपेक्षित होता है जिसमें प्रावधान है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारण रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2, 3 4 और 5 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुरूप हो। अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 मूल जांच पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग का क्षति का कारण आभ्यांतरिक है

24. आवेदक घरेलू उत्पादक पीएक्स-13 का एक अक्षम एवं अदक्ष उत्पादक है और वह चाहे उसे किसी भी अवधि के लिए किसी भी स्तर का संरक्षण प्रदान कर दिया जाए फिर भी वह इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने और उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगा। घरेलू उद्योग को क्षति का कारण आभ्यन्तरिक है, न कि संवर्धित आयात।

25. 4 एडीपीए का उत्पादन करने की अधिक क्षमता के कारण उत्पादन लागत में गैर-न्यायोचित वृद्धि

1. नई सुविधा का संस्थापन करने से पहले आवेदक घरेलू उत्पाद की 8500 एमटी 4 एडीपीए उत्पादन करने की क्षमता थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इसने दाहेज स्थित नए संयंत्र में परीक्षण उत्पादन प्रारंभ किया जिसका 4 एडीपीए का 10,000 एमटी उत्पादन करने की क्षमता है। इसलिए, आवेदक घरेलू उत्पादक ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान उन संयंत्रों की लागत पर व्यय किया जिनकी कुल क्षमता 4 एडीपीए का 18,500 एमटी उत्पादन करने की थी जबकि मर्यादाकारी कारक, अर्थात् पीएक्स-13 का केवल 8500 एमटी

उत्पादन करने की क्षमता बनी रही जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब उपान्तिम इनपुट का उत्पादन करने की लागत गैर-न्यायोचित ढंग से बहुत अधिक हो, यह निश्चय ही है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों को क्षति होगी अथवा उन्हें कम लाभ होगा, परंतु उसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

2. मध्यवर्ती का उत्पादन करने के लिए बेशी क्षमता (10,000 एमटी) से उत्पादन लागत में गैर-न्यायोचित ढंग से वृद्धि हुई (कम से कम अवक्षयण तथा अन्य निर्धारित/अर्ध-निर्धारित लागत की भारी राशि)। पुराना संयंत्र अभी भी 4 एडीपीए का उत्पादन कर रहा है, इसलिए लगाई गई पूंजी पर तर्क संगत आवक पर बिक्रियों की भारित औसत लागत का निर्धारण करने के लिए गैर-न्यायोचित नियोजित उच्च पूंजी का प्रयोग किया गया है।

25. घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पादन लागत की अन्यायपूर्ण तुलना

1. आवेदक घरेलू उत्पादक वर्ष 2009-10 के दौरान अपने कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात कर रहा था जो वर्ष 2012-13 के दौरान कुल उत्पादन के 22 प्रतिशत से कम है। इसलिए, इस उत्पाद के लिए 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन लागत को घरेलू बाजार के लिए उत्पादन पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख एक उदाहरण द्वारा निम्नवत किया जाता है।

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अन्य स्थिर एवं अर्ध स्थिर लागत (क)	रुपए	200000	200000	200000	200000
अवक्षयन (ख)	रुपए	100000	90000	80000	70000
कुल संस्थापित क्षमता (ग)	किलोग्राम	8500	8500	8500	8500
कुल उत्पादन (घ)	किलोग्राम	7500	6500	5500	4800
निर्यात की गई मात्रा (ङ.)	किलोग्राम	3750	3000	1800	1100
घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा (च)	किलोग्राम	3750	3500	3700	3700
लागत आवंटन का न्यायोचित तरीका (छ)					
घरेलू बाजार के लिए अवक्षयण का आवंटन (ज) = (ख) का 50 प्रतिशत	रुपए	100000	100000	100000	100000
घरेलू बाजार में अन्य नियत एवं अर्ध नियत लागत का आवंटन (झ) = (क) का प्रतिशत	रुपए	50000	45000	40000	35000
घरेलू बाजार के लिए प्रति यूनिट लागत (ञ) = [(ज)+(झ)]/(च)	रुपए / किलोग्राम	40	41.42857	37.83784	36.48649
लागत आवंटन का गैर न्यायोचित तरीका (ट)					
अन्य नियत एवं अर्ध नियत लागत का आवंटन (ठ) = (क) x ((च)/(घ))	रुपए	50000	48461.54	53818.18	53958.33
Allocation of Depreciation for Domestic market (M) घरेलू बाजार के लिए अवक्षयण का आवंटन (ड)	रुपए	100000	107692.3	134545.5	154166.7

$= (\text{ख}) \times ((\text{च}) / (\text{घ}))$					
घरेलू बाजार के लिए इकाई लागत (ठ) $= [(\text{ड}) + (\text{ड})] / (\text{च})$	रुपए / किलोग्राम	40	44.61538	50.90909	56.25

2. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि चूंकि आवेदक घरेलू उत्पादक के निर्यातों में वर्ष 2009-10 के पश्चात तेजी से कमी आई, इसलिए लागत आबंटन संघटन आधार वर्ष 2009-10 के आनुपातिक बनाया जाना चाहिए जिससे कि उत्तरवर्षी वर्षों के लिए लागत एवं लाभ की तुलना की जा सके। यदि उत्पादन लागत का आबंटन किसी ढंग से किया जाता है जैसे घरेलू बाजार में और निर्यात बाजार में बेची गई मात्रा या घरेलू बाजार में कारोबार और निर्यात बाजार में कारोबार या दोनों का भारित औसत के आधार पर किया जाता है तो यह घरेलू बाजार की उत्पादन लागत में आधार वर्ष से अन्य वर्षों में हुई वृद्धि की न्यायपूर्ण तुलना नहीं होगी। लागत आबंटन का केवल संभावित न्यायोचित ढंग यह है कि लागत के सभी संघटकों (विशिष्ट बाजार से विशेष रूप से जुड़े जैसे पैकिंग, बिक्री संवर्धन आदि को छोड़कर) का घरेलू बाजार और निर्यात बाजार के लिए 50 प्रतिशत – 50 प्रतिशत आबंटन किया जाए।

26. समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क को नहीं बढ़ाया जा सकता है

1. आवेदकों ने अपनी याचिका में रक्षोपाय शुल्क में संवृद्धि करने का अनुरोध किया है। इस प्रतिकथन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि किसी भी लागू रक्षोपाय शुल्क को एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय नियमावली के नियम 17, रक्षोपाय करार और रक्षोपाय नियमावली दोनों में रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता या उसके विस्तार के मामले में रक्षोपाय शुल्क का उत्तरोत्तर उदारीकरण करने का प्रावधान किया गया है, इन सभी प्रावधानों में रक्षोपाय शुल्क को उदार बनाए जाने का प्रावधान है जिसका उल्लेख निम्नलिखित किया जाता है :

"यदि नियम 12 के अंतर्गत उदग्रहित शुल्क की कालावधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है तो शुल्क को इसके अधिरोपण की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर उत्तरोत्तर रूप से उदारीकृत किया जाएगा।"

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय उपायों के संबंध में भारतीय विधि में अभिव्यक्त रूप से रक्षोपाय शुल्क का यदि ऐसा उपाय एक वर्ष से अधिक समय के लिए लगाया जाता है तो क्रमिक उदारीकरण करने का प्रावधान है। भारतीय विधि के अधिदेश से विचलित नहीं हुआ जा सकता है और इसलिए समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने के प्रतिकथन को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

3. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7 में उत्तरोत्तर उदारीकरण की अपेक्षा का भी अधिदेश किया गया है जिसमें रक्षोपाय शुल्क की कालावधि एवं समीक्षा का उल्लेख है। रक्षोपाय के अनुच्छेद 7.4 के संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं :

"..... जहां अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा अधिसूचित रक्षोपाय साधन की कालावधि एक वर्ष से अधिक की होने की प्रत्याशा की जाती है वहां इस उपाय का अनुप्रयोग करने वाला सदस्य इसके अनुप्रयोजन की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर इसका उत्तरोत्तर उदारीकरण करेगा। पैरा 2 के अंतर्गत बढ़ाया गया साधन प्रारंभिक अवधि के समय जितना प्रतिबंधात्मक या उससे अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होगा और उदारीकृत के रूप में लागू रहेगा।"

4. अनुच्छेद 7.4 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सदस्य देश ऐसे रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं जो शुरुआत की अवधि की समाप्ति से अधिक प्रतिबंधात्मक हो। सदस्य देशों को उत्तरोत्तर उदारीकृत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना बाध्यकारी है। अर्जेन्टीना – फुटबियर, डब्ल्यूटी/डीएस 121/आर (प्रदर्श 7) में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.4 का निर्वचन करते हुए डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट ने पाया कि रक्षोपाय साधन की समीक्षा में केवल दो संशोधनों की अनुमति है, या तो उस साधन को समाप्त कर दे या उदारीकरण की गति बढ़ा दे। पैनल रिपोर्ट के पैरा 8.303 में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है।

"..... हम नोट करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क में केवल एकमात्र संशोधन जिसकी अनुच्छेद 7.4 संधारणा करता है वह है कि इसकी प्रतिबंधात्मकता को कम करे (अर्थात् साधन का प्रथमन कर दे या मध्यावधि समीक्षा के अनुसरण में उदारीकरण की गति बढ़ा दे)। इस करार में उन संशोधनों पर विचार नहीं किया जाता है जिससे इस साधन की प्रतिबंधात्मकता में वृद्धि हो।"

5. इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 12.2 रक्षोपाय साधन का उत्तरोत्तर उदारीकरण करने का अधिदेश भी करता है और सदस्य देश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी अधिसूचना रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति को भी करेगा। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12 के संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

"किसी रक्षोपाय शुल्क के लागू करने का प्रस्ताव करने या उसमें संवृद्धि करने का प्रस्ताव करने वाला सदस्य रक्षोपाय समिति को सभी संगत सूचना उपलब्ध कराएगा जिसमें संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का साक्ष्य उत्तरोत्तर उदारीकरण के लिए समय-सीमा और प्रत्याशित कालावधि शामिल होगी।"

6. यदि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाई रखी जाती है अथवा उसे पुनः लागू किया जाता तो उसे उन दरों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिनका प्रावधान मूल जांच में शुल्क समय-तालिका में किया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक, रक्षोपाय कृपया रक्षोपाय शुल्क में संवृद्धि करने के आवेदकों के प्रतिकथन को अस्वीकार कर दें।

च. मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

इसके प्रस्तुतिकरण ऊपर मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी कोरिया द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के अनुरूप हैं।

छ. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (केपीसी), कोरिया**क. जांच शुरूआत के पश्चात कुछ अन्य प्रस्तुतिकरण भी किए गए जो निम्नलिखित हैं -**

1. भारत राष्ट्र में प्रचलित परम्परा और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा लागू रक्षोपाय साधन अंतर्राष्ट्रीय एरीना पर यह अनुरक्षित करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क/साधन को इसकी समाप्ति से पहले नहीं बढ़ाया गया है तो वह देश इसमें उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि नहीं कर सकता है। यदि इस साधन की समाप्ति के पश्चात कुल समय (एक दिन का भी) व्यपगत होने के पश्चात साधन/शुल्क को बढ़ाया जाता है तो वह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत कवर होगा और कूलिंग आफ अवधि को माना जाना अपेक्षित होता है।

2. भारत राष्ट्र की कार्यप्रणाली की रक्षोपाय विधि के इसके घरेलू प्रशासन पर भी परावर्तित होनी चाहिए जिससे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संगतता एवं तालमेल बना रहे। रक्षोपाय विधि के घरेलू प्रशासन में भारत द्वारा अपनाई गई कोई इसके विपरीत कार्यप्रणाली डब्ल्यूटीओ ढांचे के अंतर्गत भारत के व्यापारिक भागीदारों की विधिक प्रत्याशाएं कम होंगी और इससे वे हतोत्साहित होंगे और इससे यह प्रक्षेपित होगा कि भारत संदेहास्पद दोहरे मानदंड की अधिवक्ता कर रहा है ताकि वह अपने घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान कर सके।

3. महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान "काटन यार्न (सिलाई वाले धागे के अलावा) के आयातों के संबंध में तुर्की - रक्षोपाय साधन" ("तुर्की काटन यार्न") शीर्षक के डीएस 428 में भारत की डब्ल्यूटीओ में तुर्की के विरुद्ध की गई शिकायत की ओर आकृष्ट किया जाता है। उपर्युक्त मामले में भारत ने काटन यार्न पर तुर्की द्वारा किए गए रक्षोपाय विस्तार को चुनौती दी गई है। उपर्युक्त मामले में भारत ने जोर देकर कहा है कि तुर्की द्वारा 14 जुलाई, 2011 को रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात 28 जनवरी, 2012 को रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत असंगत है क्योंकि तुर्की ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत अधिदेशित प्रतीतन अवधि (न्यूनतम 2 वर्ष) की प्रतीक्षा किए बिना इस साधन का पुनः प्रयोग कर दिया है। तुर्की ने भारत की स्थिति को स्वीकार किया और उसने भारत के साथ एक करार किया जिसमें तुर्की उस रक्षोपाय साधन को वापस लेने के लिए सहमत हो गया। महानिदेशक रक्षोपाय इस मुद्दे के संबंध में भारत की स्थिति का आकलन करने के लिए उपर्युक्त कार्यवाही का रिकार्ड बाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त कर सकते हैं।

4. परामर्श अनुरोध में संगत उदधारण तत्काल संदर्भ के नीचे उल्लिखित किए जाते हैं -

(ग) 28 जनवरी, 2014 को लागू साधनों को दिनांक 15 जुलाई, 2011 से अतीतप्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में तुर्की नेके प्रावधानों का असंगत रूप से प्रयोग किया है।

(iii) चूंकि रक्षोपाय शुल्क की शुरूआती अनुप्रयोजन अवधि 14 जुलाई, 2011 को समाप्त हो गई थी और तुर्की ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत अपेक्षित अधिदेशित अवधि के लिए प्रतीक्षा किए बिना ही 28 जनवरी, 2012 को उसी उत्पाद पर साधन को पुनः लागू कर दिया।

5. भारत, वर्तमान समीक्षा के माध्यम से, बही गलती करने जा रहा है जिसका उसने तुर्की-काटन यार्न मामले में प्रतिरोध किया था। इससे रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 का उल्लंघन होगा और यह भारत की कार्यप्रणाली से असंगत होगा क्योंकि भारत तुर्की काटन यार्न के विपरीत स्थिति धारण कर रहा है। विश्व को पहले से ही यह प्रदर्शित करते हुए कि भारत द्वारा रक्षोपाय शुल्क के विस्तार का तभी समर्थन किया जा सकता है जब वह रक्षोपाय करार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया हो, भारत अब अपने इस अभिकथन से वापस नहीं जा सकता है और इस समीक्षा में इसके पूर्णतया विपरीत नहीं कर सकता है। भारत संबद्ध समीक्षा में पहले लगाए गए रक्षोपाय साधना की समाप्ति की तारीख 29 अगस्त, 2013 के पश्चात इस मामले में 2 वर्षों की अधिदेशित प्रतीक्षा अवधि की प्रतीक्षा किए बिना रक्षोपाय साधन का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया न केवल रक्षोपाय करार के उल्लंघन में है बल्कि यह स्थिति भारत की परम्परा से असंगत भी है। घरेलू उद्योग द्वारा रक्षोपाय करार के इस विषम निर्वचन के वेब में ऐसी समीक्षा प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह न केवल रक्षोपाय करार के असंगत है बल्कि यह भारत की छवि को निश्चित रूप से धूमिल कर देगी।

ख. जीएटीटी के अनुच्छेद X का उल्लंघन - जांच शुरूआत दोषपूर्ण है क्योंकि संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए अधिसूचना को न तो सत्वर रूप से सरकारी तौर पर प्रकाशित किया गया और न ही दिनांक 29 अगस्त, 2013 जो संबद्ध जांच प्रारंभ किए जाने की तारीख है को उपलब्ध कराया गया।

1. संबद्ध जांच की शुरूआत में गंभीर व्यपगमन और डब्ल्यूटीओ संरचना के तत्वावधान के अंतर्गत पारदर्शिता के संबंध में भारत की वचनबद्धता तथा इसके नियमों एवं विनियमों के प्रकाशन एवं प्रशासन से संबंधित विधिसम्मत प्रक्रिया अपेक्षाओं की पूर्णतया अवहेलना है।

2. जीएटीटी का अनुच्छेद X सदस्य देशों और उनके प्राधिकारियों पर यह दायित्व डालता है कि वे अपने नियमों, विनियमों और प्रशासनिक निर्णों का त्वरित प्रकाशन कराएं जिससे कि सरकार और व्यापारी उनसे परिचित हो सके। केपीसी चिंतित है कि प्राधिकारी ने दिनांक 29 अगस्त 2013 के जांच शुरूआत नोटिस, जो संबद्ध जांच की शुरूआत की तारीख है, प्रकाशित न कराए जाने से न केवल भारत

के व्यापारियों और कोरिया के बीच व्यापार संबंध प्रभावित हुए हैं बल्कि कोरिया सरकार के जीएटीटी 1994 ("जीएटीटी") के अनुच्छेद X में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा शुरू की गई संबद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया अर्थात् संबद्ध जांच की शुरुआत के साथ स्वयं कारे परिचित कराने कोरिया का अधिकार भी विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसा उपाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विधिसम्मत प्रक्रिया के अधिकार को नकार देता है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है जो भारतीय न्याय प्रणाली की जान है।

3. संबद्ध जांच के लिए जांच शुरुआत नोटिस "29 अगस्त, 2013" को भारत के राजपत्र असाधारण में सं. 437 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। उसे शासकीय तौर 2 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित किया गया और 24 घंटों से भी अधिक समय के पश्चात 3 सितम्बर 2013 को उपलब्ध कराया गया जैसाकि निम्नलिखित आरटीआई के उत्तर से स्पष्ट है।

4. मैसर्स ऋषिरूप पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार है, के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद कूपर द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रकाशन विभाग, भारत सरकार में दायर आरटीआई आवेदन पत्र के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है। दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के उत्तर के क्रम संख्या 14 पर दिया गया स्पष्टतः दर्शाता है कि राजपत्र का संख्या 437 प्रकाशन के लिए दिनांक 2 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 12.00 बजे भेजा। संगत उद्धरण निम्नलिखित है :

11. गजट संख्या 436, 437, 438 दिनांक 2.9.2013 को 12.00 बजे दोपहर को प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं। जाब संख्या है 3754, 3756, 3761 जीआई/13

5. क्रम संख्या 10 पर दिया गया उत्तर दर्शाता है कि 8 पृष्ठों तक के गजट प्रकाशनों का वितरण किए जाने का सामान्य समय मुद्रणालय में प्राप्ति के समय से 24 घंटों के पश्चात है। केपीसी प्रस्तुत करता है कि गजट संख्या 437 में 6 पृष्ठ हैं। संबंधित गजट संख्या 437 प्रेस में शासकीय प्रकाशन के लिए दिनांक 2 सितम्बर, 2013 को भेजा गया और इसलिए इसे प्रकाशन को भेजे जाने के 24 घंटों के पश्चात अर्थात् 3 सितम्बर, 2013 को उपलब्ध करा दिया गया। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह पुनरीक्षा प्रारंभ में अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात 2/3 सितम्बर, 2013 को प्रारंभ किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी संबद्ध जांच दिनांक 29 अगस्त, 2013 अर्थात् हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् निर्यातकों और संबंधित सरकारों और इस मामले में केपीसी और कोरिया सरकार को सूचना देने से 5 दिन पहले प्रारंभ करने का निर्णय पहले ही ले लिया था।

6. यह गजट के अनुच्छेद X का गंभीर उल्लंघन है और संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को प्रचुरता से सूचित न करने का पूर्वाग्रह दर्शाता है इसलिए संबद्ध जांच को प्रारंभ करने वाली अधिसूचना गजट के अनुच्छेद X में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अवैध है। अनुच्छेद X के संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

" अनुच्छेद X : व्यापार विनियमों का प्रकाशन एवं प्रशासन

(1) सामान्य अनुप्रयोग के विनियम, विधियां, न्यायिक निर्णय और प्रशासनिक नियमों, जिन्हें किसी सदस्य द्वारा प्रभावी बनाया गया हो का इस ढंग से त्वरित प्रकाशन किया जाएगा कि सरकारें और व्यापारी उनसे परिचित हो जाएं।

(2) आयातों पर कोई एक नई या अधिक बोझिल अपेक्षा, प्रतिबंध या निषेध को किसी सदस्य द्वारा अधिरोपित करते हुए सामान्य अनुप्रयोग का कोई उपाय जो ऐसे उपाय से पहले प्रभावी बनाया गया हो उसे शासकीय रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

ज. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) और इसकी सदस्य कंपनियां (जेके टायर, सियट, अपोलो टायर और एमआरएफ लिमिटेड)

1. यह जांच भारतीय रक्षोपाय अधिनियम और नियमों का उल्लंघन है

नियम 18 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई समीक्षा जांच सतत अधिरोपण के लिए होनी चाहिए और शब्द "सतत" का शब्दकोष आशय होना चाहिए। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शब्द को **"बिना किसी परिवर्तन या हस्तक्षेप के उसी रूप में मौजूदा होना"** के रूप में परिभाषित किया गया है। नियम 18 में शब्द "कान्टीन्यूड" का दो बार प्रयोग स्पष्टतः संकेत देता है कि नियम 18 का अनुपालन किया जाना चाहिए, रक्षोपाय समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले प्रकाशित किया जाना चाहिए अर्थात् जब मूल रक्षोपाय शुल्क मौजूद हो ताकि अंतिम जांच परिणाम में, यदि जरूरी हुआ तो, मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश की जा सके और न कि तब जब कि मूल रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त हो गई हो क्योंकि ऐसे परिदृष्ट में कोई भी रक्षोपाय शुल्क नहीं मौजूदा होता है जिसकी निरंतरता की जा सके। इस संबंध में न तो केंद्रीय सरकार को और न ही महानिदेशक रक्षोपाय को रक्षोपाय अधिनियम और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया जिससे वे समीक्षा जांच लंबित रहने पर रक्षोपाय शुल्क में विस्तार कर सकें।

उपर्युक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्तमान पुनरीक्षा जांच 29 अगस्त, 2013 को प्रारंभ की गई थी। सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार रक्षोपाय शुल्क दो वर्षों की अवधि के लिए अधिरोपित किया गया था, जो 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है। अतः इस समय भारत में पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में कोई रक्षोपाय शुल्क मौजूद नहीं है।

उपर्युक्त प्रस्थापना को माननीय बंबई उच्च न्यायालय के थिरूमाला कैमिकल्स बनाम महानिदेशक रक्षोपाय के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा भी समर्थन मिलता है। इस मामले में प्रार्थी ने रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की अधिरोपित करने की सीमाशुल्क की

अधिसूचना की समाप्ति के पश्चात माननीय बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस संबंध में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर्यवेक्षण किए :

24. उपर्युक्त विचार के अलावा प्रार्थी से इस न्यायालय में दिनांक 30 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 75/2009-सीमाशुल्क से समय के अंतर्गत न्यायालय में पहुंचने की उम्मीद की गई थी। एक बार अधिसूचना समाप्त हो जाने और प्राकृतिक रूप से उसका अंत हो जाने पर किसी न्यायिक आदेश द्वारा उस मृतप्रायः अधिसूचना में और वह भी अंतरिम स्तर पर प्राण डालना संभव नहीं है।

4 माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय स्पष्टतः स्थापित करता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने वाली कोई सीमाशुल्क अधिसूचना एक बार समाप्त हो जाने पर उसे न्यायिक आदेश द्वारा भी वापस नहीं लाया जा सकता है।

5 इस संदर्भ में आयातक माननीय महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान पिछली रक्षोपाय जांच समीक्षा की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तालिका 1

उत्पाद	मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम	सीमा शुल्क अधिसूचना और शुल्क की कालावधि	समीक्षा जांच के लिए जांच शुरूआत	समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम
फिनाल	11 जून, 1999	सीमाशुल्क अधिनियम सं. 82/99 शुल्क की कालावधि 30/6/1999 से 20/6/2001	1 जनवरी, 2001 (पहली समीक्षा जांच)	16 मई, 2001
फिनाल	16 मई, 2001 [प्रथम समीक्षा की अंतिम जांच की तारीख]	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 72/2001 शुल्क की कालावधि 30/6/2001 से 29/6/2003 थी	22 अक्टूबर, 2001 (द्वितीय समीक्षा जांच)	11 दिसम्बर, 2001
एसीटोन	7 अक्टूबर, 1999	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 7/2000 कालावधि का समय 27/1/2000 से 26/7/2002 तक	21 नवम्बर, 2001	4 फरवरी, 2002
सोडाऐश	6 अक्टूबर, 2009	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 122/2009 उस शुल्क की अवधि 20/4/2009 से 19/4/2010 है	19 फरवरी, 2010	13 अप्रैल, 2010

6 यदि वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा जांच में रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता के लिए इस अंतिम जांच परिणाम में सिफारिश की जाती है तो यह सिफारिश शुल्क की समाप्ति के पश्चात की जाएगी, इसका मतलब हुआ कि माननीय महानिदेशक रक्षोपाय अपनी सुस्थापित परम्पराओं का विरोध करता हूँ।

2. सांविधि के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसमें समीक्षा की अवधि के दौरान शुल्क में संवृद्धि करने का अधिकार प्राधिकारी के पास हो।

डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के अनुसार किसी समीक्षा जांच के लंबित रहने की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किया जा सकता है क्योंकि पाटनरोधी के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत ऐसा कोई समनुरूपी प्रावधान नहीं है जो पाटनरोधी करार संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 11.3 या एससीएम के अनुच्छेद 21.3 के अधीन हो। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में किसी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की गई है जहां समीक्षा जांच के लंबित रहने पर रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि की जाती हो।

माननीय महानिदेशक रक्षोपाय एक अर्धन्यायिक निकाय होने के कारण अधिनियम और उससे संबंधित नियमों की धाउरा 8ख के दायरे के अंतर्गत कार्य करने के लिए बाध्य हैं। भारत सरकार द्वारा भी एक परिपत्र के जरिए इसी पर बल दिया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने सीमाशुल्क आयुक्त को परामर्श दिया है कि वह एक अर्धन्यायिक निकाय होने के कारण उससे सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

3. समायोजन योजना की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है

1. रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 में प्रावधान है कि किसी समीक्षा जांच के संबंध में रक्षोपाय नियमावली का नियम 5 लागू होगा रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) (ख) के अनुसार, रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए याचिका में आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए योजनागत प्रयासों या दोनों के संबंध में उल्लेख होना चाहिए।

2. घरेलू उद्योग में तीन वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है और उसने अपनी समायोजन योजना का विवरण प्रस्तुत कराया है। मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के अनुसार माननीय महानिदेशक रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग की समायोजन योजना के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है :

3. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समनव्य योजना में, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार और लागत घटाने पर प्रकाश डाला गया है इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग उपरिशीर्ष लागत के कारण लागत में कमी करने के प्रति आशावान है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के दावे के समर्थन में चार्टर्ड इंजीनियर का विस्तार के लिए प्रमाणपत्र और नए संयंत्र पर होने वाले व्यय का प्रमाणपत्र और उस पर होने वाली लागत तथा लागत में कमी करने के दावे के लिए पेशेवर लागत लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह निदेशक रक्षोपाय ने समनव्य योजना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए दो वर्ष की समयावधि पर्याप्त है। वर्तमान समीक्षा याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना वही है जो मूल जांच में थी अर्थात् दाहेज संयंत्र में 4 एडीपीए का उत्पादन होने के कारण लागत में कमी होना।

4. महानिदेशक रक्षोपाय ने अपनी मूल जांच में पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि इस समायोजन योजना के आधार पर घरेलू उद्योग को दो वर्षों के लिए शुल्क के संरक्षण की जरूरत है जो उसे अगस्त, 2011 से अगस्त, 2011 तक की अवधि के लिए पहले ही प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार वही समायोजन योजना के आधार पर घरेलू उद्योग को अतिरिक्त शुल्क संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग समायोजन योजना के आधार पर 4 वर्षों के लिए शुल्क के संरक्षण की मांग कर रहा है जिसके लिए माननीय महानिदेशक ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि 2 वर्षों का शुल्क संरक्षण पर्याप्त है।

5. इस तथ्य को देखते हुए कि समायोजन योजना के बारे में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) (ख) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। उपर्युक्त के मुद्देनजर वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

4. संवर्धित आयातों, गंभीर क्षति और कारणात्मक संबंध की आवश्यकता भी रक्षोपाय समीक्षा जांच में लागू होती है।

1. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि रक्षोपाय समीक्षा जांच में आयातों में वृद्धि होने या गंभीर क्षति की मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है।

2. यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7(2), के अनुसार रक्षोपाय शुल्क समीक्षा जांच में रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 2 उल्लेख करता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से पहले संवर्धित आयातों, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती और कारणात्मक संबंधों की जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 4 में प्रावधान है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण किया जाना चाहिए।

3. संवर्धित आयातों, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी रक्षोपाय समीक्षा जांच में भी लागू होगी। वही आवश्यकता का प्रावधान भारतीय रक्षोपाय नियमावली में भी किया गया है।

4. रक्षोपाय नियमावली का नियम 18(3) यह प्रावधान करता है कि "समीक्षा के मामले में नियम 5, 6, 7 और 11 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। रक्षोपाय नियमावली का नियम 5(1) निम्नलिखित प्रावधान करता है :

उप-नियम 4 में किए गए प्रावधान को छोड़कर महानिदेशक, समान वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धा वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा या उनकी ओर से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर घरेलू उद्योग को किसी वस्तु के भारी संवर्धित मात्रा में आयातों द्वारा घरेलू उत्पादन के समग्र या संगत रूप से कारित की जा रही "गंभीर क्षति" या "गंभीर क्षति की चुनौती" का निर्धारण करने के लिए एक जांच प्रारंभ करेंगे।

5. इस प्रकार रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(1) के अनुसरण रक्षोपाय समीक्षा जांच की शुरुआत संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उत्पादन के समग्र या संगत रूप से कारित नहीं जा रही गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए की गई है।

5 घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता

घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में घरेलू बिक्रियों के लिए अनुक्रमित आंकड़े प्रदान कराए हैं यद्यपि जांच शुरुआत अधिसूचना में उनका प्रकटन कर दिया गया है।

6. घरेलू उद्योग उपयोक्ता उद्योग की मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

1. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, एटीएमए ने जांचाधीन रबड़ रसायनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग होने के कारण यह प्रस्तुत किया है कि उपयोक्ता उद्योग को आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में उपयोक्ता उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यही बात जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रदान कराए गए आंकड़ों से भी सिद्ध होती है जो निम्नलिखित हैं :

तालिका 2

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पीएक्स-13 क्षमता (एमटी)	8500	8500	8500	8500
पीएक्स-13 के लिए कुल मांग (एमटी)	14705	15949	15954	18315
पीएक्स-13 का कुल आयात (एमटी)	6205	7449	7454	9815

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2012-13 में पीएक्स-13 की मांग और आपूर्ति के बीच 9815 एमटी की कमी है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में पीएक्स-13 के आयात आंकड़े 11664 एमटी हैं जो यद्यपि इस कमी से मामूली से अधिक हैं फिर भी वे भारत में पीएक्स-13 की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पूरा करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए इस कमी को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग ने 4 एडीपीए का निर्माण करने के लिए गुजरात, दाहेज में एक नए संयंत्र की शुरुआत की है और यह 07 मार्च, 2013 से प्रचालनात्मक हो गया। तथापि इस संयंत्र के बाद भी यह संदेहास्पद है कि एन आई सी आई एल भारत में प्रयोक्ता उद्योग की मांग के पूरा करने में सक्षम होगा। क्योंकि एन ओ सी आई एल परम्परागत रूप से अपने उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का निर्यात करता आया है। भारत में प्रयोक्ता उद्योग पीएक्स-13 के संबंध में आयात करने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं रहा।

2 यदि घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग के 100 प्रतिशत का उत्पादन करता है और घरेलू उत्पाद की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति करता है तब भी वह संपूर्ण मांग की केवल 46 प्रतिशत को ही पूरा हो जाएगा। अतः यह अनिवार्य था कि प्रयोक्ता उद्योग को विचाराधीन उत्पाद का आश्रय लेना पड़ा। इस विचाराधीन उत्पाद की वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि आयातों में उसी समसामयिक अवधि के दौरान वर्ष 2012-13 में 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयातों में वृद्धि मांग में हुई भारी वृद्धि की तुलना में कम है। इसी समय, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता उसी स्तर पर अर्थात् 8500 एमटी ही बनी रही। घरेलू उद्योग पिछले आठ वर्षों से शुल्क के संरक्षण में रहा है। तथापि, उसने शुल्क संरक्षण के अंतर्गत घरेलू मांग को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता के बावजूद कुल मांग की केवल 46 प्रतिशत मांग को ही पूरा करने में सक्षम रहा।

7. विचाराधीन उत्पाद के आयात में एकाएक, तीव्र और भारी वृद्धि नहीं हुई।

1 विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अभिनव, अचानक, तीव्र या भारी वृद्धि नहीं हुई है जो रक्षोपाय अधिनियम और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत एक अपेक्षा है। इसकी सम्पुष्टि अर्जेंटीना-फुटवीय रक्षोपाय के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा भी सम्पुष्टि भी की गई है, जिसमें इसने पाया कि यह वृद्धि अनिवार्य रूप से परिमाणात्मक एवं गुणवत्तात्मक दोनों रूपों में "अत्यधिक अभिनव", "पर्याप्त तीव्र", "अत्यधिक यकायक" और "अत्यधिक भारी" होनी चाहिए ताकि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की गई हो। निम्नलिखित तालिका उसका विवरण प्रस्तुत करती है -

तालिका 3

जांच शुरुआत अधिसूचना	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पीएक्स-13 का आयात (एमटी)	10090	10607	9735	11664
पीएक्स-13 का आयात (अनुक्रमित)	100	105	96	116

2 आयातों में मांग के अनुरूप पिछले 4 वर्षों के दौरान धीरे-धीरे आयातों में यह वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था। घरेलू उद्योग तथा आयातों का हिस्सा समान बना रहा। अतः, इससे यह आशय निकलता है कि आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा नहीं किया है।

8. कोई गंभीर क्षति नहीं हुई

1 घरेलू उद्योग की याचिका के अनुसार, निर्यात विक्री में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 24 प्रतिशत तक की कमी हो गई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में 26 प्रतिशत तक की कमी आई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात विक्री में 43 प्रतिशत की कमी आई और इसके परिणामस्वरूप

घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 35 प्रतिशत तक की कमी आई। अतः यह स्पष्ट है कि निर्यात विक्रियों में गिरावट तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट का स्पष्ट संबंध है।

2 घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इस समय उसको घाटा हो रहा है। हालांकि वास्तविक आंकड़ों के अभाव में घरेलू उद्योग के दावे का सही-सही विश्लेषण करना संभव नहीं है। एटीएमए यह कहना चाहता है कि घरेलू उद्योग ने पीएक्स-13 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त व्याज में पर्याप्त एवं भारी वृद्धि का उल्लेख नहीं किया है। आयातों का बाजार हिस्सा परम्परागत रूप से 61 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक रहा है जबकि वर्ष 2012-13 में आयातों का बाजार हिस्सा 63 प्रतिशत रहा है। अतः, बाजार हिस्से में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए, पीएक्स-13 के आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पीएक्स-13 ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं, यह भी नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने कीमत अधोरदन के अनुक्रमित आंकड़े नहीं दर्शाए हैं। इसके अभाव में आयातक कीमतों की कमी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच करने की स्थिति में नहीं हैं। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एटीएमए यह प्रस्तुत करता है कि आयातों में अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि नहीं हुई है।

9 कारणात्मक संबंध टूटना

1 यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण कोई भारी क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त आयातों तथा घरेलू उद्योग की क्षति (यदि कोई) के बीच कारणात्मक संबंध भी टूट गया है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति चीन जनगण और कोरिया से पाटन के कारण हुई है।

2 पाटनरोधी शुल्क महानिदेशालय ने उसी घरेलू उद्योग अर्थात् एनसीओएल द्वारा प्रस्तुत एक आवेदनपत्र के आधार पर चीन जनगण और कोरिया आरपी से पीएक्स-13 सहित अन्य रबड़ रसायनों के आयातों के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की है। वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2009 से मार्च 2013 है जबकि निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि है जो जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 है। अतः दोनों जांचों में जांच किए जा रहे क्षति की अवधि एक दूसरे को अतिच्छादित करती है।

3 अतः समान उत्पाद अर्थात् पीएक्स-13 के लिए समान घरेलू उद्योग और समान अवधि के लिए डीजीएडी के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि उसे चीन लोक गणराज्य और कोरिया आरपी से पारित आयातों के कारण क्षति हो रही है। इसके दूसरी ओर रक्षोपाय महानिदेशक के समक्ष घरेलू उद्योग यह तर्क दे रहा है कि उसे सभी देशों से आयातों में भारी वृद्धि के कारण गंभीर क्षति हो रही है।

4 आयातकों का यह तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग यह दोनों आवेदनपत्र एक साथ दायर नहीं कर सकता है। तथापि, आयातकों का यह तर्क है कि यदि ये दो आवेदनपत्र दायर किए गए हैं तो घरेलू उद्योग को यह अलग-अलग बताना चाहिए कि उसे चीन जन गण और कोरिया आरपी से आयातों के कारण कितनी क्षति हुई और सभी देशों से आयातों के कारण कितनी क्षति हुई।

5 इस प्रकार आयातकों का यह प्रस्तुतिकरण है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति इसके निर्यात निष्पादन के कारण हुई और इससे आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट जाता है।

10 रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में नहीं है।

रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3(1) यह प्रावधान करता है कि रक्षोपाय साधन जनहित में होना चाहिए। रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करना जनहित में नहीं होगा। मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतराल है और घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग की मांग के 50 प्रतिशत का भी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग के 100 प्रतिशत का उत्पादन करता है और अपने समस्त उत्पादन को प्रदाय कर देता है तब भी वह संपूर्ण मांग के केवल 46 प्रतिशत की ही आपूर्ति कर पाता है। अतः उपभोक्ता उद्योग के पास इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

I. मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड (घरेलू उद्योग)

1. घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद भारी क्षति हो रही है जैसा कि निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट है :

क. रक्षोपाय शुल्क मौजूद होने के बावजूद आयात भारी बाजार में बढ़ी हुई दरों पर आ रहे हैं।

ख. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है।

ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है।

घ. अभिनव अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।

ङ. आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अपनी लागत से भी कम करने को मजबूर किया गया है जिसके कारण उसे भारी क्षति हो रही है।

- च. घरेलू उद्योग बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए उप-इष्टतम कीमतें प्रस्तुत कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ है।
- छ. कर-पूर्व लाभ में ऋणात्मक स्तर तक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को नकद घाटा हो रहा है।
- ज. निवेश पर अर्जन भी ऋणात्मक स्तर तक घट गया है।
- झ. उपर्युक्त तथ्य स्पष्टतः यह सिद्ध करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यदि रक्षोपाय शुल्क हटा लिया जाता है तो इस स्थिति में और भी अधिक खराबी आ जाएगी।

2. इस समय कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं है और घरेलू उद्योग को आयातों की सतत वृद्धि के कारण बिना किसी संरक्षण के छोड़ दिया गया है। रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता न होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को आयात कीमतों का मुकाबला करने के उद्देश्य से अपनी कीमतों में और अधिक कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आयात कीमतों में रक्षोपाय शुल्क की प्रमाणा के बराबर कमी आ जाएगी और इसलिए घरेलू उद्योग को भारी घाटा, नकद घाटा होगा और यदि रक्षोपाय शुल्क को जारी नहीं रखा जाता है उसे निवेश पर ऋणात्मक अर्जन होगा और घरेलू उद्योग की क्षति और अधिक बढ़ जाएगी।
3. किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा तथ्यों और विधि के आधार पर कोई प्रमाणिक तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्तुतिकरण यह सिद्ध नहीं करता है कि रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण करने से संबंधित घरेलू उद्योग का दावा उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ घरेलू उद्योग ने इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि उन्होंने क्षति या उसकी चुनौती से समायोजन करने के लिए साधन जुटा लिए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जारी रखना चाहिए।

4 उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी यह प्रस्तुत करता है कि रक्षोपाय शुल्क को अधिरोपित किए जाने में होने वाला कोई भी विलंब घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित करेगा। अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक कृपया इस जांच में शीघ्रता लाएं जिससे घरेलू उद्योग को होने वाली अपूरणीय क्षति से बचा जा सके।

12 सार्वजनिक सुनवाई

दिनांक 19/12/2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का निर्धारण किया गया जिसमें कई हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग ने भाग लिया था। हितबद्ध पक्षकारों के सुनवाई के पश्चात के अधिकांश उत्तर उनके द्वारा विगत में जांच शुरूआत पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरणों के अनुरूप ही है और संक्षिप्तता के कारण उन जांच शुरूआत पश्चात प्रस्तुतिकरणों को यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

13 . मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, कोरिया

क. घरेलू उद्योग का आधार

1. दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 की सार्वजनिक सुनवाई में महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष आवेदक ने दावा किया है कि सभी घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

- (क) एनओसीआईएल : 8500 एमटी/प्रति वर्ष
- (ख) मर्केस : 8500 एमटी/प्रति वर्ष
- (ग) लेनक्सेस : 2000 एमटी/ प्रति वर्ष
- (घ) पीएमसी : 1000 एमटी/ प्रति वर्ष

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि मर्केम उपान्तिम मध्यवर्ती कच्चे माल (4-एडीपीए) का उत्पादन करने के उद्देश्य से अपना क्षमता विस्तार करने जा रहा है। भारी क्षमता संवर्धन को देखते हुए घरेलू बाजार में उत्पादन विवरण में भारी परिवर्तन आ गया है। यह नोट किया जाना चाहिए कि मर्केम लिमिटेड अपने नए संयंत्र से 4 एडीपीए का उत्पादन कर रहा है जैसाकि उसने अपनी वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है (सामग्री को अनुबंध-3 के रूप में शामिल किया गया है)। इस प्रकार आवेदक को अन्य घरेलू उत्पादकों से भी कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जो बाजार पर अथवा कब्जा जमाना चाहते हैं। संगत उद्धरण अधोलिखित है :

"आपकी कंपनी जो टायर एवं रबड़ उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले एंटीआक्सीडेंट – एंटीओजोनेट 6 पीपीडी (एन- (1,3-डाइमिथायली ब्यूटाइल) – एन – फिनायल – पी – फिनायलीन डायामाइन) का विनिर्माण अपनी नई इकाई से करने जा रही है जिसका प्रचालन इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। आपकी कंपनी का 6 पीपीडी का विनिर्माण करने में प्रयोग किए जाने वाले एक रसायन मध्यवर्ती (4- एमिनोडाइफिनायलामाइन) 4 एडीपीए का विनिर्माण भी करने का प्रस्ताव है।"

3. आवेदक की संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः, इस बात की अत्यधिक संभावना है कि यह अंततः, 50 प्रतिशत संबद्ध वस्तु का भी उत्पादन नहीं करेगी। ऐसा स्थिति में, यह प्रश्न विचारार्थ उठता है कि क्या आवेदक उत्पादक "बड़े भाग का" उत्पादन करता है।
4. यह भी नोट किया जाना चाहिए कि किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक के आवेदक की याचिका का समर्थन नहीं किया है और यह पहले से ही ज्ञात है कि आवेदक को अपनी ही अक्षमताओं और अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हो रही है। उपर्युक्त के आलोक में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे आवेदक के इस आधार के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि आवेदक रक्षोपाय करार और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत आता भी है या नहीं।
5. केपीसी घरेलू बाजार में होने वाले परिवर्तन की समीक्षा करने की महत्ता पर बल देना चाहता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में होने वाले भारी परिवर्तन को नोट करते हुए तदनुसार आवेदक के आधार की जांच करें।

ग. भारतीय विधि इस विचार का समर्थन करती है कि अवधि का विस्तार केवल मूल अवधि की समाप्ति से पहले ही किया जा सकता है

1 भारतीय विधि इस विचार का समर्थन करती है कि यदि समय में वृद्धि करने का निर्णय विगत समयावधि की समाप्ति से पहले नहीं ले लिया जाता है तो इससे निरंतरता भंग हो जाती है और उसके पश्चात लिया गया निर्णय वैध नहीं है। एक वैध निर्णय के लिए समय विस्तार हेतु न केवल अनुरोध किया जाता है बल्कि समयावधि समाप्त होने से पहले ही समय में वृद्धि किए जाने का आदेश भी पारित करना होता है। एक बार निरंतरता भंग हो जाने पर, इससे शुल्क के समय में विस्तार किए जाने के अलावा उसे नए सिरे से लागू करना उचित होगा।

2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(2) में वह प्रावधान है जो रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 तथा रक्षोपाय नियमावली के नियम 18(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। धारा 110(2) निम्नवत पठित है :

"परंतु यह कि उपर्युक्त छह माह की अवधि को, पर्याप्त कारण होने पर, सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा एक ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो छह माह से अधिक नहीं होगी।"

3 इस मामले में निरंतरता भंग हो गई है, क्योंकि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार किए जाने का निर्णय उसकी समाप्ति से पहले नहीं लिया गया है। इसलिए किसी जांच के परिणामस्वरूप रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने का निर्णय वैध नहीं होगा क्योंकि वह निर्णय 29 अगस्त, 2013 को रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात आएगा। यह उदग्रहण भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित नीतिशास्त्र को विरुद्ध होगा।

ग. संबद्ध समीक्षा की शुरुआत करना भारत की क्रिया प्रणाली के विपरीत है और भारत के व्यापारिक भागीदारों की। डब्ल्यूटीओ ढांचे के अंतर्गत विधिक प्रत्याशाएं नष्ट हो जाएंगी।

1. केपीसी महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान भारत की राष्ट्र क्रियाप्रणालियों तथा अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य राष्ट्रों द्वारा लागू रक्षोपाय साधनों की ओर आकृष्ट करना चाहता है। केपीसी यह प्रस्तुत करता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह अनुरक्षित किया है कि यदि रक्षोपाय शुल्क की एक बार समाप्ति से पहले उसमें विस्तार नहीं किया जाता है तो कोई देश फिर उसमें उत्तरवर्ती वृद्धि नहीं कर सकता है। यदि इस साधन की समाप्ति के पश्चात कुछ समय व्यपगत (यहां तक कि एक दिन का समय भी) हो जाने के पश्चात इस साधन का विस्तार किया जाता है तो वह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत आ जाएगा और उसके लिए एक प्रशीतन समय की आवश्यकता होगी।
2. महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान "काटन यार्न (सिलाई वाले धागे के अलावा) के आयातों के संबंध में तुर्की-रक्षोपाय साधन" ("तुर्की-काटन यार्न") शीर्षक डीएस 428 में तुर्क के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की ओर आकृष्ट किया जाता है। उपर्युक्त मामले में, भारत ने तुर्की द्वारा काटन यार्न पर शुल्क में वृद्धि करने को चुनौती दी है। भारत ने उल्लेख किया कि तुर्की द्वारा रक्षोपाय साधन में 28 जनवरी, 2012 को, उपर्युक्त साधन 14 जुलाई, 2011 को समाप्त हो जाने के पश्चात, वृद्धि करना रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 का उल्लंघन है क्योंकि तुर्की ने इस साधन का प्रयोग रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत अधिदेशित कूलिंग आफ अवधि (न्यूनतम 2 वर्ष) की प्रतीक्षा किए बिना ही कर दिया। तुर्की ने भारत की स्थिति की स्वीकार किया तथा उसने भारत के साथ एक करार किया जिसमें तुर्की रक्षोपाय साधन को वापस लेने पर सहमत हो गया।
3. अतः, यह प्रस्तुत किया जाता है कि महानिदेशक रक्षोपाय आवेदक को घरेलू एवं निर्यात उत्पादन की लागत आबंटन का आधार/क्रियापद्धति प्रदान करने का निदेशक दें, यद्यपि यह वास्तविक शीर्ष लागत या आंकड़ों का प्रकटन नहीं कर सकता है।

घ. यथार्थ क्षमता का सत्यापन

1. यह एक सामान्यतः ज्ञात तथ्य है कि रक्षोपाय शुल्क की जांच करने के लिए किसी आवेदक की क्षमता की सही-सही जांच करना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसे जांच का आयोजन करते वक्त किया जाना चाहिए। महानिदेशक रक्षोपाय को यह सत्यापित करना अपेक्षित होता है कि संबद्ध वस्तु की संस्थापित क्षमता का कितना अनुपात घरेलू उत्पादन और निर्यातों के लिए चिन्हित होता है। घरेलू उत्पादक की उत्पादन क्षमताओं का सत्यापन करते समय यह मूलभूत अपेक्षा होती है जिसे पूरा किया जाना

आवश्यक होता है। यह सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात कि आवेदक दाहेज में एक नए संयंत्र की स्थापना कर रहा है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उस संयंत्र से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे कि संयंत्र की क्षमता क्या है, इस संस्थापित क्षमता की कितनी मात्रा का उपयोग संबद्ध वस्तु का घरेलू खपत के लिए उत्पादन करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए नियोजित क्षमता का वास्तविक चिन्हांकन क्या है, की जानकारी एकत्र करना और उसका सुनिश्चयन करना आवश्यक होता है।

ड. घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा

- 1 यह नोट किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के संबंध में घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से ने क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित ढंग से कार्य किया है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
एनओसीआईएल बिक्रिया	MT	3383	3443	3690	3991
लैनक्सेस इंडिया प्रा. लि.	MT		640	1188	1700
पीएमसी रबकैम प्रा. लि.	MT	1100	1005	1390	1250
कुल		4483	5088	6268	6941
घरेलू उत्पादकों के बीच उनका हिस्सा					
एनओसीआईएल	%	75.46	67.67	58.87	57.5
	इंडेक्स	100	90	78	76
लैनक्सेस इंडिया प्रा. लि.	%		12.58	18.95	24.49
पीएमसी रबड के प्रा. लि.	%	24.54	19.75	22.18	18.01
अन्य घरेलू उत्पादकों का हिस्सा	%	24.54	32.33	41.13	42.5
	इंडेक्स	100	132	168	173

2. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि घरेलू बिक्रियों के संबंध में अन्य घरेलू उत्पादकों का हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है, यह वर्ष 2009-10 में 100, से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 132 तथा वर्ष 2011-12 के 168 से बढ़कर जांच की अवधि में 173 हो गया। इसके साथ ही आवेदक की बिक्रियों में गिरावट आई है, इसके साथ ही आवेदक की बिक्रियों में गिरावट आई है, यह वर्ष 2009-10 में 100 से घटकर वर्ष 2010-11 में 90 और 2011-12 में 78 से घटकर जांच की अवधि में 76 हो गई है। इसका आशय यह हुआ कि अन्य घरेलू उत्पादकों के हिस्से में 73 आधारभूत बिंदुओं की वृद्धि हुई वही उसी समय के दौरान आवेदक के हिस्से में 24 आधारभूत बिंदुओं की गिरावट आई। इससे दो निहितार्थ उत्पन्न होते हैं :

- (i) पहला, आवेदक की बिक्री में किसी भी गिरावट के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (ii) द्वितीय, घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी भी ही क्षति का वास्तविक कारण है।
- (iii) अन्य घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तु का प्रस्ताव आवेदक से कम कीमतों पर कर रहे हैं।

च. संबद्ध वस्तु को शुल्क मुक्त दर्जा

यह एक तथ्य है कि संबद्ध परंतु के आयातों के भारी भाग (50 प्रतिशत या उससे अधिक) का प्रयोग परिष्कृत वस्तु का निर्माण करने के लिए किया जाता है जिसका उत्तरवर्ती रूप से भारत को निर्यात किया जाता है। आयातित वस्तु के उस भाग के लिए इनको सभी शुल्कों से मुक्त रखा जाता है (i) पाटनरोधी (ii) रक्षोपाय (iii) आधारभूत सीमाशुल्क (iv) सीवीडी केंद्रीय उत्पाद कर के बराबर। परिणामस्वरूप, संबद्ध वस्तु के आयातों के उस भाग का अवसारित मूल्य गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम होता है क्योंकि उसमें बीसीडी की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह आयात संरक्षण देने के लिए अधिरोपित शुल्कों जैसे रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्क द्वारा भी प्रभावित नहीं होते हैं।

छ. आयातों के कारण क्षति का कोई साक्ष्य नहीं

1. अन्य प्रस्तुतिकरणों के पूर्वाग्रह के बिना, यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के संबंधित आयातों तथा आवेदक को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

2. यह तालिका आवेदक के आवेदनपत्र और जांच शुरूआत नोटिस से तैयार की गई है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि जब आयात वर्ष 2009-10 में 10090 एमटी से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 10607 एमटी हो गए तो घरेलू उद्योग की बिक्री 100 अनुक्रमित बिंदुओं से बढ़कर 105 अनुक्रमित बिंदु हो गई जबकि जब आयात जो वर्ष 2010-11 में 10607 एमटी थे, से घटकर वर्ष 2011-12 में 9735 एमटी हो गए तो घरेलू उद्योग की बिक्री भी 105 अनुक्रमित बिंदुओं से घटकर 103 अनुक्रमित बिंदु हो गई। तथापि, जब आयात वर्ष 2011-12 में 9735 एमटी से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 11664 एमटी हो गए तो घरेलू उद्योग की बिक्री एक बार फिर 103 अनुक्रमित बिंदुओं से बढ़कर 105 अनुक्रमित बिंदु हो गई। इसका आशय यह है कि आयातों में वृद्धि के साथ-साथ आवेदक की बिक्री में वृद्धि होती है तथा आयातों में कमी होने पर आवेदक की बिक्री में भी कमी हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आवेदक की बिक्री में कमी नहीं आती है। अतः, इससे यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री तथा आयातों के बीच कारणात्मक संबंध पूर्णतया मौजूद ही नहीं है।

3. इसके अतिरिक्त, आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2009-10 से 2012-13 के बीच धीरे-धीरे कमी हुई है। आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 में 68 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2010-11 में 65 प्रतिशत तथा इससे पुनः घटकर वर्ष 2011-12 में 61 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 में आयातों के बाजार हिस्से में केवल 2 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई और यह संबद्ध उत्पाद की 18315 एमटी भारी मांग होने के बावजूद केवल 63 प्रतिशत ही था। आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में अभी भी 5 प्रतिशत कम था। दूसरी ओर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 और 2010-11 दोनों में 24 प्रतिशत स्थिर बना रहा, इसमें वर्ष 2011-12 में मामूली सी 1 प्रतिशत की और वर्ष 2012-13 में 2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आवेदक के बाजार हिस्से में आयातों के कारण कमी नहीं आई बल्कि इसके बाजार हिस्से पर अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा कब्जा कर लिया गया जिनका हिस्सा 8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 16 प्रतिशत हो गया। स्पष्टतः, आयातों और आवेदक के बाजार हिस्से के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

4. आवेदक द्वारा महानिदेशक रक्षोपाय को प्रस्तुत समायोजन योजना और इसकी वर्ष 2012-2013 को वार्षिक योजना का विश्लेषण करने के पश्चात केपीसी यह नोटिस करता है कि इसके दाहेज संयंत्र को प्रारंभ होने में एक वर्ष का विलंब हो गया। महानिदेशक रक्षोपाय को दी गई समायोजन योजना के अनुसार दाहेज संयंत्र मार्च 2012 में प्रारंभ होना था परंतु यह मार्च, 2013 में प्रारंभ हो पाया। समायोजन योजना के अनुसार आवेदक के दाहेज संयंत्र में संबद्ध वस्तु का उत्पादन होना था परंतु याचिका के अनुसार यह केवल एक मध्यवर्ती उत्पाद 4 एडीपीए का उत्पादन ही करता है। आवेदक समायोजन योजना के अनुसार प्रतिस्पर्धा से समायोजन करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने में पूरी तरह से असफल रहा और इसके परिणामस्वरूप ही वह प्राधिकारी से यह अनुरोध नहीं कर सका कि उसे सकारात्मक उपाय करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। समायोजन के लिए सकारात्मक प्रयास करने की आवेदक की असफलता आयातों तथा कथित गंभीर क्षति या उसकी चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध तोड़ देती है।

ज. महानिदेशक रक्षोपाय को अवैध जांच जारी नहीं रखनी चाहिए।

1 ऊपर किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि जांच की समाप्ति पर रक्षोपाय शुल्क में न तो विस्तार किया जा सकता है और न ही उसे पुनः लागू किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान जांच विधिक नहीं है और इसकी निरंतरता विधि की उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह का कोई प्रस्तुतिकरण कि, यह तो जांच का एक स्तर है और अंतिम निर्णय इसके पूरा होने के पश्चात ही लिया जाएगा, विधि की उचित प्रक्रिया के दुरुपयोग का ही समर्थन करेगा।

1. समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क को बढ़ाया नहीं जा सकता है

1 आवेदक ने अपनी याचिका में रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के प्रतिकथन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यदि रक्षोपाय शुल्क एक से अधिक वर्षों से लागू हो तो इसे और अधिक बढ़ाना निषेध है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय करार तथा रक्षोपाय नियमावली दोनों में रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता या विस्तार के मामले में रक्षोपाय शुल्क का उत्तरोत्तर उदारीकरण करने का प्रावधान किया गया है। रक्षोपाय नियमावली का नियम 17 जो रक्षोपाय शुल्क के उदारीकरण का वर्णन करता है, निम्नलिखित है :

"यदि नियम 12 के अंतर्गत उदग्रहित शुल्क की कालावधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस शुल्क को इसके अधिरोपण का अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर उत्तरोत्तर उदारीकरण किया जाएगा।"

2 उपर्युक्त को देखते हुए यह निवेदन किया जाता है कि रक्षोपाय साधनों संबंधी भारतीय विधि स्पष्टतः यह प्रावधान करती है कि यदि इस साधन का प्रयोग एक वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाता है तो रक्षोपाय शुल्क का उत्तरोत्तर उदारीकरण किया जाएगा। भारतीय विधि के अधिदेश से विचलन नहीं किया जा सकता है और समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि करने के प्रतिकथन को तत्काल नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

- 3 पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरोत्तर उदारीकरण करने की जरूरत को रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7 में भी, जो रक्षोपाय साधन की कालावधि एवं समीक्षा का वर्णन करता है, अधिदेशित है। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.4 के संगत उद्धरणको निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है :

"जहां अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के अंतर्गत यथाअधिसूचित रक्षोपाय साधन की प्रत्याशित कालावधि एक वर्ष से अधिक है वहां इस साधन का प्रयोग करने वाले सदस्य इस अनुप्रयोग की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर इसका उत्तरोत्तर उदारीकरण करेंगे। पैराग्राफ 2 के अंतर्गत संवर्धित साधन शुरूआती अवधि की समाप्ति पर लगाए गए प्रतिबंध से अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होगा और यह उदारीकृत होने के लिए जारी रहना चाहिए।"

- 4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 7.4 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सदस्य देश ऐसे रक्षोपाय साधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो शुरूआती अवधि की समाप्ति पर लगे प्रतिबंध से अधिक प्रतिबंधात्मक हों। सदस्य देश रक्षोपाय साधन का उत्तरोत्तर उदारीकरण करने के लिए वचनबद्ध हैं। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.4 का निर्वचन करते समय अर्जेन्टीना फुटबियर, डब्ल्यूटी/डीएस 121/आर (अनुबंध 11) मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट ने यह धारित किया कि रक्षोपाय साधन की समीक्षा में केवल दो संशोधन ही स्वीकार्य हैं या तो साधन का प्रशमन कर दिया जाए या उदारीकरण की गति बढ़ा दी जाए।

- 5 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक रक्षोपाय आवेदक के इस प्रतिकथन को समाप्त करने की कृपा करेंगे कि रक्षोपाय शुल्क में संवृद्धि की जाए।

झ. किसी समीक्षा में परिमाणात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं

- 1 आवेदकों ने अपनी याचिका में संबद्ध उत्पाद पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की मांग की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के प्रतिकथन को स्वीकार करना रक्षोपाय नियमावली और रक्षोपाय करार के अंतर्गत प्रावधान किए गए समीक्षा के दायरे का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय साधन (परिमाणात्मक प्रतिबंध) नियमावली 2012 में परिमाणात्मक प्रतिबंधों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इसलिए आवेदक का समीक्षा में शुल्क के एक नए रूप का उदग्रहण करने का दावा है जो रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा के दायरे की पूर्णतया न्यून समझ है।

14 मैसर्स ऋषिरूप पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

इसके द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण भी ऊपर मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी कोरिया द्वारा यथा प्रदर्शित बिंदुवार प्रस्तुतिकरणों के समान ही हैं।

15 ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) और इसकी सदस्य कंपनियां (जे के टायर, सिएट, अपोलो टायर और एमआरएफ लिमिटेड) :

1 पीएक्स-13 का आयात अनिवार्य है क्योंकि घरेलू उद्योग ने पीएक्स-13 के लिए मांग आपूर्ति अंतराल उत्पन्न कर दिया है।

क घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह दावा किया है कि देश में पीएक्स-13 के आयातों में भारी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने के बावजूद हुई है। पीएक्स-13 का आयात जो वर्ष 2009-10 में 10090 एमटी था बढ़कर वर्ष 2012-13 में 11664 एमटी हो गया, तथापि उसे पीएक्स-13 की मांग में हुई भारी वृद्धि के संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है जो वर्ष 2011-12 में 15954 एमटी थी बढ़कर वर्ष 2012-13 में 18315 एमटी हो गई और घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता उसी अवधि के दौरान 8500 एमटी स्थिर बनी रही।

ख इस प्रकार पीएक्स-13 की मांग में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, परंतु घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 8500 एमटी ही बनी रही। इसलिए अगर घरेलू उद्योग अपनी 100 प्रतिशत संस्थापित क्षमता का उपयोग करके भी उत्पादन करता है और अपने संपूर्ण उत्पाद की आपूर्ति घरेलू बाजार में कर देता है तब भी वह संपूर्ण घरेलू मांगों के केवल 46 प्रतिशत की ही पूर्ति कर पाएगा। इसलिए उपभोक्ता उद्योग को इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करने का आश्रय लेना पड़ा। अतः, यह उस कारण को स्पष्ट करता है जिससे भारत में पीएक्स-13 के आयात निरंतर बने रहे।

ग घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई में यह तर्क दिया कि देश में पीएक्स-13 के लिए कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है। उसका यह कथन गलत है। पीएक्स-13 के लिए रक्षोपाय जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि घरेलू उद्योग की वर्ष 2012-13 के लिए संस्थापित क्षमता केवल 8500 एमटी है। इस प्रकार नए संयंत्र की स्थापना के उपरांत पीएक्स-13 की संस्थापित क्षमता में वृद्धि होगी जो रक्षोपाय समीक्षा जांच में अगस्त, 2013 में प्रकाशित जांच शुरूआत अधिसूचना से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की क्षमता केवल 8500 एमटी है जिसमें से 50 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है और शेष बची क्षमता की भारत में प्रयोक्ता उद्योग के लिए है। अधोलिखित तालिका और ग्राफ उसका विवरण प्रस्तुत करती है :

पीएक्स-13	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
संस्थापित क्षमता (एमटी)	5500	5720	5720	5900	8024	8024	8500	8500	8500	8500
अनुक्रमित	100	104	104	107	146	146	155	155	155	155
कुल मांग (एमटी)	5971	8007	7424	8753	11095	10053	14705	15949	15954	18315
कुल मांग (अनुक्रमित)	100	134	124	147	186	168	246	267	267	307

घ उपर्युक्त तालिका एवं चार्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पीएक्स-13 की मांग और घरेलू उद्योग द्वारा उसकी आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। तथापि, इस भारी अंतर के बावजूद घरेलू उद्योग इस विसंगति को दूर करने के लिए आज की तारीख तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा दाहेज में प्रारंभ किया गया एक नया संयंत्र, केवल 4 एडीपीए का विनिर्माण करने के लिए। इस प्रकार नए संयंत्र के प्रारंभ हो जाने से भी यह विसंगति दूर नहीं होगी।

2 भारत में पीएक्स-13 की कुल क्षमता भारत में पीएक्स-13 की कुल मांग से कम है

क घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पुनः तर्क दिया है कि देश में मांग आपूर्ति अंतराल का आकलन करने के उद्देश्य से भारतीय मांग की तुलना कुल भारतीय क्षमता से करने की आवश्यकता है, न कि केवल प्रार्थी कंपनी की क्षमता से और यदि ऐसा किया जाता है तो पीएक्स-13 के लिए कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं रहेगा। तथापि घरेलू उद्योग का यह प्रस्तुतिकरण सही नहीं है तथा यह भार भ्रामक है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित तालिका इसका विवरण प्रस्तुत करती है :

तालिका 2

	2012-13 (जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार)
घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता	8500 एमटी
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	61.60%
अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा	38.4%
अन्य भारतीय उत्पादकों की संस्थापित क्षमता	5299 एमटी
भारत में पीएक्स-13 के लिए कुल संस्थापित क्षमता	13,799 एमटी
भारत में पीएक्स-13 के लिए कुल मांग	18,315 एमटी

ख इस प्रकार वर्तमान जांच में जांच शुरूआत अधिसूचना में यह सूचित किया गया कि घरेलू उद्योग का पीएक्स-13 के भारतीय उत्पादकों में 61.60 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। इसलिए यदि शेष 38.4 प्रतिशत भारतीय उत्पादकों के संबंध में भी विचार किया जाता है तो कुल भारतीय उत्पादन फिर भी लगभग 13799 एमटी के आसपास बैठता है और यह तब भी 18315 एमटी की कुल भारतीय मांग से 4516 एमटी कम है। अतः यदि घरेलू उद्योग का तर्क मान भी लिया जाए तो भी मांग एवं आपूर्ति में अंतराल बचता है।

3 यह जांच भारतीय रक्षोपाय अधिनियम एवं नियमावली के विरुद्ध है।

क आयातकों द्वारा प्रस्तुत क्षति के मद्देनर यह सुस्थापित स्थिति है कि नियम 18 के अंतर्गत रक्षोपाय समीक्षा जांच के अनुसरण में माननीय महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता के लिए की गई सिफारिश से पहले रक्षोपाय शुल्क मौजूद रहना चाहिए। नियम 18 यहां उल्लिखित किया जाता है

18. समीक्षा

1. महानिदेशक रक्षोपाय, रक्षोपाय शुल्क के निरंतर अधिरोपण की जरूरत के लिए समय-समय पर समीक्षा करेंगे और उनको प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं कि '

- (i) गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका समाधान निकालने के लिए रक्षोपाय शुल्क अनिवार्य है और इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि उद्योग सकारात्मक ढंग से समायोजन कर रहा है तो वह केंद्रीय सरकार को शुल्क का सतत अधिरोपण करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं।"

ख अतः नियम 18 के अंतर्गत माननीय महानिदेशक रक्षोपाय का दायित्व है कि वह केंद्रीय सरकार से शुल्क का सतत अधिरोपण करने की सिफारिश करें। यह नोट किया जाता है कि नियम 18 के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता के लिए सीमाशुल्क अधिसूचना रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले अधिसूचित की जानी चाहिए। अतः रक्षोपाय की समाप्ति से पहले माननीय महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा अंतिम जांच परिणाम के रूप में सिफारिश किए जाने तक नियम 18 के अंतर्गत की अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है।

ग माननीय महानिदेशक रक्षोपाय की पिछली परम्परा भी स्पष्टतः यह स्थापित करती है कि पिछली सभी रक्षोपाय समीक्षा जांचों में अंतिम जांच परिणाम के रूप में माननीय महानिदेशक रक्षोपाय तक सिफारिश को रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले प्रकाशित किया गया है। निम्नलिखित उसका विवरण स्पष्ट करती है :

उत्पाद	मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम	सीमाशुल्क अधिसूचना और कालावधि	शुल्क की समाप्ति	समीक्षा जांच के लिए जांच शुरूआत अधिसूचना	समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम
फिनाल	11 जून, 1999	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 82/99 शुल्क की कालावधि 30/06/1999 से 20/06/2001	शुल्क	1 जनवरी, 2001 (पहली समीक्षा जांच)	16 मई, 2002
फिनाल	16 मई, 2001 (प्रथम समीक्षा की अंतिम जांच की तारीख)	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 73/2001 इस शुल्क की कालावधि 30/06/2001 से 29/06/2003 तक	इस शुल्क	22 अक्टूबर, 2001 (द्वितीय समीक्षा जांच)	11 दिसम्बर, 2001
एसीटोन	07 अक्टूबर, 1999	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 7/2000 शुल्क की कालावधि 27/01/2000 से दिनांक 26/07/2002 तक	शुल्क	21 नवम्बर, 2001	4 फरवरी, 2002
सोडा ऐश	06 अक्टूबर, 2009	सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 122/2009 शुल्क की कालावधि दिनांक 20/04/2009 से दिनांक 19/04/2010 तक	शुल्क	19 फरवरी, 2010	13 अप्रैल, 2010

घ घरेलू उद्योग के सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया कि रक्षोपाय शुल्क "स्थगन सहित या स्थगन के बिना" जारी रहनी चाहिए और इस संबंध में सोडा ऐश की जांच का उल्लेख किया जिसमें रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण की सूचना रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात की गई थी। तथापि सोडा ऐश की जांच ने आयातकों की स्थिति का पुनः समर्थन किया है।

ड भारत में सोडा के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने की अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल, 2010 तक प्रभावी थी। सोडा ऐश समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित किया गया था। सोडा ऐश समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम के रूप में माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय ने केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें तब की थी जब रक्षोपाय शुल्क मौजूद था। इसलिए सोडा ऐश समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम नियम 18 के अनुपालन में था और यह आयातकों के इस प्रस्तुतिकरण का समर्थन करती है कि आज की तारीख तक ऐसी एक भी रक्षोपाय समीक्षा जांच नहीं हुई माननीय महानिदेशक रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात की गई हो।

च उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्तमान समीक्षा जांच दिनांक 29 अगस्त, 2013 को प्रारंभ की गई थी। सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया था जो 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गया है। इस प्रकार इस समय भारत में पीएक्स-13 के आयोग पर कोई रक्षोपाय मौजूद नहीं है। चूंकि इस समय कोई भी रक्षोपाय शुल्क मौजूद नहीं है, इसलिए वर्तमान समीक्षा जांच अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि केंद्रीय सरकार "शुल्क के सतत अधिरोपण" की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम के अनुसरण में मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की "निरंतरता" बरकारा नहीं रख सकती है।

4 विधायन का आशय

क घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनाई में यह तर्क दिया कि नियम 18 में "सतत अधिरोपण" का आशय है "विराम सहित या बिना विराम के" और उन्होंने सोडा ऐश रक्षोपाय जांच का उदाहरण दिया है। तथापि, आयातकों ने जैसा पहले ही सिद्ध किया है, सोडा ऐश रक्षोपाय जांच मामले में अंतिम जांच परिणाम रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने से पहले जारी किया गया था और इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा सोडा ऐश रक्षोपाय शुल्क पर भरोसा करना सही नहीं है।

ख इसके अतिरिक्त, आयातक यह भी मुद्दा उठा सकते हैं कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 19 में विधायन निर्माताओं ने "निरंतर" शब्द का प्रयोग इरादमन किया है और उन्होंने "विस्तार" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के विपरीत है जहां दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है परंतु उनका निहितार्थ अलग-अलग है। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) यहां पुनरुत्पादित की जाती है :

"इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण न किया गया हो तो, ऐसे अधिरोपण का तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगी :

परंतु शर्त यह है कि केंद्रीय सरकार का एक समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त करने में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह, समय-समय पर, ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार पांच वर्षों की अन्य अवधि के लिए कर सकते हैं और यह अतिरिक्त अवधि ऐसे विस्तार की तारीख की अवधि से प्रारंभ होगी :

परंतु यह और कि जहां उपरिलिखित पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले यह समीक्षा प्रारंभ की जाती है और उस पर ऐसी समाप्ति से पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया गया है वहां पाटनरोधी शुल्क ऐसी समीक्षा का परिणाम लंबित रहने तक प्रभावी रहेगी परंतु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ग) उपर्युक्त उपलब्ध में पैराग्राफ 2 में शब्द "विस्तार" स्पष्टतः यह विनिर्धारित करता है कि शुल्क की शुरुआत की अवधि ऐसे शुल्क के शुरुआत के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी। इस प्रकार पाटनरोधी अधिनियम स्वतः ही यह उपबन्धित करता है कि पिछले पाटनरोधी शुल्क तथा निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में अन्य पांच वर्षों के लिए संवर्धित किए जा रहे पाटनरोधी शुल्क में अंतराल हो सकता है।

घ) तथापि, यदि केंद्रीय सरकार का निर्णायक समीक्षा जांच के लंबित रहने पर पाटनरोधी शुल्क की "निरंतरता" बनाए रखने का इरादा है तो ऐसा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पहले प्रारंभ किए गए निर्णायक समीक्षा जांच में बिना कोई अंतराल रहे किया जा सकता है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा जांच के लंबित रहने तक बिना किसी अंतराल के पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा।

च) इस प्रकार शब्द "विस्तार" और "निरंतरता" के प्रयोग के संबंध में विधायन के आशय को पाटनरोधी अधिनियम के स्पष्टतः चिन्हित कर दिया गया है। आयातक इसी दिशानिर्देश पर भरोसा करते हैं और माननीय महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 में भी "निरंतरता" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्टतः अभिव्यक्त करता है कि नियम 18 में शब्द "निरंतरता" के अंतःबद्ध करने का विधान निर्माताओं का आशय यह सुनिश्चित करना था कि माननीय महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा संसृति रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले प्रकाशित की जानी चाहिए।

छ) अंत में, माननीय महानिदेशक रक्षोपाय एक अर्द्धन्यायिक निकाय होने के कारण वह रक्षोपाय अधिनियम और रक्षोपाय नियमावली के अधिदेश से परे जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। आयातकों की इस स्थिति का धिक्काला कैमिकल्स बनाम महानिदेशक रक्षोपाय के मामले में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी समर्थन किया गया है। इस मामले में प्रार्थी ने सीमाशुल्क अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के पश्चात रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस संबंध में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के निम्नलिखित पाया था :

उपर्युक्त विचार के अलावा, प्रार्थी से इस न्यायालय में दिनांक 30 जून, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 75/2009-सीमाशुल्क के समय के अंदर आना चाहिए था। एक बार अधिसूचना की अवधि समाप्त हो जाने और इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाने की अनुमति दे दिए जाने पर, किसी मृतप्राय अधिसूचना में न्यायिक आदेश द्वारा प्राण संचरण करना, और वह भी अंतरिम स्थिति पर, संभव नहीं है।

ज) माननीय बंबई उच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय स्पष्टतः स्थापित करता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने की अधिसूचना की अवधि एक बार समाप्त हो जाने की स्थिति में उसे न्यायिक आदेश द्वारा पुनः अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। माननीय महानिदेशक रक्षोपाय केंद्रीय सरकार से रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रभावी रक्षोपाय शुल्क पहले ही समाप्त हो चुका है और रक्षोपाय अधिनियम एवं रक्षोपाय नियमावली समीक्षा जांच लंबित रहने पर रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

5. सकारात्मक समायोजन की अपेक्षा को पूरी नहीं किया गया है

क) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में मूल जांच में निम्नलिखित उल्लेख किया था :

एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जहां कंपनी का इरादा *** एमटी रबड़ रसायनों और मध्यवर्तियों का उत्पादन करने का है जिसमें एक उत्पाद के रूप में पीएक्स-13 शामिल है।"

ख) तथापि घरेलू उद्योग की इस स्थिति में समीक्षा जांच में एकाएक परिवर्तन आ गया जिसमें घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि वह नए संयंत्र पर 5 एपीएल का विनिर्माण कर रहा है और घरेलू उद्योग के अनुसार यह भी एकमात्र उत्पाद है जिसका उत्पादन दाहेज संयंत्र में किया जाएगा।

ग) इसके अतिरिक्त, मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम ये उल्लेख किया गया कि नए संयंत्र में उत्पादन अप्रैल 2012 से प्रारंभ होगा। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार नए संयंत्र में उत्पादन मार्च, 2013 में प्रारंभ हुआ था और यह लगभग एक वर्ष का विलंब है।

घ) उपर्युक्त के मद्देनजर आयातकों का यह प्रस्तुतिकरण है कि घरेलू उद्योग ने विनिर्मित की गई और माननीय महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा मूल जांच में स्वीकृत समायोजन योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है घरेलू सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है क्योंकि स्वयं समायोजन योजना को ही क्रियान्वित नहीं किया गया है।

6) समायोजन योजना की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है

क) मूल जांच में घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क का तीन वर्षों तक अधिरोपण करने का अनुरोध किया था और अपनी समायोजन योजना का विवरण प्रदान किया था। मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम के अनुसार माननीय रक्षोपाय महानिदेशक ने घरेलू उद्योग की समायोजन योजना के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला था :

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना में घरेलू मांग को पूरा करने और लागत में कमी करने के लिए क्षमता विस्तार करने पर प्रकाश डाला गया है।इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को उपरिशीर्ष लागत के कारण भी लागत में कमी होने की उम्मीद हैयह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का यह दावा इस नए संयंत्र पर होने वाले व्यय और विस्तार के संबंध में सनदी अभियंता के प्रमाणपत्र और इस पर आने वाली लागत तथा लागत में कमी होने का दावा पेशेवर लागत लेखाकर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है।

ख) अतः घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क का तीन वर्षों तक अधिरोपण करने का अनुरोध किया था जिससे कि वह दाहेज में एक नए संयंत्र की स्थापना करके अपनी लागत में कमी कर सके। तथापि माननीय महानिदेशक ने दो वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। अतः माननीय महानिदेशक रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त समायोजन योजना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए दो वर्षों की समयावधि पर्याप्त है।

ग) तथापि, अब घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने और उसमें संवृद्धि करने का अनुरोध कर रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग उन दो वर्षों की अवधि से परे रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने और संवृद्धि करने का अनुरोध कर रहा है जो माननीय महानिदेशक रक्षोपाय के विचार से सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए पर्याप्त था इसलिए घरेलू उद्योग से एक नई समायोजन योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) के साथ पठित नियम 18 की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

घ) इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान समीक्षा याचिका में प्रदान कराई गई समायोजन योजना वही है जो उसने मूल जांच में उपलब्ध कराई थी अर्थात् दोहज संयंत्र में 4 एपीडीए का उत्पादन होने के कारण लागत में कमी होना। तथापि, माननीय रक्षोपाय महानिदेशक ने अपनी मूल जांच में समायोजन योजना के आधार पर यह निष्कर्ष पहले ही निकाला था कि घरेलू उद्योग को केवल दो वर्षों के लिए शुल्क के संरक्षण की जरूरत है जो उसे अगस्त, 2011 से अगस्त, 2013 तक के लिए प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार, समान समायोजन योजना वह आधार नहीं बन सकती है जिस पर घरेलू उद्योग अपनी समायोजन योजना के आधार पर चार वर्षों के शुल्क संरक्षण की मांग कर रहा है जबकि माननीय रक्षोपाय महानिदेशक ने पहले ही यह निर्णय किया है कि 2 वर्षों का शुल्क संरक्षण पर्याप्त है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के उस तर्क से, जो इस समय प्रभावी है, माननीय निदेशक रक्षोपाय के उस निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी कि 2 वर्षों की शुल्क संरक्षण की अवधि पर्याप्त है, यद्यपि भारतीय रक्षोपाय अधिनियम और नियमावली ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं।

ग) इसलिए इस तथ्य के आलोक में समायोजन योजना के संबंध में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आयातक माननीय महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष यह निवेदन करते हैं कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2)(ख) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

7. रक्षोपाय समीक्षा जांच में संवर्धित आयातों, गंभीर क्षति और कारणात्मक संबंधों की आवश्यकता भी लागू होती है।

घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका तथा सार्वजनिक सुनवाई में यह अनुरोध किया था कि रक्षोपाय समीक्षा जांच में आयातों में वृद्धि या गंभीर क्षति की मौजूदगी अपेक्षित नहीं होती है। तथापि घरेलू उद्योग के इस तर्क की रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार, रक्षोपाय अधिनियम और रक्षोपाय नियमावली के मौजूदा ढांचे द्वारा समर्थन नहीं होता है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक, तीव्र एवं पर्याप्त वृद्धि नहीं है

आयातों ने उपर्युक्त पैराग्राफों में स्पष्टतः सिद्ध किया है कि भारत में पीएक्स-13 की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है और घरेलू उद्योग भारत में उपयोक्ता उद्योग की मांग को पूरा करने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य के मद्देनजर भारत में उपयोक्ता उद्योग में अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयातों का सम्बल लिया है, एटीएमए यह प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में यह वृद्धि अभिनव रूप से यकायक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि नहीं है जो कि रक्षोपाय नियमावली और रक्षोपाय अधिनियम की एक अपेक्षा है।

9. गंभीर क्षति नहीं हुई

एटीएमए ने अपने क्षति प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि गंभीर क्षति के बारे में घरेलू उद्योग का दावा याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सिद्ध नहीं होता है। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई में गंभीर क्षति के संबंध में कोई नया तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। एटीएमए, यदि घरेलू उद्योग सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए किसी लिखित प्रस्तुतिकरण में गंभीर क्षति के नए दावे के संबंध में कुछ अन्य कहता है तो वह घरेलू उद्योग के गंभीर क्षति के दावे का खंडन करने और प्रत्युक्ति में गंभीर क्षति के नए दावे का खंडन करने के लिए अपने क्षति विश्लेषण में किए गए प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा करता है।

10. क्षति का कोई पृथक्करण नहीं

क) आयातक महानिदेशक रक्षोपाय का ध्यान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उस प्रस्तुतिकरण की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो उसने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किया है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि पीएक्स-13 का आयात मुख्यतः कोरिया आरपी चीन जन गण और यूरोपियन यूनियन से किया जाता है। इसलिए यदि आयात मुख्यतः इन्हीं देशों से किए जाते हैं तो यह प्रकल्पना करना तर्कसंगत है और घरेलू उद्योग को इन देशों से पीएक्स-13 के आयातों से भी क्षति हो रही है। तथापि महानिदेशक पाटनरोधी ने इन देशों से पीएक्स-13 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही अधिरोपित कर रखा है।

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन और चीनीतोईपेई में उदभावित अथवा वहां से आयातित रबड़ रसायनों पीएक्स-13 के आयातों पर पाटनरोधी जांच (एडी) प्रारंभ की है। उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के विरुद्ध वर्ष 2010 में एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की गई थी और उसके अनुसरण में यूरोपियन यूनियन से पीएक्स-13 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखी गई थी।
- वर्ष 2007 में उन्ही निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन गण और कोरिया जन गण से पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों के विरुद्ध एक पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और उत्तरवर्ती रूप से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था और उसे वर्ष 2011 में कोरिया आरपी से पीएक्स-13 के आयातों पर भी संवर्धित किया गया था।

ख) इस प्रकार यदि घरेलू उद्योग को इन देशों से पीएक्स-13 के आयातों पर गंभीर क्षति हो रही है तो उस पर पाटनरोधी महानिदेशालय में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करके उसका ध्यान रखा है। तथापि यदि घरेलू उद्योग अभी भी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपित करने का अनुरोध करता है तो घरेलू उद्योग को पाटनरोधी हो रही क्षति और उपर्युक्त देशों से पीएक्स-13 के बढ़ते आयातों द्वारा हो रही क्षति के बीच पृथक्करण करना चाहिए था।

ग) यह भी नोट किया जाना चाहिए कि पाटनरोधी महानिदेशालय ने इसी घरेलू उद्योग अर्थात् एनओसीआईएल द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन के आधार पर चीन जन गण कोरिया आरपी से कतिपय रबड़ रसायनों, पीएक्स-13 सहित का आयात करने के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की है। वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2013 है जबकि निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि जो जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 है। इस प्रकार क्षति अवधि, जो दोनों जांचों में परीक्षण किया जा रहा है, एक दूसरे को आच्छादित करता है।

घ) इसलिए समान घरेलू उद्योग समान उत्पाद अर्थात् पीएक्स-13 के लिए और समान अवधि के लिए सीमाशुल्क महानिदेशालय के समक्ष जांच कर रहा है जिसे चीन जन गण और कोरिया आरपी से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। दूसरी ओर महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष घरेलू उद्योग यह तर्क दे रहा है कि उसे सभी देशों से आयातों में वृद्धि के कारण गंभीर क्षति हो रही है।

ड) आयातों का यह तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग एक साथ यह दोनों आवेदनपत्र दायर नहीं कर सकता है। तथापि आयातकों का यह तर्क है कि यदि यह दोनों आवेदनपत्र दायर किए गए हैं तो घरेलू उद्योग का यह दायित्व है कि चीन जन गण और कोरिया आरपी से पारित आयातों द्वारा सहन की गई क्षति और सभी देशों से पाटित आयातों द्वारा सहन की गई क्षति का अलग-अलग विवरण दें।

11. निर्यातों में कमी के कारण हुई क्षति

इसके अतिरिक्त आयातक इस तथ्य पर भी प्रकाश डालेंगे कि घरेलू उद्योग को निर्यात बाजार में मांग में कमी होने के कारण क्षति हुई है जिसका उत्पादन और निर्यात बिक्री पर प्रभाव पड़ा है।

12. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा

क) मिथाइल एसिटोएसिटेट रक्षोपाय जांच में महानिदेशक रक्षोपाय ने यह नोट किया है कि फार्मास्युटिकल उद्योग इस उत्पाद का महत्वपूर्ण उपयोक्ता है। यह निष्कर्ष निकालने में कि इस शुल्क का उदाहरण करना जनहित में नहीं होगा। यह प्रेक्षण किया गया है "घरेलू उद्योग यह साक्ष्य देने में समर्थ नहीं हुआ है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किस तरह इन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा, जिनमें से कुछ फार्मा सेक्टर में हैं और इसका बहुत कम प्रभाव होगा जिससे कि यह जनहित में रहेगा।" माननीय रक्षोपाय महानिदेशक ने शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश से मना कर दिया क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा अन्य कारकों में जनहित की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया था।

ख) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार घरेलू उद्योग पिछले 8 वर्षों से शुल्क संरक्षण प्राप्त कर रहा है और इस अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है और इस अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि वह भारत में पीएक्स-13 की मांग को पूरा कर सके। आज की स्थिति के अनुसार घरेलू उद्योग भारत में पीएक्स-13 की कुल घरेलू मांग में से केवल 46 प्रतिशत को ही पूरा करने में सक्षम है। इसलिए उपभोक्ता उद्योग को आयातों का सहारा लेना पड़ा है। तथापि, उपभोक्ता उद्योग पिछले 8 वर्षों से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग उसका प्रदाय करने में अक्षम है और उस पर घरेलू उद्योग की 8 वर्षों के शुल्क संरक्षण के बावजूद प्रतिस्पर्धी बनने में अक्षमता के लिए और अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

ग) उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग इस समीक्षा जांच में यह प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 8 वर्षों के पश्चात रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण का प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह जनहित में होगा। हालांकि घरेलू उद्योग ने आज की तारीख तक इसका प्रदर्शन नहीं किया है। इस कमी तथा माननीय रक्षोपाय महानिदेशक की पिछली कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

16. यूरोपियन कमीशन

यूरोपियन कमीशन (आयोग) रबड़ रसायन पीएक्स-13 के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा के संबंध में इस सुनवाई में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता है।

- क) प्रारंभ में और पिछले प्रस्तुतिकरण में उठाए गए मुद्दे के संबंध में आयोग भारतीय प्राधिकारियों की इस स्थिति से सहमत नहीं है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, निष्प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त, किया जा सकता है। यदि पाटनरोधी शुल्क समामेलन या प्रतिबलन जैसे उदाहरणों के कारण निष्प्रभावी हो जाती है तो पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की जानी चाहिए।
- ख) इसलिए आयोग यह भी विचार करता है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना आवश्यक है। घरेलू उद्योग को चीन और ईयू तथा कोरिया (जिसमें भारत को आयात होने वाले लगभग समस्त आयात कवर हो जाते हैं) से होने वाले आयातों पर वर्ष 2005 और 2008 में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क द्वारा पहले से ही संरक्षण प्राप्त है।
- ग) आयोग को भरोसा है कि भारतीय प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अच्छी तरह से व्यापार किए जाने वाले आयातों को दंडित करना, चाहें उनके उद्गम का देश कुछ भी हो और वे व्यक्तिगत रूप से घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित कर रहे हो या नहीं, कोई समाधान नहीं है।
- घ) इसके अतिरिक्त हम निम्नलिखित मुद्दे भी उठाना चाहते हैं जिनकी और जांच शुरूआत के नोटिस और उद्योग याचिका का विश्लेषण करते वक्त हमारा ध्यान गया है :
 - i) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, पहले से अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के ऊपर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस समीक्षा जांच की शुरूआत में गंभीर प्रकार्यात्मक दोष है और इस प्रक्रिया से रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करना विधिक रूप से संभव नहीं होगा।
 - ii) विशेषकर, समीक्षाधीन शुल्क 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए एक ही उत्पाद के लिए पहले से अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की अतिरिक्त समय के लिए संभावना के लिए नई जांच करके नए शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक होगा।
 - iii) तथापि, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 9.2 के अनुसार किसी ऐसे उत्पाद पर जिस पर रक्षोपाय शुल्क पहले से ही अधिरोपित है रक्षोपाय शुल्क, मूल शुल्क की दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात अर्थात् इस मामले में अगस्त, 2015 के पश्चात ही अधिरोपित किया जा सकता है।
 - iv) इसलिए भारत को यह जांच तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यह संपुष्ट करना चाहिए कि यह शुल्क समाप्त हो चुका है।
 - v) यह कहा जा सकता है कि क्या भारत को वर्तमान प्रक्रिया (जो अभिव्यक्त रूप से अवैध होगा) से आगे बढ़ने का निश्चय करना चाहिए, आयोग आग्रह करता है कि विशेषकर इस मामले में रक्षोपाय साधन का विस्तार करना वांछित नहीं होगा।

vi) यह पुनः याद दिलाया जाता है कि प्रार्थी ने अपने आवेदनपत्र में दावा किया है कि क्षति कारित करने के लिए आयात जारी रहे। चूंकि शुल्क का अधिरोपण किया गया है इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री में मामूली सी वृद्धि हुई और तत्स्थानी बाजार हिस्सा संगत रूप से स्थित रहा। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक अन्य (शिकायत न करने वाले) भारतीय उत्पादक को इस साधन से लाभ हुआ क्योंकि इसका बाजार हिस्सा विचारित अवधि में दोगुना (वर्ष 2009-10 में 8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 16 प्रतिशत) हो गया। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को आयातों के अलावा अन्य कारणों द्वारा कारित समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

vii) इस संदर्भ में आयोग भारतीय प्राधिकारियों को पुनः याद दिलाना चाहेगा कि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.4 के अनुसार कोई साधन, यदि उसमें विस्तार किया जाता है तो शुरूआती अवधि की समाप्ति पर जितना प्रतिबंधात्मक था, उससे अधिक प्रतिबंधशाली नहीं होना चाहिए और वह निरंतर से उदारीकृत होना चाहिए। इस समय निष्प्रभावी साधन को अनिवार्यतः संबंधित स्तर पर विस्तारित करने को न्यायोचित ठहराया असंभव हो जाएगा।

इ) निष्कर्षतः आयोग यह पुनः दोहराती है कि चूंकि साधन समाप्त हो चुका है इसलिए उन्हें एक समीक्षा जांच के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है और नया अधिरोपण अगले दो वर्षों में नहीं किया जा सकता है।

च) किसी भी स्थिति में यह साधन निष्प्रभावी शुद्ध हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और अगले दो वर्षों तक के लिए नया अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। इस साधन में वृद्धि करना विधिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं होगा और इसलिए आयोग यह प्रेरित करता है कि भारतीय प्राधिकारी मौजूदा प्रक्रिया को समाप्त करें और साधन की समाप्ति की संपुष्टि करें।

17) घरेलू उद्योग

मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड (घरेलू उद्योग) :

क. गंभीर क्षति कारित करने वाले संबंधित आयातों का इतिवृत्त जिनसे रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया।

1. इससे पहले महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात 'रक्षोपाय नियमावली' कहा गया है) के नियम 5 के अनुसार एनओसीआईएल द्वारा भारत में पीएक्स-13 के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग करते हुए यह स्थापित करते हुए कि पीएक्स-13 के संबंधित आयात भारत के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं या/और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, दायर एक आवेदनपत्र के संबंध में एक जांच प्रारंभ की गई थी। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाएं संतुष्ट होती हैं, पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 की जांच शुरूआत नोटिस के तहत एक जांच की शुरूआत की गई। महानिदेशक ने 6 जून, 2011 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिसमें दो वर्षों के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। महानिदेशक रक्षोपाय की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार ने दिनांक 30/08/2011 से 29/08/2012 तक देय 30 प्रतिशत प्लस पाटनरोधी शुल्क की दर से और 30/08/2012 से 29/08/2013 तक के लिए देय 25 प्रतिशत जमा पाटनरोधी शुल्क की दर से दो वर्षों के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया।

ख. घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाली पीएक्स-13 का पाटन

1. पीएक्स-13 के आयात इस समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई एक व्यापक पाटनरोधी जांच के उपरांत इस समय पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं। माननीय प्राधिकारी ने इससे पूर्व चीन और कोरिया आरपी, यूरोपीयन यूनियन से पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में पाटन की प्रकृति एवं सीमा तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित देशों के उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीतों पर आयात कर रहे हैं और उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई। तदनुसार चीन और कोरियो आरपी पीएक्स-13 (6पीपीपीडी) के सभी आयातों पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था और चाइनीज ताइपेई एवं ईयू से पीएक्स-13 के आयातों पर 20 अक्टूबर, 2008 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 94/2005-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क जारी किया गया था। इसके पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए कि क्या कोरिया आरपी से पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है, एक मध्यावधि समीक्षा जांच का आयोजन किया। इसके परिणामस्वरूप, कोरिया जन गण पर पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया गया जिससे कि घरेलू उद्योग को राहत प्रदान हो सके। इस समय प्राधिकारी चीन और कोरिया जन गण से पीएक्स-13 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने ईयू तथा चाइनीज ताइपेई से पीएक्स-13 के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन किया। इसके परिणामस्वरूप ईयू पर पहले अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की दिनांक 28 जुलाई, 2011 सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 67/2001-सीमाशुल्क के तहत निरंतरता रखी गई तथा उसका संवर्धन किया।

ग. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि बढ़ाने के लिए विधि

1. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (4) निम्नलिखित है

"इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क, यदि उसक पहले प्रतिसंहरण नहीं कर लिया गया है तो उसका प्रभाव ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त हो जाएगा :

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति अथवा उसकी चुनौती का समायोजन करने के लिए उपाय कर लिए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाई रखी जाए तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि में विस्तार कर सकती है।

2. धारा 8ख(4) में निम्नलिखित दो शर्तों को निर्धारित किया गया है जिन्हें रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की अवधि में विस्तार करने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है :

क. समायोजन योजना

- (i) घरेलू उद्योग ने कुछ प्रयास आरंभ कर दिए हैं
- (ii) कुछ उपाय पहले ही कर लिए गए हैं
- (iii) कुछ उपवाय किए जा रहे हैं
- (iv) कुछ उपाय स्वयं समायोजन करने के लिए किए जाएंगे।

ख. रक्षोपाय शुल्क में विस्तार किया जाना आवश्यक हो

3. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि में विस्तार करने के लिए विधि में कोई अन्य अपेक्षा विहित नहीं है। तथापि, अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 में नियम 5,6,7 और 11 का अनुप्रयोग किए जाने का प्रावधान है और इसलिए विस्तार के मामले में संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति की अपेक्षाएं भी पूरी तरह से लागू हैं। प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि (क) शुल्क का विस्तार करने के समय आयातों या आयातों में संवृद्धि की मौजूदगी एक पूर्वापेक्षा नहीं है; (ख) विस्तार के समय क्षति की मौजूदगी भी एक पूर्वापेक्षा नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित संगत है :

क) आयातों अथवा संवर्धित आयातों की मौजूदगी शुल्क का विस्तार करते समय एक पूर्वापेक्षा नहीं है।

i. अधिनियम में रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करते समय आयातों में वृद्धि की अपेक्षा का प्रावधान नहीं है। यह धारा 8ख(4) में उल्लिखित शब्दों द्वारा स्पष्टतः सिद्ध होता है जो निम्नलिखित हैं :

"इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क, यदि उसक पहले प्रतिसंहरण नहीं कर लिया गया है तो उसका प्रभाव ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त हो जाएगा :

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति अथवा उसकी चुनौती का समायोजन करने के लिए उपाय कर लिए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाई रखी जाए तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि में विस्तार कर सकती है।

ii. इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अधीन रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 में निम्नलिखित उल्लेख है :

18. समीक्षा

1. महानिदेशक रक्षोपाय, रक्षोपाय शुल्क के निरंतर अधिरोपण की जरूरत के लिए समय-समय पर समीक्षा करेंगे और उनको प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं कि '

i. गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका समाधान निकालने के लिए रक्षोपाय शुल्क अनिवार्य है और इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि उद्योग सकारात्मक ढंग से समायोजन कर रहा है तो वह केंद्रीय सरकार को शुल्क का सतत अधिरोपण करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं।"

ii. यदि ऐसे शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए कोई औचित्य नहीं हो तो केंद्रीय सरकार से इसको समाप्त करने की सिफारिश करेगा :

परंतु यह कि जहां रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि तीन वर्षों से अधिक हो जाती है तो महानिदेशक ऐसे अधिरोपण के मध्यावधि से अनधिक उसकी समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति करने अथवा शुल्क के उदारीकरण में वृद्धि करने की सिफारिश करेंगे।

2. उपनियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई समीक्षा ऐसी समीक्षा के प्रारंभ की तारीख से 8 माह की अनधिक अवधि या ऐसी संवर्धित अवधि के अंतर्गत समाप्त की जा जाएगी। जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी।

3. समीक्षा के मामले में नियम 5,6,7 और 11 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

iii. यह देखा जा सकता है कि नियम 18 में नियम 5,6,7 और 11 की यथावश्यक परिवर्तनों सहित अनुप्रयोज्यता का प्रावधान है। इस संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित का आशय समझना अनिवार्य है। अशोक सेवा केंद्र और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया है।

17. इस तथ्य पर विचार करने से पहले कि प्रमुख अधिनियम के कौन से उपबंधों को इस अधिनियम के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, हमें 'यथावश्यक परिवर्तनों सहित का आशय समझना आवश्यक है। 'दि डिक्शनरी आफ इंग्लिश लॉ' (1959) में अर्ल जोविट "म्यूटैटिस म्यूटेंडिस" को 'विवरण के बिंदुओं में आवश्यक परिवर्तनों सहित' के रूप में परिभाषित करते हैं। ब्लैक की विधि शब्दावली (संशोधित चौथा संस्करण 1968) में "म्यूटैटिस म्यूटेंडिस" को "विवरण के बिंदुओं में आवश्यक परिवर्तनों सहित" के रूप में परिभाषित करते हैं, इसका आशय यह हुआ कि मामला या विषय सामान्यतः वही है परंतु जब नाम कार्यालय या उसके समान के रूप में आवश्यक हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हाडसमैन वी. वाटर हाउस, 191 एपीपी डिवीजन, 850, 112, एनवाईएस 249.251 ने "बैवियर्स ल्य डिक्सनरी" (तीसरा संशोधन खंड 2) में अभिव्यक्ति "म्यूटैटिस म्यूटेंडिस" को "आवश्यक परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह व्यावहारिक रूप से बार-बार घटित होने का एक वाक्यांश है जिसका आशय यह होता है कि मामला या वस्तु सामान्यतः वही बना रहता है परंतु इसमें जब भी आवश्यक हुआ तो उसके नाम, कार्यालय और उसके समान अन्य में आवश्यक परिवर्तनों के रूप में बदलाव किया जा सकता है। एक पूर्ववर्ती अधिनियम का यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी बाद के अधिनियम में विस्तार से अनुकूलन का विचार सामने आता है परंतु इसमें केवल उतने ही परिवर्तन करना चाहिए जितना इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, अर्थात् उसमें यह परिवर्तन परिवर्तित वास्ते की अनिवार्य प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए और यह परिवर्तन बाद वाले अधिनियम में प्रावधानों को व्यक्त करने के लिए होना चाहिए।'

iv यह देखा जाना चाहिए कि म्यूटैटिस म्यूटेंडिस अभिव्यक्ति का आशय "आवश्यक परिवर्तन" है, तद्वारा आशय यह है कि मामला या प्रकरण सामान्यतः समान ही रहता है परंतु उसमें जरूरत पड़ने पर परिवर्तन किया जाता है।" इसलिए इसका आशय परिवर्तनों सहित लागू किया जाता है। वर्तमान मामले में नियम 18 में यद्यपि कतिपय प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता का प्रावधान किया गया है परंतु म्यूटैटिस म्यूटेंडिस का प्रयोग स्पष्टतः यह स्थापित करता है कि इन उपबंधों को अधिनियम में किए गए उपबंधों अर्थात् सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(4) की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

v किसी रक्षोपाय शुल्क की अधिकतम कालावधि, जब तक इसमें करार के उपबंधों के संगत वृद्धि नहीं की जाती है, चार वर्ष है। विशेष रूप से किसी साधन में केवल तभी वृद्धि किया जा सकता है जब एक नई जांच के जरिए यह पाया जाए कि गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका समाधान निकालने के लिए इसकी निरंतरता आवश्यक हो और यदि साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता हो कि उद्योग समायोजन कर रहा है।

vi रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने के लिए सर्वर्धित आयात होना एक पूर्वापेक्षा नहीं है इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ग में अभी हाल में (2012) हुए संशोधन से आहरित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 8क(5) संशोधन से पहले निम्नलिखित उल्लेख करती थी :

5. इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, इस अधिरोपण की तारीख से चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा। परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि इन वस्तुओं का आयात चीन जनवादी गणराज्य से भारत को इतनी अधिक यात्रा में होता जिससे घरेलू उद्योग की बाजार विकृति कारित होती हो या उसकी चुनौती कारित होती हो तो रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता जारी रहनी चाहिए। यह ऐसे अधिरोपण की अवधि में विस्तार एक ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो प्रथम अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की तारीख से 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

vii जबकि केंद्रीय सरकार ने उक्त प्रावधान में वर्ष 2012 में संशोधन किया जो अब निम्नलिखित उल्लेख करता है

"परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार के विचार से ऐसी वस्तु का चीन जनवादी गणराज्य से भारत को आयात की निरंतरता है जिससे घरेलू उद्योग की बाजार विकृति होती हो या उसकी बाजार विकृति की चुनौती उत्पन्न होती हो तो केंद्रीय सरकार, घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी बाजार विकृति या उससे उत्पन्न बाजार विकृति की किसी चुनौती का समायोजन करने के लिए किए गए प्रयासों के होते हुए भी, यदि यह आवश्यक समझती है कि इस शुल्क की निरंतरता बनी रहनी चाहिए तो वह प्रथम अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की तारीख से ऐसी अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का विस्तार कर सकता है जो दस वर्षों की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगा।"

viii संशोधन के स्पष्टीकरण ज्ञापन में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :

"धारा 8ग चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों पर केंद्रीय सरकार को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का अधिकार प्रदान करती है। इसमें यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि इस शुल्क की निरंतरता बनी रह सकती है यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार हो कि उन वस्तुओं या मदों की भारत में आयात की निरंतरता बनी हुई है जिससे घरेलू उद्योग की बाजार विकृति कारित हुई है या बाजार विकृति की चुनौती उत्पन्न हो गई है यद्यपि घरेलू उद्योग में ऐसी विकृति का समायोजन करने के लिए उपाय किए हैं। यह

संशोधन वर्ष 2001 में डब्ल्यूटीओ के साथ हस्ताक्षरित चीनी अभिग्रहण प्रोटोकॉल के अंतर्गत परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र की धारा के उपबंधों के अनुरूप हो।

ix उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार का विशिष्ट रूप 8ग(5) के परंतु से संबंधित आयातों की जरूरत का विशिष्ट रूप से विलोपन कर दिया है जिससे यह सामान्य रक्षोपाय तंत्र के अनुरूप बन सके। इसलिए संबंधित आयात रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने के लिए एक पूर्वापेक्षा नहीं है।

x घरेलू उद्योग व्हीट ग्लुटेन : कार्रवाई का विस्तार का उल्लेख करता है और उस पर भरोसा करता है जिसमें यूएसआईटीसी ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया है :

व्यापार अधिनियम की धारा 204(ग) (1) में प्रावधान करती है कि कमीशन, अध्यक्ष या संबंधित उद्योग के अनुरोध पर निम्नलिखित का 'निर्धारण करने के लिए यह जांच' करेगा कि :

क्या गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका समाधान करने के लिए धारा 203 के अंतर्गत कार्रवाई की निरंतरता आवश्यक है और क्या इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि उद्योग आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन कर रहा है।

इस प्रकार एक सकारात्मक निर्धारण करने के लिए धारा 203(ग)(1) यह अपेक्षा करती है कि कमीशन दो स्वीकारात्मक निष्कर्ष कर सकता है कि (1) क्या गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका समाधान निकालने के लिए राहत कार्य जारी रहना चाहिए और (2) क्या इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि उद्योग आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन कर रहा है। न तो संविधि और न ही यूआरएए का विधायी इतिवृत्त उस निर्धारण की प्रकृति का विवरण प्रदान करता है जिसे आयोग द्वारा धारा 204(ग) के अंतर्गत करना चाहिए या वह निर्धारण करने के लिए विचारार्थ कारकों को निर्धारित करता है।

तथापि, वाक्यांश "सकारात्मक समायोजन" को व्यापार अधिनियम की धारा 201(ख) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आयात प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक समायोजन तब होना विचारा गया है जब

(क) घरेलू उद्योग

(i) धारा 204 के अंतर्गत की गई कार्रवाई समाप्त हो जाने पर आयातों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाता है, या

(ii) घरेलू उद्योग अपने संसाधनों का सुव्यवस्थित अंतरण अन्य उत्पादक कार्यों में करता है; और

ख) उद्योग के विस्थापित कामगार उत्पादनकारी कार्यों की ओर सुव्यवस्थित परिवर्तन अनुभव करते हैं।

इस संविधि में पुनः प्रावधान किया जाता है कि ऐसा माना जाएगा कि घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन किया है, "यद्यपि वह उद्योग उसी आकार या संघटक की नहीं है" जैसी वह धारा 202(ख) के अंतर्गत संस्थापित जांच के समय थी।

(ख) शुल्क में विस्तार करने के समय गंभीर क्षति की मौजूदगी पूर्वापेक्षित नहीं है।

1) विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करते समय संबंधित आयातों या घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी अपेक्षित नहीं है। यदि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या क्षति की चुनौती के साथ समायोजन करने के लिए उपाय किए हैं तो नियम में केवल रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने का प्रावधान है और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसलिए महानिदेशक (रक्षोपाय) को यह उपपादित करना आवश्यक है कि क्या पीएक्स-13 के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संगत के रूप में या समग्र रूप में वृद्धि हुई है न कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को यह उपपादित करना अपेक्षित होता है कि घरेलू उद्योग को नियमों के आशय के अंतर्गत गंभीर क्षति हुई है। यह नियम 18 की भाषा से भी सिद्ध हो जाता है जिसमें नियम 5 और नियम 11 का यथावश्यक परिवर्तनों सहित अनुप्रयोग करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि नियम 8 इस समीक्षा जैसे मामलों में लागू भी नहीं होता है। वास्तव में घरेलू उद्योग को हो सकता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होने के कारण ही क्षति न हुई हो और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी या अन्यथा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए एक पूर्वापेक्षा नहीं हो सकती है।

2. पिछले रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करते समय जो परिस्थितियां मौजूद थी वहीं परिस्थितियां काफी हद तक आज भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बनने के प्रयास कर रहा है और उसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। इन परिस्थितियों के अंतर्ग यदि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती रहना जारी रहेगी। अतः यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान रक्षोपाय शुल्क को अन्य 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए।

3. उपर्युक्त के होते हुए भी प्रदान कराई गई निम्नलिखित सूचना से यह देखा जा सकता है कि भारत में पीएक्स-13 के आयातों में भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की क्षति हाल ही में और भी अधिक बढ़ी है।

घ. इसकी समाप्ति के पश्चात शुल्क में विस्तार

1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि इस समय कोई रक्षोपाय शुल्क मौजूद नहीं है और वर्तमान समीक्षा अनुरक्षणीय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस समीक्षा की जांच की शुरुआत 29 अगस्त, 2013 को की गई थी अर्थात् रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने से पहले। इसके अतिरिक्त याचिककर्ता निम्नलिखित उल्लेख करता है और उसपर भरोसा करता है।

क. विगत पूर्वोदाहरण : यह प्रस्तुत किया जाता है कि विगत में भी मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात शुल्क में विस्तार किया गया था। ऐसा एक उदाहरण सोडाऐश के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क का है। संगत घटनाएं एवं तारीखें निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	दिनांक	घटना
1	महानिदेशक द्वारा जांच परिणाम	6 अक्टूबर, 2009
2	वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना	5 नवम्बर, 2009
3	शुल्क के वैधीकरण की तारीख	19 अप्रैल, 2010
4	महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा समीक्षा सिफारिश	13 अप्रैल, 2010
5	वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना	28 जून, 2010

क)। यह देखा जा सकता है कि शुल्क में विस्तार रक्षोपाय शुल्क की समयावधि की समाप्ति के पश्चात किया गया। इसके अतिरिक्त महानिदेशक रक्षोपाय ने मौजूदा शुल्क की समाप्ति के पश्चात रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने के मुद्दे का विशेष रूप से समाधान किया। इस निर्णय के संगत भाग नीचे दिए जा रहे हैं :

"महानिदेशक रक्षोपाय का उपर्युक्त निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया मुद्दा का अपने आप समाधान हो जाता है।"

ख. रक्षोपाय विधि और पाटनरोधी विधि की तुलना – पाटनरोधी शुल्क के संबंध में केंद्रीय सरकार के कई निर्णय इस मुद्दे से प्रत्यक्षतः संगत हैं। पाटनरोधी विधि और रक्षोपाय विधि के संगत प्रावधानों की निम्नलिखित तुलना की गई है।

रक्षोपाय विधि के अंतर्गत प्रावधान

धारा 8ख(4) : इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा।

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार का विचार है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी चुनौती से समायोजन करने के उपाय किए हैं और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता आवश्यक हो गई हो तो उक्त अधिरोपण की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

परंतु यह और कि किसी भी मामले में रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता इसके प्रथम अधिरोपण की तारीख से दस वर्षों से अधिक के समय के लिए अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

पाटन विधि के अंतर्गत प्रावधान

धारा 9क(5) : इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पूर्व में प्रतिसंहरण नहीं किया गया हो तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा।

परंतु यह कि, समीक्षा में, यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार हो जाता है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो, वह समय-समय पर, ऐसे अधिरोपण की अवधि को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह संवर्धित समय ऐसे संवर्धन के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगा।

परंतु यह और कि जहां उपर्युक्त पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति से पहले प्रारंभ की गई किसी समीक्षा का निष्कर्ष ऐसे समापन से पहले नहीं निकल पाता है तो ऐसी समीक्षा के परिणाम लंबित रहने तक पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनी रहेगी जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ख)। यह देखा जा सकता है कि पाटनरोधी विधि में दो विस्तार का प्रावधान है जो हैं (1) जांच लंबित रहने की स्थिति में एक वर्ष के लिए विस्तार (2) पांच वर्षों के लिए विस्तार। रक्षोपाय विधि में केवल एक ही विस्तार है। तथापि, प्रतिबद्धताएं एक समान हैं और उसमें अंतर्ग्रस्त मुद्दे भी समान हैं अर्थात् कि क्या मौजूदा शुल्क की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात पाटनरोधी शुल्क या रक्षोपाय शुल्क में विस्तार किया जा सकता है और इसलिए वर्तमान प्रक्रिया में पाटनरोधी क्रिया प्रणाली सर्वाधिक संगत प्रणाली है। यह सुस्थापित स्थिति है कि पाटनरोधी शुल्क में विस्तार मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी किया गया है। ऐसा मामला होने की स्थिति में मौजूदा शुल्क की समाप्ति होने के पश्चात रक्षोपाय शुल्क की अवधि में विस्तार किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि

इसकी समाप्ति से पहले एक समीक्षा प्रारंभ कर दी गई हो। पाटनरोधी शुल्क की अवधि में एक वर्ष के लिए विस्तार किए जोन और पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तार किए जाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

i. एक वर्ष के विस्तार का मामला

क्र.सं.	शुरू किए गए/चल रहे निर्णायक समीक्षा मामले	देश	मूल जांच की समाप्ति की तारीख	एमओएफ का विस्तार (एक वर्ष के लिए विस्तार)
1	डाइक्लोफेनक सोडियम	चीन	9 अप्रैल, 13	13 नवम्बर, 13
2	पेंटाइराइथ्रिटान	ताइवान	27 अप्रैल 13	25 जून 13
3	एसीटोन	कोरिया	9 जून, 13	25 जून 13
4	डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकार्डेबल (डीवीडी - आर एवं डीवीडी - आर डब्ल्यू)	चीन, हांगकांग, ताइवान	22 जुलाई 13	29 अगस्त 13
5	केबल टाईज	चीन, ताइवान	30 अक्टूबर 13	12 नवम्बर 13
6	नोनायल फिनल	चाइनीज ताइपेई	21 अगस्त 12	24 अगस्त 12
7	फास्फोरिक एसिड, टेक्निकल या फूड ग्रेड	चीन जन गण	13 सितम्बर 12	25 सितम्बर 13
8	फिनल	दक्षिण अफ्रीका	30 अक्टूबर, 13	12 नवम्बर 13
9	सफेद सीमेंट	यूएई, इरान	11 अप्रैल 12	21 मई 12
10	रबड़ रसायन नामशः पीएक्स-13 (6 पीपीडी)	चीन जन गण	4 मई 13	5 जुलाई 13
11	पेंटाइराइथ्रिटान	चाइनीज टाइपे	27 अप्रैल 13	25 जून 13

ii. पांच वर्ष के विस्तार वाले मामले

क्र.सं.	पूरे किए गए निर्णायक समीक्षा जांच मामले	देश	मूल जांच की समाप्ति की तारीख	वित्त मंत्रालय द्वारा विस्तार (पांच वर्ष का विस्तार)
1	ब्रूस और लारी ट्रक्स के लिए बायरस टायर्स	चीन लोक गणराज्य, थाइलैंड	8 अक्टूबर 11	30 मार्च 12
2	आस्टिक सोडा	साऊदी अरेबिया, ईरान, जापान, फ्रांस, यू एस ए	12 सितम्बर 11	6 जनवरी 12
3	मेट्रोनाइडाजोल	चीन लोक गणराज्य	14 जून 11	15 जून 11
4	पैरोक्सोसल्फेट्स	चीन लोक गणराज्य और जापान	18 मार्च 12	4 अप्रैल 12
5	पैरासिटामाल	चीन लोक गणराज्य	2 सितम्बर 12	19 सितम्बर 12
6	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन लोक गणराज्य	14 अक्टूबर 11	20 दिसम्बर 11
7	विटामिन ए पालमीटेट	चीन लोक गणराज्य स्विटजरलैंड	27 मार्च 12	13 नवम्बर 12
8	जिंक आक्साइड	चीन लोक गणराज्य	6 मई 12	18 मई 12

इ). **वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश :** इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने ऐसे उदाहरणों के संबंध में दिनांक 8 जुलाई, 2011 के परिपत्र सं. 28/2001-सीमाशुल्क के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने ऐसी स्थिति को स्वीकार किया है जहां अंतिम जांच परिणाम मूल अधिसूचना व्यपगत हो जाने के पश्चात जारी किए गए। संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

iii. "..... जहां जांच में अंतिम जांच परिणाम मूल अधिसूचना व्यपगत हो जाने के पश्चात अधिसूचित किए जाते हैं, ऐसे मामलों में अधिसूचना ऐसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी"।

ग). **भारत-तुर्की विवाद – संगत एवं अनुप्रयोज्यता –आज्ञापन**

च). **विश्व व्यापार संगत के समक्ष विवाद :** हितबद्ध पक्षकारों की ओर से यह तर्क दिया गया कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष एक ऐसा ही विवाद उठाया था और इस मुद्दे का निर्णय भारत के पक्ष में किया गया था। इस संबंध में काटन यार्न मामले में तुर्की द्वारा उठाए गए साधनों का संदर्भ दिया गया था। इस संबंध में संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

- (i) काटन यार्न मामले में भारत ने तुर्की के साथ परामर्श की मांग की और उसके साथ परामर्श किया, इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय ने कभी भी विचार नहीं किया और इस मुद्दे पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया। अतः, यह विचार किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले पर डब्ल्यूटीओ द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।
- (ii) तुर्की सरकार ने अपनी निजी समझ से और भारत के साथ परामर्श आयोजित किए जाने के पश्चात तुर्की सरकार ने भारत सरकार को आश्वस्त किया कि वह इस साधन को कुछ समय के पश्चात वापस ले लेगी। फिर भी, इन साधनों को तत्काल वापस नहीं किया गया, भारत सरकार ने यह मामला विश्व व्यापार संगठन के समक्ष कभी भी नहीं उठाया।
- (iii) इस मामले से संबंधित तथा वर्तमान मामले के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है। निम्नलिखित तालिका इन दोनों मामलों के बीच प्रारंभिक अंतर को दर्शाती है।

तुर्क़िश मामले	भारतीय मामले
प्राधिकारियों ने अंतरिम शुल्क लागू किया। भारत सरकार ने तर्क दिया कि समीक्षा मामले में अंतरिम शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है।	इस मामले में या ऐसे अन्य मामलों में महानिदेशक द्वारा किसी अंतरिम शुल्क की संस्तुति नहीं की गई।
तुर्की के प्राधिकारियों ने रक्षोपाय शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित किया था।	भारत द्वारा किए गए सोडा ऐश मामले में जहां रक्षोपाय शुल्क इसकी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात विस्तारित किया गया था, तथा उसे केवल परिप्रेक्ष्य रूप से जारी किया गया था।
भारत सरकार ने यह तर्क दिया कि शुल्क की सिफारिश अनुच्छेद 2,3, 4 और 5 की अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना की गई थी।	महानिदेशक ने इस सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और इन अपेक्षाओं का अनुपालन करते रहेंगे।
भारत सरकार ने तर्क दिया कि इस शुल्क की अवधि में विस्तार भूतलक्षी प्रभाव से इसकी समाप्ति की तारीख से तब विस्तारित किया गया जब मूल शुल्क की अवधि समाप्त हो गई थी।	इस शुल्क में विस्तार पिछले शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किया जाएगा और वह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी। भारत ऐसे शुल्क की भूतलक्षी प्रभाव से विस्तार नहीं कर रहा है।
(iv)	इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि काटन यार्न मामले में तुर्की सरकार में, एक समीक्षा मामले में, समापन समीक्षा की शुरुआत के पश्चात, अंतरिम रक्षोपाय साधन अधिरोपित किया था। यह एक तर्क योग्य मामला हो सकता है क्योंकि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान प्रतीत नहीं होता है जिनमें सदस्य देशों को समीक्षा प्रक्रिया के दौरान अंतरिम साधनों को अधिरोपित करने की अनुमति हो। इसके अतिरिक्त, तुर्की सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव से निर्णायक शुल्क अधिरोपित किया जिसके लिए रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान प्रतीत नहीं होता है।
(v)	वर्तमान मामले में, प्रार्थी ने अंतरिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की मांग नहीं की है और न ही प्रार्थी ने रक्षोपाय शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से अधिरोपित करने की मांग की है। वास्तव में, प्रार्थी पाटनरोधी शुल्क के मामले में

संदर्भ में सीबीईसी द्वारा जारी परिपत्र के प्रति पूर्णतया जागरूक है, जिसमें सीबीईसी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे साधन प्रकृति में परिदृष्टिमापेक्षी ही होंगे।

उपर्युक्त को देखते हुए, यद्यपि तुर्किश मामला यह स्थापित नहीं करता है कि वर्तमान मामले साधन का विस्तार करना उचित नहीं होगा, पिछले पाटनरोधी मामलों में अर्जित व्यापक अनुभव यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वर्तमान समीक्षा के परिणामस्वरूप रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना न्यायोचित होगा।

छ). क्या मांग – आपूर्ति के बीच अंतर वास्तव में विद्यमान है।

1. एटीएमए के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रयोक्ता उद्योग को आयात करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ था। इस संबंध में निम्नलिखित संगत है :

क. एटीएमए द्वारा प्रस्तुत तर्क का कोई तथ्यपरक आधार नहीं है।

ख. एटीएमए का अधिवक्ता भारत में मांग की तुलना प्रार्थी कंपनी से, अन्य भारतीय उत्पादकों की मौजूदगी की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय मांग की तुलना भारतीय क्षमता के साथ की जाने की जरूरत है न कि केवल प्रार्थी कंपनी की क्षमता से। एटीएमए के अधिवक्ता द्वारा अपनाई गई तुलना क्रियापद्धति पूर्णतया भ्रामक है।

ग. प्रार्थी ने मांग आपूर्ति अंतर का विवरण (शुल्क मुक्त आयातों सहित) एक मांग पर और निवल मांग (शुल्क मुक्त आयातों सहित) पर प्रदान कराया है। भारत में संबद्ध वस्तु की मांग – आपूर्ति स्थिति निम्नलिखित है (सभी आंकड़े एमटी में) जो दर्शाया है कि भारत में कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं है और घरेलू उत्पादक देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम है।

उत्पाद : पीएक्स-13

क्र. सं.	मद	2009-10	2010-11	2011-12	जनवरी, 12 से दिसम्बर, 12
क	क्षमता				
1	एनओसीआईएल	***	***	***	***
2	मरकेम	***	***	***	***
3	पीएमसी	***	***	***	***
4	लैन्केस	***	***	***	***
	भारतीय उत्पादकों की क्षमता	***	***	***	***
ख	शुल्क मुक्त आयात	***	***	***	***
ग	कुल उपलब्धता	13,660	13,670	22,400	22,800
घ	मांग	14,311	14,851	16,003	18,033
ड.	अधिशेष (+)/कमी (-)	-651	-1,181	6,397	4,767

ज). क्या मांग आपूर्ति अंतर ने उपभोक्ताओं को आयात करने के लिए वास्तव में मजबूर किया।

i. प्रार्थी यह प्रस्तुत करता है कि संगत मुद्दा यह है कि क्या मांग आपूर्ति अंतर ने उपभोक्ताओं को उस उत्पाद का आयात करने के लिए वास्तव में मजबूर किया; या, यह एक ऐसी स्थिति है जहां उपभोक्तागण मनगढ़न्त कहानी बना रहे हैं कि (क) उन्होंने भारत में कतिपय क्षमताओं की मौजूदगी की परिकल्पना की है, (ख) यह परिकल्पना की कि भारतीय उत्पादक उनको वांछित यात्रा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं और उसके बजाय वह उक्त वस्तु का निर्यात करने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए उपभोक्ताओं ने यह परिकल्पना की है कि वे उक्त सामग्री घरेलू स्रोत से प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और तदनुसार उन्होंने बड़ चढ़कर इस उत्पाद का आयात करने का आश्रय लिया। तथ्य यह है कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वर्तमान मामले की संगत अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को इस उत्पाद का आयात करने को मजबूर किया गया क्योंकि भारतीय उद्योग उपभोक्ताओं को इस सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। यदि मांग आपूर्ति अंतर के कारण ही उपभोक्ताओं को वास्तव में आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उन्हें

यह दर्शाने में समर्थ होना चाहिए था कि उन्होंने घरेलू उत्पादकों को उच्चतर मात्रा के लिए आर्डर दिया था परंतु घरेलू उत्पादकों ने उनके केवल न्यूनतर मात्रा के आर्डर्स को ही स्वीकार किया क्योंकि वांछित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं की कमी थी। इसलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि उपभोक्तागण मांग आपूर्ति के बीच अंतर को दर्शाने के लिए मनगढ़न्त कहानी अपने उन व्यवसाय कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिए बना रहे हैं जहां उन्होंने यह पाया कि आयात घरेलू कीमतों से न्यूनतर कीमतों पर उपलब्ध है और इसलिए उपभोक्ताओं ने इस उत्पाद को घरेलू स्रोतों से प्राप्त करने के बजाय आयात करने को अधिमानता दी।

झ). घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

i. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग निर्यात केंद्रित (और इस कारण ही उपभोक्ताओं को आयात करना पड़ा) है। यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए एक व्यवसाय विवशता है। घरेलू उद्योग उन मामलों में बाजार में मौजूद है जहां उपभोक्तागण माल का अधिप्रापण करने के लिए आर्डर दे रहे हैं। घरेलू उद्योग विभिन्न क्रेताओं से प्राप्त आर्डर्स पर विचार करता है, उनका संग्रहण करता है और उन अन्य आपूर्तियों पर विचार करता है जिसे घरेलू उद्योग को अन्य उपभोक्ताओं से आर्डर प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी अधिकतम उत्पाद पर विचार करते हैं। यदि ऐसे उत्पादन से मालसूची का संग्रहण होने लगता है तो प्रार्थी अपने संयंत्र को बंद करा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी द्वारा किया गया वेशी उत्पादन विदेशी क्रेताओं को प्रस्तुत किया जाता है इसलिए जब प्रार्थी को अपने माल की बेहतर कीमत घरेलू उद्योग द्वारा ही प्राप्त हो जाती है तो प्रार्थी को अपने उत्पाद का निर्यात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन निर्यातों का कारण वेशी उत्पादन है।

ii. यह उल्लेख करना भी संगत है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि :

- (क) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से निर्यातों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- (ख) घरेलू उद्योग को निर्यात बाजार में उच्चतर कीमतें प्राप्त होती हैं और उन्होंने अपनी कीमतों में भारत में संबद्ध देशों से आयात कीमतों के बराबर कभी नहीं की है।
- (ग) तथापि, घरेलू उद्योग भारत में अपनी ब्रिकी कीमत की तुलना कम कीमतों पर निर्यात करने का विरोध करता रहा है। ऐसा लक्षित उत्पादन तथा वास्तविक घरेलू बिक्रियों के बीच यथासंभव सीमा तक अंतराल को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रार्थी को निर्यात बाजार में क्षति से रही है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि निर्यात अपना वेशी उत्पादन बेचने के लिए मजबूरी में किया जाता है।

ञ). संयंत्र बंदी

i. यह तथ्य कि प्रार्थी को पीएक्स-13 के आयातों के कारण बिक्री और उत्पादन में घाटा हुआ जो प्रार्थी द्वारा संयंत्र की गई बंदी से सिद्ध हो जाता है। संयंत्र बंदी का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बंदी की अवधि	घंटों की संख्या	
		वास्तविक	अनुक्रमित
1	2009-2010	***	100
2	2010-2011	***	424
3	2011-2012	***	909
4	2012-2013	***	1,002

ii. यह देखा जा सकता है कि हाल ही अवधि में भारी बंदी हुई है। वास्तव में, बंदी के घंटों की संख्या में इस अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह तालाबंदी कंपनी के उत्पाद की मांग में कमी के कारण की गई। कंपनी को विगत में इस विचाराधीन उत्पाद की भारी मालसूची का सामना करना पड़ा है और उसे इस उत्पाद पर पिछले दो वर्षों से नकद घाटा हो रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने उत्पादन को मांग के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है और तद्वारा उसने अपनी मालसूची को विनियमित किया और इस उत्पाद के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी में कमी की। प्रार्थी जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए उत्पादन शिड्यूलिंग चार्ट संलग्न कर रहा है जो स्पष्टतः संयंत्र में तालाबंदी को दर्शाता है।

ट). केकेपीसी द्वारा सहन किया गया घाटा

i. इन प्रस्तुतिकरणों के साथ संलग्न कोरिया कुम्हो की वार्षिक रिपोर्ट में कुछ उद्धरणों से यह देखा जा सकता है कि कंपनी को अपने स्पेशियलिटी रसायन व्यवसाय में वर्ष 2012 में वित्तीय घाटा हुआ है। इस कंपनी द्वारा उत्पादन और बिक्री किया जा रहा है एकमात्र स्पेशियलिटी रसायन वस्तुतः पीएक्स-13 है, यह स्पष्टतया यह स्थापित करता है कि कोरिया कुम्हो अपने उत्पाद की बिक्री घरेलू बाजार में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घाटे पर कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कोरिया कुम्हो की निर्यात कीमत की तुलना तृतीय देशों तथा भारत को निर्यात कीमतों से करने पर यह दर्शाता है कि यह कंपनी अपने उत्पाद की भारत में बिक्री (और खासकर घरेलू बाजार में) तृतीय देशों से तुलना में बहुत कम कीमतों पर कर रहा है। इसलिए कंपनी द्वारा उठाया गया घाटा अपनी घरेलू बिक्री तथा भारतीय निर्यातों में बहुत अधिक है।

घ). विचाराधीन उत्पाद

i. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद रबड़ रसायन पीएक्स-13 (जिसे 6 पीपीडी के रूप में भी जाना जाता है) है। पीएक्स-13 का उत्पादन एक आदर्श मेटल केटालिस्ट की मौजूदगी में एक आटोकलैब में 4-नाइट्रोडाइफिनायनामाइन और मिथाइन आइसोब्यूटाइल किटोन के मिश्रण को उच्च दाब में हाइड्रोजनीकरण करके किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अभिक्रिया मास, जिसमें अनरिएक्टेड किटोन, एक सह-उत्पाद आदि, को केटालिस्ट हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है और फिर उसका पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। फिर इस फिल्टरेट को, न्यून बायलर्स दूर करने के लिए, आसवित किया जाता है और फिर परिष्कृत उत्पाद के रूप में इसके फ्लेक्स तैयार किए जाते हैं। अनभिक्रियाकृत किटोन को प्राप्त करने के लिए इन न्यून बायलर्स को पुनः आसवित किया जाता है। इस केटालिस्ट का तब तक पुनर्चक्रीकरण किया जाता है जब तक कि यह क्रियाकलाप कम न हो जाए। फिर इसे इस सिस्टम से हटा दिया जाता है। पीएक्स-13 का प्रयोग प्राकृतिक रबड़ और सिंथेटिक रबड़ (एसबीआर, ब्यूटाडाइन रबड़, नाइट्राइल रबड़ और कार्बोक्सीलेटेड रबड़) तथा विभिन्न रबड़ उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग होने वाले अन्य रबड़ रसायनों का उपचार करने के लिए किया जाता है। रबड़ की वस्तुओं के लिए कोई समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के विभिन्न सीमाशुल्क वर्गीकरण शीर्षों 3810, 3812ए तथा 2921, 2934, 2925 और 2942 (6 अंकीय स्तर पर) के उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ड). समान वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु

i. रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1975 के नियम 2(V) में यह विनिर्धारित है कि "समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो विचाराधीन वस्तु के बिल्कुल समरूप या सभी तरह से समान हो। प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित भारत में आयातित वस्तु के बिल्कुल समान है। दोनों ही उत्पादों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे प्राचलों के रूप में तुलनीय गुणधर्म हैं। घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बारे में अनिवार्य उत्पाद विनिर्दिष्टियों की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं में आयातित वस्तु के समान है।

घ). घरेलू उद्योग

1. प्रार्थी कंपनी घरेलू उद्योग है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रसंगोचित है:

6(ख) "घरेलू उद्योग" से आशय है-

- भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादकों, या
- उन उत्पादकों से होता है जिनका भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में कथित वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो;

2. रक्षोपाय शुल्क जांच के लिए यह याचिका मैसर्स एनओसीआईएल, मुंबई द्वारा दायर की गई है। इस रबड़ रसायन के भारत में तीन अन्य उत्पादक भी हैं अर्थात् लैनक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीएमसी रबड़ कैमिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मर्केम लिमिटेड।

3. प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी का उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः, प्रार्थी धारा 8ख की उपधारा 6(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है। भारतीय उत्पादन और उसमें प्रार्थी का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है जो घरेलू उद्योग के आधार को न्यायोचित ठहराता है।

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल भारतीय उत्पादन	***	***	***	***
एनओसीआईएल का हिस्सा	उपरोक्त 85%	उपरोक्त 80%	उपरोक्त 65%	उपरोक्त 60%
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	***	***	***	***

4. उपर्युक्त के मद्देनजर प्रार्थी महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध करते हैं कि प्रार्थी को "घरेलू उद्योग" के रूप में माना जाए।

ण). आयातों में वृद्धि

i. जैसाकि कि घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही यह सिद्ध किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने के लिए वर्धित आयातों का होना एक पूर्वापेक्षा नहीं है।

ii. उपर्युक्त के होते हुए भी यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीएक्स-13 के आयात नियमावली के आशय के अंतर्गत "संवर्धित आयात" बनते हैं इस संबंध में निम्नलिखित उद्धरण प्रासंगिक हैं :

(क) विधिक अपेक्षा

1) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख : रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

"यदि केंद्रीय सरकार, यथोचित समझी गई जांच का आयोजन करने के पश्चात, इस बात से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत को ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत और इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में आयात किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होने लगती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाता है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु का रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"

2) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2 : शर्तें

1. कोई सदस्य किसी उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग केवल तभी कर सकता है जब उस सदस्य ने, निम्नलिखित निर्धारित उपबंधों के अनुसरण में यह सुनिश्चित कर लिया हो कि इन उत्पादों का उसके भू-भाग में आयात, घरेलू उत्पादन के समग्र या संगत रूप से, ऐसी संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता हो, उसके समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो या गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न हो गई हो।"

3. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की शर्तें निम्नलिखित हैं : (क) संवर्धित आयात – घरेलू उत्पादन के संगत या समग्र रूप में और घरेलू मांग के संगत रूप में; (ख) संवर्धित आयातों द्वारा कारित क्षति।

(ख) नूतन, आकस्मिक, तीव्र और भारी वृद्धि का आशय

1. प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि विधि के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि आयातों में अचानक एवं भारी वृद्धि प्रदर्शित होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) मामले में यह धारित किया है कि संवर्धित आयातों में अचानक और अभिनव वृद्धि हुई हो और इसलिए अद्यतन आंकड़ों की जरूरत है।

"यह निर्धारण की कि क्या "ऐसी संवर्धित मात्रा में" आयातों की अपेक्षा को पूरा किया जाना केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी जांच के लिए साधारणतया यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं है कि इस वर्ष इस उत्पाद के आयात पिछले वर्ष की तुलना में - या पांच वर्ष पहले की तुलना में अधिक थे और यह इस बात को पुनः दोहराने जैसा लगता है कि आयातों की केवल संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी। यह "इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में" होना चाहिए जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो जिससे कि रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए निश्चित अपेक्षा पूरी हो जाती हो और रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद XIX : 1(क) देशों में प्रयुक्त यह भाषा, हमारे विश्वास है कि अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से, दोनों रूपों, पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त भारी मात्रा में हुई हो। जिससे "गंभीर क्षति" कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

2. इसके अतिरिक्त, यूएस – हवीट ग्लुटेन मामले में पैनल ने यह पाया कि :

3. "इस प्रकार आयातों में केवल कोई वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि हम अर्जेन्टीना, फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलिय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि यह वृद्धि, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में, अत्यधिक अभिनव, अचानक, तीव्र और भारी मात्रा में हुई हो, जिससे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

4. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि उत्पादन का आयात (क) अचानक; (ख) भारी; (ग) अत्यधिक अभिनव; (घ) तीव्र मात्रा में हुआ हो।

(ग). आयातों में समग्र वृद्धि

1. पीएक्स-13 के आयातों में "वृद्धि नियमों के आशय के अंतर्गत" हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा	मूल्य	औसत कीमत	उत्पादन के संबंध में आयात
		एमटी	लाख रुपए	(रुपए/किग्रा)	% (अनुक्रमित)
1	2009-10	10,090	16,197	160.53	100%
2	2010-11	10,607	16,936	159.67	106%
3	2011-12	9,735	15,888	163.20	101%
4	2012-13	11,664	18,396	157.72	126%

2. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि

- (क) भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि अचानक भारी मात्रा में तीव्र और अभिनव रूप से हुई है।
- (ख) आयातों में अत्यधिक अभिनव अवधि में भारी वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें हल्की सी गिरावट आई थी।
- (ग) संबंधित उत्पादों के आयातों में क्षति अवधि के दौरान, रक्षोपाय शुल्क मौजूद होने के बावजूद भी भारी वृद्धि हुई है।
- (घ) यह नोट करना संगत है कि आयातों में यह वृद्धि रक्षोपाय शुल्क मौजूद होने के बावजूद हुई है। यदि रक्षोपाय शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो आयातों की इस मात्रा में और अधिक वृद्धि हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त आयातों में मूल जांच के आधार पर वर्ष की तुलना में भी वृद्धि हुई है जिससे संवर्धित आयातों का स्पष्ट संकेत मिलता है।

घ) आयातों में संगत वृद्धि

पीएक्स-13 के आयातों में न केवली समग्र रूप से वृद्धि हुई है बल्कि यह वृद्धि भारत में उत्पादन के संगत रूप में भी हुई है।

इ) आयातों में वृद्धि के लिए कारण :

1. वे परिस्थितियां जो पिछले रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के समय विद्यमान थीं आज भी मौजूद हैं जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के अंतर्गत यदि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार नहीं किया जाता है तो आयातों में एकबार फिर से भारी वृद्धि होने लगेगी। आवेदक द्वारा पिछले आवेदन पत्र के साथ अभिज्ञात निम्नलिखित कारक आज भी काफी हद तक मौजूद हैं।

क. वैश्विक उत्पादकों की पेशी क्षमताएं और उनके द्वारा उसके परिणामस्वरूप कम कीमतों की पेशकर की जा रही है। (प्रार्थी के प्राक्कलनों और आसूचना के आधार पर):

सभी आंकड़े एमटी में हैं:

क्र.सं.	देश	उत्पादक	क्षमता	घरेलू मांग	बेशी
1	कोरिया	कोरिया कुम्हो (केकेपीसी)	70,000	8,000	62,000
2	चीन	सिनोर्गेकेम	120,000	-	-
		नान्जिंग रसायन	30,000	-	-
		टांगलिंग जिन्डा	10,000	-	-
		नार्थईस्ट आक्स	10,000	-	-
		शांगयु लाइकिंग	2,000	-	-
		जियांग्सु डांगलांग	8,000	-	-
		चाइना सनसाइन	15,000	-	-
	कुल चीन		195,000	90,000	105,000

3	ईयू क्षेत्र	फ्लेक्सिस	65,000	-	-
		लैंक्सेस	38,000	-	-
		डस्ले	18,000	-	-
	कुल ईयू		123,000	32,000	91,000
4	जापान	सुमिटोमो	10,000	17,000	(7,000)
5	भारत		11,500	14,500	(3,000)
6	शेष विश्व		शून्य	87,000	-
7	कुल संसार		407,500	248,500	159,000
8	भारतीय मांग				14,500
9	भारत के % के रूप में विश्व बेशी				1097%

यह देखा जा सकता है कि इस उत्पाद की मौजूदा वैश्विक बेशी क्षमता भारत में इस उत्पाद के लिए मौजूदा मांग से बहुत अधिक है।

ख. इस विचाराधीन उत्पाद के चीन के कुछ उत्पादकों तथा इसके मध्यवर्ती कोरियाई उत्पादकों के बीच कुछ व्यावसायिक व्यवस्था है जिसके द्वारा कोरियाई उत्पादक मध्यवर्ती सामान अत्यधिक कम कीमतों पर प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि कोरिया कुम्हो और साइनोर्गेकिम के बीच में स्पष्ट रूप से कुछ विशेष संबंध हैं जिसके परिणामस्वरूप 4-एडीपीए की केकेपीसी को विशेष कीमतों पर आपूर्ति की जाती है। यह सम्बंध साइनोर्गेकिम को उपलब्ध और केकेपीसी को प्रेषित किए जा रहे, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के लाभ के अलावा है। इस प्रकार केकेपीसी और साइनोर्गेकिम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी यह पुस्तुत करता है कि निम्नलिखित तथा एक बार पुनः दोनों पक्षकारों के बीच विशेष संबंधों की मौजूदगी को स्थापित करते हैं:-

- कई वर्षों से केकेपीसी की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है;
- केकेपीसी के आयातों में यूएस सहित विभिन्न देशों को आयातों में वृद्धि हुई है;
- केकेपीसी को, एक मध्यवर्ती उत्पाद, 4एडीपीए का इसानोर्गेकिम से भारी रियायती दरों पर प्रदाय होता है;
- मैसर्स कोरिया कुम्हो द्वारा वर्ष 2009 की वार्षिक रिपोर्ट में एक अभिकथन किया गया जिसमें निर्यातक ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:-

"हमारी विशेषज्ञता प्राप्त रसायन व्यवसाय- 6पीपीडी उत्पादन क्षमता में उद्योग में अग्रणी- की बिग्री में गिरावट आ गई और कीमतों में कमी आ गई क्योंकि चीन के प्रतिस्पर्धियों ने न्यून कीमत कार्यनीति का अनुसरण किया। 4 एडीबीए फीडस्टाक बाजार में कमी और फीडस्टाक प्रदायक सिनोर्केम के साथ हमारे विशेष संबंधों के कारण चीन के बाजारों में हमारे प्रवेश करने की योग्यता पर हमारे प्रतिबंध के परिणामस्वरूप प्रचालन दर न्यून हो गई जिससे हमारी लाभप्रदायकाता को और अधिक नुकसान हुआ।"

- इस विचाराधीन उत्पाद का कोरिया से वैश्विक रूप से विभिन्न देशों और चीन को निर्यात की पद्धति दर्शाती है कि कोरिया कुम्हो ने अपने निर्यातों की चीन के एकमात्र अपवाद को छोड़कर विश्व बाजार में भारी वृद्धि कर ली। यदि कोरिया कुम्हो ने अपने निर्यातों की लगभग सभी बाजारों में इतनी अधिक वृद्धि कर ली और यदि कोरिया कुम्हो के पास इतनी अधिक क्षमताएं हैं तो चीन को उसके निर्यात में वृद्धि न होने का कोई व्यावसायिक एवं आर्थिक औचित्य साइनोर्केम एवं कोरिया कुम्हो के बीच एक समझ को छोड़कर नहीं है जिसमें कोरिया कुम्हो चीन को अपना निर्यात न बढ़ाने पर सहमत हुआ जिसके बदले साइनोर्केम द्वारा कोरिया कुम्हो को 4 एडीपीए का प्रदाय किए जा रहे हैं।

- उपर्युक्त तथ्य यह स्पष्टतः दर्शाते हैं कि साइनोर्केम और केकेपीसी के बीच लेन-देन दोनों कम्पनियों के बीच कुछ विशेष व्यवस्था का एक भाग है।

क. भारतीय बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद के आपूर्तिकर्ताओं में से एक कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स (केकेपीसी) इस विचाराधीन उत्पाद का अपना उत्पादन 44000 एमटी/ वार्षिक से बढ़ाकर 80000 एमटी/वार्षिक कर लिया। इस कम्पनी का मौजूदा प्रचालन स्तर बहुत कम है (45-50 प्रतिशत के क्षेत्र में) वास्तव में इस कम्पनी के पास उपलब्ध वैशी क्षमता ही देश में सम्पूर्ण मांग की तुलना में अधिक है। इसके परिणामस्वरूप भारत में इस उत्पाद के लिए मांग में कोरिया का हिस्सा जो वर्ष 2003-2004 में 1 प्रतिशत से भी कम था, वर्ष 2012-13 की अवधि में बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-06 तक पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद कोरिया से कुल आयातों का हिस्सा 31 प्रतिशत से अधिक नहीं था जबकि अब कोरिया से 52 प्रतिशत आयात होने की रिपोर्ट दी जा रही है।

त). घरेलू उद्योग को क्षति:

1)क. नियमावली के अनुबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

"किसी जांच में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबंधित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है और/या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती कारित कर दी है, महानिदेशक उन सभी उद्देश्यपरक एवं परिमाणनीय प्रकृति के संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें शामिल हैं खासकर, संबंधित वस्तु के आयातों में समग्र एवं संगत रूप से वृद्धि की दर एवं राशि, सम्बंधित आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन और उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन।"

ख. रक्षोपाय शुल्क में विस्तार किए गए स्तर पर पहले किए गए उल्लेख के अनुसार आयातों में वृद्धि या घरेलू उद्योग को गंभीर क्षतिकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। नियम में स्पष्टतः रक्षोपाय शुल्क में तब विस्तार करने का प्रावधान है जब घरेलू उद्योग ने इस क्षतियां उसकी चुनौती के प्रतिसमायोजन करने के साधन कर लिए हैं और यह आवश्यक है कि यह रक्षोपाय शुल्क निरंतररूप से लगे रहना चाहिए। इसलिए महानिदेशक (रक्षोपाय) को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पीएक्स-13 के आयातों में भारत में खपत और उत्पादन के संगत रूप में या समग्र रूप से वृद्धि हुई है। न ही महानिदेशक रक्षोपाय के यह निर्धारित करने की अपेक्षा है कि क्या घरेलू उद्योग को नियमावली के आशय के अंतर्गत गंभीर क्षति हुई है। यह बात नियम 18 की भाषा द्वारा भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें नियम 5 और नियम 11 का अनुप्रयोग "यथावश्यक परिवर्तनों सहित" किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह इस तथ्य से भी सिद्ध हो जाता है कि ऐसी समीक्षा के मामले में नियम 8 को अनुप्रयोज्य भी नहीं बनया जाता है। वास्तव में हो सकता है कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के कारण ही क्षति न हो रही हो और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी अथवा अन्यथा रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने के लिए एक पूर्वपेक्षा नहीं हो सकती है।

ग. ऐसा होते हुए भी प्रार्थी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन/संबंधित सूचना प्रदान कराई है। यह सूचना स्पष्टतः दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की हालत बिल्कुल खराब बनी रही। वास्तव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होना जारी रही। इन हालातों में यदि रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि नहीं की जाती है तो हो सकता है कि घरेलू उद्योग की क्षति में और अधिक वृद्धि हो जाए।

घ. जो परिस्थितियां पिछले रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के वक्त मौजूद थी, वहीं परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बनने के प्रयास कर रहा है और यह प्रक्रियाधीन है। इन हालातों में यदि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग को एक बार फिर गंभीर क्षति होने लगेगी। अतः यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान रक्षोपाय शुल्क को दो अन्य वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2) मांग

प्रार्थी ने वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ, मांग को भारत में इस उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयातों की बिक्री के योग के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात को वास्तविक खपत का सुनिश्चयन करने के उद्देश्य से, इस संगठन से उपवर्णित कर दिया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र मांग क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक रही है।

3) बाजार हिस्सा

क. बाजार हिस्से का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की विचारा की गई मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा अनुरक्षित उत्पाद कर रिकोर्डों के अनुरूप है। बाजार हिस्से का निर्धारण भारतीय उद्योग द्वारा किए गए प्रेषण और भारत को किए गए आयातों पर विचार करते हुए किया गया है। वर्ष 2009-10 से संक्षिप्त स्थिति निम्नलिखित है।

क्र.सं.	वर्ष	% का हिस्सा			
		प्रार्थी	अन्य भारतीय उत्पादक	भारतीय उत्पादक	आयात

1	2009-10	***	***	31.39%	68.61%
2	2010-11	***	***	33.50%	66.50%
3	2011-12	***	***	38.98%	61.02%
4	2012-13	***	***	36.32%	63.68%

- ख. यह देखा जा सकता है कि प्रार्थी के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। आयातों के संबंध में कुल मांग में आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई है और उसके पश्चात् अत्यधिक अभिनव समय के दौरान उसमें वृद्धि हुई है।
- ग. यह नोट करना प्रासंगिक है कि भारतीय उत्पादकों में से एक मैसर्स लैनेक्स, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी भारत तथा भारत से बाहर उत्पादन क्षमताएं हैं। कंपनी इस वस्तु का उत्पादन कभी तो भारत में करती है और कभी आयातों का आश्रय लेती है। कंपनी ने इस विचाराधीन उत्पाद का वर्ष 2009-10 के दौरान आयात किया है जब यह कंपनी अपना संयंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान को अंतरित करने की प्रक्रिया में थी। कंपनी ने नए स्थल पर अपना उत्पादन वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ किया था। इस प्रकार अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन वर्ष 2009-10 में सामान्य से भी कम (1000 एमटी के बराबर) था और इसके परिणामस्वरूप उसी अवधि में आयात सामान्य से अधिक (लगभग समान प्रमाणा के बराबर) थे।
- घ. प्रार्थी ने मूल जांच में यह प्रस्तुत किया है कि मैसर्स लैनेक्स ने अस्थायी रूप से अपना उत्पादन बंद कर दिया है और अपने उपभोक्तों की जरूरत को पूरा करने के लिए इसने भारत से बाहर स्थित अपनी उत्पादन सुविधाओं से इस सामग्री की आपूर्ति की है। यदि इस उत्पादन को बंद नहीं किया गया होता तो कंपनी ने संबद्ध वस्तु की उसी मात्रा का उत्पादन घरेलू रूप से किया होता। उक्त व्यवस्था में स्थायित्व के अभाव के कारण इन आयातों का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका समावेशन करने से आंकड़ों में विकृति उत्पन्न हो जाती।
- ङ. उपर्युक्त के आलोक में प्रार्थी ने बाजार हिस्से का निर्धारण लैनेक्स द्वारा आयातों एवं उत्पादन को पृथक से दर्शाकर किया है इस तरह निर्धारित किया गया बाजार हिस्सा निम्नलिखित है।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
चीन	%	12.45	11.51	21.09	12.97
कोरिया	%	41.00	32.99	28.23	34.12
ईयू	%	3.92	6.14	5.11	16.61
अन्य देश	%	3.01	10.68	5.47	2.01
लैनेक्स द्वारा आयात	%	8.23	5.19	1.13	-
एनओसीआईएल	%	***	***	***	***
लैनेक्स से इण्डिया प्रा. लि.	%	-	***	***	***
पीएमसी रबकेम प्रा. लि.	%	***	***	***	***
भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

- च. यह देखा गया कि लैनेक्स के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई। स्पष्ट: यह दर्शाते हुए कि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्सा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है लैनेक्स ने एक बार फिर आयात करने के बजाय इस रबड़ रसायन का उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया था।

4. उत्पादन

क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है:

वर्ष	उत्पादन (एमटी) अनुक्रमित
2009-10	100
2010-11	92
2011-12	74
2012-13	65

5. क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है

वर्ष	क्षमता उपयोग (%) (अनुक्रमित)
2009-10	100
2010-11	90
2011-12	73
2012-13	64

6. घरेलू बिक्रियां

घरेलू बिक्री मात्रा पर उत्पाद कर रिकार्डों के अनुरूप विचार किया गया है जिसमें फैक्टरी से प्रेषण को बिक्री के रूप में लिया गया है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है तथापि बिक्री में यह वृद्धि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कम थी। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद पर अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क तथा कोरिया से आयातों पर संवर्धित पाटनरोधी शुल्क होने के कारण घरेलू उद्योग को उच्चतर बिक्रियां प्राप्त होनी चाहिए थीं। तथापि, इन उपायों के बावजूद, आयातों में पुनः वृद्धि हो गई और यह वृद्धि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी। यह इस कारण से हुआ कि पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क की अनुप्रयोज्यता के बावजूद आयातों की अवसारित कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी।

	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	***	***	***	***
आयात	10,090	10,607	9,735	11,664
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन				
➤ घरेलू उद्योग की बिक्री		***	***	***
➤ आयात		517	(872)	1928

7. मालसूची

इस संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के इति भंडार में गिरावट आई है। यह इस तथ्य के कारण हुआ कि घरेलू उद्योग ने बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने और संचित मालसूची का निपटान करने के उद्देश्य से अपने उत्पादन को नियंत्रित करना और उप-इष्टतम कीमतों की पेशकश करना शुरू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो बिक्री में वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर प्रार्थी को भारी नुकसान हुआ। तथापि, हाल ही अवधि में दिनों की संख्या की बिक्री के रूप में स्टॉक भी बहुत अधिक बना रहा।

8. कीमत प्रभाव

विचाराधीन उत्पाद के आयात न केवल घरेलू उद्योग की कीमतों बल्कि घरेलू उद्योग की लागत से भी बहुत कम कीमतों पर रिपोर्ट किया जाना जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग, रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद, सकारात्मक कीमत अधोरदन का सामना कर रहा है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल घरेलू लागत (अनुक्रमित)	रुपए/किग्रा	100	103	114	121
बिक्री कीमत	रुपए/किग्रा	100	101	103	98
अवसारित कीमत	रुपए/किग्रा	172.93	172.00	175.81	169.91
लाभ/हानि (अनुक्रमित)	रुपए/किग्रा	100	76	(33)	(190)
कीमत अधोरदन (रेंज)	%	35-45	35-45	35-45	35-45
लागत अवसारित कीमत (अनुक्रमित)	रुपए/ एमटी	100	108	136	163

9. लाभप्रदायकता

संक्षेप में स्थिति निम्नवत है :

विवरण (अनुक्रमित)	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लाभ/हानि	रुपए/किग्रा	100	76	(33)	(190)
कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	100	80	(34)	(180)
नकद लाभ	लाख रुपए	100	85	(8)	(150)
आरओसीई	%	100	70	(28)	(46)

यह देखा जा सकता है कि

- (क) घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में संपूर्ण अवधि में इस सीमा तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में वित्तीय घाटा सहन करना पड़ा। सहन किया गया यह घाटा अभिनव अवधि में और भी अधिक बढ़ गया है।
- (ख) पीबीआईटी और नकद लाभ ने भी लाभप्रदायकता की तरह ही समान प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। घरेलू उद्योग को भारी नकद घाटा हो रहा है।
- (ग) लगाई गई पूंजी पर आवक में भी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कमी आई है। घरेलू उद्योग को पिछले दो वर्षों से ऋणात्मक आवक सहन करना पड़ रहा है।

10. रोजगार एवं उत्पादकता

घरेलू उद्योग को रोजगार में अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट आई है। संदत्त पारिश्रमिक में भी गिरावट आई है। उत्पादकता प्रतिदिन में भी गिरावट आई है। प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि यह पैरामीटर कई अन्य पैरामीटरों पर निर्भर है और वे घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। कर्मचारियों को नियोजित करना और उन्हें नौकरी से निकालना घरेलू उद्योग की स्थिति का अंतिम आशय है।

11. संयंत्र में तालाबंदी

- क) यह तथ्य कि प्रार्थी को पीएक्स-13 के आयातों के कारण बिक्री एवं उत्पादन में नुकसान हुआ है, इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि प्रार्थी को अपने संयंत्र में तालाबंदी करनी पड़ी है। संयंत्र में तालाबंदी का विवरण निम्नलिखित है :
- ख) यह देखा जा सकता है कि अभिनव अवधि में भारी तालाबंदी दी हुई। वास्तव में, तालाबंदी के घंटों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त यह तालाबंदी कंपनी के उत्पाद की कमी के कारण हुई है। कंपनी को विगत में विचाराधीन उत्पाद की भारी मालसूची का सामना करना पड़ी है और उसे पिछले दो वर्षों से इस उत्पाद पर घाटा हो रहा है। इसलिए प्रार्थी ने अपने उत्पाद

को मांग के अनुरूप बनाने का निश्चय किया और तद्वारा इस उत्पाद की मालसूची का विनियमन किया और इस उत्पाद की कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं में कमी की है। प्रार्थी जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए अपना उत्पादन शिड्यूलिंग चार्ट प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रूप से संयंत्र की तालाबंदी को दर्शाता है।

ग) यह स्पष्टरूप से दृष्ट है कि घरेलू उद्योग को इस सीमा तक घाटा हो रहा है कि उसे विपरीत तरीकों जैसे संयंत्र तालाबंदी का सहारा लेना पड़ा है। यह स्थिति रक्षोपाय शुल्क में विस्तार न किए जाने की स्थिति में और भी अधिक खराब हो जाएगी।

12). गंभीर क्षति संबंधी निष्कर्ष

1. प्रार्थी यह प्रस्तुत करता है कि निम्नलिखित कारक यह स्थापित करते हैं कि यदि रक्षोपाय शुल्क में और अधिक विस्तार नहीं किया गया तो आयातों से गंभीर क्षति होने की संभावना है।

- (क) रक्षोपाय शुल्क की अवस्थिति होने के बावजूद आयात बढ़ी हुई मात्रा में भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- (ख) रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद अत्यधिक अभिनव अविध में आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- (ग) आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।
- (घ) घरेलू उद्योग ने बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उप-इष्टतम कीमतों की पेशकश कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और ऋणात्मक अर्जन हुआ।
- (ङ) विदेशी उत्पादकों के पास भारी अनुप्रयुक्त क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी उत्पादक यथा संभव अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
- (च) घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी आई है जिसे रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके सुधारा जा सकता है।

2. यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क मौजूद होने के बावजूद गंभीर क्षति हो रही है। यदि रक्षोपाय शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो इस स्थिति में और अधिक निकृष्टता आ जाएगी।

3. यदि रक्षोपाय शुल्क में और अधिक विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग को आयात कीमतों से मुकाबला करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में और भी अधिक कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आयात कीमत में रक्षोपाय शुल्क की प्रमात्रा के बराबर गिरावट आ जाएगी और इसलिए घरेलू उद्योग को भारी नुकसान, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक अर्जन होगा। यदि रक्षोपाय शुल्क में और अधिक वृद्धि नहीं की जाती है तो घरेलू उद्योग की क्षति और भी अधिक बढ़ जाएगी।

थ) क्षति के अन्य कारक

1. पाटन और कम कीमत वाले आयातों के अलावा कोई अन्य कारक ऐसे नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो। चीन, कोरिया और ईयू से इस उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है। तथापि, केंद्रीय सरकार द्वारा, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि ईयू भारतीय बाजार में पीएक्स-13 का पाटन कर रहा है, पीएक्स-13 के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का पहले ही अधिरोपण किया हुआ है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समय चीन और कोरिया पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि कोई अन्य ऐसे सूचीबद्ध ज्ञात कारक नहीं हैं जिनकी महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित हो, इसलिए प्रार्थी ने कुछ अन्य ज्ञात कारकों के कारण होने वाली संभावित क्षति की जांच की है। इस संबंध में निम्नलिखित संगत कारक हैं :

- (क) इस उत्पाद की मांग संभावित गिरावट : क्षति अवधि से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि भारत में पीएक्स-13 की मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इस प्रकार मांग में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई है।
- (ख) खपत की प्रणाली में परिवर्तन : इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति के लिए खपत की प्रणाली में परिवर्तन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा भारतीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा : ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो।
- (घ) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन : इस उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास को क्षति के एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (ङ) निर्यात निष्पादन : प्रार्थी ने इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति के लिए निर्यातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

2. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन : घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति विचाराधीन उत्पाद पर हो रही है। घरेलू उद्योग को अध्यर्थन क्षति घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कारण नहीं है।

द) कारणात्मक संबंध

1. विगत पैराग्राफ में की गई अभिव्यक्ति के अनुसार कुछ अन्य ज्ञात संभावित कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद का पाटन और संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नलिखित कारक संगत हैं :

- (क) रक्षोपाय शुल्क मौजूद होने के बावजूद भारतीय बाजार में आयात संवर्धित मात्रा में प्रवेश कर रहे हैं।
- (ख) इस उत्पाद की बिक्री स्पष्टतः आयातों से तुलना/प्रतिस्पर्धा करके की जा रही है। आयातों की अवसारित कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।
- (ग) बाजार में सस्ते आयातों की मौजूदगी के कारण, घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें अपने माल की लागत सभी कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
- (घ) इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग को अभिनव अवधि में ऋणात्मक नकद लाभ और ऋणात्मक आवक का सामना करना पड़ा है।

2. अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति संवर्धित आयातों के कारण हो रही है और इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यदि वर्तमान रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि नहीं की जाती है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह गंभीर क्षति आयातों के कारण ही होगी।

घ) रक्षोपाय शुल्क की कालावधि

प्रार्थी रक्षोपाय शुल्क में अगले दो वर्षों के लिए और अधिक विस्तार करने का अनुरोध करते हैं।

न) सार्वजनिक हित

1. रक्षोपाय की अवधि में विस्तार करना जनहित में होगा। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने विगत में भी इस मुद्दे की विस्तार से जांच की थी और निम्नलिखित उपपादित किया था।

283. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में नहीं होगा। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने उसके प्रमाणस्वरूप कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

284. आवेदक नरे यह प्रस्तुत किया है कि टायर उद्योग में पीएक्स-13 का हिस्सा 0.71 प्रतिशत है और गैर-टायर सेगमेंट का हिस्सा 0.5 प्रतिशत है। इस तथ्य का एटीएमए द्वारा विरोध नहीं किया गया है जिसमें वर्तमान जांच में टायर विनिर्माता और अखिल भारतीय रबड़ विनिर्माता एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व है।

285. उपर्युक्त हिस्सा और पीएक्स-13 की अमहत्वपूर्ण लागत को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि टायर और गैर-टायर उद्योग की कीमत पर रक्षोपाय शुल्क का शून्य प्रभाव या न्यूनतम प्रभाव होगा।

286. आवेदक तथा एक अन्य घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति पहले ही कर ली गई है जैसा कि इस जांच परिणाम के पैरा 279 में चर्चा की गई है। आवेदक के यहां ही*** से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त, निवेश का भारी हिस्सा वित्तीय संस्थान से आया है। यदि भारतीय विनिर्माताओं को इस संवर्धित आयातों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है तो यह रोजगार और सार्वजनिक वित्त भारी जोखिम में होगा।

287. इसके अतिरिक्त, आवेदक घरेलू उद्योग के अलावा अन्य सभी भारतीय उत्पादक इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए इसके प्रमुख मध्यवर्ती 4 एडीपीए के लिए विदेशी उत्पादकों पर निर्भर है। आवेदक उद्योग समाप्त हो जाने की स्थिति में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य भारतीय उत्पादकों को 4 एडीपीए की प्राप्ति समय पर और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर होगी। अतः, आवेदक घरेलू उत्पादकों की अतिजीविता उपभोक्ताओं के हित में होगी। इसके अतिरिक्त, इस समय आवेदक के यहां कार्य कर रहे*** से अधिक कर्मचारियों का रोजगार भी जोखिम में पड़ जाएगा।

288. रक्षोपाय शुल्क, जो संवर्धित आयातों द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए घरेलू उद्योग की रक्षा करने में सक्षम होगी, इस विचाराधीन उत्पाद के क्रेताओं और उससे विनिर्मित उत्पाद के क्रेताओं के लिए भी जनहित में होगी। अतः यह विचार किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा।

2. उपर्युक्त को देखते हुए, प्रार्थी यह प्रस्तुत करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना जनहित में होगा। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा बिना किसी प्रमाण के है। उनका यह दावा

पूर्णतया अप्रमाणित एवं अभिप्रेरित है। किसी संगत साक्ष्य के अभाव में इस तर्क को अस्वीकार किया जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा। सार्वजनिक हित का बहुत व्यापक आशय है जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है

3. सार्वजनिक हित से आशय है : यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने मूलबश सार्वजनिक हित का आशय केवल उपभोक्ताओं के लिए को समक्ष रखा है। महानिदेशक द्वारा कई जांच परिणामों में धारित किए गए के अनुसार वाक्यांश सार्वजनिक हित का बहुत व्यापक आशय है जिसके दायरे में काफी बड़े सामाजिक कल्याण तथा व्यापक समुदाय हित को शामिल किया जाता है। इसलिए वाक्यांश सार्वजनिक हित का आशय इसी भावना से समझना चाहिए जिससे कि इसमें निम्नलिखित का हित शामिल हो सके :

- (क) उत्पादकों का हित
- (ख) उपभोक्ताओं का हित
- (ग) सार्वजनिक हित

4. वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना निम्नलिखित कारणों से जनहित में होगा।

- (क) यह विचाराधीन उत्पाद बहुत संवेदनशील है, परंतु उपभोक्ताओं के लिए यह न्यून लागत इनपुट है। उपभोक्ताओं के लिए इसका कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी है। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रतिस्थानी या तो बहुत महंगे हैं अथवा उनके परिणामस्वरूप टायर की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा।
- (ख) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप भारत में घरेलू उद्योग की अतिजीविता एवं उसका विकास होगा।
- (ग) 6 पीपीडी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा लागत तत्व नहीं है। 6 पीपीडी की अधिकांश खतप टायर उद्योग द्वारा की जाती है। 6 पीपीडी के कारण टायर उद्योग की कीमत पर 1 प्रतिशत से भी कम प्रभाव पड़ता है।
- (घ) 6-पीपीडी गैर-टायर उपभोक्ताओं के लिए तो और भी कम कीमत पर पड़ जाता है। यह बात गैर-टायर सेगमेंट के उपभोक्ताओं से और उनकी एसोसिएशनों अभी तक व्यावहारिक रूप में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने से भी सिद्ध हो जाता है।
- (ङ) इस उत्पाद के उत्पादकों के लिए 6 पीपीडी एक बड़ा उत्पाद है।
- (च) घरेलू उद्योग की उपस्थिति ने कीमतों को तर्कसंगत स्तर पर बनाए रखा है। कोरिया के और चीन के उत्पादकों का इरादा यह है कि भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन का उपशमन कर दिया जाए और तब उच्च कीमतें प्रभावित की जाए। अगर घरेलू उद्योग की अतिजीविता बनी रहती है तो उससे उपभोक्ताओं को लाभ ही होगा।

5. इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क के आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को दूर करने की सीमा तक ही होगा और इस प्रकार आयातों से प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

6. इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू उद्योग को क्षति बनी रहती है तो इससे घरेलू उद्योग समाप्त हो सकता है। जिसके परिणामस्वरूप पीएक्स-13 भारत में विनिर्मित नहीं होगा और तद्वारा पीएक्स-13 के सभी उपभोक्ताओं को पूर्णतया आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा।

7. उपर्युक्त के मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि रक्षोपाय का विस्तार करना जनहित में होगा और खासकर इससे इसके अंतिम प्रयोक्ताओं को हित संरक्षित होंगे।

प) समायोजन योजना

i. मूल जांच में प्रदान कराई गई समायोजन योजना : प्रार्थी ने अपनी समायोजन योजना में निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा की स्थापना का रहा है जहां कंपनी का इरादा पीएक्स-13 के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती का 10000 एमटी उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। कुल लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से विनिर्मित यह उद्योग क्रियान्वयन के स्तर पर है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2013 में कभी भी उत्पादन शुरू हो सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र लगभग तीन वर्षों की अवधि में अपनी इष्टतम क्षमता के साथ प्रचालनात्मक होगा। यह संवर्धित क्षमता अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं और मांग में संभावित वृद्धि और निर्यातों के पीएक्स-13 के आयातों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में पीएक्स-13 की मौजूदा और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इस अतिरिक्त, क्षमताओं में यह विस्तार कंपनी को आयातों से होने वाली उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने के समर्थ बनाएगी। इसलिए प्रार्थी तीन वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने का अनुरोध करता है जिससे कि प्रार्थी आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ हो सके।"

ii. समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

नियम 4(3) (iii) रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण की कालावधि और जहां इस तरह संस्तुत अवधि एक वर्ष से अधिक है, वहां सकारात्मक समायोजन सुलभ बनाने के लिए उत्तरोत्तर उदारीकरण की संस्तुति करना।

नियम 5(1) (ख) : आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए योजनाबद्ध या दोनों का विवरण।

नियम 11 महानिदेशक शुल्क की उस राशि के संबंध में भी सिफारिशें करेंगे जो, यदि उद्ग्रहण की गई तो, "गंभीर क्षति" का निवारण करने या उसका समाधान निकालने और सकारात्मक समायोजन सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

iii. यह देखा जा सकता है कि नियमों में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे सकारात्मक समायोजन सुलभ हो। दूसरे शब्दों में केवल संगत विचार यह है कि क्या समायोजन योजना घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी।

iv. चूंकि कंपनी ने दाहेज संयंत्र में 4 एडीपीए का विनिर्माण करना प्रारंभ कर दिया है इसलिए प्रार्थी ने आयात प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उपयुक्त एवं समुचित उपाय किए हैं। नियम में यह विहित नहीं किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क के विस्तार की मांग करने से पहले घरेलू उद्योग को सकारात्मक योजना से पूर्ण लाभ उपचित होना प्रारंभ हो जाए। वास्तव में, यदि घरेलू उद्योग को पूर्ण लाभ पहले से ही प्राप्त हो जाएंगे तो रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करने की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब पहले से ही की गई समायोजन योजना से पूरा परिणाम न प्राप्त होता है और यदि लाभ प्राप्त होना शुरू भी हो गया हो तो भी कंपनी को पूर्णतया प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

v. प्रार्थी ने दाहेज में 4 एपीपीए का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। योजना के अनुसार, यह वह एकमात्र उत्पाद है जिसका प्रार्थी दाहेज में उत्पादन कर रहा होगा। यह संयंत्र केवल पीएक्स-13 के लिए ही है जिसका अनन्य रूप से प्रयोग पीएक्स-13 के लिए ही किया जाएगा। पीएक्स-13 के उत्पादन की व्यापक उत्पादन प्रक्रिया तथा इसके विनिर्माण के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं :

एनिलाइन,
नाइट्रोबेन्जीन
होइड्रोजन
एम आई बी के
कैटालिस्ट

→ 4 एनडीपीए → 4 एडीपीए → पीएक्स-13

vi. यह देखा जा सकता है कि 4 एनडीपीए और 4 एडीपीए, पीएक्स-13 का उत्पादन करने की प्रक्रिया के चरण हैं। तथापि, 4 एडीपीए पीएक्स-13 के लिए प्रमुख उत्पाद है और इसका उत्पादन 4 एनडीपीए का उत्पादन कर लेने के पश्चात किया जाता है। वास्तव में 4 एनडीपीए का उत्पादन करने के पश्चात केवल एक अंतिम स्तर बाकी रहता है। इस समय केवल एक उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है और भविष्य में दाहेज में एक अन्य उत्पाद अर्थात् 4 एडीपीए का उत्पादन करने का प्रस्ताव है।

vii. मूल योजना में यथा प्राविधानित समायोजन योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थी द्वारा किए गए उपाय : यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी ने पूर्व में परिकल्पित समायोजन योजना को पूरा करने के लिए उचित उपाय किए हैं। यह तथ्य निम्नलिखित से स्पष्ट है :

(क) कंपनी ने दाहेज संयंत्र में भारी राशि का निवेश किया है। प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सी डब्ल्यू आई पी) विभिन्न समय पर विभिन्न रहा है जो निम्नवत है :

अवधि (तक)	सी डब्ल्यू आई पी (लाख रुपए)	अवधि के दौरान निवेश की गई राशि (लाख रुपए)	टिप्पणियां
मार्च, 2011	***		
नवम्बर, 2011	***	***	अप्रैल से नवम्बर 2001 के बीच
मार्च, 2012	***	***	दिसम्बर से मार्च 2012 के बीच
मई, 2012	***	***	अप्रैल से मई 2012 के बीच
अगस्त, 2012	***	***	जून से अगस्त 2012 के बीच

यह देखा जा सकता है कि प्रार्थी ने दाहेज संयंत्र में उत्तरोत्तर रूप से निवेश किया है। सीए प्रमाणपत्र और तुलनापत्र से उद्धरण के रूप में समर्थनकारी दस्तावेज इस याचिका के साथ प्रस्तुत कराए जा रहे हैं।

(ख) प्रार्थी ने पर्याप्त प्रचालनपूर्व व्यय किया है जिसमें कर्मचारी लागत, विपणन पूर्व व्यय, परीक्षण लागत तथा अन्य व्यय शामिल हैं। प्रचालनपूर्व व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

अवधि (तक)	प्रचालनपूर्व व्यय (लाख रुपए)
21 सितम्बर, 2011	***
31 मार्च, 2012	***

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने संसाधनों की अधिकांश राशि का पूर्व में प्रकल्पित समायोजन योजना का क्रियान्वयन करने के लिए किया है।

ग. वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट के संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

परियोजना

हमारी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, दाहेज स्थित नई परियोजना लगभग पूरी होने वाली है और अगस्त, 2012 तक इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है। हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस परियोजना के लिए निर्धारित कुल व्यय मूल रूप से अनुमोदित 250 करोड़ रुपए की राशि के अंदर है। हमें यह उल्लेख करते हुए की गर्व हो रहा है कि संकल्पनागत स्तर से लेकिन निष्पादन के स्तर तक की इस समस्त परियोजना का निष्पादन आपकी कंपनी की अपनी टीम द्वारा किया गया है इसमें कोई विदेशी तकनीकी जानकारी को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपको यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि इस परियोजना के लिए ऋण संघटक भी मूल से चिन्हित की गई राशि से कम होगी। कंपनी के प्रबंध वर्ग द्वारा दाहेज संयंत्र के लिए आवश्यक उत्पाद अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनियों से वार्ता करना भी प्रारंभ कर दिया है। हमें आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन ग्राहकों का रुझान बहुत सकारात्मक रहा है।

घ. वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट से संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

परियोजना

गुजरात में दाहेज स्थित हमारी परियोजना ट्रायल रन हेतु वर्ष के द्वितीय अर्धार्थ से प्रारंभ की गई थी। दाहेज स्थल पर वाणिज्यिक उत्पादन एक संधारित एवं स्थित उत्पादन परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर और सभी प्रमुख ग्राहकों से उत्पाद अनुमोदन प्राप्त होने पर शुरू हो गया है। यह नोट करने योग्य है कि यह समस्त परियोजना समर्पित इन-हाउस तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम द्वारा पूरी की गई है। हमें यह उल्लेख करते हुए गर्व हो रहा है कि यह वह परियोजना है जहां किसी भी प्रकार के बाह्य सहयोग (कोलैबोरेशन) की मांग नहीं की गई खासकर तब जब कि इसमें इतनी अधिक जटिल एवं कठिन रसायन प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त है। विश्व में केवल कुछ ही उत्पादक इस रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करने में सफल हुए हैं। यह परियोजना कुछ माह पहले की प्रारंभ हो गई होती यदि विद्युत बोर्ड ने समय पर एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई होती। इस संयंत्र पर उत्पादन आगामी वर्ष के प्रथम छमाही में प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना से कंपनी अपना प्रचालनात्मक निष्पादन बढ़ाने में सक्षम होगी क्योंकि इस नवीन विनिर्माण प्रक्रिया में तकनीकी नवाचार/सुधार किया गया है। इस परियोजना पर किया गया कुल व्यय मूल रूप से अनुमोदित 250 करोड़ रुपए की राशि के अंदर ही है और इस परियोजना का ऋण संघटक मूल रूप से अनुमानित राशि से कम होगा।

ड. घरेलू उद्योग ने दाहेज संयंत्र में परीक्षण उत्पादन नवम्बर, 2012 से ही प्रारंभ कर दिया था और वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2013 में प्रारंभ हुआ था। प्रार्थी यह आशंका व्यक्त करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग अपने मौजूदा पीएक्स-13 के उत्पादन की बिक्री बिना नुकसान सहन किए जाने में समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसे मौजूदा रक्षोपाय शुल्क में और अधिक विस्तार न किए जाने की स्थिति में दाहेज संयंत्र में क्षमताओं से तीव्रकृत नुकसान पड़ेगा। यदि मौजूदा रक्षोपाय शुल्क में और अधिक विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग को न केवल मौजूदा क्षमताओं से तीव्रकृत नुकसान होगा। बल्कि दाहेज संयंत्र में किए गए निवेश से भी घाटा होगा।

च. प्रार्थी ने दाहेज संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन पहले से ही प्रारंभ कर दिया है और इसके संगत साक्ष्य (उत्पादन कर रिकार्ड) याचिका के साथ संलग्न हैं।

viii. उपर्युक्त तथ्य यह स्पष्टतः सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है और शुल्क की निरंतरता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

फ) समायोजन योजना द्वारा पहले से ही उपचित लाभ

दाहेज संयंत्र पर प्रार्थी के उत्पादन की अधिकतम उत्पादन लागत और यदि प्रार्थी अपने पुराने संयंत्र पर अपने उत्पादन की निरंतरता बनाए रखता है तो इसके द्वारा सहन की गई उत्पादन लागत को याचिका में उपलब्ध कराया गया है। यह देखा जा सकता है कि प्रार्थी ने दाहेज में उत्पादन प्रारंभ करके पर्याप्त लागत बचत पहले ही प्राप्त कर रखी है।

ब) विगत जांच एवं वर्तमान जांच अवधि के बीच कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि

प्रार्थी की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए, यह विचार किया जाना चाहिए कि वर्तमान अवधि में विभिन्न कच्चे माल की कीमतों में, मूल जांच के समय व्याप्त कीमतों की तुलना में, भारी वृद्धि हो गई है। इन दोनों अवधियों में कीमतों की तुलना दर्शाते हुए एक

विवरण संलग्न है। यह प्राकृतिक है कि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में, कच्चे माल की लागत में वृद्धि के मद्देनजर, आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी। इसलिए, विगत अवधि और मौजूदा अवधि के बीच की गई कोई लागत तुलना कच्चे माल की कीमतों के उसी स्तर पर विचार करते हुए की जानी चाहिए। प्रार्थी ने अपनी उत्पादन लागत का निर्धारण उसी तरह किया है जैसा वह तब होता जब कच्चे माल की कीमतें समान बनी रहती जैसी वह मूल जांच के समय थीं। याचिका दायर करते समय संगत विवरण संलग्न किए गए हैं। इस उत्पादन लागत की तुलना वर्तमान उत्पादन लागत से करने पर यह दर्शाता है कि वर्तमान अवधि की उत्पादन लागत बहुत अधिक है क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। प्रार्थी महानिदेशक रक्षोपाय से यह अनुरोध करते हैं कि वह प्रार्थी द्वारा पहले किए गए प्रयासों की जांच करते समय इसका ध्यान रखें।

भ) निष्कर्ष

1. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि :

- (क) भारी आयातों की सतत निरंतरता बनी हुई है;
- (ख) यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि में विस्तार नहीं किया जाता है तो आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है;
- (ग) घरेलू उद्योग का निष्पादन नाजुक है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को भारी घाटा हो रहा है;
- (घ) यदि रक्षोपाय शुल्क में विस्तार नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में और अधिक गिरावट होने की संभावना है।
- (ङ) घरेलू उद्योग ने समायोजन करने के प्रयास किए हैं और प्रयास कर रहा है। घरेलू उद्योग को समस्त प्रयास करने में सक्षम बनाने के लिए रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना आवश्यक है।

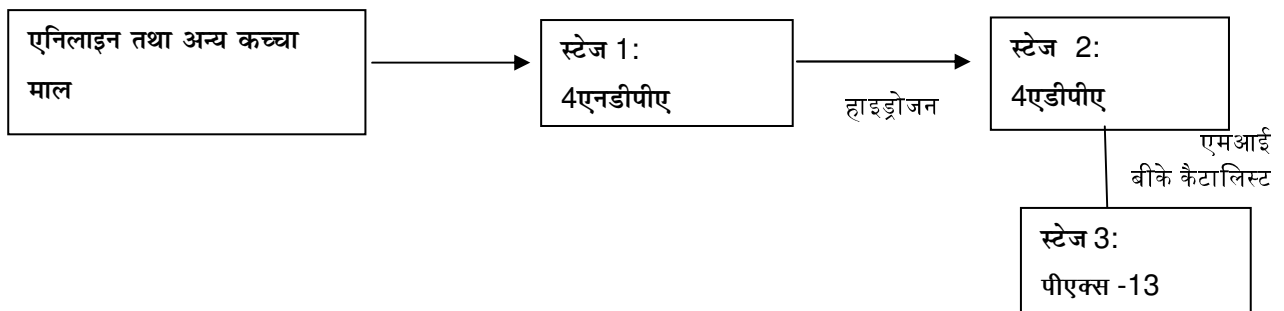
2. हितवद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रार्थी की संस्थापित क्षमता के संबंध में संभ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हितवद्ध पक्षकार जानबूझकर यह संभ्रम पैदा कर रहे हैं कि 4 एडीपीए में निवेश करने का आशय 6 पीपीडी में निवेश करना नहीं है। हम इसके साथ कुछ ऐसे दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं जो प्राधिकारी को विगत जांच और वर्तमान जांच दोनों में प्रदान किए गए थे। निम्नलिखित तालिका इस अवधि के दौरान प्रार्थी की मध्यवर्ती एवं परिष्कृत उत्पाद के लिए क्षमता दर्शाती है :

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
थाणे स्थित 4 एन डी पी ए	***	***	***	***	***
4 ए डी पी ए (दाहेज संयंत्र)	***	***	***	***	***
थाणे स्थित संयंत्र पर पीएक्स-13 / 6 पीपीडी	8,500	8,500	8,500	8,500	14,000

3. नोट : वर्ष 2012-13 में 4 एडीपीए के लिए क्षमता केवल एक माह (वाणिज्यिक उत्पादन मार्च 2014 में प्रारंभ हुआ और परीक्षण उत्पादन नवम्बर 2012 में प्रारंभ हुआ) और दाहेज संयंत्र में 4 एडीपीए की वार्षिकीकृत संस्थापित क्षमता 10000 एमटी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

- (क) यद्यपि प्रार्थी पहले अपने थाणे स्थित संयंत्र से 4 एनडीपीए का उत्पादन कर रहा था और उसके पश्चात उसे ही 6 पीपीडी के लिए पूरा करवाया जा रहा है और थाणे स्थित संयंत्र की क्षमता 6 पीपीडी का उत्पादन करने के लिए बढ़ाई गई है।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त है : 4 एनडीपीए और तत्पश्चात 4 एडीपीए और तब 6 पीपी डी। यह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में दर्शायी गई है :



इस प्रकार देखा जा सकता है कि पहले 4 एन डी पी ए का उत्पादन किया गया जो चार ए डी पी ए में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उनको 6 पी पी डी में परिवर्तित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा पहले अपनाई गई प्रौद्योगिकी में, प्रार्थी थाणे संयंत्र में चरण 1, चरण 2 एवं चरण 3 के कार्य संपन्न किया करता था। अब प्रार्थी दाहेज में चरण 2 का कार्य सीधे संपन्न कर रहा है और फिर दूसरे कदम के रूप में चरण 3 में 6 पी पी डी के उत्पादन के लिए उन्हें अंतरित कर रहा है।

4. प्रार्थी ने दो अतिरिक्त कारणों से स्वयं थाणे में 4 ए डी पी ए की 6 पी पी डी में प्रोसेसिंग जारी रखी है :

- (क) थाणे में उपलब्ध 4 एन डी पी ए / 4 ए डी पी ए के उत्पादन के लिए उत्पादन की सुविधाओं का उपयोग अब 6 पी पी डी के उत्पादन के लिए किया जा रहा है और इसलिए इन सुविधाओं का कम उपयोग हो पाता या उपयोग नहीं हो पाता / निष्क्रिय पड़ी रहती, यदि प्रार्थी दाहेज में 6 पी पी डी का उत्पादन जारी रखता;

- (ख) दाहेज में 6 पी पी डी का अभिप्राय दाहेज में ... रुपए का अतिरिक्त निवेश करना तथा थाणे स्थित उत्पादन की सुविधाओं को निष्क्रिय रखना है। व्यवसाय की दृष्टि से यह विवेकपूर्ण नहीं है।
- (ग) प्रार्थी टायर उद्योग को तब तक बिक्री नहीं कर सकता है जब तक कि टायर उद्योग द्वारा न केवल उत्पाद को अपितु संयंत्र को भी अनुमोदित न किया गया हो। टायर उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया बहुत ही परिपक्व तथा अच्छी तरह से स्थापित है। टायर कंपनी अनुमोदन की एक लंबी प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद कच्चा माल प्राप्त करती है, जिसमें न केवल उत्पाद का अनुमोदन शामिल होता है अपितु उत्पादन संयंत्र का अनुमोदन भी शामिल होता है। किसी नए संयंत्र एवं नए उत्पाद का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व टायर कंपनी को इस प्रक्रिया में - से - के बीच का समय लग सकता है। इसलिए इस अतिरिक्त वजह से प्रार्थी ने थाणे संयंत्र में 6 पी पी डी के उत्पादन को जारी रखा है ताकि परिवर्तन के लिए इसके क्रेताओं द्वारा उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत न पड़े। तथापि स्पष्ट किया जाता है कि टायर के सभी उपभोक्ताओं को अवगत करा दिया गया था कि कंपनी अब दाहेज में 4 ए डी पी ए का उत्पादन कर रही है तथा उसे मुम्बई में 6 पी पी डी में पुनः प्रोसेस किया जा रहा है। एन ओ सी आई एल द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए इस तरह के कुछ ईमेल तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त जवाब इस पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त जवाबों से देखा जा सकता है कि टायर उद्योग जनवरी, 2013 में एन ओ सी आई एल की सटीक स्थिति से पूरी तरह से अवगत है।

5. हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भ्रम पैदा करने के लिए इच्छुक पक्षकारों द्वारा बार बार उठाए जा रहे क्षमता के मुद्दे का अब समाधान हो जाएगा। तथापि, इस मामले में भ्रम पैदा करने के लिए इच्छुक पक्षकारों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे प्रयास को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षमता से संबंधित मुद्दा है, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे दोनों संयंत्रों का एक बार और सत्यापन करें ताकि हम दौरा करने वाली टीम को दिखा सकें कि कंपनी ने वास्तव में एक समायोजन योजना शुरू की है, जैसा कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को पहले सूचित किया गया है।

18. इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर

19. मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी, कोरिया :

19.1 घरेलू उद्योग द्वारा 31 दिसंबर, 2013 की लिखित प्रस्तुति के संबंध में मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी लि. (प्रतिवादी) की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग ने अपनी लिखित प्रस्तुति में क से थ तक आधार प्रस्तुत किए हैं तथा अनेक आधारों के खंडन पहले ही प्रतिवादी की लिखित प्रस्तुति में शामिल हैं जिसमें 31 दिसंबर, 2013 को जन सुनवाई के पश्चात दाखिल की गई हाल की प्रस्तुति भी शामिल है। प्रारंभिक जांच, अतिरिक्त जांच तथा जन सुनवाई के अनुसरण में लिखित प्रस्तुति के दौरान पहले दी गई प्रस्तुतियों को दोहराया गया है तथा संक्षेप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यहां उन्हें पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां नीचे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आधारों का खंडन किया गया है तथा केवल कुछ मुद्दों का केवल इसलिए विस्तार से उल्लेख किया गया है कि उन्हें और स्पष्ट किया जा सके।

आधार (क) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार क के पैराग्राफ 1 की अंतर्वस्तुएं तथ्यपरक एवं रिकार्ड से संबंधित हैं और इसलिए उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है।

आधार (ख) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ख के पैराग्राफ 2 की अंतर्वस्तुएं उपर्युक्त उत्पाद पर एंटी डंपिंग अन्वेषण से संबंधित तथ्य हैं तथा वर्तमान कार्यवाही से इनका कोई भी सरोकार नहीं है। पैराग्राफ 2 की अंतर्वस्तुएं वर्तमान कार्यवाही से असंगत हैं और इसलिए इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आधार (ग) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ग के पैराग्राफ 3 से 8 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है और ये विवादित हैं। प्रतिवादी रक्षोपाय की कार्यवाही में समीक्षा की सही कानूनी समझ के संबंध में पहले अपनी विस्तृत प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुका तथा उनको यहां दोहराता है। प्रतिवादी का कहना है कि घरेलू उद्योग रक्षोपाय नियमावली, विशेष रूप से नियम 18 के केवल कुछ अंश का चयन करके प्राधिकरण को गुमराह कर रहा है तथा अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग से नियम 18 का वाचन करके जानबूझकर ऐसी व्याख्या कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण जैसे किसी अर्ध न्यायिक फोरम के समक्ष इस प्रकार की समझ एवं दलील स्वीकार्य नहीं हो सकती है। उल्लेखनीय है कि रक्षोपाय की कार्यवाही में कानून की सही समझ जी ए टी टी के अनुच्छेद 19, रक्षोपाय पर डब्ल्यू टी ओ करार (ए ओ एस) तथा रक्षोपाय शुल्क नियमावली 1997 को एक साथ पढ़ने से ही प्राप्त हो सकती है।

आधार (घ) -i) प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार घ के पैराग्राफ 9 तथा 9क से 9ड की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवादित हैं। प्रतिवादी यह समझने में असमर्थ है कि कैसे लिखित प्रस्तुति के पृष्ठ 9 पर उल्लिखित एंटी डंपिंग शुल्क के विस्तार के मामले इस प्रकरण में मददगार हो सकते हैं। जी ए टी टी के अनुच्छेद 19, ए ओ एस तथा रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण को कवर करते हैं। जब रक्षोपाय की कार्यवाही में समीक्षा को अभिशासित करने के लिए विशिष्ट कानून हैं तो किसी और कानून की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो किसी भिन्न व्यापार निदान उपाय से संबंध रखता है, जब तक कि घरेलू उद्योग सहमत न हो तथा हमारा यह मानना है कि घरेलू उद्योग ने सहमति व्यक्त की है कि एंटी डंपिंग कानून, न कि रक्षोपाय कानून के तहत यह प्रकरण आता है। उल्लेखनीय है कि एंटी डंपिंग नियमावली के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (5) में विशेष रूप से किसी समीक्षा के लंबित रहने के दौरान एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का प्रावधान है तथा इसमें ऐसी अधिसूचना की तारीख से शुल्क के लागू होने का भी प्रावधान है। ए ओ एस तथा रक्षोपाय नियमावली में इन जैसे कोई समतुल्य नियम नहीं हैं जो विधायन के इस मंशा को दर्शाते हैं कि समीक्षा के लंबित रहने के दौरान रक्षोपाय शुल्क जारी नहीं रह सकती है तथा रक्षोपाय के समाप्त हो जाने के पश्चात इसका विस्तार नहीं हो सकता है। उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करके कानून की वरणात्मक समझ में पुनः शामिल हो गया है जहां रक्षोपाय शुल्क का विस्तार एक्सपायर होने के बाद किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस तरह का उदाहरण ऐसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है जब ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां महानिदेशक

(रक्षोपाय) ने अतीत में रक्षोपाय की अवधि समाप्त होने से पूर्व समीक्षा का कार्य पूरा किया है। ऐसे मामलों को यहां नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

उत्पाद	मूल अन्वेषण में अंतिम निष्कर्ष	सीमा शुल्क अधिसूचना तथा शुल्क की अवधि	समीक्षा अन्वेषण आरंभ करने की अधिसूचना	समीक्षा अन्वेषण में अंतिम निष्कर्ष
फेनोल	11 जून, 1999	सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 82/99; शुल्क की अवधि 30 जून, 1999 से 29 जून, 2011 तक थी	1 जनवरी, 2001 (पहली समीक्षा)	16 मई, 2001
फेनोल	16 मई 2001 (पहले अन्वेषण में अंतिम निष्कर्ष की तारीख)	सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 73/2001। शुल्क की अवधि 30 जून, 2001 से 29 जून, 2003 तक थी	22 अक्टूबर 2001 (द्वितीय समीक्षा)	11 दिसंबर, 2001
एसेटोन	7 अक्टूबर, 1999	सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 7/2000। शुल्क की अवधि 27 जनवरी 2000 से थी। शुल्क की अवधि 27 जनवरी, 2000 से 26 जुलाई 2002 थी।	21 नवंबर, 2001	4 फरवरी, 2002
सोडा ऐश	6 अक्टूबर, 2009	सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 122/2009। शुल्क की अवधि 20 अप्रैल, 2009 से 19 अप्रैल, 2010 तक थी।	19 फरवरी, 2010	13 अप्रैल, 2010

ii) इसके अलावा प्रतिवादी यह समझने में असमर्थ है कि क्यों घरेलू उद्योग परिपत्र संख्या 28/2011 दिनांक 8 जुलाई, 2011 पर निर्भरता व्यक्त कर रहा है, जो वैधता की अवधि के बाद एंटी डंपिंग शुल्क संग्रहीत करने के संबंध में है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि यदि घरेलू उद्योग इस बात से सहमत है कि उनका प्रकरण उक्त उत्पाद के डंपिंग से संबंधित है, जहां निदान डी जी ए जी के पास है न कि डी जी (रक्षोपाय) के पास है। यह पूरी तरह से समझ से परे है कि क्यों और कैसे कतिपय परिपत्र जो एंटी डंपिंग शुल्क के संग्रहण से संबंधित हैं, इस प्रकरण से प्रासंगिक होंगे।

iii) इसके अलावा घरेलू उद्योग डब्ल्यू टी ओ की विवाद निस्तारण से संबंधित कार्य विधियों को समझने में असफल रहा है तथा भोलेपन में दलील दी है कि डी एस 428 में भारत एवं तुर्की के बीच विवाद कभी डब्ल्यूटीओ पैनल में नहीं पहुंचा। उल्लेखनीय है कि परामर्श के लिए अनुरोध दाखिल करने के पश्चात डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश द्विपक्षीय परामर्श में शामिल होते हैं तथा हस्तक्षेप करने के लिए डब्ल्यूटीओ के किसी पैनल से अनुरोध करने से पूर्व आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकरण में परामर्श की प्रक्रिया की वजह से तुर्की ने सुरक्षोपायों को वापस ले लिया, इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए डब्ल्यू टी ओ किसी पैनल को जरूरत नहीं पड़ी। प्राधिकरण से इसकी जांच करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के संबंधित विभाग से निस्तारण के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवादी दृढ़तापूर्वक इस बात को दोहराता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत का दृष्टिकोण यह है कि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार इसकी अवधि समाप्त होने के बाद नहीं हो सकता है तथा इस उपाय के समाप्त होने से पूर्व रक्षोपाय की समीक्षा पूरी करनी होगी।

आधार (ड. और च) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ड. के पैराग्राफ 10 की अंतर्वस्तुओं तथा आधार च के पैराग्राफ 11 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि 2011 - 12 में तथा जनवरी, 2012 से दिसंबर, 2012 की अवधि में उक्त उत्पाद का अतिरिक्त गलत है। इसके विपरीत भारत में उक्त उत्पाद की भारी कमी है, जिसकी वजह से वर्ष 2012 - 13 में उक्त उत्पाद का 11,664 मीट्रिक टन आयात किया गया। पैराग्राफ 11 में यह दलील देकर कि उक्त उत्पाद का आयात उक्त उत्पाद की कम कीमत के कारण किया गया, घरेलू उद्योग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान प्रकरण रक्षोपाय की कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। घरेलू उद्योग किसी अन्य उपयुक्त फोरम से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है, यदि यह उक्त उत्पाद के कम मूल्य पर आयात से व्यथित है।

आधार (छ.) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार छ. के पैराग्राफ 12-13 की अंतर्वस्तुएं दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में नुकसान उठा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस तरह की स्थिति में निदान के लिए रक्षोपाय कानून में कोई प्रावधान नहीं है। घरेलू उद्योग निर्यात केन्द्रित हो या न हो, उक्त उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय को लागू करने के प्रस्ताव से उसका कोई लेनादेना नहीं है। इस प्रकरण में यह आधार पूरी तरह से अप्रासंगिक है तथा इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

आधार (ज) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ज के पैराग्राफ 14-15 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण संयंत्र की बंदी के संबंध में डाटा की जांच कर सकता है तथा वह इस

तरह की बंदी के वास्तविक कारणों की भी जांच कर सकता है। संयंत्र की बंदी के लिए आयात को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, यदि इसके लिए अन्य कारण मौजूद हों।

आधार (झ) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार झ के पैराग्राफ 16 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। इसके अलावा प्रतिवादी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्यों घरेलू उद्योग ऐसे आधार प्रस्तुत कर रहा है जो एंटी डंपिंग की कार्यवाही में प्रासंगिक हो सकते हैं। सहमत हुए बगैर यह मानना कि बिक्री में के पी सी को नुकसान हो रहा है, यह सूचना कैसे उक्त उत्पाद पर रक्षोपाय लागू करने के कार्य को उचित ठहराने में मददगार हो सकती है? इस तरह के आधार प्रस्तुत करके घरेलू उद्योग में लगातार इस बात को स्वीकार किया है कि रक्षोपाय शुल्क की बजाय एंटी डंपिंग शुल्क उनके लिए उपयुक्त निदान है।

आधार (ञ) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ज के पैराग्राफ 17 की अंतर्वस्तुएं तथ्यपरक तथा रिकार्ड से संबंधित हैं और इसलिए किसी उत्तर की जरूरत नहीं है।

आधार (ट) - प्रतिवादी का कहना है कि जहां तक लिखित प्रस्तुति के आधार ट के पैराग्राफ 18 की अंतर्वस्तुएं तथ्यपरक तथा रिकार्ड से संबंधित हैं और इसलिए किसी उत्तर की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण इस बात को नोट कर सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित चार ए डी पी ए न तो विचाराधीन उत्पाद या उक्त उत्पाद के समान है और न ही इनके प्रतिस्थापन के योग्य है।

आधार (ठ) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ठ के पैराग्राफ 19 से 22 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं है। महानिदेशक (रक्षोपाय) के समक्ष 19 दिसंबर, 2013 की जन सुनवाई में प्रार्थी ने दावा किया था कि सभी घरेलू उत्पादकों में क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क) एन ओ सी आई एल : 8500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

ख) मर्चेम : 8500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

ग) लैनेक्स : 2000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

घ) पी एम सी : 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

प्रार्थी के पास अब उक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता नहीं रह गई है। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि यह उक्त उत्पाद के 50 प्रतिशत का अंततः उत्पादन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रार्थी उक्त उत्पाद के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करता है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण को वर्तमान कार्यवाही में प्रार्थी के दृष्टिकोण का निर्माण करने वाले इस महत्वपूर्ण पहलू की जांच अवश्य करनी चाहिए।

आधार (ड और ढ) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ड के पैराग्राफ 23 से 33 तथा आधार ढ के पैराग्राफ 34 से 36 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि जी ए टी टी के अनुच्छेद 19 तथा ए ओ एस के अंतर्गत आवश्यकता यह नहीं है कि पी ओ आई से संबंधित कुछ डाटा एवं आंकड़ों को प्रदर्शित करने मात्र से आयात में वृद्धि हुई है। आवश्यकता यह है कि प्रार्थी को सबसे पहले इस बात की पहचान करनी होगी कि जी ए टी टी के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं करते समय कैसे कतिपय घटनाक्रमों की प्रत्याशा नहीं की गई जिनकी वजह से उक्त उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई। द्वितीयतः, प्रार्थी को इस बात की पहचान करनी होगी कि कैसे उक्त उत्पाद के संबंध में जी ए टी टी के अंतर्गत विशिष्ट बाध्यताओं की वजह से आयात में वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि अन्वेषण के वर्तमान स्तर तक प्रार्थी ने ऐसी कोई प्रस्तुति या दावा नहीं किया है जहां इसने अप्रत्याशित घटनाक्रमों तथा किसी विशिष्ट बाध्यता की मौजूदगी को साबित किया है जिसे भारत ने उक्त उत्पाद के संबंध में वहन किया है जिससे आयात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तृतीयतः, भले ही प्रार्थी उपर्युक्त दो आवश्यकताओं को स्थापित करने में असफल हो, उपर्युक्त विश्लेषण पूरा करने तथा अपने निष्कर्ष में उनको दर्ज करने का दायित्व अवधि प्राधिकरण के ऊपर है। प्रतिवादी इस बात को समझने में असमर्थ है कि कैसे लिखित प्रस्तुति में पी ओ आई के केवल आंकड़ों से उपर्युक्त आवश्यकताएं स्थापित होती हैं। केवल आंकड़ों का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है। प्राधिकरण से आग्रह किया जाता है कि वे अपने निष्कर्ष में उपर्युक्त विश्लेषण को पूरा करें। हमारी पिछली प्रस्तुतियों में तथा हमारी लिखित प्रस्तुतियों में भी इस संबंध में सारवान प्रस्तुतियां पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

आधार (ण) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ण के पैराग्राफ 37 से 60 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। इस संबंध में हमारी पिछली प्रस्तुतियों में सारवान प्रस्तुतियों पर विचार किया गया है। हमारी पिछली प्रस्तुतियों में पहले ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क प्रदान करने से पूर्व घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग न केवल गंभीर नुकसान को प्रमाणित करने में असफल रहा है अपितु जी ए टी टी के अनुच्छेद 19 की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को स्थापित करने में भी असफल रहा है। पहले ही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी घटने का वास्तविक कारण अन्य घरेलू उत्पादक जैसे कि मर्चेम हैं, जो इस याचिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के माध्यम से घरेलू उद्योग ने 19 दिसंबर, 2013 की जन सुनवाई में इस बात का उल्लेख किया है कि मर्चेम ने उक्त उत्पाद के लिए अपनी क्षमता बढ़ाकर 8500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर ली है। इसके अलावा मर्चेम चार ए डी पी ए के उत्पादन के लिए भी सुविधा सृजित कर रहा है, जैसा कि 31 दिसंबर, 2013 की हमारी लिखित प्रस्तुति में पहले ही उपलब्ध कराई गई उनकी वार्षिक रिपोर्ट से साबित होता है। उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि जैसे कारकों के आधार पर कोई और जांच विश्लेषण ऐसी स्थिति में निरर्थक होगा जब घरेलू उद्योग अनुच्छेद 19 एवं ए ओ एस की पूर्वापेक्षाओं को स्थापित करने में असफल रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, डेटा एवं आंकड़ों का केवल अनुशीलन पर्याप्त नहीं है। विश्लेषण से यह पता चलना चाहिए कि गंभीर नुकसान से इसका कोई न कोई संबंध है, अन्यथा यह मात्र सांख्यिकी की कवायद रह जाएगी, जिसमें घरेलू उद्योग शामिल है। इस तरह का खोखला विश्लेषण अस्वीकार्य है और इसलिए अस्वीकार कर देना चाहिए।

आधार (त) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार त के पैराग्राफ 61-62 की अंतर्वस्तुएं साबित करती हैं कि घरेलू उद्योग ने अंततः इस बात को स्वीकार किया है कि नुकसान का कारण डंपिंग है। लिखित प्रस्तुति के पैराग्राफ 61 के पहले दो वाक्यों, जो इस प्रकार उल्लेख करते हैं:

"डंपिंग एवं कम मूल्य के उत्पाद के आयात को छोड़कर ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। चीन, कोरिया एवं यूरोपीय संघ से उत्पाद की डंपिंग के कारण घरेलू उत्पाद को नुकसान हुआ।"

के अनुशीलन मात्र से इस बात का संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग ने इस बात को माना है कि इस प्रकरण में उपयुक्त निदान एंटी डंपिंग शुल्क होना चाहिए न कि रक्षोपाय शुल्क।

i) उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग की उपर्युक्त स्वीकृति से वर्तमान प्रकरण पूरी तरह से रक्षोपाय कानून के दायरे से बाहर हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से फोरम शॉपिंग और कानून की समुचित प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है। प्राधिकरण से अनुरोध है कि कृपया वे तत्काल इस अन्वेषण को समाप्त कर दें।

आधार (थ) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार थ के पैराग्राफ 63-64 की अंतर्वस्तुएं इस बात को और सुदृढ़ करती हैं कि वर्तमान प्रकरण रक्षोपाय कानून की रूपरेखा के अंतर्गत शुरू नहीं किया जाना चाहिए था। पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। लिखित प्रस्तुति के पैराग्राफ 63 का दूसरा वाक्य, जो इस प्रकार उल्लेख करता है:

"... विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग एवं कम मूल्य के उत्पाद के आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।"

दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने इस बात को पुनः माना है कि इस प्रकरण में उपयुक्त निदान एंटी डंपिंग शुल्क, न कि रक्षोपाय शुल्क होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि कैसे आयात में वृद्धि की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि यह इस बात को साबित नहीं कर सका है कि कैसे कतिपय अप्रत्याशित घटनाओं तथा उक्त उत्पाद से संबंधित जी ए टी टी के अंतर्गत कतिपय विशिष्ट बाध्यता की वजह से आयात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए इनके बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है।

आधार (द) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार द के पैराग्राफ 65 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। इस अन्वेषण के फलस्वरूप रक्षोपाय शुल्क प्रदान नहीं की जा सकती है, जैसा कि हमारी पिछली प्रस्तुतियों में पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

आधार (ध) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार ध के पैराग्राफ 66 से 71 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में रक्षोपाय शुल्क का विस्तार जनहित में नहीं होगा। जैसा कि हमारी पिछली प्रस्तुतियों में पहले ही स्थापित किया जा चुका है, घरेलू बाजार में उक्त उत्पाद की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा प्रार्थी केवल सुविधा के विस्तार के कार्य में शामिल है जो मध्यवर्ती चार ए डी पी ए का उत्पादन करती है, जिससे उत्पादकों जैसे कि ए टी एम ए के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, जो उक्त उत्पाद पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वास्तव में रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित के खिलाफ होगा तथा इससे कानून की समुचित प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए प्रार्थी जैसे अक्षम उद्योगों को बड़ावा मिलेगा। इसलिए प्राधिकरण से आग्रह किया जाता है कि वे जनहित में उक्त अन्वेषण को बंद कर दें।

आधार (न) - प्रतिवादी का कहना है कि लिखित प्रस्तुति के आधार न के पैराग्राफ 72 से 82 की अंतर्वस्तुओं का पूरी तरह से खंडन किया जाता है तथा ये विवाद के अधीन हैं। हमारी पिछली प्रस्तुतियों में इस बात को व्यापक रूप से स्थापित किया गया है कि प्रार्थी न केवल अपनी समायोजन योजना को पूरा करने में असफल रहा है अपितु वर्तमान अन्वेषण में जालसाजीपूर्ण समायोजन योजना पर भी निर्भर रहा है। मूल अन्वेषण में प्रस्तुत की गई आरंभिक समायोजन योजना दाहेज में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए थी जो पी एक्स- 13 का उत्पादन करेगा तथा वर्तमान योजना दाहेज में एक संयंत्र स्थापित करने के संबंध में है जो मध्यवर्ती चार ए डी पी ए का उत्पादन करेगा, जो उक्त उत्पाद से पूरी तरह से भिन्न उत्पाद है। प्रार्थी ने न केवल जालसाजीपूर्ण समायोजन योजना प्रदान की है अपितु अपनी आरंभिक समायोजन योजना का पालन करने के में भी असफल रहा है तथा अब दलील दे रहा है कि वह समायोजन योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए रक्षोपाय शुल्क का विस्तार चाहता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि प्रार्थी ने अपनी योजना का पालन किया होता तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि इसकी वजह से अन्य इच्छुक पक्षकारों को नुकसान होना चाहिए। यह रक्षोपाय कानून का प्रयोजन नहीं है।

i) घरेलू उद्योग ने मूल अन्वेषण के दौरान प्रदान की गई अपनी पिछली समायोजन योजना के बारे में गलत बयानी करके वर्तमान अन्वेषण में तथ्यों को मिथ्या रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तमान अन्वेषण में उल्लिखित विवरण पिछले अन्वेषण में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं से पूरी तरह भिन्न हैं। घरेलू उद्योग पिछली समायोजन योजना में की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करने में भी असमर्थ रहा है और इस प्रकार लगाए गए रक्षोपाय का पूरा लाभ लेने में असमर्थ रहा है। उपर्युक्त के आलोक में अपनी समायोजन योजना का पालन करने के संबंध में घरेलू उद्योग की दलील को सीधे अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए इस जांच को बंद किया जाना चाहिए।

ii) घरेलू उद्योग आयात में महत्वपूर्ण, भारी एवं अचानक वृद्धि की मौजूदगी का साबित करने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग अप्रत्याशित घटनाओं तथा उक्त उत्पाद के संबंध में जी ए टी टी के अंतर्गत किसी विशिष्ट बाध्यता की मौजूदगी को साबित करने में असफल रहा है, जिसकी वजह से आयात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। घरेलू उद्योग को न तो कोई गंभीर नुकसान हुआ है और न ही इस तरह की कोई संभावना है। घरेलू उद्योग अपनी समायोजन योजना का पालन करने में भी असफल रहा है। इसके अलावा उक्त उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई विकृति नहीं आई है।

iii) निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि किसी अप्रत्याशित घटना की मौजूदगी तथा 1994 के दौरान वहन की गई भारत की किसी बाध्यता के कारण आयात में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, आयात की कल्पित वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को नुकसान के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है, जो किसी रक्षोपाय को लागू करने के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं। इसके अलावा रक्षोपाय लागू करना जनहित में भी नहीं होगा क्योंकि

घरेलू उद्योग के पास प्रयोक्ता उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता नहीं है। इसके अलावा अपनी समायोजन योजना का पालन न करने की वजह से घरेलू उद्योग रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 के अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा है और इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क प्रदान नहीं की जा सकती है। iv) जैसा कि घरेलू उद्योग ने डंपिंग को नुकसान के एक कारण के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए निवेदन है कि प्राधिकरण प्रार्थी को डीजीएडी के समक्ष निदान प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है।

v) मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी लि., कोरिया (के पी सी) उक्त अन्वेषण में एक इच्छुक पक्षकार है। के पी सी ने 18 मार्च, 2014 के प्राधिकरण के ईमेल का हवाला दिया है जिसमें उक्त अन्वेषण में प्राधिकरण के पास प्रार्थी घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल दो पत्रों दिनांक 14 मार्च, 2014 पर इच्छुक पक्षकारों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

vi) इस पत्र में निहित निवेदनों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना के पी सी ने निवेदन किया कि पी एक्स- 13 (6 पी पी डी) पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा का कार्य इस प्रकार की रक्षोपाय शुल्क के समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए। समीक्षा अन्वेषण के पूरा हो जाने पर रक्षोपाय शुल्क का इस तरह का विस्तार, यदि इस तरह की सिफारिश की जाती है, केवल ऐसी शुल्क के समाप्त होने के बाद इस अन्वेषण में की जाएगी, जो कानून में असमर्थनीय है। उपर्युक्त के फलस्वरूप के पी सी का यह कहना है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को यह अन्वेषण इच्छुक पक्षकारों से कोई और स्पष्टीकरण मंगाए बगैर तत्काल बंद कर देना चाहिए।

vii) के पी सी ने इस बात को नोट किया है कि प्रार्थी ने अपने थाणे संयंत्र में 8500 मीट्रिक टन की पिछली क्षमता की बजाय 14000 मीट्रिक टन के हिसाब से उक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए क्षमता में वृद्धि के संबंध में इसमें कतिपय दावा किया है। प्रार्थी का दावा निम्नलिखित पर आधारित है:

- (क) उक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्चा माल के रूप में 4 ए डी ए पी की बजाय 4 एन डी पी ए को अपनाने की वजह से थाणे संयंत्र में समय चक्र 150 मिनट से घटकर 90 मिनट हो गया है;
- (ख) इसके दाहेज संयंत्र में उक्त उत्पाद के विनिर्माण के लिए एक मध्यवर्ती के रूप में 4 ए डी पी ए का उत्पादन, जो उक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए थाणे संयंत्र को 4 ए डी पी ए की आपूर्ति करता है; और
- (ग) लेखाकार इंजीनियर द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2014 का एक प्रमाणन जिसमें दर्शाया गया है कि थाणे संयंत्र में क्षमता बढ़कर 14000 मीट्रिक टन हो गई है।

viii) के पी सी ने इस बात को नोट किया है कि उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से प्रार्थी किसी न किसी रूप में उक्त उत्पाद की क्षमता में वृद्धि से संबंधित अपनी दलील को साबित करना चाहता है जिसे प्रार्थी ने 19 दिसंबर, 2013 की जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने प्राधिकरण के पास जन सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए सभी इच्छुक पक्षकारों को 31 दिसंबर, 2013 तक का समय दिया था। के पी सी इस बात को समझने में असमर्थ है कि प्रार्थी को 12 माह से अधिक का पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात 19 दिसंबर, 2013 की जन सुनवाई में अपनाई गई दलीलों के संबंध में पूर्वोक्त प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति क्यों दी गई। जन सुनवाई के बाद प्रस्तुति देने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय देकर प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन किया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा प्रार्थी की पूर्वोक्त प्रस्तुतियों को अकेले इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

ix) उपर्युक्त पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, केपीसी ने इस बात को नोट किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने ऊपर उल्लिखित पत्रों के अनुसार अपने थाणे संयंत्र में उठाए गए कदम प्रार्थी की समायोजन योजना का शायद ही अनुपालन करते हैं जिसे इसने मूल अन्वेषण के समय प्रस्तुत किया था। जैसा कि के पी सी अपनी पिछली प्रस्तुतियों में पहले ही स्थापित कर चुका है, प्रार्थी ने मूल अन्वेषण में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण की बजाय अपनी वर्तमान समीक्षा में अलग तरह की समायोजन योजना पर भरोसा किया है। जबकि छ: जून, 2011 के अंतिम निष्कर्ष में उल्लिखित मूल समायोजन योजना के अनुसार, प्रार्थी ने एक सनदी इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणन के आधार पर अपने दाहेज संयंत्र में उक्त उत्पाद का उत्पादन आरंभ करने का वचन दिया था, जिसे यह अप्रैल, 2012 तक पूरा कर लेगा। वर्तमान अन्वेषण में प्रस्तुत योजना में प्रार्थी ने दलील दी है कि इसने वित्त वर्ष 2013 से अपने दाहेज संयंत्र में 10,000 मीट्रिक टन मध्यवर्ती 4 ए डी पी ए का विनिर्माण शुरू करने का प्रस्ताव किया था। के पी सी का निवेदन है कि प्रार्थी अपनी समायोजन योजनाओं के जरिए प्राधिकरण को भ्रमित करके प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसके अलावा प्रार्थी लगभग दो साल तक अपनी समायोजन योजना का अनुपालन करने में विलंब करके अपनी समायोजन योजना का अनुपालन करने में असफल रहा है, हालांकि समायोजन योजना आवेदक द्वारा व्यवहार्य मानी गई थी क्योंकि यह एक सनदी इंजीनियर द्वारा सत्यापित थी। अपनी समायोजन योजना का अनुपालन करने में असफलता का परिणाम यह है कि भारत तथा उक्त उत्पाद से जुड़े अन्य देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

x) अब प्रार्थी ने पुनः एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी लेखाकार इंजीनियर द्वारा प्रदान किया गया है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी के थाणे संयंत्र में उक्त उत्पाद के लिए उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो गई है। उल्लेखनीय है कि यदि प्रार्थी 2011 की अपनी समायोजन योजना को पूरा नहीं कर सका जो किसी सनदी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित थी, तो किसी सनदी इंजीनियर द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर आधारित थाणे संयंत्र में क्षमता में वृद्धि से संबंधित ऊपर उल्लिखित पत्रों में आवेदक के वर्तमान दावा के संबंध में इसकी संभाव्यता एवं व्यवहार्यता के बारे में फिर से संदेह उत्पन्न होते हैं। वास्तव में यह संभव है कि इस तरह का दावा कुछ और न होकर दोषों को ढकने तथा अपनी मूल समायोजन योजना के कार्यान्वयन में विलंब से प्राधिकरण का ध्यान हटाने के लिए प्रार्थी द्वारा खोखले विवरण हों। ऊपर उल्लिखित पत्र तथा उनके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र किसी व्यावहारिक संभाव्यता के बगैर मात्र सैद्धांतिक दावा हैं। प्राधिकरण द्वारा इस तरह के दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं और इसलिए इन्हें तत्काल अस्वीकार कर देना चाहिए।

xi) ऊपर बताए गए कारणों के सिलसिले में के पी सी इस बात का भी उल्लेख करना चाहता है कि ऊपर उल्लिखित पत्र केवल इस बात का संकेत देते हैं कि समय चक्र में कटौती के कारण आवेदक उक्त उत्पाद के लिए 14000 मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त करने में

समर्थ है। परंतु पत्रों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रार्थी अपने दाहेज संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में मध्यवर्ती 4 ए डी पी ए का विनिर्माण करने में समर्थ है, जो इसे 14000 मीट्रिक टन उक्त उत्पाद का उत्पादन करने में समर्थ बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि समय चक्र में कटौती के आधार पर थाणे संयंत्र में क्षमता में वृद्धि से संबंधित दावा मात्र उक्त उत्पाद के 14000 मीट्रिक टन के विनिर्माण की वास्तविक क्षमता का कोई संकेत नहीं है, यदि दाहेज संयंत्र से थाणे संयंत्र को मध्यवर्ती 4 ए डी पी ए की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है। प्रार्थी को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह दाहेज संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में 4 ए डी पी ए का उत्पादन कर रहा है जिसे थाणे संयंत्र में उक्त उत्पाद के 14000 मीट्रिक टन में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा न कर पाने पर प्रार्थी का दावा खोखला हो जाएगा और इसलिए इन दावों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। क्षमता में वृद्धि के बारे में प्रार्थी का उपर्युक्त दावा किसी सारवान समर्थन से वंचित है, जैसे कि दाहेज संयंत्र से मध्यवर्ती 4 ए डी पी ए के पर्याप्त उत्पादन का डाटा तथा उसके थाणे संयंत्र को इसकी आपूर्ति वास्तव में प्रार्थी को थाणे संयंत्र में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि से संबंधित अपने दावे के समर्थन में दाहेज संयंत्र तथा किसी शाखा द्वारा थाणे संयंत्र को चार ए डी पी ए के अंतरण का उत्पादन लागू शीट प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे इसने उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया है।

xii) उपर्युक्त पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उपर्युक्त पत्र के माध्यम से इस बात को स्वीकार करके कि यह दाहेज संयंत्र में केवल 4 ए डी पी ए का उत्पादन करता है जो उक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए उसके थाणे संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है, प्रार्थी ने इस बात को माना है कि उसने मूल अन्वेषण के दौरान प्रस्तुत अपनी समायोजन योजना का पालन नहीं किया है, जिसमें इसने वचन दिया था कि वह अपने दाहेज संयंत्र में उक्त उत्पाद का उत्पादन करेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 16 (2) तथा नियम 18 (1) (i) के परंतुक के साथ पठित रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5.1 की दृष्टि से प्रार्थी सकारात्मक रूप से समायोजन करने में असफल रहा है तथा अपनी स्वयं की समायोजन योजना का पालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी की समायोजन योजना के अनुसार सकारात्मक रूप से समायोजन करने में प्रार्थी की विफलता को देखते हुए वर्तमान समीक्षा को तत्काल बंद कर देना चाहिए।

xiii) उपर्युक्त पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उल्लेखनीय है कि इस समीक्षा के प्रयोजन के लिए, रक्षोपाय नियमावली 1997 के नियम 18 (2) (i) की दृष्टि से, प्रार्थी को रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि से लेकर 29 अगस्त, 2013 तक इसके समापन की अवधि में उपर्युक्त कदम उठाना चाहिए था। वह विश्लेषण सार्थक होता तथा रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता का आकलन करने में सभी इच्छुक पत्रकारों की सहायता करता। रक्षोपाय शुल्क के समापन के बाद उठाया गया कोई भी कदम वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए अप्रासंगिक है। चूंकि प्रार्थी के ऊपर उल्लिखित पत्र तथा उनके साथ प्रस्तुत किया गया डेटा रक्षोपाय शुल्क के समापन के बाद उठाए गए कदमों से संबंधित हैं। इसलिए इस तरह की प्रस्तुतियों को तत्काल अस्वीकार किया जाना चाहिए।

xiv) के पी सी का यह कहना है कि प्रार्थी की उपर्युक्त प्रस्तुतियों का वर्तमान समीक्षा से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए तथा के पी सी किसी उपर्युक्त मंच में उपर्युक्त प्रस्तुतियों को चुनौती देने का अधिकार रखता है।

xv) के पी सी का यह कहना है कि ऊपर बताए गए कारणों तथा वर्तमान अन्वेषण के दौरान पहले इसके द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में वर्तमान समीक्षा को तत्काल रोक देना चाहिए तथा भारत एवं डब्ल्यू टी ओ अन्य सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार बहाल किया जाना चाहिए।

20. मैसर्स ऋषिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई:

प्रस्तुतियां बिंदुवार समान हैं, जैसा कि ऊपर मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया द्वारा दर्शाया गया है।

21. आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (ए टी एम ए) तथा इसकी सदस्य कंपनियां (जे के टायर, सिएट, अपोलो टायर तथा एम आर एफ लिमिटेड):

1. नियम 18 के अंतर्गत आवश्यकता रक्षोपाय पुनरीक्षा जाँच में लागू होगी

(क) अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस के पृष्ठ 2 के माध्यम से डीआई ने दलील दी है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (भारतीय एस जी अधिनियम) की धारा 8ख (4) के अंतर्गत अपेक्षाएं वर्तमान एस जी पुनरीक्षा अन्वेषण में लागू होती हैं। तथापि डी आई की यह प्रस्तुति गलत है तथा इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(ख) ए टी एम ए ने माननीय डी जी एस के समक्ष निवेदन किया है कि एस जी पुनरीक्षा अन्वेषण में, जिसमें एस जी शुल्क की अवधि चार साल से कम है, नियम 18 की अपेक्षाएं लागू होंगी, न कि धारा 8ख (4) की अपेक्षाएं लागू होंगी। धारा 8ख (4) की अपेक्षाएं ऐसे परिदृश्य में लागू होंगी जहां एस जी शुल्क की अवधि चार साल हो तथा चार साल के बाद एस जी का विस्तार करने के लिए आवेदन किया गया हो। धारा 8ख (4) को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

धारा 8ख (4): इस धारा के अंतर्गत लगाई गई शुल्क, जब तक कि पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से चार वर्ष के पूरा होने पर समाप्त होने का प्रभाव रखेगी:

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसे नुकसान या उसके खतरे को समायोजित करने के लिए कदम उठाया है और यह आवश्यक है कि एस जी शुल्क लगती रहनी चाहिए, वह इस शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है:

परंतु यह भी कि किसी भी स्थिति में एस जी शुल्क को पहली बार लगाए जाने की तारीख से 10 साल की अधिक अवधि के बाद लगाना जारी नहीं रखा जाएगा।

(ग) इस प्रकार धारा 8ख (4) में यह प्रावधान है कि जब तक कि पहले निरस्त नहीं की जाती है, एस जी शुल्क चार साल के बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रावधान में एस जी शुल्क की अवधि का उल्लेख है। इसके अलावा शर्तों के रूप में इस प्रावधान में दो अपवाद दिए गए हैं। पहला अपवाद यह है कि केन्द्र सरकार चार साल के बाद एस जी शुल्क लगाने की अवधि बढ़ा सकती है, यदि घरेलू उद्योग ने इसमें उल्लिखित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा किया है तथा दूसरा परंतुक यह है कि किसी भी स्थिति में पहली बार लगाए जाने की तारीख से 10 साल की अवधि बीत जाने के बाद एस जी शुल्क जारी नहीं रह सकती है।

(घ) आयातकों की उपर्युक्त प्रस्तुति इस तथ्य से और भी सुदृढ़ होती है कि इस जांच को आरंभ करने से संबंधित अधिसूचना में भी इस बात का उल्लेख है कि यह जांच नियम 16 एवं नियम 18 के साथ पठित धारा 8ख (4) के अंतर्गत शुरू की गई है। इस प्रकार नियम 18 में विशेष रूप से एस जी समीक्षा अन्वेषण के परिदृश्य पर विचार किया गया है, जब एस जी शुल्क की अवधि चार साल से कम हो, जो वर्तमान जांच में, न कि धारा 8ख (4) में लागू होगी।

(ड.) घरेलू उद्योग ने यह भी दलील दी है कि धारा 8ख (4) में 'जारी' शब्द का प्रयोग किया गया है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (भारतीय ए डी अधिनियम) की धारा 9क (5) प्रयुक्त 'जारी' शब्द के समान है। चूंकि ए डी शुल्क विद्यमान ए डी शुल्क के समाप्त होने के बाद भी लगाई जा सकती है। इसलिए यह एस जी समीक्षा जांच में भी लागू होनी चाहिए। तथापि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 8ख (4) के अंतर्गत अपेक्षा वर्तमान जांच में लागू नहीं होगी। इसकी बजाय नियम 18 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षा लागू होगी। इस प्रकार घरेलू उद्योग की इस दलील को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(च) इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच को समाप्त किया जा सकता है।

2. आयात में वृद्धि, गंभीर नुकसान तथा सांयोगिक संबंध की अपेक्षा भी एस जी समीक्षा जांच में लागू होती है :

(क) घरेलू उद्योग ने अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में यह दलील प्रस्तुत की है कि आयात में वृद्धि तथा गंभीर नुकसान की अपेक्षा एस जी समीक्षा जांच की शुरुआत के समय कोई पूर्वापेक्षा नहीं है। घरेलू उद्योग की यह प्रस्तुति सही नहीं है तथा इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि अपनी पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में आयातकों ने बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि सुरक्षोपायों पर डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 7.1 एवं 7.2 के तहत स्पष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि जांच प्राधिकरण आयात में वृद्धि, गंभीर नुकसान या गंभीर नुकसान के संकट तथा सांयोगिक संबंध की एस जी समीक्षा जांच में जांच करे। माननीय डी जी एस द्वारा इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने इस दलील का खंडन नहीं किया है तथा बहुत सुविधाजनक ढंग से एटी एम ए की इस प्रस्तुति की अनदेखी की है।

(ख) सुरक्षोपायों पर डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत उपर्युक्त बाध्यता भारतीय एस जी अधिनियम तथा भारतीय एस जी नियमावली में भी परिलक्षित होती है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय एस जी नियमावली के नियम 5, 6, 7 और 11 आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। घरेलू उद्योग ने अशोक सर्विस सेंटर तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए इसका खंडन करने का प्रयास किया है। तथापि इस प्रकरण के एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय वास्तव में आयातकों की दलील का ही समर्थन करते हैं।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा सरकार के प्रतिवाद को अस्वीकार कर दिया तथा निम्नानुसार टिप्पणी की : अधिनियम की धारा 3(2) दर्शाती है कि राज्य विधान मंडल का उद्देश्य प्रधान अधिनियम से सारवान मूलतः से विपथन करना नहीं है, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम कुछ अतिरिक्त बिक्री कर लगाता है जो उसके अलावा है जो प्रधान अधिनियम द्वारा लगाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत तथा प्रधान अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए करों का स्वरूप समान था तथा विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से प्रधान अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत लेवी पर लागू किया। ... हमारी यह राय है कि दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़ना एवं इस तरह समझना आवश्यक है जैसे कि दोनों अधिनियम एक हों तथा ऐसा करते समय प्रधान अधिनियम के प्रावधानों पर विधानमंडल के अधिनियम को तरजीह दिया जाना चाहिए, जहां भी अधिनियम में प्रधान अधिनियम को संशोधित करने की मंशा व्यक्त की है।

(घ) इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा सरकार की दलील को अस्वीकार कर दिया तथा स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की कि प्रधान अधिनियम के प्रावधान लागू हैं क्योंकि नए अधिनियम ने आवश्यक संशोधनों सहित शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह भारतीय एस जी नियमावली के नियम 18 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि नियम 5, 6, 7 और 11 आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे। इस प्रकार नियम 5, 6, 7 और 11 वर्तमान जांच में लागू होंगे। इस बात को भी नोट किया जाए कि भारतीय एस जी अधिनियम एवं नियमावली के अंदर ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो नियम 5, 6, 7 और 11 की प्रयोज्यता के विपरीत बात कहता हो। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के प्रतिवाद को अस्वीकार किया जाना चाहिए तथा माननीय डी जी एस से अपेक्षा की जाती है कि वे आयात में वृद्धि, गंभीर नुकसान तथा इनके बीच सांयोगिक संबंध की मौजूदगी की जांच करें।

3. जांच एस जी अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है :

(क) आयातकों ने जांच के दौरान अपनी प्रस्तुति में बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि यह जांच भारतीय एस जी अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है। संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए आयातक जांच के दौरान अपनी प्रस्तुति तथा पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस के दौरान प्रस्तुत की गई अपनी दलीलों को दोहराना नहीं चाहते हैं परंतु वे इन पर भरोसा करेंगे। तथापि आयातक यहां घरेलू उद्योग द्वारा अपनी पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में प्रस्तुत गलत प्रस्तुति को उजागर करना चाहेंगे।

(ख) पहली बात यह है कि घरेलू उद्योग ने अपनी दलील के समर्थन में सोडा ऐश अन्वेषण का हवाला दिया है कि विश्राम के साथ या बगैर भी एस जी शुल्क जारी रख सकती है। तथापि जैसा कि आयातकों द्वारा अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में स्थापित किया गया है, सोडा ऐश अन्वेषण में अंतिम निष्कर्ष माननीय डी जी एस द्वारा एस जी शुल्क की समाप्ति से पूर्व जारी किया गया और इसलिए यह आयातकों की इस दलील का ही समर्थन करता है कि माननीय डी जी एस द्वारा अंतिम निष्कर्ष को एस जी शुल्क की समाप्ति के पश्चात प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

(ग) दूसरी बात यह है कि घरेलू उद्योग ने भारतीय ए डी अधिनियम की धारा 9क (5) और भारतीय एस जी अधिनियम की धारा 8ख (4) में 'जारी' और 'विस्तार' शब्द के प्रयोग के बीच समानता लाने का प्रयास किया है। तथापि आयातकों ने इस प्रस्तुति में प्रस्तुत की गई अपनी दलीलों पर भरोसा किया है जिसमें यह स्थापित किया गया है कि भारतीय एस जी अधिनियम की धारा 8ख (4) के अंतर्गत

अपेक्षाएं वर्तमान जांच में लागू नहीं हैं। इसकी बजाय एस जी नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाएं वर्तमान जांच पर लागू होती हैं।

(घ) तीसरी बात यह है कि घरेलू उद्योग में सी बी ई सी द्वारा जारी एक सीमा शुल्क परिपत्र तथा कुछ ए डी अन्वेषण का हवाला दिया है। तथापि न तो परिपत्र और न ही घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत अन्वेषण वर्तमान जांच में प्रासंगिक हैं क्योंकि इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (5) के अंतर्गत प्रवर्तित किया गया है और जिसमें वर्तमान जांच नियम 16 और 18 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (4) के अंतर्गत शुरू की गई है।

(ङ.) निष्कर्ष के तौर पर आयातकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई एक भी दलील इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती है कि अंतिम निष्कर्ष एस जी शुल्क के समाप्त होने के पास एस जी समीक्षा जांच में माननीय डी जी एस द्वारा जारी किया जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत किए गए वृत्तांतों में से कोई भी वृत्तांत घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। वास्तव में सोडा ऐश अन्वेषण तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है, आयातकों के दृष्टिकोण का ही समर्थन करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयातकों का यह निवेदन है कि इस जांच का जारी रहना भारतीय एस जी अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है और इस प्रकार वर्तमान जांच बंद होनी चाहिए।

4. पी एक्स 13 के संबंध में मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर है

(क) आयातकों ने अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि देश में पी एक्स 13 के लिए मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर मौजूद है और इसकी वजह से आयातक पी एक्स 13 का आयात करने के लिए बाध्य हैं।

(ख) चूंकि घरेलू उद्योग ने अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में कोई नई दलील नहीं दी है इसलिए आयातक अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में प्रस्तुत अपनी दलीलों पर बने हुए हैं आयातक माननीय डी जी एस से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे पी एक्स 13 के संबंध में घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता का सत्यापन करें, जो घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता को स्पष्ट रूप से स्थापित करेगी।

5. पी यू सी के आयात में कोई अचानक, भारी एवं महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है:

(क) पी यू सी के आयात में कोई अचानक, भारी एवं महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में दावा किया गया है। पिछले चार वर्षों में मांग के अनुसरण में आयात में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, जिसकी वजह यह है कि घरेलू उद्योग भारत में पी यू सी की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान पी यू सी की कुल मांग में आयात का बाजार हिस्सा वास्तव में घटा है।

(ख) चूंकि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई नई दलील नहीं दी है इसलिए आयातक संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए अपनी दलीलों को नहीं दोहराएंगे परंतु उन पर भरोसा करेंगे।

6. कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है:

(क) जांच के दौरान अपनी प्रस्तुति में ए टी एम ए ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि गंभीर नुकसान के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा याचिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर स्थापित नहीं होता है।

(ख) घरेलू उद्योग ने अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में गंभीर नुकसान के संबंध में कोई नहीं दलील नहीं दी है। इस प्रकार ए टी एम ए घरेलू उद्योग के गंभीर नुकसान के दावे का खंडन करने के लिए जांच के दौरान प्रस्तुति में दी गई अपनी दलीलों पर भरोसा करता है।

7. सांयोगिक संबंध में व्यवधान:

(क) ए टी एम ए ने अपनी पिछली प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि सांयोगिक संबंध में व्यवधान है तथा घरेलू उद्योग द्वारा कारगर ढंग से इसका खंडन नहीं किया गया है।

(ख) जैसा कि घरेलू उद्योग ने अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में इस मुद्दे के संबंध में कोई नई दलील नहीं दी है, इसलिए संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए आयातक अपनी पिछली दलीलों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा उन पर भरोसा करेंगे।

8. एस जी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है:

(क) जैसा कि आयातकों की कार्यवाही संबंधी प्रस्तुति में स्थापित किया गया है, वर्तमान अन्वेषण में एस जी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है तथा यह माननीय डी जी एस की पिछली प्रथा के अनुरूप भी नहीं है। इस बात को नोट करना चाहिए कि अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस तक घरेलू उद्योग ने इस बारे में कोई दलील प्रस्तुत नहीं की है कि एस जी शुल्क जनहित में है तथापि अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि जनहित के संबंध में अपने दावे को स्थापित करने के लिए अन्य पक्षकारों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और दूसरा, चूंकि टायर के विनिर्माण में पी एक्स 13 का हिस्सा बहुत मामूली है, इसलिए प्रयोक्ता उद्योग पर इसका प्रभाव नहीं होगा।

(ख) तथापि घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुति गलत एवं माननीय डी जी एस की पिछली प्रथा के विपरीत है। मिथाइल एसिटोसेटेट रक्षोपाय जांच में, डी जी एस ने इस बात को नोट किया है कि भेषज उद्योग उक्त उत्पाद का एक महत्वपूर्ण प्रयोक्ता है। यह निष्कर्ष निकालते समय कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा, यह टिप्पणी की गई थी कि घरेलू उद्योग इस बारे में साक्ष्य प्रदान करने में समर्थ नहीं हुआ है कि कैसे पी यू सी पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से ये उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार इस बात को स्थापित करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है कि एस जी शुल्क का जारी रहना जनहित में होगा तथा यह किसी भी दृष्टि से प्रतिकूल नहीं होगा। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है अपने पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस तक घरेलू उद्योग ने जनहित के संबंध में कोई दलील प्रस्तुत नहीं की थी।

(ग) दूसरा, घरेलू उद्योग की इस दलील के संबंध में कि चूंकि टायर के निर्माण में पी एक्स 13 का हिस्सा मामूली है, इसका प्रयोक्ता उद्योग पर मामूली प्रभाव होगा। पहली बात यह है कि घरेलू उद्योग ने अपने इस निष्कर्ष के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान

नहीं किया है कि टायर के निर्माण में पी एक्स 13 का हिस्सा मामूली है। इसके अभाव में ए टी एम ए से इसका विरोध करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और इसलिए घरेलू उद्योग की दलील को अस्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि माननीय डी जी एस द्वारा यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रयोक्ता उद्योग को पिछले 8 साल से ए डी और / या एस जी शुल्क वहन करने के लिए बाध्य किया गया है जिससे यह मान लेने पर भी कि घरेलू उद्योग की दलील सही है, प्रयोक्ता उद्योग स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ है। इस प्रकार ए टी एम ए पोस्ट पी एच डब्ल्यू एस में प्रस्तुत अपनी दलील पर बना हुआ है कि एस जी शुल्क का जारी रहना वर्तमान अन्वेषण में जनहित में नहीं है।

9. घरेलू उद्योग की प्रस्तुति स्थापित करती है कि समायोजन योजना की अपेक्षा का पालन नहीं हुआ है :

क. भारतीय रक्षोपाय (एस जी) नियमावली के नियम 18 (1) के तहत यह अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग इससे पहले सकारात्मक रूप से समायोजन करे कि माननीय डी जी एस समीक्षा जांच के अनुसरण में एस जी शुल्क लगाना जारी रखने के लिए कोई सिफारिश करे। हमारी पिछली प्रस्तुतियों में आयातकों ने माननीय डी जी एस का ध्यान घरेलू उद्योग की समायोजन योजना के संबंध मूल अन्वेषण में घरेलू उद्योग की प्रस्तुति की ओर खींचा था :

एन ओ सी आई एल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है, जिसमें कंपनी ... मीट्रिक टन रबड़ केमिकल तथा इंटरमीडिएट का उत्पादन करने का इरादा रखती है जिसमें उत्पादों में से एक के रूप में पी एक्स 13 शामिल है।

ख. घरेलू उद्योग के उपर्युक्त वक्तव्य की मूल जांच के अंतिम निष्कर्षों में भी पुष्टि की गई। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने मूल जांच में यह दृष्टिकोण अपनाया था कि वे अपने नए संयंत्र में पी एक्स 13 का उत्पादन करेंगे। तथापि समीक्षा जांच में अचानक घरेलू उद्योग का यह दृष्टिकोण बदल गया जिसमें घरेलू उद्योग अब इस बात का उल्लेख कर रहा है कि वे अपने नए संयंत्र में 4 ए डी पी ए का निर्माण कर रहे हैं तथा घरेलू उद्योग के अनुसार यह एक मात्र उत्पाद है, जिसका विनिर्माण दाहेज में किया जाएगा।

ग. इस बात की अब घरेलू उद्योग की दिनांक 14 मार्च, 2014 की अतिरिक्त प्रस्तुति से भी पुष्टि हुई है, जिसमें घरेलू उद्योग में निम्नवत उल्लेख किया है :

जहां तक पी एक्स 13 का संबंध है, इसका उत्पादन थाणे में होता है। 4 ए जी पी ए, जो पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती है, का उत्पादन दाहेज में होता है।

घ. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना का कार्यान्वित नहीं किया है, जिसे मूल जांच में रेखांकित किया गया था। भारतीय एस जी नियमावली के नियम 16 (1) में यह प्रावधान है कि नियम 12 के अंतर्गत लगाई गई शुल्क केवल ऐसी अवधि के लिए होगी जो गंभीर नुकसान को रोकने या निदान करने के लिए तथा सकारात्मक समायोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकती है। इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को सकारात्मक रूप से समायोजन करने में समर्थ बनाना है ताकि वे प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें और समायोजन योजना में घरेलू उत्पादकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा प्रदान की जाती है ताकि सकारात्मक रूप से समायोजन किया जा सके तथापि यदि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं करता है तो भारतीय एस जी नियमावली के नियम 18 (2) में यह प्रावधान है कि माननीय डी जी एस समीक्षा जांच के अनुसरण में एस जी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं।

ङ. इस संबंध में आयातक माननीय डी जी एस का ध्यान फथैलिक एनहाइड्राइड के आयात के विरुद्ध दिनांक 7 जून, 2013 की रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा में अंतिम निष्कर्षों की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें माननीय डी जी एस ने निष्कर्ष के रूप में कहा है कि घरेलू उद्योग से सकारात्मक समायोजन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा है जो एस जी शुल्क का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मूल जांच में प्रस्तावित योजना के अनुरूप होनी चाहिए। चूंकि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया था इसलिए माननीय डी जी एस ने फथैलिक एनहाइड्राइड के आयात के विरुद्ध एस जी समीक्षा जांच को बंद कर दिया।

च. इसी तरह वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने आज की तिथि तक इस बात का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि उन्होंने समायोजन योजना को लागू किया है जिसे उन्होंने मूल जांच में प्रस्तावित किया था तथा माननीय डीजीएस द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके विपरीत वर्तमान जांच में उपलब्ध साक्ष्य से स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग में मूल जांच में रेखांकित समायोजन योजना को कार्यान्वित नहीं किया है। इस प्रकार आयातकों का यह निवेदन है कि रक्षोपाय शुल्क जारी रखने एवं बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है तथा भारतीय एस जी नियमावली के नियम 18 (2) को ध्यान में रखते हुए इसे अस्वीकार किया जाए।

10. घरेलू उद्योग की प्रस्तुति किसी गंभीर नुकसान को स्थापित नहीं करती है :

घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पी एक्स 13 के आयात की वजह से उसे गंभीर नुकसान हो रहा है। इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि अन्य पैरामीटरों में उत्पादन एवं क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है। जवाब में आयातकों ने अपनी पिछली प्रस्तुति में इस बात का उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग निर्यात उन्मुख कंपनी है तथा उत्पादन एवं क्षमता के उपयोग में गिरावट घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट की वजह से है। दिनांक 14 मार्च, 2014 की घरेलू उद्योग की अतिरिक्त प्रस्तुति आयातकों के उपर्युक्त कथन का समर्थन करती है।

(क) उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है :

(i) आयातकों ने पहले प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग परंपरा रूप से अपने उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत निर्यात करता है तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है। चार मार्च, 2014 को माननीय डी जी एस को घरेलू उद्योग द्वारा लिखे गए पत्र में प्रस्तुत आंकड़ों से भी इस दलील की पुष्टि होती है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्पादन (मीट्रिक टन में)	7264	6672	5408	4732
उत्पादन (अनुक्रमणित)	1000	92	74	65
घरेलू बिक्री (मीट्रिक टन में)	3516	3697	3641	3701
घरेलू बिक्री (अनुक्रमणित)	100	105	104	105
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्री (प्रतिशत में)	48	55	67	78
निर्यात बिक्री (मीट्रिक टन में)	3656	2767	2040	1162
निर्यात बिक्री (अनुक्रमणित)	100	76	57	37
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में निर्यात बिक्री (प्रतिशत में)	50	41	38	25

(ii) आयातकों ने 2009-10 से 2012-13 तक के आंकड़ों को लिया है क्योंकि रक्षोपाय समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए घरेलू उद्योग का आवेदन 2009-10 से 2012-13 तक की जांच के पैरामीटरों पर आधारित था। ये आंकड़े तथा उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यद्यपि घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही निर्यात बिक्री में गिरावट आई है जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग 2009-10 में अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात कर रहा था। उदाहरण के लिए 2009-10 में घरेलू बिक्री 3516 मीट्रिक टन थी तथा यह कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत था। तथापि यह 2012-13 में बढ़कर 3701 मीट्रिक टन हो गया जो घरेलू बिक्री का 78 प्रतिशत था।

इस प्रकार उत्पादन के समग्र अनुपात में घरेलू बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि से स्पष्ट रूप से घरेलू निर्यात में भारी गिरावट स्थापित होती है। इस गिरावट को आगे निर्यात मूल्य में भारी गिरावट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
घरेलू बिक्री मूल्य (लाख रु. में)	10,125	10,709	10,772	10,418
घरेलू बिक्री मूल्य (अनुक्रमणित)	100	106	106	103
निर्यात बिक्री मूल्य (लाख रु. में)	7257	5139	4060	2399
निर्यात बिक्री मूल्य (अनुक्रमणित)	100	71	56	33

iii) इस प्रकार यदि घरेलू बिक्री के मूल्य से तुलना करें तो 2009-10 की तुलना में 2012-13 में निर्यात बिक्री के मूल्य में 77 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसमें इसी अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) सांयोगिक संबंध में व्यवधान :

(i) भारतीय एस जी नियमावली के अनुबंध के खंड (2) के तहत यह प्रावधान है कि जब आयात में वृद्धि से भिन्न कारकों की वजह से उसी समय घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा हो तो ऐसे नुकसान का कारण आयात में वृद्धि को नहीं माना जा सकता है। यह बाध्यता रक्षोपाय पर करार के अनुच्छेद 4.2 (ख) में दर्शाई गई है जिसे गैर श्रेय विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.2 (ख) की व्याख्या निम्नानुसार की है :

इस प्रकार अनुच्छेद 4.2 (ख) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए, अंतिम वाक्य, सक्षम प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से कारण सहित एवं पर्याप्त व्याख्या के माध्यम से अवश्य स्थापित करना चाहिए कि आयात में वृद्धि से भिन्न कारकों से उत्पन्न नुकसान की वजह आयात में वृद्धि नहीं है। स्पष्टीकरण स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना चाहिए। यह केवल निहितार्थ नहीं होना चाहिए या किसी स्पष्टीकरण का सुझाव नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप में सीधा स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस प्रकरण में यू एस आई टी सी ने अभी स्वीकार किया है कि आयात में वृद्धि से भिन्न कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। तथापि अपने निष्कर्ष में इसने बस इस बात का उल्लेख किया है कि इसने घरेलू उद्योग को नुकसान का श्रेय ऐसे अन्य कारकों को नहीं दिया है। अपीलीय निकाय ने इस स्पष्टीकरण को रक्षोपाय पर करार के अनुच्छेद 4.2 (ख) की अपेक्षाओं का पालन करने वाला नहीं पाया क्योंकि यू एस आई टी सी रिपोर्ट कारणों के साथ तथा पर्याप्त स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करती है कि आयात में वृद्धि से भिन्न कारकों से उत्पन्न नुकसान आयात में वृद्धि की वजह से है।

(ii) इस प्रकार आयात से भिन्न कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को नुकसान का श्रेय आयात को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे सांयोगिक संबंध में व्यवधान का मार्ग प्रशस्त होता है। तथापि वर्तमान जांच में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को नुकसान निर्यात में गिरावट के कारण हुआ है। इसके अलावा अपनी पिछली प्रस्तुति में आयातकों ने ऐसे अन्य कारकों को भी उपलब्ध कराया है जिन्होंने सांयोगिक संबंध में व्यवधान का मार्ग प्रशस्त किया है तथा इस वजह से उनको अलग करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान के बीच सांयोगिक संबंध तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कि इन अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को नुकसान को अलग नहीं किया जाता है और दूर नहीं किया जाता है। इसके अलावा अपीलीय

निकाय के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयातक यह अनुरोध करेंगे कि इसके संबंध में कोई कारण सहित एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयात में वृद्धि की वजह से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान के बीच कारणात्मक संबंध में तब तक व्यवधान है जब तक कि अन्य कारकों की वजह से गंभीर नुकसान को कारण सहित एवं विस्तृत व्याख्या के साथ अलग नहीं किया जाता है।

11. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता नहीं है :

क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 2012-13 तक उसकी संस्थापित क्षमता 8992 मीट्रिक टन थी, जबकि 2012-13 में समग्र मांग 18315 मीट्रिक टन थी। इस प्रकार प्रयोक्ता उद्योग के पास 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान आयात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार इस अवधि के दौरान जो आयात किया गया वह घरेलू उद्योग की असमर्थता की वजह से था तथा प्रयोक्ता उद्योग को घरेलू उद्योग की असमर्थता की वजह से और दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

ख) घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2014 के लिए अपनी क्षमता के संबंध में आंकड़ें प्रदान करके इस असमर्थता को ठगने का प्रयास किया है जिसमें घरेलू उद्योग की क्षमता को 12,000 मीट्रिक टन के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा मार्च, 2014 के लिए आंकड़ों को 14,500 मीट्रिक टन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि माननीय डी जी एस द्वारा इन आंकड़ों का सत्यापन किया जाना है, यदि यह मान भी लें कि यह आंकड़े सही हैं तो आयातकों का यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का आकलन करने के लिए इन अतिरिक्त आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

22. घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर :

यह पी एक्स 13 (6 पी पी डी) के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अन्वेषण के विस्तार के मामले में नामोद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित मौखिक सुनवाई के संदर्भ में है। हम मौखिक सुनवाई के अवसर पर मौखिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए हमें अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकारी के आभारी हैं। निम्नलिखित इच्छुक पक्षकारों ने सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुति दी है :

1. मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
2. मैसर्स ऋषिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3. आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (ए टी एम ए)
4. यूरोपीय संघ

घरेलू उद्योग ने नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के पास दाखिल पिछली प्रस्तुतियों में प्रस्तुत सभी तथ्यों, प्रतिवादों, विरोधों एवं वक्तव्यों को दोहराया है तथा अनुरोध किया है कि इन प्रस्तुतियों को इसमें शामिल माना जाए। अब तक घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर वर्तमान प्रस्तुतियों की इन दलीलों की गैर प्रस्तुति को घरेलू उद्योग के विरुद्ध न माना जाए। घरेलू उद्योग की ओर से किसी अन्य प्रस्तुति या एक दूसरे की प्रस्तुति पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना नीचे प्रस्तुतियां व्यक्त की जा रही हैं।

क. समीक्षा के समय विश्लेषण के मानक :

एक प्रमुख मुद्दा जो महानिदेशक द्वारा विचार एवं निर्णय के लिए उत्पन्न हुआ है, इस बारे में है कि कैसे आयात में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को नुकसान का निर्धारण वर्तमान समीक्षा जैसी समीक्षा में किया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित बातें संगत हैं :

(झ) **कानूनी अपेक्षा :** देखा जा सकता है कि किसी समीक्षा में महानिदेशक से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा होती है कि क्या रक्षोपाय शुल्क आगे भी जारी रहनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा होती है कि क्या भारत में ऐसी अधिक मात्रा में उत्पाद का आयात जारी है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होता है या गंभीर नुकसान होने का खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा महानिदेशक से इस बात पर विचार करने एवं निर्धारित करने की अपेक्षा होती है कि क्या गंभीर नुकसान को रोकने या इसके निदान के लिए रक्षोपाय शुल्क को सतत रूप से लगाना आवश्यक है। प्रार्थी ने इस बात का उल्लेख किया है कि नियमों में इस संबंध में निर्धारण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि क्या रक्षोपाय शुल्क आवश्यक है। रक्षोपाय शुल्क के इस तरह से सतत रूप से जारी रहने के उद्देश्य को भी नियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है अर्थात् रक्षोपाय शुल्क के निरसन के फलस्वरूप गंभीर नुकसान को रोकना या निदान करना। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि गंभीर नुकसान को रोकने या इसके निदान के लिए रक्षोपाय शुल्क आवश्यक हो सकती है या नहीं - इस संबंध में निर्धारण का अभिप्राय यह है कि (क) क्या घरेलू उद्योग को लगातार गंभीर नुकसान हो रहा है और ऐसे सतत गंभीर नुकसान का निदान करने की जरूरत है; या (ख) क के विकल्प के रूप में जहां अब कोई गंभीर नुकसान नहीं हो सकता है, क्या ऐसी रक्षोपाय शुल्क के निरसन पर ऐसे गंभीर नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है। बाद वाली इस स्थिति का स्पष्ट रूप से अभिप्राय यह है कि घरेलू उद्योग अब रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात गंभीर नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं हो सकता है (जो रक्षोपाय शुल्क लगाने की वजह से हो सकता है) परंतु ऐसा गंभीर नुकसान वर्तमान रक्षोपाय शुल्क पर रोक लगाने की स्थिति में हो सकता है तथा ऐसे संभावित गंभीर नुकसान को रक्षोपाय शुल्क को पुनः जारी रखकर रोका जाना चाहिए।

रक्षोपाय नियम 18 (3) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि नियम 5, 6 और 11 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के आधार पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में नियम 5, 6 और 11 के प्रावधानों को उसी ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है जिस ढंग से उनको किसी नए अन्वेषण में पढ़ने एवं व्याख्या करने की अपेक्षा होती है। इस बात को देखते हुए कि रक्षोपाय शुल्क पहले से ही लागू है, इसका अभिप्राय यह है कि आयात में वृद्धि तथा गंभीर नुकसान से संबंधित निर्धारण लागू रक्षोपाय शुल्क को ध्यान में रखते हुए करना होगा।

दोनों सुनवाई के समय तथा अपनी लिखित प्रस्तुतियों में भी इच्छुक पक्षकारों ने बृहद रूप में यह दलील दी है कि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि :

- उत्पाद का आयात "आयात में वृद्धि" को नहीं दर्शाता है; और
- घरेलू उद्योग का निष्पादन गंभीर नुकसान को दर्शाता है।

(i) यदि अन्य रूप में प्रस्तुत करें तो इन अपेक्षाओं को इस रूप में पढ़ना एवं समझना चाहिए जैसे कि मूल अन्वेषण में उन्हें लागू किया गया है। इसका अभिप्राय मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से आयात में वृद्धि का निर्धारण करना होगा क्योंकि यह मूल अन्वेषण में अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में महानिदेशक को आयात में अचानक, महत्वपूर्ण, भारी एवं हालिया वृद्धि को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कानून के तहत अपेक्षा यह है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात निम्नलिखित कसौटियों से गुजरना चाहिए :

- (क) वृद्धि बिल्कुल हाल ही की होनी चाहिए;
- (ख) वृद्धि बिल्कुल अचानक होनी चाहिए;
- (ग) वृद्धि बिल्कुल भारी होनी चाहिए; और
- (घ) वृद्धि बिल्कुल महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

ii) कल्पना की किसी भी उड़ान के माध्यम से यह दलील नहीं दी जा सकती है कि कानून निर्माता ने समीक्षा के समय उपर्युक्त निर्धारण के साथ कानून का निर्माण किया है जिसका अर्थ यह है कि सबसे हाल की अवधि के डेटा की तुलना पूर्ववर्ती अवधि के डेटा से की जानी चाहिए। एकमात्र संभावित स्थिति जिसमें (रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात आयात में बिल्कुल हालिया, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल भारी और बिल्कुल पर्याप्त वृद्धि के ऐसे दृष्टिकोण) का अस्तित्व होगा, वहां होती है जहां रक्षोपाय शुल्क केवल गलत ढंग से लगाई जाती है या रक्षोपाय शुल्क की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती है कि उत्पाद का आयात रक्षोपाय शुल्क लगने के बावजूद बहुत ही लाभप्रद बना रहता है और इसके फलस्वरूप उत्पाद का आयात और वृद्धि का प्रदर्शन करता है, वह भी रक्षोपाय कानून के अभिप्राय के अंदर घरेलू उत्पाद का निष्पादन और खराब होता है। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां उचित एवं पर्याप्त मात्रा में रक्षोपाय शुल्क लगाई जाती है परंतु उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है तथा आयात में वृद्धि की स्थिति बनी रहती है तथा घरेलू उद्योग को नुकसान होता रहता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि रक्षोपाय कानून के अंतर्गत ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो ऐसी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क के विस्तार की अनुमति देता है जहां रक्षोपाय शुल्क के वांछित प्रभाव हुए हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से, परंतु पहले लगाई गई रक्षोपाय शुल्क का आगे विस्तार इसलिए करने की जरूरत होती है कि नुकसान को रोका जा सके या निदान प्रदान किया जा सके। कानून का यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि कानून में शून्यता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

iii) इच्छुक पक्षकारों ने जो दलील दी है उसके विपरीत तथा जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है, किसी समीक्षा में महानिदेशक से जिस बात का निर्धारण करने की अपेक्षा होती है वह यह है कि क्या उत्पाद का आयात रक्षोपाय शुल्क लगने के बावजूद इतना महत्वपूर्ण बना रहेगा तथा इसका अभिप्राय ऐसी स्थिति में आयात में वृद्धि से होगा जब उद्घाल पूर्व अवधि से इसकी तुलना की जाती है और क्या इस स्तर पर रक्षोपाय शुल्क को समाप्त करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां ऐसे आयात से नुकसान होता है या होने का खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा महानिदेशक से इस बात का निर्धारण करने की अपेक्षा होती है कि क्या नुकसान को रोकने या निदान प्रदान करने के लिए रक्षोपाय शुल्क आगे भी जारी रहनी चाहिए। उपर्युक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाल की अवधि के लिए आयात पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आयात की मात्रा से निर्णय पारित करते समय आयात में वृद्धि प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके अलावा तुलना को सन्निकट अवधि तक प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है।

(ii) **अन्य अन्वेषण प्राधिकारियों की प्रथा :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अन्वेषण किसी जांच समीक्षा का पहला प्रकरण है तथा इच्छुक पक्षकारों की दलील को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी ने अन्य देशों द्वारा किए गए निर्धारणों की समीक्षा की। निम्नलिखित प्रकरणों का हवाला दिया जा रहा है तथा उन पर भरोसा किया जा रहा है :

(क) ग्लास मिरर (डब्ल्यू टी ओ रिपोर्ट संख्या : जी/एस जी/एन/11/पीएचएल/3/प्रक 2 तथा जी/एसजी/एन/14/पीएचएल/4) - 12 मई, 2006 को व्यापार एवं उद्योग विभाग (डी टी आई), फिलीपींस ने अशाही ग्लास फिलीपींस, इंक (ए जी पी) से एक पत्र प्राप्त किया जिसमें विभिन्न देशों से ए एच टी एन संख्या : 7009.9100 तथा 7009.9200 के अंतर्गत वर्गीकृत आयातित ग्लास मिरर (काँपर आधारित) के विरुद्ध निश्चायक सामान्य सुरक्षोपायों के विस्तार का अनुरोध किया गया था। ए जी पी ने दावा किया कि अपनी समायोजन योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने तथा आयात प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उद्योग को और समय की जरूरत है। इसके अलावा बाहरी कारकों जैसे कि बिजली एवं ईंधन की कीमतों में वृद्धि, समग्र परिवहन लागत तथा चीन की व्यापक आयात मांग जिसकी वजह से अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में उद्घाल आया, ने उनकी लागत प्रभावकारिता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। प्राधिकरण ने निम्नानुसार राय व्यक्त की है :

5 अक्टूबर, 2006 को डी टी आई ने ए जी पी की याचिका पर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त की। निष्कर्ष के तौर पर आयोग ने कहा कि ग्लास मिरर के अनन्य विनिर्माता के रूप में प्रार्थी अर्थात् अशाही ने उक्त वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पाद का उत्पादन किया। घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना का पालन करने के लिए गंभीर प्रयास किए तथा इस बात के साक्ष्य हैं कि आयात प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा है। वर्तमान रक्षोपाय कारगर है। आयात की मात्रा घटकर उद्घाल पूर्व स्तर पर पहुंच गई। घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन, बिक्री, बाजार शेयर, उत्पादकता, क्षमता उपयोग तथा लाभप्रदता में सुधार का प्रदर्शन किया। रक्षोपाय शुल्क के बगैर घरेलू बिक्री मूल्य काफी नीचे गिर जाएंगे जो उत्पाद की लागत की भरपाई करने एवं बिक्री करने के लिए अनुकूल नहीं होगा। गंभीर नुकसान का पर्याप्त खतरा है, यदि रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाई जाती है। चीन के घरेलू बाजार में वर्तमान अत्यधिक क्षमता, अधिक वित्त का निर्माण होने तथा फिलीपींस में आयात की रुझानें दर्शाती हैं कि यदि रक्षोपाय शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो आयात में पर्याप्त वृद्धि की बहाली की काफी संभावना है। फिलीपींस से चीन की निकटता तथा मुक्त रूप से निस्तारण के योग्य उत्पादन की उनकी पर्याप्त क्षमता फिलीपींस को निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत देती है, यदि रक्षोपाय शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है। अशाही के नियंत्रण से बाहर के कारकों ने उसकी अवरुद्ध समायोजन योजना से प्राप्त लाभों को समाप्त कर दिया। आयात प्रतिस्पर्धा का कारगर ढंग से सामना करने के लिए

अशाही को अपनी समायोजन योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए और समय की जरूरत है। रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाए न जाने से ग्लास मिरर के आयात में वृद्धि होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होगा।

(ख) हवाईट शुगर (जी / एस जी / एन / 13 / एम डी ए / 1), जहां 2004 में शुल्क लगाई गई थी तथा 2006 में आयोजित समीक्षा अन्वेषण में 2002 से 2006 के डेटा का अन्वेषण किया गया। विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला :

		2002	2003	2004	2005	2006
घरेलू उत्पादन	1000 टन	114	83	111	133	148
चीनी का आयात	1000 टन	72	74	0	8	0
निर्यात	1000 टन	38	26	5	13	30
घरेलू बाजार में बिक्री सहित	1000 टन	150	105	101	114	86
घरेलू स्तर पर चीनी का उत्पादन	1000 टन	111	40	101	106	86
चीनी का आयात	1000 टन	39	65	0	8	0
घरेलू उत्पाद का बाजार शेयर		74 प्रतिशत	38 प्रतिशत	100 प्रतिशत	93 प्रतिशत	100 प्रतिशत
आयात का बाजार शेयर		26 प्रतिशत	62 प्रतिशत	0 प्रतिशत	7 प्रतिशत	0 प्रतिशत
वर्ष के अंत में घरेलू उत्पादकों का स्टॉक	1000 टन	63	73	71	83	111

इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घरेलू उद्योग के समुत्थान के संकेतों तथा समझौता को लागू करने के लिए उसके सफल प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र के और समुत्थान के लिए रक्षोपाय अभी भी आवश्यक है।

(ग) डेसीकेटेड पील्ड कोकोनट (जी / एस जी / एन / 13 / बी आर ए / 3) : जहां मूल शुल्क 2002 में लगाई गई थी तथा 2004 में आयोजित समीक्षा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए 2002 और 2003 की अवधि के डेटा का विश्लेषण किया गया। प्राधिकारी ने टिप्पणी की कि मात्रा में गिरावट तथा आयात की एफओबी कीमतों में उत्थान पाया गया। इसके बावजूद वर्ष 2002 एवं 2003 के लिए आयात की मात्रा, जो क्रमशः 4782.6 टन तथा 4519.9 टन थी, रक्षोपाय के पहले तीन वर्षों के लिए निर्धारित कोटा अर्थात क्रमशः 3957 टन, 4154 टन और 4353.7 टन से अधिक थी। इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस क्षेत्र के पूर्ण समुत्थान को सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अभी भी आवश्यक है।

(घ) क्राउन कॉर्क्स (जी / एस जी / एन / 13 / बी जी आर / 1), जहां मूल शुल्क 2002 में लगाई गई थी तथा 2004 में आयोजित समीक्षा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए 2002, 2003 और 2004 की अवधि के डेटा का विश्लेषण किया गया। यहां घरेलू उद्योग का विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस क्षेत्र के समुत्थान का सुनिश्चय करने के लिए रक्षोपाय अभी भी आवश्यक है क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भले ही रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद आयात पर पूरी तरह से रोक लग गई हो तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ हो, रक्षोपाय शुल्क को समाप्त करने या इसे और आगे न बढ़ाने के लिए यह अपर्याप्त औचित्य है। इस स्तर पर जो प्रासंगिक है वह यह है कि क्या रक्षोपाय शुल्क को निरंतर लगाना गंभीर नुकसान को रोकने या इसके निदान के लिए आवश्यक है। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य गंभीर नुकसान का निदान करना था, ताकि घरेलू उद्योग आयात में वृद्धि से उत्पन्न पिछले नुकसान से उबर सके। दूसरे शब्दों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में समुत्थान पहले से परिकल्पित है तथा इसकी संभावना है और यह वास्तव में रक्षोपाय शुल्क लगाने का मकसद भी है। इस तरह का प्रकरण होने के नाते, यह तथ्य कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है, रक्षोपाय शुल्क के अस्तित्व में न होने का कोई कारक नहीं हो सकता है। इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क लगाने की जरूरत है ताकि घरेलू उद्योग अपने निष्पादन में सुधार ला सके।

(iii) डंपिंग कानून से उत्पन्न होने वाली विवेकशीलता – इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एंटी डंपिंग के मामले में बहुत अधिक संख्या में अवसान / समापक समीक्षाओं का संचालन किया गया है, इस बात को समझना प्रासंगिक एवं उपयोगी होगा कि कैसे एंटी डंपिंग पर नामोद्विष्ट प्राधिकारी समापक समीक्षा के समय घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करते हैं और कैसे प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या एंटी डंपिंग शुल्क का आगे विस्तार किया जाना चाहिए। तथापि सबके प्रति निष्पक्ष होने के लिए, एंटी डंपिंग तथा उभरती विवेकशीलता पर प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारणों का हवाला देने से पूर्व स्वयं कानून पर विचार करना आवश्यक है।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (5) में इस प्रकार प्रावधान है :

इस धारा के अंतर्गत लगाई गई एंटी डंपिंग शुल्क, जब तक पहले निरस्त नहीं की जाती है, इस तरह लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष के बीत जाने के बाद प्रभावी नहीं रहेगी, परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसी शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग एवं नुकसान के जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है तो वह समय समय पर पांच वर्ष की अगली अवधि के लिए यह शुल्क लगाने की अवधि बढ़ा सकती है तथा ऐसी अगली अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी;

परंतु यह भी कि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व शुरू की गई समीक्षा ऐसी अवधि के समाप्त होने से पूर्व अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है तो एंटी डंपिंग शुल्क अधिक से अधिक एक वर्ष की अगली अवधि के लिए ऐसी समीक्षा के परिणाम के लंबित रहने तक प्रभाव में बनी रह सकती है।

डंपिंग नियमावली के नियम 23 में इस प्रकार प्रावधान है :

(iv) समीक्षा : (1) अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान के अंतर्गत लगाई गई कोई एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग जिससे नुकसान हो रहा है, का प्रतिकार करने के लिए तब तक तथा जिस सीमा तक आवश्यक है तब तक प्रभाव में बनी रहेगी।

(1क) नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या किसी इच्छुक पक्षकार जो इस तरह की समीक्षा के लिए आवश्यकता को साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर आवश्यक होने पर किसी एंटी डंपिंग शुल्क को निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा तथा इस तरह की समीक्षा निश्चायक एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के बाद एक तर्कसंगत अवधि के बीत जाने के बाद की जाएगी तथा ऐसी समीक्षा पर नामोद्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से इसकी वापसी के लिए सिफारिश करेगा, जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त एंटी डंपिंग शुल्क हटा ली जाती है या उसमें भिन्नता लाई जाती है और इसलिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है।

(1ख) उप नियम 1 या 1क में निहित किसी भी बात के बावजूद अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई कोई निश्चायक एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाने की तारीख से अधिक से अधिक पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से या उसके द्वारा विधिवत रूप से स्थापित अनुरोध पर इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व शुरू की गई समीक्षा पर उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी तर्कसंगत अवधि के अंदर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उक्त एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग तथा घरेलू उद्योग को नुकसान के जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना है।

(2) उप नियम 1 के अंतर्गत शुरू की गई किसी समीक्षा को ऐसी समीक्षा शुरू करने की तारीख से अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के अंदर अंजाम पर पहुंचाया जाएगा।

(3) नियम 6, 7, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ समीक्षा के मामले में लागू होंगे। देखा जा सकता है कि यद्यपि एंटी डंपिंग कानून के तहत समापक समीक्षा के समय डंपिंग एवं नुकसान के जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना का निर्धारण करने की जरूरत होती है, रक्षोपाय नियमावली के तहत ऐसे निर्धारण की जरूरत होती है कि क्या रक्षोपाय शुल्क को निरंतर लगाने की आवश्यकता गंभीर नुकसान को रोकने या निदान करने के लिए है।

समापक समीक्षा के समय नामोद्दिष्ट प्राधिकारी किस पर विचार करता है – एंटी डंपिंग, विवेकशीलता पर निर्णयों / निर्धारणों की भारी संख्या से जो स्पष्ट रूप से निम्नानुसार उभरता है :

(क) क्या डंपिंग जारी है; और यदि हां तो क्या डंपिंग के जारी रहने की संभावना है;

(ख) क्या घरेलू उद्योग को नुकसान जारी है; और यदि हां तो क्या नुकसान के जारी रहने की संभावना है;

(ग) यदि डंपिंग जारी नहीं है तो क्या शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में डंपिंग के पुनः घटित होने की संभावना है; और

(घ) यदि नुकसान जारी नहीं है तो क्या शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान पुनः घटित होने की संभावना है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि डंपिंग या नुकसान का अस्तित्व में होना एंटी डंपिंग शुल्क के विस्तार के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं है। नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच अवश्य करनी चाहिए कि क्या एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में डंपिंग एवं नुकसान की संभावना है।

उपर्युक्त विवेकशीलता के आलोक में प्रार्थी का यह निवेदन है कि इस स्तर पर महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित का निर्धारण करने की जरूरत है :

(क) क्या उत्पाद का आयात, आयात में वृद्धि का कारण बना हुआ है – महानिदेशक को सबसे पहले उत्पाद के आयात पर विचार करना होता है और इस बात का निर्धारण करना होता है कि क्या उत्पाद का आयात उस सीमा तक जारी है कि इसकी वजह से आयात में वृद्धि हो रही है। प्रार्थी का यह कहना है कि इस तरह का निर्धारण बिल्कुल हाल की अवधि में आयात पर विचार करके तथा मूल अन्वेषण की उद्घाल पूर्व अवधि के साथ उसकी तुलना करके ही किया जा सकता है। कल्पना की किसी भी उद्घाल के माध्यम से सबसे हाल की अवधि में आयात की तुलना पहले स्थापित आयात में उद्घाल की अवधि तथा आयात में वृद्धि के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। यदि यह आवश्यकता एवं समझ होती तो डब्ल्यू टी ओ के सदस्य ऐसे समय में रक्षोपाय शुल्क का विस्तार नहीं करते जब आयात घट गया था या रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद बिल्कुल बंद हो गया था।

(ख) जहां तक गंभीर नुकसान का संबंध है, महानिदेशक से यह स्थापित करने की जरूरत होती है कि क्या घरेलू उद्योग को निरंतर गंभीर नुकसान हो रहा है या गंभीर नुकसान का खतरा बना हुआ है अर्थात् घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान की संभावना है अर्थात् क्या रक्षोपाय शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में आयात से गंभीर नुकसान होगा या होने का खतरा उत्पन्न होगा।

(vii) ए टी एम ए द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर :

(1) शुल्क संरक्षण के 8 साल के बावजूद घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। यह घरेलू बाजार में मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर से साबित होता है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करता है जिससे घरेलू उद्योग के लिए विकल्प और भी घट जाते हैं।

याचिका, लिखित प्रस्तुतियां तथा महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी पिछले निष्कर्ष उन पर निर्भर हैं जो स्पष्ट रूप से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित हैं। देश में इस उत्पाद के लिए मांग एवं आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग अपनी पसंद / तरजीह के आधार पर अपने उत्पाद का निर्यात नहीं करता है। निर्यात बाध्यता से जुड़े मामले हैं जैसा कि कम कीमत पर किए जा रहे निर्यात से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। मूल्य को ध्यान में रखकर न कि देश में उत्पाद की उपलब्धता न होने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा आयात किया गया है। विस्तार से लिखित प्रस्तुतियों का हवाला दिया गया है तथा उन पर भरोसा किया गया है।

(2) आयात में वृद्धि को मांग में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता के स्थिर बने रहने के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। दाहेज में नए संयंत्र का अधिष्ठापन केवल 4 ए डी पी ए के उत्पादन के लिए है।

लिखित प्रस्तुतियों का हवाला दिया गया है तथा उन पर भरोसा किया गया है। आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि की वजह से उचित नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन प्राप्त करना चाहिए था तथा उसकी क्षमता का उपयोग अधिकतम होना चाहिए था, यदि देश में मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर के कारण आयात किया जा रहा है। दाहेज में नया संयंत्र स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए है, इस बात को देखते हुए कि 4 ए डी पी ए पी एक्स 13 के उत्पादन में एक मामूली इंटरमीडिएट है तथा पी एक्स 13 के उत्पादन के अलावा इसका कोई और प्रयोग नहीं है।

(3) भारत में पी एक्स 13 के लिए कुल संस्थापित क्षमता 13,799 मीट्रिक टन (बाजार शेयर से परिगणित) है, जबकि कुल मांग 18315 मीट्रिक टन है।

उपयुक्त गणनाएं दोषपूर्ण हैं। क्षमता की गणना बाजार में हिस्सेदारी से नहीं की जा सकती है। बाजार में हिस्सेदारी का निर्धारण बिक्री से होता है, जबकि क्षमता का निर्धारण माल का उत्पादन करने कि किसी कंपनी की सामर्थ्य के आधार पर किया जाता है। अन्वेषण की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की संस्थापित क्षमता 20500 मीट्रिक टन थी जो देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, भारत सरकार की शुल्क छूट स्कीम को देखते हुए हर हाल में देश में कुछ न कुछ आयात करना ही पड़ता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध निवल मांग किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित खपत के आंकड़ों से कम है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि लिखित प्रस्तुतियों में बताया गया है, देश में मांग की तुलना घरेलू उद्योग की क्षमता से नहीं की जा सकती है। देश में उत्पाद के लिए मांग की तुलना कुल मिलाकर घरेलू उत्पादकों की संस्थापित क्षमता के साथ करने की जरूरत होती है।

(4) यदि शुल्क के समाप्त होने के पूर्व महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अंतिम निष्कर्ष के रूप में सिफारिश की जाती है तो नियम 18 के अंतर्गत अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है। सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत सोडा ऐश सहित पिछले सभी मामलों में ऐसा किया गया है। निम्नलिखित संगत हैं:

यहां नीचे नियम 18 को उद्धृत किया जा रहा है:

18. समीक्षा

क. महानिदेशक समय समय पर रक्षोपाय शुल्क को निरंतर लगाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे तथा यदि वह प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट होते हैं कि

- (i) गंभीर नुकसान को रोकने या उसका निदान करने के लिए रक्षोपाय शुल्क आवश्यक है तथा इस बात के प्रमाण हैं कि उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है तो वह रक्षोपाय शुल्क निरंतर लगाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं;
- (ii) ऐसी शुल्क को निरंतर लगाने का कोई औचित्य नहीं है तो वह इसे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं, परंतु यह कि जहां रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि तीन साल से अधिक हो तो महानिदेशक ऐसी अवधि के अधिक से अधिक मध्य में स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि उपयुक्त होगा तो ऐसी रक्षोपाय शुल्क को वापस लेने या शुल्क के उदारीकरण में वृद्धि करने की सिफारिश करेंगे।

ख. उप नियम 1 के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा को ऐसी समीक्षा शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक आठ माह की अवधि के अंदर या ऐसी विस्तारित अवधि जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत हो सकती है, के अंदर अंजाम पर पहुंचाया जाएगा।

ग. नियम 5, 6, 7 और 11 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ समीक्षा के मामले में लागू होंगे।

(क) इसके अलावा रक्षोपाय शुल्क का विस्तार धारा 8ख (4) द्वारा अभिशासित होता है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है।

(ख) धारा 8ख (4): इस धारा के अंतर्गत लगाई गई शुल्क, जब तक पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रभावी नहीं रह जाएगी:

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसे नुकसान या उसके खतरे को समायोजित करने के लिए कदम उठाए हैं तथा यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क निरंतर लगनी चाहिए तो वह ऐसी शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है:

परंतु यह भी कि किसी भी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क ऐसी तारीख जब पहली बार ऐसी शुल्क लगाई गई, से 10 साल की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगी।

(ग) देखा जा सकता है कि यह तथ्य पूरी तरह से नगण्य है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने रक्षोपाय शुल्क के समाप्त होने से पूर्व या इसके पश्चात सिफारिश की है। जो संगत है वह केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना है। इसके अलावा जैसा कि लिखित प्रस्तुति में बताया गया है, प्रार्थी ने एंटी डंपिंग के संदर्भ में अनेक प्रकरणों का हवाला दिया है जहां शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसकी अवधि बढ़ाई गई है।

(5) एसजी नियमावली के नियम 18 में जानबूझकर 'जारी' शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि 'विस्तार' शब्द का प्रयोग किया गया है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (5) में पैराग्राफ 2 में विस्तार शब्द स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि शुल्क आरंभ होने की अवधि ऐसी शुल्क को आरंभ करने के आदेश की तारीख से होगी। इसलिए स्वयं ए डी अधिनियम प्रावधान करता है कि पिछली

ए डी शुल्क तथा समापक समीक्षा अन्वेषण के अनुसरण में पांच साल की और अवधि के लिए बढ़ाई जा रही ए डी शुल्क के बीच अंतर हो सकता है। तथापि यदि केन्द्र सरकार समापक समीक्षा अन्वेषण के लंबित रहने पर ए डी शुल्क को जारी रखने का इरादा रखती है तो यह किसी अंतर के बिना होना चाहिए, ए डी शुल्क के समाप्त होने से पूर्व समापक समीक्षा अन्वेषण शुरू किया गया है।

इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक हैं :

क. अकेले नियम 18 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान नहीं है। वास्तव में नियम 18 केवल समीक्षा की कार्यविधि तथा मध्यावधि / अंतरिम समीक्षा से संबंधित है। नियम 16 समीक्षा की समाप्ति या शुल्क की अवधि से संबंधित है।

इसके अलावा धारा 8ख (4) शुल्क के विस्तार से संबंधित है। संगत नियमों को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

धारा 8ख (4) : इस धारा के अंतर्गत लगाई गई शुल्क, जब तक पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से चार साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगी :

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसे नुकसान या उसके खतरे को समायोजित करने के लिए कदम उठाया है और यह आवश्यक है कि एस जी शुल्क लगती रहनी चाहिए, वह इस शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है:

परंतु यह भी कि किसी भी स्थिति में एस जी शुल्क को पहली बार लगाए जाने की तारीख से 10 साल की अधिक अवधि के बाद लगाना जारी नहीं रखा जाएगा।

16. अवधि :

नियम 12 के अंतर्गत लगाई गई शुल्क केवल ऐसी अवधि के लिए होगी जो गंभीर नुकसान को रोकने या निदान के लिए तथा सकारात्मक समायोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

इस नियम के उप नियम 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद नियम 12 के अंतर्गत लगाई गई शुल्क, जब तक पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से चार साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगी:

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसे नुकसान या उसके खतरे को समायोजित करने के लिए कदम उठाया है और यह आवश्यक है कि एस जी शुल्क लगती रहनी चाहिए, वह इस शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है;

परंतु यह भी कि किसी भी स्थिति में एस जी शुल्क को पहली बार लगाए जाने की तारीख से 10 साल की अधिक अवधि के बाद लगाना जारी नहीं रखा जाएगा।

देखा जा सकता है कि वर्तमान प्रकरण में नियम 16 प्रासंगिक है, क्योंकि यह विद्यमान शुल्क की अवधि समाप्त होने पर शुल्क के विस्तार से संबंधित है। नियम 16 एवं नियम 18 दोनों पर धारा 8ख (4) के साथ विचार करने की जरूरत है। वास्तव में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने आरंभ करने की नोटिस में नियमावली के नियम 16 एवं 18 के साथ धारा 8ख (4) का स्पष्ट रूप से हवाला दिया है। इसके अलावा नियम 18 केवल मध्यावधि या समापन समीक्षा के संचालन में अपनायी जाने वाली कार्यविधि के संबंध में प्रासंगिक है।

नियम 16 में स्पष्ट रूप से शुल्क का विस्तार करने का उल्लेख है न कि शुल्क को जारी रखने का उल्लेख है। विद्यमान शुल्क की समीक्षा का प्रश्न तब उठता है जब कोई शुल्क प्रभावी हो तथा महानिदेशक यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा का आयोजन करें कि क्या शुल्क जारी रहनी चाहिए या वापस ले लेनी चाहिए। विस्तार का प्रश्न तब उठता है जब शुल्क अपनी अवधि पूरा कर रही होती है तथा उसके आगे विस्तार का प्रश्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से नियम 18 में जारी शब्द पूरी तरह से वर्तमान परिस्थितियों में नगण्य है। इस स्तर पर नियम 16 में उल्लिखित विस्तार शब्द एक प्रासंगिक कानूनी प्रावधान है।

इन सब बातों के अलावा शुल्क का विस्तार धारा 8ग (4) द्वारा अभिशासित होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से विस्तार शब्द का उल्लेख है, न कि जारी शब्द का उल्लेख है।

घ. इसके अलावा वर्तमान परिस्थिति में चाहे जारी शब्द पर विचार किया जाए या विस्तार शब्द पर विचार किया जाए, दोनों शब्दों पर "विश्राम के बगैर या विश्राम के साथ सततता" के संदर्भ में विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार भले ही सततता शब्द पर विचार किया जाए, ऐसी सततता विश्राम / व्यवधान के साथ या बगैर हो सकती है। केवल यह तथ्य कि शुल्क पहले ही समाप्ति पर पहुंच गई है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह आगे जारी नहीं रह सकती है।

ड. एंटी डंपिंग नियमावली में दो प्रकार की समीक्षा का भी उल्लेख है – (क) यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा कि क्या शुल्क जारी रहनी चाहिए अथवा शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए, और (ख) शुल्क के आगे विस्तार पर विचार करने के लिए समीक्षा। यहां नीचे दोनों कानूनी प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया है :

धारा 9क (5) : इस धारा के अंतर्गत लगाई गई एंटी डंपिंग शुल्क, जब तक पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगी:

परंतु यह कि यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसी शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग एवं नुकसान के जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना है तो वह समय समय पर पांच साल की अगली अवधि के लिए ऐसी शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है तथा ऐसी अगली अवधि लगाए जाने के आदेश की तारीख से आरंभ होगी :

परंतु यह कि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू की गई समीक्षा ऐसी समाप्ति से पूर्व ऐसे अंजाम पर नहीं पहुंचती है तो एंटी डंपिंग शुल्क अधिक से अधिक एक वर्ष की अगली अवधि के लिए ऐसी समीक्षा के परिणाम के लंबित होने पर प्रभाव में बनी रह सकती है।

23 (1) अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के अंतर्गत लगाई गई एंटी डंपिंग शुल्क तब तक तथा आवश्यक सीमा तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि यह डंपिंग का प्रतिकार करती है, जिससे नुकसान हो रहा है।

(1क) नामोद्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक होगा वहां अपनी स्वयं की पहल पर या किसी इच्छुक पक्षकार जो इस तरह की समीक्षा की आवश्यकता को साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर तथा निश्चायक एंटी डंपिंग शुल्क के लगने के बाद से एक तर्क संगत अवधि के बीत जाने पर एंटी डंपिंग शुल्क को निरंतर लगाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे तथा इस तरह की

समीक्षा पर नामोद्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने के लिए सिफारिश करेंगे, जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त एंटी डंपिंग शुल्क को हटाया दिया जाता है या उसमें अंतर किया जाता है तथा इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

(1ख) उप नियम 1 या 1क में निहित किसी भी बात के बावजूद अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई कोई निश्चायक एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाने की तारीख से अधिक से अधिक पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से या उसके द्वारा विधिवत रूप से स्थापित अनुरोध पर इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व शुरू की गई समीक्षा पर उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी तर्कसंगत अवधि के अंदर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उक्त एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग तथा घरेलू उद्योग को नुकसान के जारी रहने या पुनः घटित होने की संभावना है।

(2) उप नियम 1 के अंतर्गत शुरू की गई किसी समीक्षा को ऐसी समीक्षा शुरू करने की तारीख से अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के अंदर अंजाम पर पहुंचाया जाएगा।

(3) नियम 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ समीक्षा के मामले में लागू होंगे।

च. इस प्रकार देखा जा सकता है कि एंटी डंपिंग के तहत दो प्रकार की समीक्षा का प्रावधान है - (क) शुल्क की अवधि के लिए समीक्षा, और (ख) शुल्क के अस्तित्व के लिए समीक्षा शुल्क के अवधि के लिए समीक्षा का परिणाम इसकी अवधि में विस्तार होगा, जब कि शुल्क के अस्तित्व के लिए समीक्षा का परिणाम शुल्क की सततता या समय से पूर्व उसकी वापसी होगा। नियम 23 (1क) के अंतर्गत शुल्क की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा होती है कि क्या इसकी अवधि लंबित होने के दौरान शुल्क प्रभाव में बनी रहनी चाहिए या कोई और औचित्य न मिलने पर समय से पहले शुल्क को वापस ले लेना चाहिए। इसे ठेठ रूप में मध्यावधि समीक्षा या एंटी डंपिंग के दायरे में परिवर्तित परिस्थितियों की समीक्षा कहा जाता है। रक्षोपाय कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि ऐसी शुल्क मूल रूप से तीन साल से अधिक अवधि के लिए लगाई गई हो तो मध्यावधि समीक्षा अनिवार्य है, जबकि एंटी डंपिंग कानून में आवश्यकता पर आधारित अंतरिम समीक्षा का प्रावधान है।

छ. धारा 9क (5) का दूसरा परंतुक भी घरेलू उद्योग की दलील का समर्थन करता है। यहां ऊपर नियम को पुनः प्रस्तुत किया गया है। देखा जा सकता है कि दूसरा परंतुक समीक्षा के परिणाम के लंबित होने पर अधिक से अधिक एक साल की अवधि के लिए शुल्क को जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। जहां "प्रभाव में बनी रह सकती है" शब्द का प्रयोग किया गया है। नामोद्दिष्ट प्राधिकारी तथा वित्त मंत्रालय द्वारा यह अर्थ निकालने के लिए इसकी बृहद पैमाने पर व्याख्या की गई है कि समाप्ति के बाद भी इस शुल्क का विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार यदि एक वर्ष की अवधि के लिए शुल्क के विस्तार के संबंध में नामोद्दिष्ट प्राधिकारी तथा वित्त मंत्रालय द्वारा आह्वित व्याख्या स्वीकार्य है तो इसका अभिप्राय यह है कि रक्षोपाय शुल्क विद्यमान शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी आगे जारी रह सकती है। वास्तव में इच्छुक पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि एंटी डंपिंग कानून विद्यमान शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की ऐसी सततता की अनुमति प्रदान करता है। चूंकि यह इस तरह का मामला है इसलिए इच्छुक पक्षकारों की दलीलों का बारीकी से अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि इसकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी शुल्क को जारी रखने के संबंध में सरकार का निर्णय उचित है।

ज. यद्यपि धारा 9क (5) के पहले परंतुक में विस्तार शब्द का प्रयोग किया गया है, इस धारा के दूसरे परंतुक में जारी शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों ही स्थितियों में वित्त मंत्रालय ने विद्यमान शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाई है। इस प्रकार वित्त मंत्रालय ने विस्तार और जारी शब्द के बीच कोई भेद एवं अंतर नहीं किया है।

6. जब एस जी शुल्क लगाने वाली सीमा शुल्क अधिसूचना कालातीत हो जाती है, तो न्यायिक आदेश के माध्यम से उसे बहाल नहीं किया जा सकता है (तिरुमूला केमिकल्स बनाम महानिदेशक (रक्षोपाय) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय)।

उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिस मुद्दे का निर्णय किया गया वह वर्तमान मुद्दे से पूरी तरह असंगत है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसे जारी रखने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के पास अधिकार है, जबकि वर्तमान प्रकरण में मुद्दा यह है कि क्या महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अन्वेषण एवं सिफारिश के आधार पर शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास अधिकार है। स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय उस अवधि के बाद रक्षोपाय शुल्क का विस्तार नहीं कर सकता जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा मूल रूप से शुल्क लगाई गई थी, क्योंकि शुल्क का विस्तार इस संबंध में कानूनी प्रावधानों का अनुसरण करने के बाद ही अनुमत है।

7. मूल प्रकरण की याचिका में घरेलू उद्योग ने इस बात का उल्लेख किया था कि पी एक्स 13 सहित रबड़ केमिकल तथा इंटरमीडिएट के विनिर्माण के लिए दाहेज संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। समीक्षा अन्वेषण में बताया गया है कि यह केवल चार ए डी पी ए का विनिर्माण करेगा। मूल अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों में इस बात का उल्लेख है कि दाहेज संयंत्र में उत्पादन अप्रैल 2012 में आरंभ हो जाएगा, जबकि उत्पादन वास्तव में मार्च, 2013 में आरंभ हुआ। घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप में समायोजन नहीं कर रहा है।

घरेलू उद्योग ने मूल अन्वेषण के समय नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को साक्ष्य उपलब्ध कराया था जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग 4 ए डी पी ए के उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगा रहा है तथा यह कि ऐसे 4 ए डी पी ए का प्रयोग पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पिछले अन्वेषण के रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से साबित होगा कि दाहेज में जो संयंत्र लगाया जा रहा है वह 4 ए डी पी ए के उत्पादन के लिए है, जिसका प्रयोग अनन्य रूप से पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए किया जाएगा। प्रार्थी ने उस दायित्व को पूरी तरह से पूरा किया है जिसका उसने पहले उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा किए गए दावे तथा पिछले अन्वेषण एवं वर्तमान अन्वेषण के बीच कोई अंतर नहीं है। वास्तव में मूल अन्वेषण के समय महानिदेशक (रक्षोपाय) को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान किए गए थे, जिनकी प्रतिलिपि तत्काल संदर्भ के लिए इन प्रस्तुतियों के साथ संलग्न है :

क. परियोजना रिपोर्ट की प्रतिलिपि

ख. सनदी इंजीनियर से प्रमाण पत्र

ग. परियोजना लागत का प्रमाण पत्र

इन दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रार्थी पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए संयंत्र लगा रहा था। इस प्रकार मूल अन्वेषण के समय महानिदेशक (रक्षोपाय) को अच्छी तरह से पता था कि प्रार्थी पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगा रहा है। महानिदेशक (रक्षोपाय) से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया इस संबंध में मूल प्रकरण के अभिलेख की जांच करें।

प्रार्थी ने अप्रैल 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन का लक्ष्य रखा था। वाणिज्यिक उत्पादन वास्तव में मार्च, 2013 में आरंभ हुआ है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने में विलंब हुआ, किसी भी स्थिति में इससे यह स्थापित नहीं होता है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं कर रहा है। सभी निवेश कुछ अनुमान पर आधारित हैं तथा यह जरूरी नहीं है कि सभी उपलब्धियां वैसी ही हों जैसा अनुमानित किया गया है। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए आरंभ किए जाने वाले असंख्य कदमों के संबंध में अनेक अनुमानों एवं धारणाओं के साथ सभी परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। इन कदमों से ज्यादातर कदम ऐसे होते हैं जो आमतौर पर उस कंपनी के नियंत्रण से परे होते हैं जो परियोजना को कार्यान्वित कर रही होती है। कुछ कार्य जो अन्य पक्षकारों द्वारा संपन्न किए जाने होते हैं, स्पष्ट रूप से परियोजना को कार्यान्वित करने वाली कंपनी के नियंत्रण से परे होते हैं। इस प्रकार भले ही सभी कारोबार उद्यम लक्ष्यों का पीछा करने के लिए हर संभव प्रयास करें, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लक्ष्यों को मूल रूप से परिकल्पना के अनुसार पूरा कर लिया जाए। तथापि जहां तक उपभोक्ताओं का संबंध है, इसकी वजह से इन उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने विद्यमान संयंत्र से उत्पाद का उत्पादन करना एवं बिक्री करना जारी रखा और वास्तव में प्रार्थी द्वारा प्राप्त अपर्याप्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान संयंत्र का भी बहुत ही कम उपयोग हो पाया। इस प्रकार जब प्रार्थी अपनी विद्यमान विनिर्माण सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करने की स्थिति में नहीं था तो नुकसान की वजह से प्रार्थी की व्यथा में वृद्धि ही होती यदि उसने अप्रैल, 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया होता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की क्षमताओं का लक्ष्य उत्पादन को ... मीट्रिक टन से बढ़ाकर ... मीट्रिक टन करने का था। इसके विपरीत अन्वेषण की अवधि के दौरान उत्पादन केवल ... मीट्रिक टन था, हालांकि प्रार्थी ने 2009 – 10 में ... मीट्रिक टन तक का उत्पादन किया था। यदि हम ... मीट्रिक टन की क्षमता के लक्ष्य को अलग छोड़ दें, तो भी प्रार्थी को विद्यमान उत्पादन क्षमता का उपयोग करने से रोका गया तथा वह इसे उस सीमा तक भी प्राप्त नहीं कर पाया जो उसने 2009 – 10 में आयात में उछाल के मद्देनजर प्राप्त किया था। इस प्रकार यह तथ्य कि नए संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने में विलंब हुआ है, किसी भी रूप में वर्तमान प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति का उल्लंघन नहीं है।

8. किसी भी समीक्षा में घरेलू उद्योग से सकारात्मक समायोजन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है, जो मूल अन्वेषण में प्रस्तावित योजना के अनुरूप होना चाहिए (फथैलिक एनहाइड्राइड की रक्षोपाय समीक्षा में डी जी एस)।

प्रार्थी ने कंपनी द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक समायोजनों के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किया है। निम्नलिखित संगत दस्तावेज हैं, जिन्हें प्रार्थी ने याचिका के साथ संलग्न किया है :

क. सी ए प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेज तथा तुलन पत्र से उद्धरण, जिनका उद्देश्य यह दर्शाना है कि कंपनी ने दाहेज संयंत्र पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी का निवेश किया है तथा कर्मचारी लागत, विपणन पूर्व खर्च, ट्रायल रन संबंधी लागत तथा अन्य खर्च सहित पर्याप्त प्रचालन पूर्व व्यय किया है।

ख. दाहेज संयंत्र के स्टेटस पर वार्षिक रिपोर्ट से संगत उद्धरण

ग. उत्पाद शुल्क से संबंधित अभिलेख, जिनका उद्देश्य यह दर्शाना है कि कंपनी ने दाहेज संयंत्र पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

घ. दाहेज संयंत्र पर प्रार्थी के उत्पादन की अभीष्ट लागत तथा ऐसी स्थिति में उसके द्वारा वहन की जाने वाली उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला विवरण जब प्रार्थी पुराने संयंत्र पर उत्पादन जारी रखता, जिसका उत्पादन यह दर्शाना है कि प्रार्थी दाहेज में उत्पादन शुरू करके पर्याप्त मात्रा में पहले ही लागत की बचत प्राप्त कर ली है।

यदि महानिदेशक कोई और दस्तावेजी साक्ष्य चाहते हैं, तो प्रार्थी उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

9. मूल अन्वेषण में डी जी एस ने पाया कि सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए दो साल की अवधि पर्याप्त है। घरेलू उद्योग शुल्क की अवधि बढ़ाने तथा शुल्क की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध कर रहा है। इसलिए घरेलू उद्योग को नियम 5 (2) के साथ पठित नियम 18 के अनुसार एक नई समायोजन योजना प्रदान करनी होगी। यह उसी समायोजन योजना के आधार पर चार साल के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है जिसके संबंध में डी जी एस ने राय व्यक्त की है कि उसके कार्यान्वयन के लिए केवल दो साल की अवधि की जरूरत है।

यह तथ्य कि महानिदेशक ने पहले दो साल की अवधि को पर्याप्त समझा था, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि महानिदेशक इस बात की समीक्षा नहीं कर सकते या उस पर विचार नहीं कर सकते कि क्या शुल्क की अवधि में वृद्धि करना आवश्यक है। भले ही महानिदेशक ने मूल रूप में विचार किया था कि शुल्क 4 या 6 साल के लिए आवश्यक है, महानिदेशक को हमेशा केवल अल्प अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश करने की स्थिति में होना चाहिए और इसके पश्चात उसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर उनको विचार करना चाहिए। वास्तव में महानिदेशक ने अल्प अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश करके उपभोक्ताओं एवं निर्यातकों के हित में दकियानूसी रवैया अपनाया है; और इसलिए अब यह घरेलू उद्योग को और संरक्षण से इंकार करने का आधार नहीं बन सकता है। वास्तव में इस बात पर विचार करते समय कि क्या सेफगार्ड शुल्क 10 साल के लिए प्रभावी हो सकती है, नियम निर्दिष्ट करता है कि शुल्क केवल चार साल के लिए प्रस्तावित की जानी चाहिए और इसके पश्चात इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, यदि आवश्यक समझा जाए। इससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि पहली बार पूरी अवधि, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, के लिए शुल्क लगाने की जरूरत नहीं होती है।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में प्रयोक्ता उद्योग को अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ेगा, आयात में कोई हालिया, अचानक, भारी या महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण पिछले चार वर्षों में आयात में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। वास्तव में आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

यह कोई मुद्दा नहीं है कि भारत में प्रयोक्ता उद्योग को अपनी मांग पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है। इसके विपरीत कम कीमत पर आयात के उपलब्ध होने के कारण आयात किया गया है। यह स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के माध्यम से स्थापित होता है— (1) घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं क्षमता के उपयोग में गिरावट, (2) घरेलू बाजार में मिलने वाली कीमत की तुलना में अपने निर्यात से घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त होने वाली कम कीमत (3) घरेलू उद्योग के आयात मूल्य एवं बिक्री मूल्य की तुलना, (4) विद्यमान रक्षोपाय शुल्क के बावजूद आयात में वृद्धि। रक्षोपाय शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप आयात में गिरावट की रजान, और न कि वृद्धि की रजान प्रदर्शित होनी चाहिए थी।

11. घरेलू उद्योग ने बताया है कि मुख्य रूप से चीन, कोरिया और यूरोपीय संघ से आयात प्रवेश कर रहा है, जिस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाई गई है। आयात में वृद्धि द्वारा नुकसान से डंपिंग द्वारा नुकसान को अलग करने की जरूरत है।

रक्षोपाय शुल्क एवं एंटी डंपिंग शुल्क को एक साथ लगाने से निपटने के दो तरीके हैं— (क) नुकसान की कुल मात्रा का निर्धारण करना और इसके पश्चात् एंटी डंपिंग शुल्क की विद्यमान मात्रा को कम करना, वर्तमान में इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है; और (ख) आयात की कीमत में एंटी डंपिंग शुल्क को जोड़ने के पश्चात् नुकसान के अंतर का निर्धारण करना। प्रार्थी ने इस वैकल्पिक आधार पर तथा इन प्रस्तुतियों के साथ संलग्न आधार पर अपनी गणनाएं की हैं। देखा जा सकता है कि नुकसान का अंतर अभी भी महत्वपूर्ण है। तथापि यदि इस वैकल्पिक कार्यविधि का अनुसरण किया जाता है तो इस प्रकार निर्धारित नुकसान का अंतर रक्षोपाय शुल्क बनेगी तथा उसे एंटी डंपिंग शुल्क के लिए समायोजित किए बगैर सभी आयात पर उसको लागू करना होगा। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह होगा कि उन स्रोतों से भी आयात पर रक्षोपाय शुल्क प्रभारित की जाए जहां घरेलू उद्योग को डंपिंग शुल्क द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उन स्रोतों पर रक्षोपाय शुल्क प्रभारित न की जाए जहां घरेलू उद्योग डंपिंग शुल्क द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। इस प्रकार की विधि सभी पक्षकारों— घरेलू उद्योग, उपभोक्ताओं एवं विदेशी उत्पादकों के लिए अनुचित होगी। इसका अभिप्राय यह होगा कि कुछ स्रोतों जैसे कि चीन से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाई जाए तथा कोरिया से आयात पर घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए।

12. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार निर्यात बाजार में मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है जिससे उत्पादन एवं निर्यात बिक्री प्रभावित हुई है।

ए टी एम ए ने एक ओर दावा किया है कि देश में इस उत्पाद के लिए मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर है तथा साथ ही उसने निर्यात बाजार में मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट का उल्लेख किया है। प्रार्थी यह समझने में असमर्थ है कि क्यों ऐसी स्थिति में उत्पाद एवं क्षमता के उपयोग में गिरावट के रूप में उसे नुकसान होने चाहिए जहां देश में उत्पाद की मांग में वृद्धि हो रही है और जहां उपभोक्ता लगातार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि देश में मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर है। देश में उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग को देखते हुए किसी भी स्थिति में निर्यात बाजार में मांग में इन गिरावटों से घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं होना चाहिए था, यदि उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग को ऑर्डर दिए। किसी भी स्थिति में प्रार्थी ने निर्यात के संबंध में अपने निष्पादन को अलग किया है तथा जिस नुकसान का दावा किया गया है वह केवल घरेलू बाजार के कारण है।

13. जनहित की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है (मिथाइल एसिटोसिटेट में डी जी एस)।

वर्तमान मामला समीक्षा का मामला है तथा मूल अन्वेषण में जनहित की आवश्यकता की पहले ही पूर्ति हो गई है। ए टी एम ए तथा अन्य पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे सूचना एवं साक्ष्य उपलब्ध कराएं जिससे साबित हो कि महानिदेशक (रक्षोपाय) का पिछला निर्धारण अनुचित था। महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा किए गए पिछले निर्धारण की असत्यता स्थापित करने के लिए इन इच्छुक पक्षकारों द्वारा कोई सूचना / साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इस तरह का मामला होने के कारण महानिदेशक (रक्षोपाय) के पिछले निर्धारण में अपनी राय को जारी रखने का निर्णय लिया तथा महानिदेशक (रक्षोपाय) को इस मुद्दे की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद प्रार्थी ने अपनी प्रस्तुतियों में स्थापित किया है कि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार जनहित में जारी रहेगा। विचाराधीन उत्पाद कंजूर उद्योग के उत्पादन की लागत का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षोपाय शुल्क की प्रस्तावित मात्रा का उपभोक्ताओं पर काफी प्रभाव होगा। साथ ही रक्षोपाय शुल्क के विस्तार से घरेलू उद्योग के निरंतर अस्तित्व का सुनिश्चय होगा तथा इसकी वजह से घरेलू उद्योग स्वयं को सकारात्मक रूप से समायोजित करने में समर्थ होगा।

(vii) यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर

1. किसी निष्प्रभावी एंटी डंपिंग उपाय के अतिरिक्त रक्षोपाय नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि एंटी डंपिंग से संबंधित उपाय उल्लंघन या समामेलन के कारण निष्प्रभावी हैं तो इनकी समीक्षा होनी चाहिए।

विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों का हवाला दिया गया है तथा उन पर भरोसा किया गया है, जो पर्याप्त रूप से इस मुद्दे का निदान करती हैं। जैसा कि कोरिया की कंपनी कुम्हो के वकील द्वारा स्वीकार किया गया है, जारी शब्द का अभिप्राय किसी गतिविधि या प्रक्रिया में बने रहना है; अस्तित्व या प्रचालन में बने रहना है; किसी विनिर्दिष्ट स्थिति या अवस्था में बने रहना है; व्यवधान के पश्चात् पुनः आरंभ करना या बहाल करना है। रक्षोपाय शुल्क (या एंटी डंपिंग शुल्क) के विस्तार के संदर्भ में विस्तार के अर्थ को व्यवधान के पश्चात् बहाली या पुनः प्रारंभ होने के रूप में देखने की जरूरत है।

2. भारतीय उद्योग चीन, कोरिया एवं यूरोपीय संघ से आयात पर ए डी डी के माध्यम से पहले से ही संरक्षित है।

घरेलू उद्योग में रक्षोपाय शुल्क के विस्तार की मांग इसलिए की है कि विद्यमान एंटी डंपिंग शुल्क से घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हुई है। यह एक सुस्थापित कानूनी दृष्टिकोण है कि एंटी डंपिंग कानून के तहत संरक्षण डंपिंग मार्जिन से अधिक नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार यदि घरेलू उद्योग को नुकसान डंपिंग मार्जिन और परिणामतः एंटी डंपिंग शुल्क मात्रा से अधिक हो तो निदान न किए गए नुकसान का निदान केवल रक्षोपाय शुल्क लगाकर किया जा सकता है। इस उत्पाद पर तथा कार्बन ब्लैक एवं कास्टिक सोडा जैसे अन्य उत्पादों पर पूर्व में रक्षोपाय शुल्क लगाकर इसे स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। किसी भी स्थिति में, जिस रूप में भारत में एंटी

डंपिंग शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क लागू की गई है, बिल्कुल स्पष्ट है कि नुकसान के अंतर से अधिक घरेलू उद्योग को संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है।

3. समीक्षा के अंतर्गत उपायों की अवधि 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है तथा जहां तक रक्षोपाय शुल्क लगाने का संबंध है, एक नए अन्वेषण के बाद किसी नए उपाय की जरूरत है। तथापि सुरक्षोपायों पर करार के अनुच्छेद 9.2 के अनुसार, यह केवल उपाय की अवधि समाप्त होने के दो साल बाद घटित हो सकता है।

वर्तमान याचिका रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए है। केवल यह तथ्य कि रक्षोपाय शुल्क की अवधि 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसके बाद इसकी अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए है। यह नए सिरे से रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7.5 या 9.2 के अंतर्गत निर्धारित क्लिंग पीरियड की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं जहां एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाई जा रही है। केवल यह तथ्य कि एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि विश्राम / व्यवधान के बाद बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह कोई नई लेवी बन जाती है।

4. जब से उपाय लागू किए गए हैं, घरेलू उद्योग की बिक्री में न केवल मामूली तौर पर वृद्धि हुई है अपितु बाजार में उसकी हिस्सेदारी भी स्थिर है। तथापि शिकायत न करने वाले भारतीय उत्पादक की बाजार हिस्सेदारी दोगुना होने के कारण इस उपाय से उनको लाभ हुआ है।

जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल मामूली तौर पर वृद्धि हुई है तथा बाजार हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है। यदि तथ्यों को देखें तो वास्तव में घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी घटी है। इसके अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री एवं बाजार में हिस्सेदारी एक तरफ घरेलू उद्योग की पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता और दूसरी तरफ उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग को देखते हुए रक्षोपाय शुल्क लगने के साथ काफी बढ़नी चाहिए थी। पिछले स्तरों से आगे अपने उत्पादन में सुधार लाने संबंधी घरेलू उद्योग की असमर्थता तथा इसकी बजाय रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को उत्पन्न नुकसान में वृद्धि को स्थापित करता है।

जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार में हिस्सेदारी में वृद्धि का संबंध है, जैसा कि लिखित प्रस्तुतियों में स्थापित किया गया है, वास्तव में अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार में हिस्सेदारी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। लैनसेक्स द्वारा बिक्री का केवल रिएलाइनमेंट किया गया है। जबकि कंपनी ने पहले उत्पाद का आयात करके उत्पाद की बिक्री की थी, कंपनी ने पहले उत्पाद को बेचा और फिर बाद में भारत में उत्पादन किया। नीचे दी गई सारणी इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस प्रकार घरेलू बाजार से आयात एवं आपूर्ति के बीच लैनसेक्स द्वारा बिक्री की स्विचिंग को घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री में वृद्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

मांग में बाजार हिस्सेदारी	यूनिट	2009 – 10	2010-11	2011 – 12	2012 – 13
चीन	प्रतिशत	12.45	11.51	21.09	12.97
कोरिया	प्रतिशत	41.00	32.99	28.23	34.12
यूरोपीय संघ	प्रतिशत	3.92	6.14	5.11	16.61
अन्य देश	प्रतिशत	3.01	10.68	5.47	2.01
लैनसेक्स द्वारा आयात	प्रतिशत	8.23	5.19	1.13	-
एन ओ सी आई एल	प्रतिशत	*	*	*	*
लैनसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्रतिशत	-	*	*	*
पी एम सी रबड़ केम	प्रतिशत	*	*	*	*
भारतीय उद्योग	प्रतिशत	*	*	*	*
कुल	प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00

टिप्पणी : आयात के माध्यम से लैनसेक्स द्वारा की गई आपूर्तियों को घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति के रूप में माना गया है।

इस बात का उल्लेख करना भी संगत है कि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री इस तथ्य को देखते हुए सारवान रूप में बढ़नी चाहिए थी कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए मार्च में महत्वपूर्ण सुविधाएं स्थापित की हैं।

5. करार के अनुच्छेद 7.4 में इस बात का उल्लेख है कि कोई उपाय यदि उसकी अवधि बढ़ाई जाती है, उससे अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं हो सकता है जितना वह मूल अवधि के अंत में था। इसलिए अनिवार्य रूप से बढ़े हुए स्तर पर किसी निष्प्रभावी उपाय की अवधि बढ़ाने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा सुरक्षोपाय शुल्क की मात्रा में वृद्धि से संबंधित अनुरोध वर्तमान अवधि में नुकसान के अंतर पर आधारित है।

(viii). मैसर्स कुम्हो पेट्रो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया तथा रिषीरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर

1. 29 अगस्त, 2013 (आरंभ होने की तारीख) को आरंभ करने की अधिसूचना प्रकाशित करने में प्राधिकारी की विफलता से कोरिया के व्यापारियों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा है तथा इससे जी ए टी टी अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कोरिया सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

निम्नलिखित प्रासंगिक हैं :

क. इस संबंध में अनेक तारीखें प्रासंगिक हैं जो भिन्न हैं। इन तारीखों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

- (i) तारीखें जिन पर महानिदेशक द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया अर्थात् तारीख जिसको महानिदेशक ने अन्वेषण आरंभ करने के लिए अधिसूचना दाखिल करने का निर्णय लिया;
- (ii) तारीख जिसको महानिदेशक द्वारा अन्वेषण शुरू करने के लिए सार्वजनिक नोटिस पर हस्ताक्षर किया गया;
- (iii) तारीख जिस दिन अन्वेषण आरंभ करने की सार्वजनिक नोटिस प्रकाशन के लिए भारत सरकार के मुद्रणालय को भेजी गई;
- (iv) तारीख जिस दिन प्रकाशन के लिए भारत सरकार द्वारा अन्वेषण आरंभ करने की सूचना प्राप्त की गई;
- (v) तारीख जिस दिन भारत सरकार के मुद्रणालय ने रजिस्ट्री में कार्य प्राप्त किया;
- (vi) तारीख जिस दिन भारत सरकार के मुद्रणालय द्वारा अधिसूचना छपाई गई;
- (vii) तारीख जिस दिन भारत सरकार के मुद्रणालय ने आम जनता में परिचालन के लिए अधिसूचना भेजी।

वास्तव में भारत सरकार के मुद्रणालय के अंदर और भी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। अन्वेषण आरंभ करने की वास्तविक तिथि वह तारीख होती है जिसको महानिदेशक द्वारा अन्वेषण आरंभ करने की सूचना पर हस्ताक्षर किया जाता है तथा मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए उसे भारत सरकार के मुद्रणालय को भेजा जाता है। जिस तारीख को अधिसूचना छपती है या जिस तारीख को प्रकाशन के लिए अधिसूचना परिचालित की जाती है वह पूरी तरह से महत्वहीन होती है।

ख. प्रार्थी ने भारत संघ बनाम गणेश दास भोजराज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है :

तथ्य : प्रतिवादी ने स्वीकृत तौर पर बीजक संख्या 14/099, दिनांक 31 दिसंबर, 1986 के माध्यम से 505 – 505 मीट्रिक टन वजन के ग्रीन विंग्स (दाल) के एक कंसाइनमेंट का आयात किया। उन्होंने 5 फरवरी, 1987 को इसके लिए प्रविष्टि बिल दाखिल किया है। आयातक ने छूट अधिसूचना संख्या 129 / 76 – सीमा शुल्क, दिनांक 2 अगस्त, 1976 के आधार पर उक्त माल के लिए शुल्क फ्री निकासी का दावा किया तथापि इस बात का उल्लेख किया गया कि 4 फरवरी, 1987 को अधिसूचना संख्या 40/87 – सीमाशुल्क के माध्यम से उक्त अधिसूचना को संशोधित किया गया जिसके माध्यम से 25 प्रतिशत की दर से बेसिक शुल्क लगाई गई। चूंकि 25 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाई गई इसलिए आयातक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 535/1987 दाखिल की तथा अन्य बातों के साथ-साथ विरोध किया कि उक्त अधिसूचना को विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं किया गया तथा यह कि उस तारीख को यह प्रभावी नहीं थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपार प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1985 – 22 ई एल टी 644) के मामले में उक्त न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के आधार पर उक्त विरोध को स्वीकार करते हुए रिट याचिका को स्वीकार किया। इसलिए राज्य द्वारा वर्तमान अपील की गई है।

निर्णय :

(20) तथापि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि यह साबित करने के लिए रिकार्ड में कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि सीमा शुल्क से पूर्ण छूट को वापस लेने वाली दिनांक 4 फरवरी, 1987 की अधिसूचना इसी तारीख को प्रकाशित हुई थी। इस प्रयोजन के लिए उक्त तारीख को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 फरवरी, 1987 की अधिसूचना की मूल प्रति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सार्वजनिक कार्यों के प्रमाण के रूप में सरकारी रिकार्ड होने के कारण राजपत्र स्वीकार्य है तथा न्यायालय से साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के साथ पठित धारा 35 एवं 38 के अंतर्गत जायज के रूप में इसकी अंतर्वस्तुओं को मानने की अपेक्षा की जाती है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं होता है। इसलिए इस विरोध में कोई सार नहीं है कि दिनांक 4 फरवरी, 1987 की अधिसूचना राजपत्र में इसी तारीख को प्रकाशित हुई। हमारी राय में उक्त अधिसूचना इसी तारीख को प्रभाव में आई।

(21) अंत में इस स्तर पर हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि संसद ने 1 जून, 1998 से 1998 के अधिनियम नंबर 21 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 में उप धारा 4 एवं 5 को जोड़ा है जिसके तहत अधिसूचना के प्रकाशन की विधि एवं पद्धति तथा जिस तारीख को अधिसूचना प्रकाशित होती है उस तारीख को इसके प्रभाव में आने का निर्धारण किया गया है। धारा 25 में हाल ही में अंतःस्थापित की गई उप धारा 4 और 5 को यहां नीचे दिया गया है :

"(4) उप धारा 1 के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना -

- (क) जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, राजपत्र में प्रकाशन के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाने की तारीख को प्रभाव में आएगी;
- (ख) बोर्ड के प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने की तारीख को प्रकाशित भी की जाएगी तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(5) उप धारा 4 में कोई भी बात निहित होने के बावजूद, जहां कोई अधिसूचना ऐसी तारीख से बाद की किसी तारीख को प्रभाव में आती है, जिस तारीख को उसे जारी किया जाता है, तो उसे उक्त प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय द्वारा उस तारीख को या उससे पहले, जिस तारीख को उक्त अधिसूचना प्रभाव में आई थी, प्रकाशित किया जाएगा तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(22) परिणाम के तौर पर अपील को अनुमत किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश को अलग रखा जाता है तथा निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी को अधिसूचना संख्या 40/87- सीमा शुल्क, दिनांक 4 फरवरी, 1987 के तहत 25 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत तिथि राजपत्र में प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इसे जारी करने की तिथि है। चूंकि इसे भारत सरकार के मुद्रणालय द्वारा 29 अगस्त, 2008 को प्राप्त किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अन्वेषण 29 अगस्त, 2013 को शुरू किया गया।

ग. वर्तमान शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व अन्वेषण आरंभ किया गया। इच्छुक पक्षकारों ने वरणात्मक रूप से आर टी आई के अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त उत्तर का हवाला दिया है। पत्र में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है :

- i) रजिस्टर में जी संख्या 436 और जी संख्या 437 नामक जॉब 29 अगस्त, 2013 को और जी संख्या 438 नामक जॉब 30 अगस्त, 2013 को प्राप्त किया।
 - ii) जी संख्या 436 एवं 437 की प्राप्ति की तारीख 29 अगस्त, 2013 है तथा जी संख्या 438 की प्राप्ति की तारीख 30 अगस्त, 2013 है। इन सभी को 2 सितंबर, 2013 को किताब महल को भेजा गया।
 - iii) जी संख्या 436, 437 एवं 438 को प्रकाशन के लिए 2 सितंबर, 2013 को दोपहर 12 बजे भेजा गया। जॉब संख्या 3754, 3756, 3761 जीआई/13
 - iv) इस प्रकार देखा जा सकता है कि भारत सरकार के मुद्रणालय द्वारा गजट अधिसूचना 29 अगस्त, 2013 को प्राप्त हुई। इस प्रकार स्वीकृत तौर पर शुरुआत 29 अगस्त, 2013 को हुई तथा प्रकाशन के लिए अधिसूचना भी 29 अगस्त, 2013 को जारी हुई। यह तथ्य कि अधिसूचना 2 सितंबर, 2013 को मुद्रित हुई तथा आम जनता के लिए इसके बाद उपलब्ध हुई, पूरी तरह से महत्वहीन है।
 - v) इस संबंध में यहां इस बात का उल्लेख करना संगत है कि समय सीमा की आखिरी तिथि को एंटी डंपिंग पर नामोद्विष्ट प्राधिकारी द्वारा समापक समीक्षा शुरू करने एवं अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अनेक नोटिस जारी किए जाते हैं। नीचे दी गई सारणी ऐसे मामलों को दर्शाती है जहां शुल्क की अवधि समाप्त होने की तारीख को पहल की गई।
- सारणी : जहां समाप्त होने की तारीख वही है जो पहल की तारीख है

उत्पाद	देश	कालातीत होने की मूल तिथि	पहल की तिथि
डिक्लोफेनाक सोडियम	चीन	9 अप्रैल, 2013	9 अप्रैल, 2013
सोडियम हाइड्रो सल्फाइड	लोक गणराज्य चीन	14 अक्टूबर, 2011	14 अक्टूबर, 2011

नीचे दी गई सारणी ऐसे मामलों को दर्शाती है जहां अंतिम निष्कर्ष पूरा होने की अंतिम तारीख को निकाले गए

उत्पाद	देश	कालातीत होने की मूल तिथि	— तक मंजूर किया गया एक वर्षीय विस्तार	पहल की तारीख	अंतिम निष्कर्षों की तारीख
बायस टायस फॉर बस एण्ड लॉरी ट्रक्स	लोक गणराज्य चीन, थाईलैंड	8 अक्टूबर, 2011	लागू नहीं	3 अगस्त, 2011	2 अगस्त, 2012
कास्टिक सोडा	सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएस और फ्रांस	12 सितंबर, 2011	लागू नहीं	2 सितंबर, 2011	31 अगस्त, 2012 (1 सितंबर, 2012 शनिवार था)
पार्सिली ओरिएंटेड यार्न (पी ओ बाई)	लोक गणराज्य चीन	1 अगस्त, 2011	लागू नहीं	11 फरवरी, 2011	10 फरवरी, 2012
पेरेक्सो सुल्फाटेस	लोक गणराज्य चीन और जापान	18 मार्च, 2012	लागू नहीं	13 मार्च, 2012	12 मार्च, 2013
विश्वकोस फिलामेंट यार्न	लोक गणराज्य चीन	23 मई, 2011	लागू नहीं	25 फरवरी, 2011	24 फरवरी, 2012
कास्टिक सोडा	सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए और फ्रांस	12 सितंबर, 2011	1 सितंबर, 2012	2 सितंबर, 2011	31 अगस्त, 2012
पार्सिली ओरिएंटेड यार्न (पी ओ बाई)	लोक गणराज्य चीन	1 अगस्त, 2011	10 फरवरी, 2012	11 फरवरी, 2011	10 फरवरी, 2012
विश्वकोस फिलामेंट यार्न	लोक गणराज्य चीन	23 मई, 2011	24 फरवरी, 2012	25 फरवरी, 2011	24 फरवरी, 2012

vi) इस प्रकार देखा जा सकता है कि एंटी डंपिंग के मामलों को उनकी अवधि समाप्त होने से पूर्व शुरू किया गया है। इसके अलावा अधिकांश मामलों में अंतिम निष्कर्ष जारी होने की अंतिम तारीख से ठीक पहले अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए हैं। स्पष्ट है कि समय सीमा से पहले इन सभी मामलों में भारत सरकार के मुद्रणालय द्वारा अधिसूचना को मुद्रित करना एवं उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार के मुद्रणालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिसूचना को मुद्रित करने के लिए अपेक्षित समय महत्वपूर्ण होता है तथा राजपत्र की प्रतिलिपि परिचालन की तिथि मुद्रणालय के लोड पर निर्भर होती है।

घ. यद्यपि वर्तमान प्रकरण में आरंभ करने की अधिसूचना स्पष्ट रूप से वर्तमान शुल्क के समाप्त होने से पहले जारी की गई है, यहां इस बात का उल्लेख करना संगत है कि किसी भी स्थिति में नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि अन्वेषण शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व अवश्य शुरू हो जाना चाहिए। एंटी डंपिंग कानून तथा रक्षोपाय कानून में अंतर इसे स्पष्ट करता है, जैसा कि यहां नीचे उद्धृत संगत प्रावधानों से देखा जा सकता है :

धारा 9क (5), सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, जो किसी एंटी डंपिंग मामले में समापक समीक्षा से संबंधित है, संगत अंश में निम्नानुसार कहती है :

"परंतु यह भी कि जहां पांच साल की पूर्वोक्ति अवधि के समाप्त होने से पूर्व शुरू की गई समीक्षा ऐसी समाप्ति से पूर्व अंजाम पर नहीं पहुंची है, एंटी डंपिंग शुल्क अधिक से अधिक एक वर्ष की अगली अवधि के लिए इस तरह की समीक्षा के परिणाम के लंबित होने पर प्रभाव में बनी रह सकती है।

रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए समतुल्य धारा का नाम धारा 8ख (4) है जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"4. इस धारा के अंतर्गत लगाई गई शुल्क, जब तक कि पहले निरस्त नहीं की जाती है, लगाए जाने की तारीख से चार साल की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रभावी नहीं रह जाएगी :

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसे नुकसान या उसके खतरे को समायोजित करने के लिए कदम उठाया है और यह आवश्यक है कि एस जी शुल्क लगती रहनी चाहिए, वह इस शुल्क की अवधि बढ़ा सकती है:

परंतु यह भी कि किसी भी स्थिति में एस जी शुल्क को पहली बार लगाए जाने की तारीख से 10 साल की अधिक अवधि के बाद लगाना जारी नहीं रखा जाएगा।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि एंटी डंपिंग समापक समीक्षा एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व शुरू हो जानी चाहिए तथापि रक्षोपाय शुल्क से संबंधित कानून में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। इस प्रकार किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) विद्यमान रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व अन्वेषण शुरू करने के लिए बाध्य हैं।

(ix) अन्वेषण शुरू करने की अधिसूचना की तारीख 29 अगस्त, 2013 है परंतु आधिकारिक तौर पर इसे 2 सितंबर, 2013 को प्रकाशित किया गया तथा 24 घंटे बाद अर्थात् तीन सितंबर, 2013 को उपलब्ध कराया गया।

अन्वेषण शुरू करना तथा उसे इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराना दो अलग अलग कार्य हैं। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि आरंभ करने की अधिसूचना उसी तारीख को इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिस तारीख को अधिसूचना शुरू की गई। इस संबंध में नियम 16 का प्रासंगिक है, जिसका स्पष्ट रूप से निहितार्थ यह है कि ये गतिविधियां अन्वेषण आरंभ होने के बाद शुरू होती हैं। इसके अलावा देखा जा सकता है कि नियम 6 में निर्धारित की गई एक मात्र समय सीमा इच्छुक पक्षकारों को संगत सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित समय सीमा है। तथापि अन्वेषण शुरू करने के बारे में इच्छुक पक्षकारों को सूचित करने या संगत सूचना प्राप्त करने या अन्वेषण शुरू करने के बारे में इच्छुक पक्षकारों को सूचित करने के लिए नियम 6 के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(क) प्रकाशन एवं मुद्रण स्पष्ट रूप से दो अलग अलग पहलू हैं, जैसा कि भारत के राजपत्र के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए अनुदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस अनुदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि जिन अधिसूचनाओं को किसी विशिष्ट तारीख तक प्रकाशित किया जाना होता है उनको संबंधित प्रेस को पर्याप्त समय देते हुए भेजा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार की समझ यह है कि कोई भी प्रकाशन तब पूरा होता है जब मुद्रित गजट आम जनता को उपलब्ध हो जाता है।

शुरुआत, मुद्रण और प्रकाशन तीन अलग अलग कार्य हैं। यद्यपि शुरुआत वर्तमान शुल्क के समाप्त होने से पूर्व की गई है, उसके मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद संपन्न हुआ है। तथापि नियमों में केवल अन्वेषण के आरंभ होने का उल्लेख है तथा शुरुआत के मुद्रण एवं प्रकाशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। शुरू करने की बाध्यता को शुरुआत या अंतिम निष्कर्ष के मुद्रण एवं प्रकाशन की बाध्यता के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है।

(ख) यह उपाय वास्तव में एक नया अन्वेषण आरंभ करना है, जो दो साल की अवधि समाप्त होने के अंदर घटित नहीं हो सकता है (अनुच्छेद 7.5)।

याचिका एवं शुरुआत की नोटिस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्वेषण वर्तमान शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए है, न कि कोई नई शुल्क लगाने के लिए है। शुल्क की अवधि बढ़ाने को केवल शुल्क में व्यवधान के कारण नई लेवी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(ग) अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमता में पर्याप्त अभिवृद्धि की गई है तथा प्रार्थी तगड़ी घरेलू प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। उसके पास अब उक्त माल के 50 प्रतिशत का उत्पादन करने की क्षमता नहीं रह गई है। अन्य उत्पादकों में से किसी ने भी याचिका का समर्थन नहीं किया है।

यह दलील निराधार है। नीचे दी गई सारणी विभिन्न घरेलू उत्पादकों की बाजार में हिस्सेदारी को दर्शाती है। देखा जा सकता है कि अपनी क्षमता में वृद्धि करने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी गंवाई है। जहां तक याचिका का समर्थन करने का संबंध है, त्रुंकि प्रार्थी के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है इसलिए प्रार्थी कानून के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने का हकदार है, चाहे अन्य घरेलू उत्पादक याचिका का समर्थन करें या न करें।

"(घ) अस्तित्व या प्रचालन में बने रहना" एक मात्र अभिप्राय है जिसे अनुच्छेद 7.2 की व्याख्या के लिए अपनाया जा सकता है क्योंकि यदि "व्यवधान के बाद बहाली या पुनः प्रारंभ" अपनाया जाता है, तो अनुच्छेद 7.5 में उपलब्ध निषेध निरर्थक हो जाएगा।

विरोध दोषपूर्ण है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 7.5 की भूमिका तब होती है जब किसी उत्पाद को रक्षोपाय शुल्क से नुकसान हो रहा है तथा कुछ समय पश्चात पुनः रक्षोपाय शुल्क लगाई जानी हो। रक्षोपाय शुल्क को पुनः लगाना रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने से भिन्न है।

स्पष्ट रूप से यह करार के अनुच्छेद 7 से उत्पन्न हुआ है जो स्पष्ट रूप से विद्यमान शुल्क की अवधि बढ़ाने तथा नए सिरे से एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के बीच अंतर करता है। शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए शुल्क की अवधि के दौरान शुल्क की समीक्षा तथा उसी उत्पाद पर शुल्क को पुनः लगाने के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से दो भिन्न प्रक्रियाएँ हैं। वास्तव में शुल्क की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में विस्तार शब्द की व्याख्या इस रूप में की जानी चाहिए कि उसका निहितार्थ "विश्राम के साथ या बगैर पुनः प्रारंभ करना या बहाल करना" हो।

(इ) अवधि बढ़ाने का निर्धारण पिछली अवधि के समाप्त होने से पूर्व किया जाना होता है। वर्तमान मामले में, यदि डी जी एस उपाय के जारी रहने की सिफारिश करते हैं तो एक अंतराल के पश्चात पुनः उपाय पुनः प्रारंभ होगा या लागू होगा। कानून रक्षोपाय शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लगाने का प्रावधान नहीं करता है और यह केवल वहाँ संभव है जहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान हो।

पहले दी गई प्रस्तुतियों पर भरोसा किया गया है। विद्यमान शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व शुल्क की अवधि बढ़ाने का मुद्दा वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है। डी जी एस द्वारा की गई सिफारिश इस मुद्दे पर पूरी तरह से असंगत है। इसके अलावा प्रार्थी ने रक्षोपाय शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लगाने की मांग नहीं की है। प्रार्थी एतद्वारा स्पष्ट रूप से निवेदन करता है कि उसने भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगाने की मांग नहीं की है तथा प्रार्थी केवल संदर्शी प्रभाव से शुल्क की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रार्थी को इस बात की जानकारी है कि वह पिछली शुल्क की अवधि समाप्त होने की तारीख तथा सरकार द्वारा नई शुल्क लगाए जाने की तारीख के बीच की मध्यवर्ती अवधि के लिए राहत प्राप्त नहीं करेगा।

इस संबंध में इस बात का उल्लेख करना कि संगत है कि प्रार्थी ने वास्तव में 1 जनवरी, 2013 को रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए अपना आवेदन दाखिल किया था। तथापि, डी जी एस ने केवल 29 अगस्त, 2013 को अन्वेषण आरंभ किया।

(च) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (तरसेम कुमार बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, चंडीगढ़) और केरल उच्च न्यायालय (अंबाली कार्तिकेयन बनाम सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक) ने निर्णय दिया कि माल की जब्ती की मूल अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब्ती की अवधि बढ़ाने का निर्णय गैर कानूनी है। सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 110 (2) का परंतुक रक्षोपाय के प्रावधान के लिए आंशिक रूप से महत्वपूर्ण है।

उल्लिखित निर्णय वर्तमान प्रकरण में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, जैसा कि दोनों स्थितियों के संदर्भ से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा था वह माल की जब्ती की मूल अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब्ती की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में था, जबकि वर्तमान प्रकरण में जो मुद्दा है वह आयात पर रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने से संबंधित है। दोनों मुद्दों में निश्चित रूप से समानता स्थापित नहीं की जा सकती है।

छ) उच्चतम न्यायालय (बाबू वर्गीज बनाम केरल बार काउंसिल) ने केरल बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उसका कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित निर्णय को गैर कानूनी ठहराया।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय केरल बार काउंसिल के कार्यकाल को बढ़ाने के संदर्भ में है। वर्तमान स्थिति पूरी तरह से भिन्न है।

ज) जी ए टी टी के अनुच्छेद 19 के तहत यह अपेक्षित है कि प्राधिकारी (क) जी ए टी टी के अंतर्गत उक्त उत्पाद के संबंध में भारत द्वारा वहन की गई टैरिफ रियायत सहित विशिष्ट बाध्यता की पहचान करे और (ख) स्थापित करे कि विशिष्ट बाध्यता का संबंध भारत में उक्त उत्पाद के आयात में वृद्धि से है। (कोरिया – कतिपय डेरी उत्पाद, अर्जेंटीना – फुटबियर, यूएस – लैंब, डोमिनिका गणराज्य – पोली प्रोपलीन बैग और ट्यूबलर – फैब्रिक)। भारत के लिए उत्पाद के लिए बाध्यकारी दर 40 प्रतिशत है तथा वर्तमान सीमा शुल्क की दर 7.5 प्रतिशत है। इसलिए सीमा शुल्क में 40 प्रतिशत से नीचे कटौती के कारण आयात में किसी वृद्धि का श्रेय 1994 में भारत द्वारा वहन की गई बाध्यता एवं टैरिफ रियायत को नहीं दिया जा सकता है।

(i) अपनी प्रस्तुतियों में प्रतिवादी पक्षकार ने कहा है कि :

"55. इस संदर्भ में डी जी एस इस बात को नोट कर सकते हैं कि अन्य देशों के साथ ही भारत आयात पर सीमा-शुल्क कम करने के लिए सहमत हुआ है तथा एक नियत दर प्रदान की है जो उससे अधिक है जो यह बुनियादी सीमा शुल्क के रूप में प्रभारित करता है। अधिकतम दर जिस पर सहमति हुई है, को बाध्यकारी दर के रूप में जाना जाता है तथा यह दर ऐसी है जिसके लिए भारत ने बाध्यता वहन की है। इस बाध्यकारी दर से नीचे सीमा शुल्क में कोई और कटौती भारत द्वारा वहन की गई किसी बाध्यता के शर्तों के अधीन नहीं है। बाध्यकारी दर 40 प्रतिशत है तथा उक्त माल के आयात पर वर्तमान सीमा शुल्क की दर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ, 2013 – 14 के अनुसार 10 प्रतिशत है। इस प्रकार 40 प्रतिशत से नीचे सीमा शुल्क में कटौती के कारण आयात में किसी वृद्धि का श्रेय 1994 में भारत द्वारा वहन की गई बाध्यता एवं टैरिफ रियायत को नहीं दिया जा सकता है।"

(ii) तथापि, कोरिया – डेरी के मामले में अपीलीय निकाय द्वारा यह व्याख्या नहीं अपनाई गई है, जो ऐसा मामला है जिसे प्रतिवादी पक्षकार द्वारा उद्धृत किया गया है। कोरिया – डेरी में, अपीलीय निकाय ने पाया कि "टैरिफ रियायत सहित इस करार के तहत किसी सदस्य द्वारा वहन की गई बाध्यताओं का प्रभाव" पदबंध का अभिप्राय मात्र यह है कि तथ्य के रूप में यह अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य देश ने जी ए टी टी 1994 के अंतर्गत टैरिफ रियायत सहित बाध्यता वहन की है।

डोमिनिकन गणराज्य – पोली प्रोपलीन बैग एवं ट्यूबलर फैब्रिक में, प्रतिवादी पक्षकार द्वारा एक अन्य मामले पर भरोसा किया गया है, पैनल ने निर्णय दिया है कि :

"तथ्य के रूप में आयात करने वाले सदस्य देश को जी ए टी टी 1994 के तहत बाध्यता अवश्य वहन करनी चाहिए, उदाहरण के लिए उक्त उत्पाद के संबंध में टैरिफ रियायत। इसके पश्चात आयात करने वाले सदस्य देश की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जी ए टी टी

1994 के अंतर्गत वहन की गई उन बाध्यताओं की पहचान करें जो आयात में वृद्धि से संबंधित हैं जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है।"

(iii) पैनल ने यह राय व्यक्त की कि चूंकि डोमिनिकन गणराज्य में उत्पाद पर 40 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क की टैरिफ रियायत प्रदान की है इसलिए इसने जी ए टी टी 1994 के अंतर्गत उत्पाद के संबंध में बाध्यता वहन की है। तथापि डोमिनिका गणराज्य ने इन बाध्यताओं (या) जी ए टी टी 1994 के अंतर्गत अन्य बाध्यताओं की पहचान नहीं की थी क्योंकि उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि आयात में वृद्धि से संबद्ध बाध्यताओं से उसके घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ। चूंकि यह पाया गया कि प्राधिकारी की रिपोर्ट में इस संबंध में कोई निष्कर्ष या कारण सहित उपसंहार नहीं है कि कैसे डोमिनिकन गणराज्य ने बाध्यता वहन की जिसकी वजह से आयात में वृद्धि हुई जिससे गंभीर नुकसान हुआ, इसलिए पैनल ने इस मुद्दे की आगे जांच नहीं की। इस प्रकार पैनल ने उस समय वह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसे प्रतिवादी पक्षकार द्वारा अपनाया गया है, जब उसने कहा कि 40 प्रतिशत से नीचे सीमा शुल्क की कटौती के कारण आयात में किसी वृद्धि का श्रेय 1994 में भारत द्वारा वहन की गई बाध्यता एवं टैरिफ रियायत को नहीं दिया जा सकता है।"

i. घरेलू उद्योग ने जन सुनवाई में स्वीकार किया कि टैरिफ में कटौती कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है तथा के पी सी एवं सिनोर्गचेम के बीच विशेष संबंध एक अप्रत्याशित घटना है। विश्व व्यापार संगठन के पैल्लों ने इस ढंग से अप्रत्याशित घटनाओं की कभी व्याख्या नहीं की है। संगत रियायत प्रदान करते समय वार्ताकारों द्वारा घटनाएं अप्रत्याशित होनी चाहिए (अर्जेंटीना – प्रिसवर्ड पीच, कोरिया – कतिपय डेरी उत्पाद, अर्जेंटीना – फुटबियर, डोमिनिकन गणराज्य – पोली प्रोपलीन बैग एवं ट्यूबलर फैब्रिक)।

क. जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद 19 (1क) की अपेक्षाओं को इच्छुक पक्षकारों द्वारा गलत रूप में समझा गया है। प्रावधान को यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

"यदि अप्रत्याशित घटनाओं तथा इस करार के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा वहन की गई बाध्यता के प्रभाव के फलस्वरूप, जिसमें टैरिफ रियायत भी शामिल है, किसी उत्पाद का आयात उस सदस्य देश के भू-भाग में ऐसी अधिक मात्रा में तथा ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे उस भू-भाग में समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर नुकसान हो रहा है या नुकसान होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है तो सदस्य ऐसे उत्पाद के संबंध में उस सीमा तक तथा ऐसी अवधि के लिए जो ऐसे नुकसान को रोकने या निदान करने के लिए आवश्यक हो सकती है, पूर्णतः या आंशिक रूप से बाध्यता को निलंबित करने या रियायत को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

ख. देखा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए दो स्थितियां हैं जो इस प्रकार हैं: (क) अप्रत्याशित घटनाओं की मौजूदगी, और (ख) भारत सरकार द्वारा टैरिफ रियायत सहित बाध्यताओं का वहन किया जाना। डोमिनिकन गणराज्य - पोली प्रोपलीन बैग एवं ट्यूबलर फैब्रिक के आयात पर रक्षोपाय शुल्क में (ऐसा मामला जिस पर प्रतिवादी पक्षकार द्वारा भरोसा किया गया है) पैनल ने इन दो आवश्यकताओं की अलग से छानबीन की। वर्तमान प्रकरण में टैरिफ रियायत की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से पालन हुआ है, जैसा कि भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद पर सीमा शुल्क की दर घटा दी है। इसके अलावा सीमा शुल्क की दर में ऐसी कटौती न केवल विचाराधीन उत्पाद के मामले में की गई है अपितु कच्चे माल पर भी की गई है।

ग. इस प्रकार देखा जा सकता है कि टैरिफ में कटौती तथा अप्रत्याशित घटनाएं आपस में परिवर्तनीय आवश्यकताएं नहीं हैं। ये दो पूरी तरह से भिन्न आवश्यकताएं हैं। केवल एक की पूर्ति ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार मात्र यह तथ्य कि भारत सरकार ने सीमा शुल्क की दर घटा दी है, रक्षोपाय शुल्क को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी तरह यदि भारत सरकार ने टैरिफ में कटौती नहीं की है या पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसार इस तरह के अन्य कदम नहीं उठाए गए हैं तो अप्रत्याशित घटना की केवल मौजूदगी रक्षोपाय शुल्क हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छुक पक्षकार का मानना है कि दोनों आवश्यकताएं आपस में परिवर्तनीय हैं। इसी संदर्भ में प्रार्थी ने मौखिक सुनवाई के समय बयान दिया था कि भारत सरकार द्वारा टैरिफ में कटौती कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया है। टैरिफ में कटौती केवल वहन की गई कोई बाध्यता हो सकती है।

घ. प्रार्थी ने इस वजह से टैरिफ में कटौती का हवाला नहीं दिया है कि उत्पाद को पहले से ही रक्षोपाय शुल्क से नुकसान हो रहा है तथा भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पहले भी विचार किया जा चुका है। भारत सरकार स्वयं को इस बारे में पहले संतुष्ट किए बगैर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाई होती कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आवश्यकता की पूर्ति हुई है। न तो कोरिया सरकार और न ही किसी अन्य देश ने इस संबंध में डब्ल्यू टी ओ के समक्ष कोई सरोकार खड़ा किया है। इस प्रकार सभी पक्षकार अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान प्रकरण में रक्षोपाय शुल्क को तभी हटाया गया जब इस बारे में पुष्टि हो गई कि भारत सरकार की बाध्यताओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। चूंकि वर्तमान प्रकरण केवल समीक्षा का मामला है इसलिए प्रार्थी द्वारा बाध्यता का पुनः उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी।

ड. वर्तमान प्रकरण में अपनी प्रस्तुतियों में प्रतिवादी पक्षकार ने बताया है कि के पी सी तथा सिनोर्गचेम के बीच विशेष संबंध कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है क्योंकि न तो डब्ल्यू टी ओ पैनल और न ही अपीलीय निकाय ने इस तरह की घटना पर अप्रत्याशित घटना के रूप में विचार किया है (के पी सी की प्रस्तुतियों का पृष्ठ 20, पैराग्राफ 48)। तथापि उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी पक्षकार द्वारा डब्ल्यू टी ओ के जिन निर्णयों का हवाला दिया गया है उनमें से किसी ने भी ऐसी घटना के स्वरूप पर कोई सीमा निर्धारित की है जो अप्रत्याशित घटना हो सकती है।

च. अर्जेंटीना – फुटबियर (ई सी प्रकरण) में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित घटना नामक पदबंध का अभिप्राय ऐसी घटनाओं से है जो अप्रत्याशित हैं। अप्रत्याशित घटना के तहत यह अपेक्षित है कि जिन घटनाओं की वजह से इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में उत्पाद का आयात किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिनकी वजह से घरेलू उत्पादकों को गंभीर नुकसान हो रहा है या नुकसान होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, उन्हें निश्चित रूप से अप्रत्याशित घटना माना जाना चाहिए।

छ. कोरिया – डेरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस समय अप्रत्याशित या अनपेक्षित होती हैं जब किसी सदस्य ने वह बाध्यता की थी। अर्जेन्टीना – फुटबियर (ई सी) मामले में अपीलीय निकाय ने जी ए टी टी पैनल की एक रिपोर्ट को नोट किया जिसमें पुष्टि की गई है कि टैरिफ पर वार्ता के समय घटना निश्चित रूप से अप्रत्याशित होनी चाहिए : "इसके अलावा हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 19 1(क) में 'इस करार के अंतर्गत किसी सदस्य देश द्वारा टैरिफ रियायत सहित वहन की गई बाध्यताओं के प्रभाव तथा अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप' – उपबंध का हमारा वाचन जी ए टी टी 1947 के एक मामले से भी संगत है जिसमें अनुच्छेद 19 शामिल था, तथाकथित हैटर फर प्रकरण। इस प्रकरण में कार्यकारी पक्षकार के सदस्यों ने 1951 में निम्नानुसार कहा:

... 'अप्रत्याशित घटना' की व्याख्या इस रूप में की जानी चाहिए कि उसका अभिप्राय संगत टैरिफ रियायत की वार्ता के बाद घटित होने से हो जिसकी अपेक्षा करना तर्कसंगत नहीं होगा जिसके बारे में रियायत प्रदान करने वाले देश के वार्ताकार उस समय प्रत्याशा कर सकते हैं और करनी चाहिए जब रियायत पर वार्ता हुई।'

वर्तमान प्रकरण में अप्रत्याशित घटना तथा वहन की गई बाध्यता :

ज. इस प्रकरण में आयात में वृद्धि को जन्म देने वाली अप्रत्याशित घटनाएं, जिससे गंभीर नुकसान हुई है, जैसा कि याचिका में तथा इन प्रस्तुतियों में अन्यत्र बताया गया है, वैश्विक उत्पादकों की अतिरिक्त सुविधाएं, के पी सी एवं सिनोर्गनेम के बीच विशेष व्यवस्था तथा के पी सी द्वारा क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार हैं।

वार्ताकारों द्वारा उस समय इन घटनाओं की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है जब विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत की बाध्यताएं निर्धारित की जा रही थी। वर्तमान प्रकरण में वहन की गई बाध्यता उत्पाद के संबंध में भारत द्वारा मंजूर की गई टैरिफ रियायत है।

(ज) **तुर्की – कॉटन यार्न के विरुद्ध भारत की शिकायत में, भारत ने कहा कि 14 जुलाई 2011 को रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद 28 जनवरी, 2012 को तुर्की द्वारा रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाना अनुच्छेद 7.5 की दृष्टि से असंगत है। तुर्की इसे वापस लेने के लिए सहमत हो गया। घरेलू स्तर पर भी भारत की उपर्युक्त प्रथा का अनुसरण किया जाना चाहिए।**

लिखित प्रस्तुतियों पर भरोसा किया गया है जो इस मुद्दे से संबंधित हैं। तुर्की मामले के तथ्य पूरी तरह से भिन्न हैं। वर्तमान प्रकरण में सरकार द्वारा न तो विद्यमान शुल्क समाप्त होने के बाद कोई अंतरिम शुल्क लगाई गई है और न ही प्रार्थी ने एंटी डंपिंग शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लगाने की मांग की है। किसी भी स्थिति में, डब्ल्यू टी ओ द्वारा इस मुद्दे का कभी निर्णय नहीं किया गया।

(ट) **मूल अन्वेषण के लिए आवेदन में (और लिखित प्रस्तुतियों में अपनी समायोजन योजना में एन ओ सी आई एल ने बताया कि दाहेज संयंत्र का उद्देश्य इसके एक उत्पाद के रूप में पी एक्स 13 का उत्पादन करना है तथा इसका वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में शुरू हुआ। डी जी एस द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में इसे नोट किया गया तथापि वर्तमान आवेदन में एन ओ सी आई एल ने कहा है कि उसका उद्देश्य दाहेज संयंत्र में पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए 10,000 मीट्रिक टन इंटरमीडियरी का उत्पादन करना है। वर्तमान आवेदन में प्रार्थी ने दावा किया है मूल अन्वेषण के लिए अपने आवेदन में उन्होंने बताया था कि दाहेज संयंत्र पी एक्स 13 के उत्पादन के लिए प्रयुक्त इंटरमीडियरी के लिए है।**

प्रार्थी ने समायोजन योजना शुरू की है, जैसा कि पिछली याचिका में बताया गया है, जिससे रक्षोपाय शुल्क लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले की गई प्रस्तुतियों पर भरोसा किया गया है। प्रार्थी ने नवंबर, 2012 में अपना ट्रायल उत्पादन शुरू किया तथा मार्च, 2013 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

(ठ) **यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या दाहेज संयंत्र का प्रचालन पी एक्स 13 के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करेगा, जिसे शुरुआत नोटिस में 8500 मीट्रिक टन के रूप में नोट किया गया है।**

स्पष्ट किया जाता है कि दाहेज संयंत्र का प्रचालन पी एक्स 13 के लिए प्रार्थी की क्षमता को बढ़ाकर 14000 मीट्रिक टन करेगा। इन संबंध में, डी जी एस को पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है।

(ड) **प्राधिकार पत्र पर 23 अगस्त, 2013 की तारीख अंकित है परंतु प्रारंभ अधिसूचना में आवेदन दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई, 2013 है।**

याचिका 31 जुलाई, 2013 को दाखिल की गई। समीक्षा करने और रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए डी जी एस से अनुरोध करने के लिए एन ओ सी आई एल के पत्र पर 26 जुलाई, 2013 की तारीख अंकित है। तथापि, एन ओ सी आई एल ने इस पत्र में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए टी पी एम को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए डी जी एस ने एन ओ सी आई एल के एक विशिष्ट प्राधिकार पत्र की मांग की, जिस पर 23 अगस्त, 2013 को हस्ताक्षर किए गए। इस प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि भी याचिका के गैर गोपनीय संस्करण के साथ संलग्न की गई है।

(ढ) **मूल अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों में समायोजन योजना में भारी अंतर है तथा याचिका में उन पर भरोसा किया गया है।**

मूल अन्वेषण के समय डी जी एस को सूचित समायोजन तथा इस समय डी जी एस को सूचित समायोजन योजना में कोई अंतर नहीं है।

(ण) **समायोजन के पूरे लाभ को प्राप्त न करना रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए कोई बहाना नहीं है (पी ए एन समीक्षा में शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाई गई क्योंकि घरेलू उद्योग ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हुआ कि उन्होंने सकारात्मक कदम उठाए हैं)।**

पीएएन समीक्षा का संदर्भ प्रस्तुत करना पूरी तरह से असंगत है, क्योंकि डी जी एस ने इस मामले में यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। आदेश के संगत भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"प्रार्थियों ने स्पष्ट रूप से यह मांग की गई कि वे इस अन्वेषण के शुरू होने से पूर्व 17 जनवरी, 2012 से उक्त उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद से उठाए गए सकारात्मक समायोजन के कदमों के बारे में विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करें। तथापि, दिनांक 26 सितंबर, 2012 के अपने उत्तर के माध्यम से परामर्शदाताओं ने केवल निकट भविष्य में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समायोजन योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस बीच घरेलू उद्योग की 3 यूनिटों के ऑन साइट सत्यापन के दौरान, जिसे सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार संचालित किया गया, घरेलू उद्योग से विशेष रूप से रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 18 (1) (i) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट द्वारा उठाए गए सकारात्मक समायोजन के कदमों के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तथापि, जिन यूनिटों का सत्यापन किया गया उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस निर्णय के साथ रक्षोपाय अन्वेषण शुरू करने का आदेश दिया गया कि समायोजन योजना के प्रश्न पर समीक्षा आदेश पारित करते समय विचार किया जाएगा।

अब, चूंकि इस मामले में सकारात्मक समायोजन योजना का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा पी एच के बाद लिखित प्रस्तुतियां पहले ही उठाए गए कुछ कदमों की बात करती हैं तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके द्वारा कौन से विशिष्ट कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में बिक्री की अपनी लागत को नियंत्रित करने / सीमित करने में समर्थ नहीं हुआ है। बिक्री की लागत (अनुक्रमणित) में निरंतर वृद्धि हुई है तथा यह 2009-10 में 100 रूपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 2010-11 में 110 रूपए प्रति मीट्रिक टन, 2011-12 में 148 रूपए प्रति मीट्रिक टन और 2012-13 में 172 रूपए प्रति मीट्रिक टन हो गई है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में इस महत्वपूर्ण पहलू में समर्थ नहीं हो पाया है। घरेलू उद्योग के परामर्शदाता ने पी एच पश्चात अपनी लिखित प्रस्तुतियों में स्वयं ही इस बात पर जोर दिया है कि सी टी ए 1975 की धारा 8 ख (4) के अनुसार केवल ऐसी दो शर्तें हैं जिनको रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि बढ़ाने के समय पूरा करने की जरूरत होती है - (क) समायोजन योजना, और (ख) रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। उनके अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि बढ़ाने के लिए कानून में कोई अन्य आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। यह प्रस्तुति सकारात्मक समायोजन योजना का साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रश्न को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, जिसका पालन करने में घरेलू उद्योग समर्थ नहीं हुआ है।"

(झ) देखा जा सकता है कि डी जी एस ने इस प्रकरण में पाया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं को समायोजित करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। प्रार्थी नए संयंत्र पर वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू कर चुका है तथा ग्राहकों से आर्डर के अभाव में ज्यादातर क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

(त) प्रार्थी एक अक्षम उत्पादक है तथा नुकसान के कारण अंतर्भूत है। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद, प्रयोक्ता उद्योग को जिस कीमत पर पी एक्स 13 उपलब्ध था उसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा प्रार्थी अपना बिक्री मूल्य या बिक्री की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ था तथा अपना निर्यात बाजार खोना जारी रखा।

(i) इस दलील का कोई आधार नहीं है कि प्रयोक्ता उद्योग के लिए आयातित उत्पाद की कीमत में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई या प्रार्थी अक्षम उत्पादक है। इसके अलावा, एंटी डंपिंग शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क प्रभारित करने के बाद भी आयात की कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम थी। इस संबंध में, उल्लेखनीय है कि इनपुट की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत बढ़कर ... रूपए प्रति किलो हो गई, जबकि आयात मूल्य घटकर लगभग ... रूपए प्रति किलो हो गया।

नीचे दी गई सारणी गत चार वर्षों के दौरान प्रमुख इनपुट की कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है:

क्रम सं.	कच्चा माल	यूनिट	उत्पादन की प्रत्येक यूनिट में वास्तविक खपत			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	एनीलाइन	रूपए प्रति किग्रा	100	119	132	164
2	पी एन सी बी	रूपए प्रति किग्रा	100	112	114	119
3	एक्सवाईलेन	रूपए प्रति किग्रा	100	115	136	182
4	एम आई बी के	रूपए प्रति किग्रा	100	121	147	156

नीचे दी गई सारणी उपर्युक्त इनपुट के कारण पी एक्स 13 की लागत में वृद्धि को दर्शाती है:

(रूपए प्रति किग्रा में यूनिट)

क्रम सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	कच्चे माल की लागत	100	104	115	129
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		4	11	14
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				29
2	अन्य परिवर्तन लागत	100	101	112	111
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		1	11	(1)
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				11
3	बिक्री की लागत	100	103	114	121

	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		3	11	7
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				21
4	बिक्री मूल्य	100	101	103	98
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		1	2	(5)
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				(2)
5	आयात सुगम्य कीमत	160.53	159.67	163.20	157.72
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		-0.86	3.53	-5.48
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				-2.81

(ii) इस प्रकार देखा जा सकता है कि कच्चे माल की कीमत में ... रूपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है, जबकि आयात मूल्य में ... रूपए प्रति किलो की गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, यदि अमरीकी डालर के रूप में आयात मूल्य पर विचार करें, तो देखा जा सकता है कि वास्तव में आयात मूल्य में गिरावट आई है। इस प्रकार, इनपुट की लागतों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है, जबकि उक्त निर्यातकों ने भारत को निर्यात के लिए अपनी कीमतों में कारगर ढंग से कमी की है।

अमरीकी डालर में आयात मूल्य को दर्शाने वाली सारणी

क्रम सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	आयात सुगम्य कीमत (प्रति किलो अमरीकी डालर में)	3.32	3.46	3.39	2.88
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		0.13	-0.07	-0.51
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				-0.44
2	कच्चे माल की लागत	100	109	115	114
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		9	7	(2)
	आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				14

(iii) इसके अलावा, एंटी डंपिंग शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क को शामिल करने के पश्चात आयात मूल्य तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना करने पर पता चलता है कि आयात मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम रहा है।

क्रम सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	बिक्री मूल्य (अनुक्रमणित)	100	101	103	98
2	एडीडी / रक्षोपाय शुल्क सहित आयात मूल्य (प्रति किलो रूपए में)	184.18	165.94	224.74	212.59

(थ) उत्पादन की लागत में औचित्य रहित वृद्धि 4 ए डी पी ए का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक क्षमता के कारण थी क्योंकि वित्त वर्ष 2012-13 में प्रार्थी ने 18500 मीट्रिक टन 4 ए डी पी ए की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए संयंत्र पर लागत वहन की, जबकि पी एक्स 13 के उत्पादन की क्षमता (8500 मीट्रिक टन) में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ।

4 एडीपीए संयंत्र में वहन की गई किसी लागत की वजह से उत्पादन की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में प्रार्थी द्वारा जिस व्यय पर विचार किया गया है उसमें दाहेज संयंत्र पर किया गया कोई व्यय शामिल नहीं है। प्रार्थी ने दाहेज संयंत्र एवं थाणे संयंत्र पर किए गए व्यय का रिकार्ड अलग-अलग रखा है। विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित लाभ / नुकसान तथा उत्पादन की लागत केवल थाणे संयंत्र पर किए गए व्यय पर आधारित है। दाहेज संयंत्र पर किया गया कोई भी व्यय प्रदान की गई सूचना में शामिल नहीं किया गया है। प्रार्थी इस संबंध में लागत लेखाकार से अलग से एक प्रमाणपत्र प्रदान कर रहा है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रार्थी लेखाकरण की ऐसी पद्धति का अनुसरण करता है जिसमें व्यय को संबंधित स्थानों पर दर्शाया जाता है तथा दाहेज संयंत्र पर किए गए व्यय को थाणे संयंत्र पर किए गए व्यय में शामिल नहीं किया गया है।

(द) जब आयात में वृद्धि होती है तो बिक्री में भी वृद्धि होती है तथा जब बिक्री में वृद्धि होती है, तो आयात में भी वृद्धि होती है। प्रार्थी की बाजार हिस्सेदारी को अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा न कि आयात द्वारा हथिया लिया गया (जहां अन्य उत्पादकों के बाजार की हिस्सेदारी में 73 आधार बिंदु की वृद्धि हुई, जबकि प्रार्थी के बाजार की हिस्सेदारी में 24 आधार बिंदु की वृद्धि हुई)।

(i) नीचे दी गई सारणी घरेलू उद्योग की बिक्री, मांग तथा भारत में आयात को दर्शाती है। देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि से काफी कम है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि रक्षोपाय शुल्क 29 अगस्त, 2011 को लगाई गई

और इस प्रकार प्रार्थी ने रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की वजह से बिक्री में काफी वृद्धि तथा आयात में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट की अपेक्षा की थी।

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मांग	14,705	15,949	15,994	17,753
आयात	10,090	10,607	9,735	11,664
एन ओ सी आई एल की बिक्री (अनुक्रमणित)	100	105	104	105
2009-10 की तुलना में वृद्धि				
मांग		1,244	5	1,799
आयात		517	-872	1,929
एन ओ सी आई एल की बिक्री		5	-2	2

(ii) जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार में हिस्सेदारी और बिक्री में वृद्धि का संबंध है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है, अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवाई है। केवल लैनसेक्स द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों से उत्पादन एवं आयात के बीच रिएलाइन्मेंट की वजह से उसका उत्पादन एवं बाजार में हिस्सेदारी वृद्धि का प्रदर्शन करता है। वास्तव में, चूंकि लैनसेक्स ने भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संयंत्र को शिफ्ट करने की अवधि के दौरान अपनी सहयोगी कंपनियों के उत्पादन एवं आयात के बीच स्विचिंग किया है, इसलिए समूची स्थिति को लैनसेक्स द्वारा किए गए आयात को बहिष्कृत करने के बाद तथा घरेलू प्रतिस्पर्धी द्वारा आपूर्ति के रूप में उसे मानकर देखना चाहिए, जैसा कि यहां ऊपर दी गई सारणी में दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि वास्तव में आयात में काफी वृद्धि हुई है तथा सभी घरेलू उत्पादकों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवाई है।

(ध) अन्य घरेलू उत्पादक प्रार्थी की तुलना में कम कीमत पर उक्त माल की पेशकश कर रहे हैं (तुर्की से मिस्र – स्टील रेबार; जापान से यूएस – हॉट रोल्ड स्टील उत्पाद)।

यह दलील निराधार है। वास्तव में, आयात मूल्य घरेलू मूल्य से सारवान रूप से कम है। इस प्रकार, यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि नहीं बढ़ायी जाती है, तो एक भी घरेलू उत्पादक आयात से होड़ करने में समर्थ नहीं होगा तथा उनको भारी नुकसान होगा।

(न) 50 प्रतिशत या अधिक आयात का प्रयोग उस माल का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है जिसका निर्यात किया जाता है। इन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर एडीडी, एस जी डी, बेसिक कस्टम शुल्क तथा सी वी डी से छूट प्राप्त है। उस भाग का लैंडेड मूल्य एन आई पी से कम है।

उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि तकरीबन 50 प्रतिशत आयात शुल्क संदत्त आधार पर है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत सरकार की शुल्क में छूट संबंधी स्कीम के कारण आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि 50 प्रतिशत आयात एंटी डंपिंग शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क के भुगतान पर किया गया है, यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि और बढ़ायी जाती है, तो आयात के लैंडेड मूल्य में पर्याप्त रूप से गिरावट आएगी जिसका आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमत घटानी चाहिए या फिर और अधिक नुकसान उठाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम नहीं करता है, तो घरेलू उत्पाद की कीमत और आयातित उत्पाद की कीमत के बीच महत्वपूर्ण अंतर तथा विदेशी उत्पादकों की भारी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपभोक्ताओं को आयात से अपनी आवश्यकता को पूरा करने से आगे भी रोक पाएगा। वास्तव में, इस उत्पाद के दो सबसे बड़े उत्पादक अर्थात् कोरिया कुम्हो तथा सिनोर्गचेम व्यक्तिगत रूप से भारत की पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ हैं।

(प) समीक्षा में रक्षोपाय शुल्क की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है क्योंकि रक्षोपाय नियमावली के नियम 17 में यह प्रावधान है कि यदि एक वर्ष से अवधि के लिए शुल्क लगाई जाती है, तो उसे उत्तरोत्तर उदार बनाया जाना चाहिए।

पहले दी गई प्रस्तुतियों पर भरोसा किया गया है। पिछली शुल्क नुकसान के अंतर की सीमा तक लगाई गई थी तथा प्रार्थी ने नुकसान के अंतर तक शुल्क लगाने की मांग की है।

(फ) समीक्षा में मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि नियम 18 डी जी एस को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे या तो शुल्क को निरंतर लगाए जाने की सिफारिश करें या फिर समीक्षा में उसे वापस लेने की सिफारिश करें। मात्रात्मक प्रतिबंध मूल अन्वेषण में अपनाए गए उपाय से अधिक प्रतिबंधात्मक होंगे।

मात्रात्मक प्रतिबंध एवं रक्षोपाय शुल्क लगाना रक्षोपाय पर करार के अंतर्गत प्रदत्त दो भिन्न – भिन्न राहें हैं। दोनों को एक की समय पर लगाया जा सकता है या एक के बाद एक को लगाया जा सकता है। यह तथ्य कि उत्पाद पर पहले ही उत्पाद शुल्क लगाई गई है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यदि दोनों उपायों को एक ही समय पर लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से इनको एक के बाद एक के रूप में लगाया जा सकता है। प्रार्थी डी जी एस से अनुरोध करता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि विद्यमान शुल्क के बावजूद आयात में उछाल है तथा मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। इसके पश्चात मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने संबंधी अनुरोध को मात्रात्मक प्रतिबंध प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है।

(ix) कुम्हो पेट्रो केमिकल्स द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर

(क) शुल्क की अवधि समाप्त होने से पूर्व जांच का पूरा होना

- i. हमने अपनी पिछली प्रस्तुतियों में इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से विचार किया है। अपनी पिछली प्रस्तुतियों के अतिरिक्त, जिसमें हमने सूचित किया है कि (1) सोडा ऐश मामले में डी जी एस का निर्णय वर्तमान प्रकरण पर बाध्यकारी है। यह तथ्य कि उस प्रकरण में अंतिम निष्कर्ष अंतिम तारीख से पूर्व जारी किए गए थे, इन इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के निर्णय में पूरी तरह से महत्वहीन है, (2) शुरुआती तौर पर लगाए जाने की तारीख से 6 साल की अवधि बीत जाने के बाद अनेक मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है। हम एक विवरण संलग्न कर रहे हैं जिसमें इन मामलों में सभी विभिन्न संगत तिथियों को दर्शाता है (हमने पहले इन मामलों में केवल कुछ तिथियों को प्रस्तुत किया था। तथापि, अब हम सभी अन्य तिथियां प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि साबित हो कि 6 साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है)।
- ii. जहां तक इच्छुक पक्षकारों द्वारा संदर्भित तुर्की मामले का संबंध है, प्रार्थी का यह निवेदन है कि इस प्रकरण से संबंधित तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की तुलना में पूरी तरह से भिन्न हैं। नीचे दी गई सारणी दोनों प्रकरणों के बीच कुछ संगत अंतर को दर्शाती है (प्रार्थी ने अपनी सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुतियों में ये प्रस्तुतियां दी हैं)।

तुर्की का मामला	भारतीय मामला
प्राधिकारियों ने अंतरिम शुल्क लागू किया। भारत सरकार ने विरोध किया कि समीक्षा के मामले में अंतरिम शुल्क लागू नहीं की जा सकती है।	इस प्रकरण में या इस तरह के अन्य प्रकरणों में डी जी एस द्वारा किसी अंतरिम शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है।
तुर्की के प्राधिकारियों ने भूतलक्षी प्रभाव से रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाई।	भारत द्वारा सोडा ऐश का मामला किया गया जिसमें रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी अवधि बढ़ाई गई थी, इसे केवल भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था।
भारत सरकार ने विरोध किया कि अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 की अपेक्षाओं का पालन किए बगैर शुल्क की सिफारिश की गई है।	डीजीएस ने पालन किया है तथा इस तरह की सभी अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
भारत सरकार ने विरोध किया कि आरंभिक तौर पर शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद शुल्क की अवधि बढ़ाई गई तथा इसे कालातीत होने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाया गया।	पिछली शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद शुल्क की अवधि बढ़ाई जाएगी तथा यह उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत भूतलक्षी प्रभाव से इस तरह की शुल्क की अवधि नहीं बढ़ा रहा है।

iii. देखा जा सकता है कि इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों की समूची प्रस्तुति पूरी तरह से अनुपयुक्त है। इन सबके अलावा, जब भारत सरकार एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि नेमी तौर पर बढ़ा रही है, तो प्रार्थी यह समझने में असमर्थ है कि क्यों वर्तमान प्रकरण में यह मुद्दा प्रासंगिक होना चाहिए। इस संबंध में एंटी डंपिंग कानून एवं रक्षोपाय कानून में कोई अंतर नहीं हो सकता है। हम एंटी डंपिंग मामले के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एक रिट याचिका संलग्न कर रहे हैं। इसमें जो निर्यातक शामिल हैं वह वही निर्यातक हैं जो वर्तमान मामले में शामिल रहा है। देखा जा सकता है कि उन्होंने अब एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में उसी मुद्दे को उठाया है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ये इच्छुक पक्षकार एंटी डंपिंग शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों को एक जैसा मानते हैं परंतु डी जी एस के समक्ष विरोध किया कि प्रावधान/स्थितियां भिन्न हैं। इसके अलावा, इससे भी एंटी डंपिंग शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क के बीच मुद्दे की तुलनीयता प्रदर्शित होती है।

(ख) सुनवाई के पश्चात और प्रस्तुतियों के लिए प्रार्थी को प्रदान किए गए अवसर

महानिदेशक (रक्षोपाय) ने सुनवाई के आयोजन के पश्चात संगत सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग को अवसर प्रदान किया है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। रक्षोपाय अन्वेषण या एंटी डंपिंग अन्वेषण जैसे किसी अन्वेषण में इस तरह की दलील पूरी तरह से निराधार है। वास्तव में डी जी एस ने घरेलू उद्योग को केवल इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई दलील के कारण मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया है। इस संबंध में यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अब घरेलू उद्योग द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई हैं उन्हें संयंत्र की क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई पिछली प्रस्तुति की सत्यता स्थापित करने के संबंध में दिए गए निर्देश की वजह से दिया गया है। घरेलू उद्योग ने पहले कहा था कि उसकी क्षमता 14000 मीट्रिक टन है। प्रार्थी के कथन का विरोध इच्छुक पक्षकारों द्वारा किया गया और इसलिए डी जी एस ने उचित रूप में घरेलू उद्योग को यह निर्देश देने का निर्णय लिया था कि घरेलू उद्योग अपने कथन की सत्यता स्थापित करे। घरेलू उद्योग ने नए तथ्यों को रिकार्ड में लाया है। घरेलू उद्योग ने अपने पिछले कथन के समर्थन में केवल साक्ष्य / औचित्य / दलील प्रस्तुत की कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कंपनी की क्षमता 14000 मीट्रिक टन है।

(ग) मूल अन्वेषण के समय डी जी एस को सूचित समायोजन योजना भिन्न थी

घरेलू उद्योग द्वारा अब जो समायोजन योजना प्रस्तुत की गई है वह उस समायोजन योजना से भिन्न है जिसे घरेलू उद्योग ने मूल अन्वेषण के समय डी जी एस को सूचित किया था। प्रार्थी का यह कहना है कि इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। यह पूरी तरह से भ्रामक कथन है। पिछले अंतिम निष्कर्षों में डी जी एस ने निम्नानुसार कहा था :

278. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना बढ़ती मांग को पूरा करने तथा लागत में कटौती के लिए क्षमता के विस्तार पर केंद्रित है।

279. प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वे आयात से उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उत्पादन की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। अन्य भारतीय उत्पादकों की क्षमता के साथ घरेलू उद्योग की विस्तारित क्षमता आयात के साथ उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। प्रार्थी घरेलू उद्योग ... करोड़ रुपये की लागत से ... मीट्रिक टन तक अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। 30 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार ... करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की गई है। उक्त राशि में से ... करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। उम्मीद है कि मार्च, 2012 में विस्तार कार्य पूरा हो जाएगा तथा अप्रैल, 2012 से उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

280. प्रार्थी ने दावा किया है कि इस विस्तार से कम से कम ... रुपये प्रति किग्रा लागत में बचत होगी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को उम्मीद है कि जब वे बाजार में अधिक माल बेचने में समर्थ होंगे, तो ओवरहेड लागत की मद में लागत की कटौती हो सकती है।

281. पुनर्गठन योजना का ब्यौरा मंगाया गया। देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में विस्तार पर सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र तथा नए संयंत्र के लिए व्यय तथा किए गए व्यय पर अभ्यासी लागत लेखाकार प्रमाण पत्र एवं लागत में कटौती का दावा प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी की समायोजन योजना तर्कसंगत एवं व्यवहार्य है।

282. शुल्क को क्रमिक रूप से उदार बनाने के लिए समायोजन योजना पर विचार किया गया है। जैसा कि डी जी एस को सूचित किया गया है, प्रार्थी ने उसी समायोजन योजना को निष्पादित किया है। इस संबंध में, यहां इस बात का उल्लेख करना संगत है कि समायोजन योजना में इन सुविधाओं पर तकरीबन 250 करोड़ रुपये का निवेश करने की परिकल्पना थी। कंपनी के समग्र प्रचालन में यह निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा किसी भी रूप में ऐसा मामला नहीं बनता है कि कंपनी पहले किसी भिन्न समायोजन योजना का निर्माण करे और अब दूसरी समायोजन योजना का निर्माण करे।

(घ) क्षमता बनाम सक्षमता

केपीसी ने अब इस बात का उल्लेख किया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रार्थी 4 ए डी पी ए का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में समर्थ (अर्थात् सक्षम) है ताकि वह उक्त माल के 14000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर सके तथा विचाराधीन उत्पाद के 14000 मीट्रिक टन के विनिर्माण के लिए वास्तविक क्षमता का कोई संकेत नहीं है। प्रार्थी का यह कहना है कि क्षमता एवं सक्षमता दो अलग-अलग पैरामीटर हैं। इच्छुक पक्षकारों द्वारा जो मुद्दा विवादित है वह संयंत्र की क्षमता के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा 14000 मीट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन के संबंध में मुद्दा कभी नहीं रहा। जब प्रार्थी अपनी पुरानी क्षमता की सीमा तक भी सामग्री का उत्पादन करने एवं आपूर्ति करने में समर्थ नहीं हुआ है तो पी एक्स 13 के उत्पादन की 14000 मीट्रिक टन क्षमता प्राप्त करने या पूरी मात्रा में 4 ए डी पी ए का उत्पादन करने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रार्थी केवल उस हद तक उत्पादन कर सकता है जिस हद तक वह इसकी बिक्री कर सकता है। इसके अलावा, प्रार्थी 4 ए डी पी ए का उत्पादन केवल उस हद तक करेगा जिस हद तक वह इसका उत्पादन कर सकता है तथा पी एक्स 13 की बिक्री कर सकता है। प्रार्थी इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री का उत्पादन और भंडारण नहीं कर सकता है। तथ्य यह है कि उत्पाद का आयात बड़ी मात्रा में इस हद तक होता रहा है कि प्रार्थी कभी भी इस हद तक उत्पादन करने में समर्थ नहीं हुआ जिस हद तक वह उत्पादन कर सकता है।

तथापि, यह तथ्य कि प्रार्थी पहले प्रति चक्र 160 मिनट का समय लेकर पी एक्स 13 का उत्पादन कर रहा था और यह तथ्य कि प्रार्थी अब प्रति चक्र 90 मिनट का समय लेकर पी एक्स 13 का उत्पादन कर रहा है, यह प्रार्थी द्वारा पहले उपलब्ध कराया गई लॉग शीट की प्रतियों से स्थापित होता है। इस प्रकार, प्रार्थी ने 14000 मीट्रिक टन की सीमा तक पी एक्स 13 का उत्पादन करने की अपनी क्षमता स्थापित की है जिसके लिए स्थापित किया गया है कि उसका एल्लिकेशन चक्र समय अब 90 मिनट है, जबकि पहले यह 160 मिनट था। ऐसा मामला होने के नाते यह स्थापित है कि प्रार्थी उत्पाद का 14000 मीट्रिक टन उत्पादन करने में समर्थ होगा, यदि वह इसे बेचने में समर्थ होता है।

(ङ.) रक्षोपाय शुल्क की अवधि के दौरान समायोजन योजना के लिए उठाए गए कदम

केपीसी ने दावे के साथ कहा है कि रक्षोपाय झूड़ी की अवधि के दौरान प्रार्थी को सकारात्मक समायोजन की दिशा में कदम उठाना चाहिए था तथा इसके बाद उठाया गया कोई भी कदम अप्रासंगिक है। इस संबंध में निम्नलिखित संगत है।

i) सबसे पहले, इस दलील का कोई कानूनी आधार नहीं है। नियम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि प्रार्थी को रक्षोपाय शुल्क की अवधि के दौरान कदम उठाना चाहिए था। इसके वितपरीत कोरिया - डेरी मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया है कि रक्षोपाय पर करार का अनुच्छेद 5.1 समायोजन योजना पर विचार करने का दायित्व थोपता है। पैनल ने निम्नवत कहा है:

"... हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 5.1 की व्याख्या इस रूप में नहीं करते हैं कि यह प्राधिकारियों द्वारा किसी समायोजन योजना पर विचार करने की अपेक्षा रखता है ... पैनल ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा प्राप्त नहीं करता है कि समायोजन योजना जैसी किसी योजना के लिए रक्षोपाय पर करार के पाठ में अनुरोध किया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इसके दो प्रावधानों में उद्योग समायोजन का उल्लेख है, रक्षोपाय पर करार के पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव दे कि किसी उपाय को अपनाने से पूर्व किसी विशिष्ट समायोजन योजना पर विचार करने की जरूरत होती है। इसकी बजाय, हमारा यह मानना है कि गंभीर नुकसान को रोकने या निदान करने के प्रश्न के साथ समायोजन का प्रश्न उपाय के बारे में प्राधिकारियों के कारण सहित व्याख्या का अंग होना चाहिए, यदि उसे लागू करने का विकल्प चुना गया है। फिर भी हम नोट करते हैं कि किसी रक्षोपाय शुल्क को लागू करने के संदर्भ में किसी समायोजन योजना की जांच इस बात का मजबूत साक्ष्य होगी कि प्राधिकारियों ने इस बात पर विचार किया कि क्या उपाय गंभीर नुकसान को रोकने या निदान करने के उद्देश्य के अनुपातिक है तथा समायोजन में सुविधा प्रदान कर रहा है..."

ii) इस प्रकार, नियमावली के तहत एकमात्र अपेक्षा यह है कि जहां रक्षोपाय शुल्क की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, डी जी एस उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करेंगे जो सकारात्मक समायोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए रक्षोपाय शुल्क की दृष्टि से पर्याप्त हो।

iii) दूसरी बात यह है कि प्रार्थी ने बताया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए वह कदम उठा रहा है जिसके लिए प्रार्थी को अपना कच्चा माल 4 एन डी पी ए से बदलकर 4 ए डी पी ए करने के लिए एक अन्य संयंत्र लगाना था। 4 ए डी पी ए संयंत्र दाहेज में स्थापित किया जाना चाहिए। प्रार्थी ने 29 अगस्त, 2013 को शुल्क की अवधि समाप्त होने तक इन सभी कदमों को उठाया है। वास्तव में, प्रार्थी ने दिसंबर, 2012 में ट्रायल उत्पादन शुरू किया तथा वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2013 में शुरू किया जिससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रार्थी द्वारा रक्षोपाय शुल्क की अवधि के दौरान कदम उठाए गए हैं।

(x) ए टी एम ए द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर

(क) प्रार्थी ने अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है

पहले दी गई प्रस्तुतियों पर भरोसा किया गया है। यह साक्ष्य कि एल्किलेशन समय चक्र 160 मिनट से घटकर 90 मिनट हो गया है, स्वयं स्थापित करता है कि प्रार्थी ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। जबकि प्रार्थी पहले कच्चे माल के रूप में 4 एन डी पी ए का उपयोग करके एल्किलेशन में लगभग 160 मिनट का समय ले रहा था, परंतु वह कच्चा माल के रूप में 4 ए डी पी ए का प्रयोग करके एल्किलेशन में 90 मिनट का समय ले रहा है। इस प्रकार, प्रार्थी की क्षमता 8500 मीट्रिक टन से बढ़कर 14000 मीट्रिक टन हो गई है।

(ख) निर्यात की मात्रा में गिरावट से उत्पादन में गिरावट आई है

i. संदर्भाधीन पत्रों में घरेलू उद्योग द्वारा जिस मुद्दे का समाधान किया गया है वह घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में वृद्धि से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने इन पत्रों में किसी अन्य मुद्दे का समाधान नहीं किया है। इसके अलावा, निर्यात में गिरावट के मुद्दे का समाधान पहले ही घरेलू उद्योग द्वारा किया जा चुका है।

ii. पांच वर्ष की अवधि के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाने के मुद्दे का समाधान धारा 9 क (5) के अंतर्गत विस्तार प्रावधान द्वारा किया जा सकता है। 6 वर्ष की अवधि के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाना ऐसा मुद्दा है जो वर्तमान प्रकरण में इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे से मिलता – जुलता है। देखा जा सकता है कि भारत सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यह है कि 6 साल के बाद शुल्क की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एंटी डंपिंग की दृष्टि से इस तरह का मामला होने की वजह से प्रार्थी को उम्मीद है कि रक्षोपाय शुल्क पर स्थिति भिन्न हो सकती है।

iii. जहां तक घरेलू उद्योग के पास पी एक्स 13 की क्षमता का संबंध है, घरेलू उद्योग ने एक स्वतंत्र सनदी इंजीनियर से एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि कंपनी की क्षमता पहले 8500 मीट्रिक टन थी तथा वही क्षमता आज 14000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस प्रमाण पत्र में विस्तार से बताया गया है कि कैसे क्षमता का निर्धारण किया गया है तथा कहां संयंत्र में क्षमता अवरूद्ध है। सनदी इंजीनियर ने प्रक्रिया में शामिल वर्तमान एल्किलेशन समय को भी प्रमाणित किया है।

(ग) जहां तक इच्छुक पक्षकारों द्वारा संदर्भित तुर्की मामले का संबंध है, प्रार्थी का यह निवेदन है कि इस प्रकरण से संबंधित तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की तुलना में पूरी तरह से भिन्न हैं। नीचे दी गई सारणी दोनों प्रकरणों के बीच कुछ संगत अंतर को दर्शाती है (प्रार्थी ने अपनी सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुतियों में ये प्रस्तुतियां दी हैं)।

तुर्की का मामला	भारतीय मामला
प्राधिकारियों ने अंतरिम शुल्क लागू किया। भारत सरकार ने विरोध किया कि समीक्षा के मामले में अंतरिम शुल्क लागू नहीं की जा सकती है।	इस प्रकरण में या इस तरह के अन्य प्रकरणों में डी जी एस द्वारा किसी अंतरिम शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है।
तुर्की के प्राधिकारियों ने भूतलक्षी प्रभाव से रक्षोपाय शुल्क की अवधि बढ़ाई।	भारत द्वारा सोडा ऐश का मामला किया गया जिसमें रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी अवधि बढ़ाई गई थी, इसे केवल भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था।
भारत सरकार ने विरोध किया कि अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 की अपेक्षाओं का पालन किए बिना शुल्क की सिफारिश की गई है।	डीजीएस ने पालन किया है तथा इस तरह की सभी अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
भारत सरकार ने विरोध किया कि आरंभिक तौर पर शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद शुल्क की अवधि बढ़ाई गई तथा इसे कालातीत होने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाया गया।	पिछली शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद शुल्क की अवधि बढ़ाई जाएगी तथा यह उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत भूतलक्षी प्रभाव से इस तरह की शुल्क की अवधि नहीं बढ़ा रहा है।

(घ) देखा जा सकता है कि इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों की समूची प्रस्तुति पूरी तरह से अनुपयुक्त है। इन सबके अलावा, जब भारत सरकार एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि नेमी तौर पर बढ़ा रही है, तो प्रार्थी यह समझने में असमर्थ है कि क्यों वर्तमान प्रकरण में यह मुद्दा प्रासंगिक होना चाहिए। इस संबंध में एंटी डंपिंग कानून एवं रक्षोपाय कानून में कोई अंतर नहीं हो सकता है। हम एंटी डंपिंग मामले के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एक रिट याचिका संलग्न कर रहे हैं। इसमें जो नियंतक शामिल है वह वही नियंतक है जो वर्तमान मामले में शामिल रहा है। देखा जा सकता है कि उन्होंने अब एंटी डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में उसी मुद्दे को उठाया है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ये इच्छुक पक्षकार एंटी

डंपिंग शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों को एक जैसा मानते हैं परंतु डी जी एस के समक्ष विरोध किया कि प्रावधान/स्थितियां भिन्न हैं। इसके अलावा, इससे भी एंटी डंपिंग शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क के बीच मुद्दे की तुलनीयता प्रदर्शित होती है।

(क) डीजीएस के निष्कर्ष :

विभिन्न पक्षकारों द्वारा तथा घरेलू उद्योग द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर वर्तमान आदेश में विचार किया गया है। इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर में दी गई प्रस्तुतियों पर भी समुचित रूप से

23. महानिदेशक रक्षोपाय के जांच परिणाम

मैंने इस समीक्षा प्रक्रिया के मामलों के अभिलेख और घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकारों से प्राप्त उत्तरों का गंभीरता से अध्ययन किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस समीक्षा में उचित स्थानों पर समाधान कर दिया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की घरेलू विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ के अंतर्गत जांच की गई है। तदनुसार ही अपने जांच परिणाम दिए गए हैं।

सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का विवरण दिया है। धारा 8ख (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है जिसका भारत संबंधित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता रहा हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति करने की आशंका उत्पन्न हो गई हो।

सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले तरीकों एवं सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। यह नियम सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के अंतर्गत बनाए गए है। मुझे इन नियमों के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि मैं विधि के अनुसार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करूं।

रक्षोपाय संबंधी करार एवं डब्ल्यूटीओ निकायों के निर्णयों द्वारा किए गए प्रावधानों का उपयुक्त स्थानों पर उल्लेख किया गया/ चर्चा की गई। यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई है और इस अधिसूचना के जरिए अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किए गए हैं।

25. संक्षिप्त इतिवृत्त : मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में रबड़ रसायनों पीएक्स-13 के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया कि पीएक्स-13 के संबंधित आयात भारत में पीएक्स-13 घरेलू उत्पादों को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं और/या गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर रहे और इस आवेदनपत्र के आधार पर महानिदेशक (रक्षोपाय) ने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत एक जांच प्रारंभ की थी। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 की सभी अपेक्षाएं तत्रैव पूरी होती हैं, इसलिए पीएक्स-13 के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 की जांच शुरूआत अधिसूचना नोटिस के तहत जांच प्रारंभ की गई।

25.1 इस मामले में जांच के पश्चात महानिदेशक (रक्षोपाय) ने 6 जून, 2011 को अंतिम जांच परिणाम जारी किया जिसे रक्षोपाय संबंधी स्थायी बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 29 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 83/2011-सीमाशुल्क (एसजी) के तहत एक रक्षोपाय शुल्क 2 वर्षों के लिए उदग्रहित किया गया। यह रक्षोपाय शुल्क 29 अगस्त, 2013 तक प्रभावी है। यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग द्वारा रक्षोपाय शुल्क की मौजूदा शुल्क की समाप्ति की तारीख से दो अन्य वर्षों की अवधि के लिए, निरंतरता बनाए रखने/उसका विस्तार करने के लिए दायर किया गया है जिससे कि घरेलू उद्योग अपनी अतिजीविता के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सके। रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह रक्षोपाय समीक्षा जांच सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16 और नियम 18 के साथ पठित सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है।

26. घरेलू उद्योग : मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड, नवी मुंबई भारत में घरेलू उद्योग है जो उन रबड़ रसायनों अर्थात् पीएक्स-13 या 6 पीपीडी का विनिर्माण करती है। आवेदक उत्पादक का भारत में पीएक्स-13 के कुल उत्पादन में 61.60 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक के घरेलू उद्योग के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। अतः, यह धारित किया जाता है कि आवेदक रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 की धारा 8 ख(6) (ख) (iii) के अंतर्गत यथापारिभाषित और उसके आशय के अंतर्गत यथापेक्षित घरेलू उद्योग है और वह घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।

27. अन्वेषण के अधीन उत्पाद : अन्वेषण के अधीन उत्पाद रबर केमिकल है जिसे पी एक्स 13 या 6 पी पी डी कहा जाता है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 18 के अंतर्गत शीर्ष 3812, 3813 के अंतर्गत तथा 2921, 2925, 2934 और 2942 (6 डिजिट स्तर पर) के अंतर्गत आता है। इसका उत्पादन एक नोबल मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में संयत रूप से उच्च दाब पर एक आटोक्लेव में 4 एन डी पी ए और एमआईबीके के मिश्रण के हाइड्रो जेनेशन द्वारा होता है। परिणामी रिएक्शन मास, जिसमें अनरिएक्टेड किटोन, उपोत्पाद आदि होते हैं, को कैटलिस्ट को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है और उसे फिर रिसाइल किया जाता है। लो बायलर को हटाने के लिए फिल्ट्रेट को डिस्टिल किया जाता है और फिर फिनिश उत्पाद प्रदान करने के लिए फ्लेक किया जाता है। अनरिएक्टेड किटोन प्राप्त करने के लिए लो बायलर को फिर से डिस्टिल किया जाता है। जब तक गतिविधि घट नहीं जाती है तब तक कैटलिस्ट को रिसाइल किया जाता है। इसके बाद उसे सिस्टम से हटाया जाता है। प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (एस डी आर, बूटाडिन रबर, नाइट्राइल रबर और कार्बोक्सिलेटेड रबर) तथा

विभिन्न रबर उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य सिंथेटिक रबर आधारित यौगिकों के शोधन में बड़े पैमाने पर पी एक्स 13 का प्रयोग किया जाता है। पी एक्स 13 के मुख्य कच्चे माल इस प्रकार हैं— (क) 4 एन डी पी ए, (ख) एम आई बी के, (ग) केटलिस्ट और (घ) हाइड्रोजन। अन्वेषण के अधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसलिए यह पक्का है कि अन्वेषण के अधीन उत्पादन पी एक्स 13 या 6 पी पी डी नामक रबर केमिकल है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 2921, 2925, 2934 और 2942 (6 डिजिट के स्तर पर) के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, आयातित पी एक्स 13 और घरेलू स्तर पर उत्पादित पी एक्स 13 के बीच उत्पादन की प्रक्रिया, विशेषताओं या अंतिम प्रयोगों के बारे में इस अन्वेषण की अवधि के दौरान किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा किसी भिन्नता का मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसलिए यह भी माना जाता है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पी एक्स 13 हर दृष्टि से अन्वेषण के अधीन आयातित उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा या समान परिधि में आता है और यह कि घरेलू स्तर पर उत्पादित पी एक्स 13 सुरक्षोपाय ज्यूटी नियमावली, 1997 के नियम 2 (ड.) के अर्थ के अंदर आयातित पी एक्स 13 के समान वस्तु है।

28. रबर केमिकल एन1, 3 डी मिथाइल ब्रिटिल— एन फिनायल नेडिमिन जिसे पी एक्स 13 या 6 पी पी डी के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर सुरक्षोपाय ज्यूटी जारी रखने / अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एन ओ सी आई एल लिमिटेड, पावने गांव, नवी मुंबई द्वारा आवेदन दिनांक 31 जुलाई, 2013 को दाखिल किया गया है।

29. अन्वेषण की अवधि (पी ओ आई) :

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमा-शुल्क टैरिफ (सुरक्षोपाय ज्यूटी की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997, सुरक्षोपाय पर करार तथा जी ए टी टी के संगत अनुच्छेद 19 विशिष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं करते हैं कि अन्वेषण की अवधि क्या होनी चाहिए। सुरक्षोपाय ज्यूटी पर अनेक प्रकरण कानूनों से स्पष्ट है कि न तो सुरक्षोपाय पर घरेलू कानून और न ही सुरक्षोपाय पर करार तथा जी ए टी टी के अनुच्छेद 19 में अन्वेषण की अवधि पर कोई विशिष्ट दिशानिर्देश है, केवल यह तथ्य है कि संगत अन्वेषण की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए ताकि आयात में वृद्धि एवं गंभीर नुकसान के बारे में अंजाम पर पहुंचा जा सके। अन्वेषण आरंभ करने की नोटिस में 2009-10 से 2012-13 के आयात डेटा पर विचार किया गया था। इसलिए अन्वेषण की अवधि 2009-10 से 2012-13 तक की ली गई है। इसके अलावा, अस्थायी उतार— चढ़ाव के प्रभावों एवं मौसमी प्रभावों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए तर्कसंगत रूप से लंबी अवधि पर विचार किया गया है।

30. डेटा का स्रोत : 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए आयात डेटा को आई बी आई एस से लिया गया है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा मार्च, 2013 की अपनी याचिका में प्रस्तुत विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित डेटा का सत्यापन इस निदेशालय द्वारा संभव सीमा तक किया गया है तथा नुकसान के विश्लेषण के लिए सत्यापित डेटा पर विचार किया गया है। 2009-10 से 2012-13 के लिए डेटा निदेशालय को परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थी यूनिट के ई आर-1 की प्रतिलिपियों से लिया गया है तथा संकलित किया गया है।

समीक्षा अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण

31. मैंने पाया कि कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए समीक्षा प्रक्रिया घरेलू उद्योग के इस तर्क के विपरीत कि यह अपेक्षा उक्त उपबंधों के अंतर्गत स्पष्टतः या अन्यथा अपेक्षित नहीं है। उक्त रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले पूरी कर ली गई थी जैसा कि रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 18 के उपबंधों में प्रावधान किया गया है।

31.1 उपर्युक्त के मद्देनजर समीक्षा से संबंधित संगत विधिक स्थिति/अपेक्षा को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है :

82. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(4)

"इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है, तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा :

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि घरेलू उद्योग इस क्षति या उसकी चुनौती का समायोजन करने के लिए उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण रहना जारी रहना चाहिए तो यह ऐसे अधिरोपण की अवधि में विस्तार कर सकती है।

83. धारा 8ख (4) में निम्नलिखित दो शर्तों का प्रावधान है जिसे रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि में विस्तार करते वक्त पूरा किए जाने की जरूरत है।

क. घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन के लिए किए गए प्रयास;

ख. रक्षोपाय शुल्क की अवधि में विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता बनी रहनी चाहिए।

31.2 इसके अतिरिक्त सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :

18 समीक्षा

1. महानिदेशक रक्षोपाय , समय-समय पर रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करेंगे और यदि वह उनको प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हो जाते हैं कि;

- (i) गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका उपचार करने के लिए रक्षोपाय शुल्क आवश्यक है और इस बात के साक्ष्य हैं कि उद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा है, तो वे केंद्रीय सरकार को शुल्क के सतत अधिरोपण की सिफारिश कर सकते हैं।

- (ii) ऐसे शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए कोई औचित्य नहीं है; इसकी वापसी के लिए केंद्रीय सरकार से सिफारिश कर सकते हैं परंतु यह कि जहां रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि तीन वर्षों से अधिक हो जाती है वहां महानिदेशक ऐसे अधिरोपण की मध्यावधि से अनधिक स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि उचित हुआ तो उस रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को वापस लेने अथवा उसका उदारीकरण करने की सिफारिश करेंगे।"

2. उपनियम (1) के अंतर्गत प्रारंभ की गई कोई समीक्षा, उस समीक्षा के प्रारंभ की तारीख से 8 माह की अनधिक अवधि के अंतर्गत या ऐसी संवर्धित अवधि के अंतर्गत जिसकी केंद्रीय सरकार अनुमति दे, उस समीक्षा का निष्कर्ष निकाला जाएगा।

3. इस समीक्षा के मामले में नियम 5,6,7 और 11 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

32. घरेलू उद्योग ने सुनवाई के पश्चात अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि चूंकि नियम 18 में नियम 5,6,7 और 11 की यथावश्यक परिवर्तनों सहित अनुप्रयोज्यता का प्रावधान किया गया है इसलिए इस संबंध में "म्यूटैरिस म्यूटेंडिस" का आशय समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अशोक सर्विस सेंटर तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया है जिसके द्वारा वे दावा करते हैं कि वर्तमान मामले में, यद्यपि नियम 18 में कतिपय उपबंधों की अनुप्रयोज्यता का प्रावधान है : परंतु अभिव्यक्ति यथावश्यक परिवर्तनों सहित यह स्पष्टतः सिद्ध करती है कि अधिनियम अर्थात् सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(4) के अभिव्यक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इन उपबंधों को अनुप्रयोज्य बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि किसी साधन में विस्तार केवल तभी किया जा सकता है जब यह उपपादित होता हो कि एक नवीन जांच के जरिए इसकी निरंतरता गंभीर क्षति का निवारण करने उसका उपचार करने के लिए जरूरी है और यह केवल तभी किया जा सकता है जब साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता हो कि घरेलू उद्योग समायोजन कर रहा है। रक्षोपाय शुल्क जांच का विस्तार करने के लिए संवर्धित आयात भी एक पूर्वापेक्षा है।

33. मामले की तदनुसार जांच की गई है। मेरा विचार है कि विधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की मौजूदगी होना भी आवश्यक है। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निर्धारण का विश्लेषण करने के लिए यह महत्वपूर्ण कारक का निर्धारण करना आवश्यक है कि क्या रक्षोपाय समीक्षा जांच के दौरान मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की निरंतरता रखी जाए या नहीं। दूसरे घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन के संबंध में दिया गया साक्ष्य मूर्त प्रवृत्ति का होना चाहिए। इन प्रावधानों का सघन अध्ययन यह अभिव्यक्ति करता है कि प्रार्थी घरेलू उद्योग को सकारात्मक समायोजन के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वह शुल्क के सतत अधिरोपण की सिफारिश करने में सक्षम हो सके। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 16(1) में यह उल्लेख है कि नियम 12 के अंतर्गत अधिरोपित शुल्क ऐसी अवधि के लिए होगा जिससे कि गंभीर क्षति का निवारण या उपचार हो सके और सकारात्मक समायोजन सुलभ हो सके। इसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क के जरिए संरक्षण प्राप्त होने के अनुरूप सकारात्मक समायोजन प्रारंभ करना चाहिए। अतः, क्या यह निर्धारण विगत के मामलों के अनुरूप है और/या अंतर्राष्ट्रीय विधि/एओएस स्तर के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ तथा भारत की स्थिति के अनुरूप हो।

34. क्या संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई

मैंने पाया कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 की अवधि वह अवधि है जब रक्षोपाय शुल्क लगा था। तथापि, उक्त अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण निम्नलिखित है :

35. **संवर्धित आयात (संगत एवं समग्र रूप से) :** पीएक्स-13 या 6 पीपीडी का भारत को कई देशों से और प्राथिकतः कोरिया गणराज्य से आयात किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के आभावों की प्रमात्रा निम्नलिखित है :

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उत्पादन (एमटी)	उत्पाद के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2009-10	10090	7264	139
2010-11	10607	6672	159
2011-12	9735	5408	180
2012-13	11664	4732	246

ऐसा प्रतीत होता है कि आधार वर्ष अर्थात् वर्ष 2009-10 में 10090 एमटी के आयातों तथा पिछले वर्ष 2011-12 में हुए 9735 एमटी के आयातों से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 में आयातों में समग्र रूप से वृद्धि होकर 11666 एमटी हो गए। इन आयातों में उत्पादन के संबंध में भी तीव्र वृद्धि हुई अर्थात् आधार वर्ष के लगभग 107 प्रतिशत की भारी वृद्धि की तुलना में 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में लगभग 66 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अतः यह स्पष्ट है कि इन आयातों में उस अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जब इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगा था।

36. **क्षति विश्लेषण :** घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

रबर केमिकल एन1, 3-डिमिथाइल बूटिल – एन फेनिलेनिडिमाइन जिसे पी एक्स 13 या 6 पी पी डी के नाम से भी जाना जाता है

वित्त वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल आयात (मीट्रिक टन में)	10090	10607	9735	11664
रुझान	100	105	96	116
घरेलू उद्योग का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	7264	6672	5408	4732
रुझान	100	92	74	65
उत्पादन के अनुपात में आयात (प्रतिशत में)	139	159	180	246
मांग के अनुपात में आयात (प्रतिशत में)	69	67	61	66
अन्य उत्पादकों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	1100	1645	2578	2388
रुझान	100	150	234	217
निर्यात (मीट्रिक टन में)	3656	2768	2079	1359
रुझान	100	76	57	37
घरेलू उद्योग की बिक्री (मीट्रिक टन में)	3516	3697	3641	3701
रुझान	100	105	104	105
अन्य उत्पादकों की बिक्री (मीट्रिक टन में)	1100	1645	2578	2388
कुल खपत (मीट्रिक टन में)	14706	15949	15954	17753
घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	24	23	23	21
आयात की बाजार में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	69	67	61	66
संस्थापित क्षमता (मीट्रिक टन में)	8500	8500	8500	8500
क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	87	79	64	56
नियोजन (संख्या)	18	18	18	16
प्रतिदिन उत्पादकता (मीट्रिक टन में)	21	19	15	14
इंवेन्ट्री (मीट्रिक टन में)	328	532	257	238
लाभ / हानि (लाख रुपए में)	753	605	(260)	(1507)
रुझान	100	(80)	(35)	(200)

37. बाजार में हिस्सेदारी : उक्त उत्पाद के कुल उत्पादन एवं घरेलू खपत में घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी का विश्लेषण नीचे दी गई सारणी में किया गया है। आयात की बाजार में हिस्सेदारी 2011-12 में 61 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 66 प्रतिशत हो गई है। घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी 2011-12 में 23 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 21 प्रतिशत हो गई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी 2011-12 में 3641 मीट्रिक टन से बढ़कर 2012-13 में 3701 मीट्रिक टन हो गई है।

38. उत्पादन : घरेलू उद्योग से संबंधित उत्पादन के संबंध में सांख्यिकी ऊपर दी गई सारणी में प्रस्तुत की गई। घरेलू उत्पादन 2011-12 में 5408 मीट्रिक टन से घटकर 2012-13 में 4732 मीट्रिक टन हो गया है।

39. क्षमता का उपयोग : घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान गिरावट की रुझान का प्रदर्शन किया है। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षमता उपयोग के संबंध में सांख्यिकी यहां नीचे सारणी में दर्शाई गई है:

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)	मालसूची (एमटी)
2009-10	7264	8500	87%	328
2010-11	6672	8500	79%	532
2011-12	5408	8500	64%	257
2012-13	4732	8500	56%	238

40. मालसूची : उपर्युक्त तालिका मालसूची के स्तर को दर्शाती है जिसमें वर्ष 2011-12 के 257 से सुधार होकर वर्ष 2012-13 में 238 हो गई।

41. घरेलू बिक्री : उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि घरेलू बिक्री वर्ष 2012-13 में 3701 एमटी थी, जबकि पिछले वर्ष यह 2079 एमटी थी। इस प्रकार निर्यात विगत वर्ष 2079 एमटी के स्तर से वर्ष 2012-13 में 1359 एमटी हो गए थे।

42. रोजगार : क्षति अवधि में रोजगार और उत्पादकता के स्तर में भारी परिवर्तन नहीं आया, परंतु वर्ष 2011-12 की तुलना में इसमें वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है।

43. लाभ एवं हानि (नकद लाभ) : घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तेजी से इस हद तक गिरावट आई कि अब घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। वर्ष 2012-13 में घाटे में वृद्धि हुई है। यह घाटा वर्ष 2011-12 में -35 (अनुक्रमित) तथा बढ़कर वर्ष 2012-13 में -200 (अनुक्रमित) हो गया।

44. उत्पादकता : घरेलू उद्योग को उत्पादकता में पिछले वर्ष 2011-12 और आधार वर्ष 2009-10 दोनों की तुलना में कमी आई है।

45. मांग की तुलना में आयात : विगत वर्ष 2011-12 की तुलना में मांग के संबंध में आयातों में वर्ष 2012-13 में 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

46. निर्यात : निर्यात सेगमेंट में घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष तथा विगत वर्ष से तुलना करने पर अत्यधिक अभिनव अवधि वर्ष 2012-13 में तीव्र गिरावट आई है।

47. घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति :

उपर्युक्त किए गए संपूर्ण विश्लेषण से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन निर्यात, क्षमता उपयोग, रोजगार और उत्पादकता के क्षेत्र में निष्पादन में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक कमी आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में मामूली सी वृद्धि हुई है। मालसूची की स्थिति में भी सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायता में वर्ष 2012-13 की अभिनव अवधि में, आधार वर्ष से तुलना करने पर तथा विगत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 की तुलना करने पर, भारी गिरावट आई है। पुनः यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। यह वर्ष 2011-12 के 23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 21 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्सा 61 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया।

47.1 इस प्रकार, लगभग उन सभी संगत तथ्यों के आलोक में, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, घरेलू उद्योग का समग्र स्थिति का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में भारी परिक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के संबंधित आयातों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है और घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बाजार हिस्से में गिरावट तथा आयातों में समग्र एवं संगत रूप से समानरूपी तीव्र वृद्धि के कारण भारी क्षति हुई है, इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की गंभीर चुनौती भी उत्पन्न हो गई है।

48. समायोजन योजना : चूंकि रक्षोपाय शुल्क के विस्तार/निरंतरता की मांग करते हुए यह एक समीक्षा मामला है, इसलिए इस मामले में समायोजन योजना का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं उपपादित करता हूं कि घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान किए गए सकारात्मक प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है :

48.1. घरेलू उद्योग ने मूल जांच के लिए प्रस्तुत अपने आवेदनपत्र में निम्नलिखित समायोजन योजना प्रस्तुत की है :

"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा * एमटी रबड़ रसायन तथा मध्यवर्तियों, जिनमें पीएक्स-13 एक उत्पाद के रूप में शामिल है, का उत्पादन करने का है।** इस संयंत्र में कुल *** रुपए के अनुमानित व्यय पर *** एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग *** करोड़ रुपए है जो क्रियान्वयन के स्तर पर है। कंपनी को आशा है कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में किसी भी समय प्रारंभ हो सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता में लगभग तीन वर्षों के दौरान पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो जाएगा। अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं और पीएक्स-13 निर्यातों की तुलना में आयातों में और मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र की संबंधित क्षमता देश में पीएक्स-13 की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।"

48.2. महानिदेशक रक्षोपाय ने दिनांक 6 जून, 2011 के अपने अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित समायोजन योजना का उल्लेख किया है।

"34. भारतीय उत्पादकों ने एक समायोजन योजना बनाई है जो (क) लागत कटौती (ख) मौजूदा उत्पादन क्षमता का और अधिक उपयोग (ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार पर प्रकाश डालती है।

35. प्रार्थी उद्योग अर्थात् एनओसीआईएल **"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा *** एमटी रबड़ रसायन तथा मध्यवर्तियों, जिनमें पीएक्स-13 एक उत्पाद के रूप में शामिल है, का उत्पादन करने का है।** ऐसा उल्लेख किया गया है कि यह परियोजना मार्च, 2012 से चलना प्रारंभ हो जाएगी और अप्रैल, 2012 से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्य का विवरण देते हुए एक सनदी इंजीनियर से प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया कि बहुत संभव है कि उत्पादन अप्रैल 2012 में प्रारंभ हो जाए।"

48.3. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् घरेलू उद्योग ने एक लिखित प्रस्तुतिकरण में उपर्युक्त समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया है :

प्रार्थी पुनः उल्लेख करते हैं कि "एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा *** एमटी रबड़ रसायन तथा मध्यवर्तियों, जिनमें पीएक्स-13 एक उत्पाद के रूप में शामिल है, का उत्पादन करने का है। इस संयंत्र में कुल *** रुपए के अनुमानित व्यय पर *** एमटी पीएक्स-13 का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग *** करोड़ रुपए है जो क्रियान्वयन के स्तर पर है। कंपनी को आशा है कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2013 में प्रारंभ हो जाएगा।

कंपनी को उम्मीद है कि यह संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता में लगभग तीन वर्षों के दौरान पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो जाएगा। अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं और पीएक्स-13 निर्यातों की तुलना में आयातों में और मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र की संवर्धित क्षमता देश में पीएक्स-13 की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।"

48.4. घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान आवेदन में दावा किया है कि मूल जांच के अपने आवेदन में उन्होंने निम्नलिखित समायोजन योजना का उल्लेख किया था :

"एनओसीआईएल दाहेज में एक अन्य विनिर्माण सुविधा की स्थापना कर रहा है जिसमें कंपनी का इरादा पीएक्स-13 के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती का 10000 एमटी का उत्पादन करने का है। इस संयंत्र में 250 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर पीएक्स-13 के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले 10000 एमटी मध्यवर्ती पीएक्स-13 के उत्पादन करने की क्षमता है। कंपनी को उम्मीद है कि इसका वाणिज्यिक उत्पादन कहीं न कहीं वित्त वर्ष 2013 में प्रारंभ हो जाएगा। कंपनी को आशा है कि यह संयंत्र लगभग तीन वर्षों की अवधि में अपनी इष्टतम क्षमता से पूर्णतया प्रचालनात्मक हो जाएगा।

48.5. आवेदन घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान दावे में पुनः उल्लेख किया है कि :

"चूंकि कंपनी ने दाहेज संयंत्र में 4 एपीपीए का विनिर्माण करना पहले ही प्रारंभ कर दिया है इसलिए प्रार्थी ने आयात प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उचित एवं उपयुक्त उपाय पहले ही कर लिए हैं।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. प्रार्थी ने दाहेज में 4 एपीपीए का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। संयंत्र के अनुसार यह ही एकमात्र उत्पाद है जिसका प्रार्थी दाहेज में उत्पादन करेगा। यह संयंत्र केवल पीएक्स-13 के लिए है। एसआईसी..... 4 एडीपीए जिसका प्रयोग अन्यतः पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ड. घरेलू उद्योग ने नवम्बर, 2012 से दाहेज संयंत्र में उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है

48.6. वर्तमान समीक्षा जांच में उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में समीक्षा जांच शुरुआत नोटिस में निम्नलिखित समायोजन योजना का उल्लेख किया गया है :

48.7. समायोजन योजना : प्रार्थी ने इस विचाराधीन उत्पाद के एक मध्यवर्ती का लगभग 100000 एमटी का विनिर्माण करने के लिए दाहेज में एक नए संयंत्र की स्थापना करने की सूचना प्रदान की है जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि, नवम्बर, 2012 से उत्पादन होना शुरू हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रदान कराए गए रिकार्ड के अनुसार वे एक परीक्षण उत्पादन में इस विचाराधीन उत्पाद के एक मध्यवर्ती स्तर के उत्पाद/मध्यवर्तियों अर्थात् 4एडीपीए का विनिर्माण कर रहे हैं और उन्होंने इस नए संयंत्र को शुल्क के सतत अधिरोपण के लिए समीक्षा के प्रयोजनार्थ समायोजन योजना के रूप में प्रस्तुत किया है।

48.8. प्रथम दृष्टया : जहां तक इस विचाराधीन उत्पाद अर्थात् पीएक्स-13 या 6पीपीडी के उत्पादन से संबंधित समायोजन योजना का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग के दावे में कुछ विसंगतियां हैं। प्रथम, मूल जांच के समय घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया था कि आवेदक घरेलू उद्योग ने दाहेज में एक नए उत्पादन सुविधा की स्थापना की है, जो इस विचाराधीन उत्पाद और दाहेज संयंत्र पर इसके मध्यवर्तियों सहित खड़ रसायनों का उत्पादन करेगा। तथापि, प्रस्तुत किए गए तथा मूल जांच में महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जिसपर भरोसा किया गया, प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक अपने दाहेज संयंत्र में खड़ रसायन (विचाराधीन उत्पाद) के मध्यवर्तियों का उत्पादन करेगा। तत्पश्चात् समीक्षा के लिए दायर किए गए आवेदनपत्र में उन्होंने दाहेज में एक नए संयंत्र में संवर्धित उत्पादन सुविधाओं का समायोजन योजना के रूप में उल्लेख किया है क्योंकि उनके अपने थाणे संयंत्र में क्षमताओं में वृद्धि हो गई है।

48.9. मुझे दृष्टव्य है कि प्रार्थी ने यथादावाकृत 8500 एमटी से उत्पादन क्षमता में 10000 एमटी की वृद्धि करने के संबंध में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया है और न ही उन्होंने केंद्रीय उत्पाद कर विभाग या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को कोई सूचना प्रदान कराई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 4एनडीपीए का प्रयोग करने के बजाय 4एडीपीए का प्रयोग करके पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए साइकल समय को करके कुछ तकनीकी परिवर्तन किए हैं, तथापि जो, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, प्रार्थी द्वारा उसके थाणे और दाहेज स्थित इकाई का दिनांक 13.03.2013 से 18.03.2013 तक स्थल सत्यापन के दौरान रक्षोपाय कार्यालय की जानकारी में नहीं लाए गए हैं। तथापि, यह एक अन्य मुद्दा है कि क्या घरेलू उद्योग स्पष्टतः यह प्रदर्शित करने में सफल रहा है कि क्या दाहेज संयंत्र के प्रचालन से भी पीएक्स-13 के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि पीएक्स-13 का उत्पादन करने की क्षमता अभी भी 8500 एमटीएस ही है जैसा कि स्थल सत्यापन के दौरान पाया गया और इस जांच में समायोजन योजना की अपेक्षा को पूरा करने के लिए सत्यापन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

48.10. तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में इस वृद्धि की वास्तविक क्रिया पद्धति के बारे में इस कार्यालय द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने अपने दिनांक 14.03.2014 के एक पत्र के तहत एक चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जो दर्शाता है कि 14000 एमटी की संवर्धित क्षमता की उपलब्धि उत्पादन चक्र में परिवर्तन किए जाने के कारण आई है। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 14.03.2014 के पत्र के साथ एक सनदी इंजीनियर, आर. सूरि की एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सभी हितवद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियों के लिए दिनांक 18.03.2014 को परिचालित किया गया। विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों से दिनांक 26.03.2014 तक टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् घरेलू उद्योग को दिनांक 31.03.2014 तक उन टिप्पणियों पर अपना प्रत्युक्ति प्रत्युत्तर दायर करने का अवसर दिया गया।

48.11. मैं प्रतिपादित करता हूँ कि आवेदक घरेलू उद्योग ने उसी सीई की रिपोर्ट पर भरोसा किया है जिसका रिपोर्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके थाणे संयंत्र में इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया यह है कि पहले 4एनडीपीए का उत्पादन किया जाता है और फिर उसे 4एडीपीए में परिवर्तित किया जाता है और फिर उसी को पीएक्स-13/6पीपीडी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें "बाधित एवं अबधित क्षमता" है। घरेलू उद्योग द्वारा पहले अपनाई गई प्रौद्योगिकी में घरेलू उद्योग अपने थाणे संयंत्र में स्टेज 1, स्टेज 2, और स्टेज 3 चला रहा था। अब घरेलू उद्योग दाहेज में स्टेज 2, को प्रत्यक्षतः चलाता है और द्वितीय स्टेप (स्तर -3) में 6पीपीडी/पीएक्स-13 का उत्पादन करने के लिए उसे थाणे अंतरित किया जाता है। इस प्रकार अबाधित क्षमता में सुधार करके वे जैसाकि उनके सीई का उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता बढ़ाकर 14000 एमटीएस करने का इरादा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा थाणे में 4एडीपीए को 6पीपीडी/पीएक्स-13 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

क. थाणे में 4एनडीपीए/4एडीपीए का उत्पादन करने के लिए उत्पादन सुविधाओं का अब 6पीपीडी का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और इसलिए यदि प्रार्थी ने दाहेज में भी 6पीपीडी का उत्पाद कार्य प्रारंभ किया तो इन सुविधाओं का या तो कम उपयोग होगा या वे अप्रयुक्त/निष्क्रिय पड़ी रहेंगी।

ख. दाहेज में 6पीपीडी का उत्पादन करने का आशय यह होगा कि दाहेज में *** करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाए और थाणे स्थित उत्पादन सुविधाओं को निष्क्रिय छोड़ दिया जाए। यह कोई व्यवसाय विवेक तो है नहीं।

ग. प्रार्थी किसी टायर उद्योग को तब तक बिक्री नहीं कर सकता है जब तक टायर उद्योग इस संयंत्र को तथा उसके उत्पादन में मंजूर नहीं कर देता है। टायर उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक परिपक्व और सुस्थापित है। टायर कंपनियां कच्चे माल की खरीद एक लंबी अनुमोदन प्रक्रिया के बाद करती है जिससे उत्पाद के अनुमोदन के साथ-साथ उनके द्वारा संयंत्र का अनुमोदन होना भी आवश्यक है। किसी टायर कंपनी द्वारा किसी नए संयंत्र और नए उत्पाद का अनुमोदन करने की प्रक्रिया में लगभग *** वर्षों का समय लगता है। इसलिए इस अतिरिक्त कारण के लिए प्रार्थी ने अपने थाणे संयंत्र में 6पीपीडी का उत्पादन जारी रखा ताकि इस परिवर्तन के लिए क्रेताओं द्वारा अपेक्षित उत्पाद की प्रक्रिया पूरी न करनी पड़े। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी टायर विनिर्माताओं को इस तथ्य के प्रति जागरूकता बना दिया गया कि कंपनी अब दाहेज में 4एडीपीए का उत्पादन कर रही है और उसे मुंबई में 6पीपीडी के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है। एनओसीआईएल द्वारा भेजे गए कुछ ऐसे ई-मेल और उपभोक्ताओं से भेजे गए उनके उत्तर इस पत्र के साथ संलग्न हैं। उपर्युक्त प्रत्युत्तरों से यह देखा जा सकता है कि यथा उद्योग को जनवरी, 2013 में एनओसीआईएल की उक्त स्थिति की पूरी जानकारी थी।

48.12. घरेलू उद्योग की इस समायोजन योजना के संबंध में इस पत्र का हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया है कि आवेदक ने वर्तमान समीक्षा में मूल जांच में प्रस्तुत समायोजन योजना से भिन्न योजना प्रस्तुत की है जबकि, दिनांक 6 जून, 2011 के अंतिम जांच परिणाम में उल्लिखित मूल समायोजन योजना के अनुसार, आवेदक ने दाहेज संयंत्र में संबद्ध वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और एक सनदी अभियंता से प्राप्त प्रमाणन के आधार पर, यह कार्य अप्रैल, 2012 तक पूरा होगा। वर्तमान जांच में प्रस्तुत किए गए रूपांतर में आवेदन ने यह प्रस्तुत किया कि इसने वित्त वर्ष 2013 से दाहेज संयंत्र में एक मध्यवर्ती 4एडीपीए का 10000 एमटी का विनिर्माण प्रारंभ करने का केवल प्रस्ताव किया है। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक प्राधिकारी को समायोजन योजना के संबंध में संभ्रम में डाल रहा है। इसके अतिरिक्त आवेदक अपनी समायोजन योजना को पूरा करने में असफल रहा है क्योंकि इसके समायोजन में लगभग 2 वर्षों का विलंब हो गया है यद्यपि आवेदक ने यह कहा था कि यह समायोजन योजना व्यवहार्य है क्योंकि चार्टर्ड इंजीनियर पूरा प्रमाणित किया गया है।

48.13. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अपनी वर्ष 2011 की उस समायोजन योजना को प्राप्त नहीं कर सका जिसे सनदी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है, तब आवेदक के एक सनदी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित थाणे संयंत्र की संवर्धित क्षमता के संबंध में उपर्युक्त पत्र में किए गए दावे के संबंध में भी उसकी अर्थक्षमता एवं व्यवहार्यता पर संदेह उठने लगा है। वास्तव में यह संभव है कि, ऐसे दावे कुछ भी नहीं हैं बल्कि केवल खोखले अभिकथन हैं जो आवेदक ने त्रुटियों को छिपाने और मूल समायोजन योजना के क्रियान्वयन में होने वाले विलंब से ध्यान बांटने के लिए किया है। इसके अतिरिक्त पत्रों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आवेदक अपने दाहेज संयंत्र में 4एडीपीए एक मध्यवर्ती की पर्याप्त मात्रा का विनिर्माण करने में सक्षम है जिससे इसे संबद्ध वस्तु का 14000 एमटी का विनिर्माण करने की अनुमति मिल जाएगी। यह नोटिस किया जाता है कि घटे हुए चक्रीय समय के आधार पर थाणे संयंत्र की संवर्धित क्षमता का केवल आकलन कर लेने से संबद्ध वस्तु के 14000 एमटी का विनिर्माण करने की वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो जाता है, यदि दाहेज संयंत्र से मध्यवर्ती 4एडीपीए का आपूर्ति थाणे संयंत्र को अपर्याप्त मात्रा में होता है तो यह उत्पादन कैसे होगा। आवेदक को यह दिखाना पड़ता है कि वह अपने दाहेज संयंत्र में 4एडीपीए का पर्याप्त उत्पादन कर रहा है जिसको थाणे संयंत्र में संबद्ध वस्तु का 14000 एमटी उत्पादन करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। मैं यह प्रतिपादित करता हूँ कि संवर्धित क्षमता के संबंध में आवेदक के उपरोक्त दावों के समर्थन में खास प्रमाण नहीं है जैसे दाहेज संयंत्र में मध्यवर्ती 4एडीपीए का पर्याप्त उत्पादन करने संबंधी आंकड़े और थाणे संयंत्र में इसकी आपूर्ति करने के संबंध में आंकड़े।

48.14. तदनुसार, मैं उपपादित करता हूँ कि जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजना को आयतों के प्रति अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पूरी तरह से न्यायोचित नहीं ठहरा पाया गया है। मैं यह भी उपपादित करता हूँ कि

यह पहलू अत्यधिक अभिनव अवधि में घरेलू उद्योग की बढ़ती बिक्री लागत में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यद्यपि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए चक्रीय प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। घरेलू उद्योग निष्कर्ष रूप से यह भी सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाया है कि रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्राप्त होने की अवधि के दौरान वे संवर्धित आयातों से लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी उत्पादन लागत में कमी करने में भी सक्षम नहीं हुए हैं। इस कारण, उनका यह तर्क कि भरोसे लायक नहीं है कि इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसलिए, समायोजन योजना की अपेक्षा को रक्षोपाय नियमावली के अनुरूप पूरा नहीं किया गया है।

49. शुल्क की समाप्ति के पश्चात अंतिम जांच परिणाम जारी करना – पाटनरोधी मामला

49.1. मैं उपपादित करता हूँ कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई पश्चात किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युक्तियों में यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा मामले की तुलना में जहाँ मामले की शुरुआत पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पहले की जानी चाहिए, रक्षोपाय शुल्क विधि में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी निदेशालय से संबंधित मामलों की एक सूची प्रस्तुत की है। इनकी जांच करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क की जांच शुरुआत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के पश्चात की गई थी, जबकि कुछ मामलों में यह जांच शुरुआत मौजूदा शुल्क की समाप्ति की अंतिम तारीख को की गई थी, परंतु किसी भी हाल में नियमों के अंतर्गत अनुमेय विहित अवधि के पश्चात अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं किया गया। हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ रक्षोपाय मामलों की तालिका भी प्रदान करवाई है जिनके द्वारा समीक्षाधीन अंतिम जांच परिणाम लागू रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से ठीक पहले जारी किए गए थे जैसे सोडा ऐश मामले में किया गया। यह तथ्य कि सोडा ऐश के मामले में रक्षोपाय शुल्क उद्ग्रहण करने की अधिसूचना रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के पश्चात जारी की गई थी, इस निदेशालय के लिए असंगत है।

49.2. वर्तमान मामले में मुझे उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर मैं यह उपपादित करता हूँ कि समीक्षा के किसी भी मामले में, चाहे वह पाटनरोधी जांच हो या रक्षोपाय जांच, संबंधित प्राधिकारी ने अपने-अपने रक्षोपाय नियमावली/पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप विहित समयावधि के उपरांत कोई अंतिम जांच परिणाम/सिफारिश जारी नहीं की है। इसलिए, मैं इस संबंध में घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ।

50. अनपेक्षित परिस्थितियाँ

मैं उपपादित करता हूँ कि कई हितबद्ध पक्षकारों ने इस समीक्षा याचिका में अनपेक्षित परिस्थितियों की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण से सहमत हूँ कि, चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है, इसलिए अनपेक्षित विकास को फिर से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अनपेक्षित विकास को इस साधन का अधिरोपण करते समय सिद्ध किया गया था। वर्तमान याचिका इस साधन में विस्तार किए जाने के लिए है। तथापि, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद कोरिया और चीन से आयातों में उद्रेक बने रहने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े उनके तर्क की पूर्णतया समर्थन करते हैं और अनपेक्षित परिस्थितियों से संबंधित शर्त को भी पूरा करते हैं।

51. जनहित : कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीएक्स-13 पर रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण जनहित में नहीं होगा। इन प्रस्तुतियों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि चूंकि वर्तमान मामला अधिरोपित शुल्क के सतत अधिरोपण से संबंधित है और जनहित के मुद्दे पर मूल जांच के समय विगत में ही चर्चा कर ली गई थी, इसलिए विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार उसके किसी अन्य विश्लेषण पर विचार नहीं किया जा सकता है। मैं उपपादित करता हूँ कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई पश्चात किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युक्तियों में यह प्रस्तुत किया है कि पीएक्स-13/6पीपीडी पर इस रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा क्योंकि यह उपभोक्ताओं के लिए लागत का एक बड़ा लागत कारक नहीं है और यह कि पीएक्स-13/6पीपीडी की अधिकांश खपत टायर उद्योग द्वारा की जाती है। घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि पीएक्स-13/6पीपीडी के कारण टायर उद्योग की कीमत 1 प्रतिशत से भी कम बनती है और गैर-टायर उपभोक्ताओं के लिए तो यह लागत मद और भी कम कुल लागत का मुश्किल से 05 प्रतिशत है, यह तथ्य गैर-टायर (सेगमेंट के उपभोक्ताओं और उनकी एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतरों से सिद्ध हो जाता है। मैं यह उपपादित करता हूँ कि घरेलू उद्योग का यह तर्क कि इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, और इसलिए इसका अधिरोपण करना जनहित में है, इसका किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्यकित साक्ष्य से विरोध नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि इसका प्रभाव न्यूनतम होगा और आयातों में उद्रेक है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित की जा रही है, यह उपपादित किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हो, का सतत अधिरोपण करना जनहित में होगा।

52. डब्ल्यूटीओ तुर्की मुद्दा

52.1. एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया है, यह है कि क्या इस मामले में महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा की गई सकारात्मक सिफारिश डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत रक्षोपाय करार के उपबंधों के अनुपालन में होगा।

52.2. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत परिकल्पित रक्षोपाय साधनों की कालावधि एवं समीक्षा के लिए किए गए ढांचे के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क में इसकी अवधि समाप्त होने से पहले विस्तार किया जा सकता है न कि बाद में। रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 7.2 तब लागू होता है जब रक्षोपाय साधन बिना किसी अंतराल के निरंतर बनाए रखना हो और रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 7.5 तब लागू होता है जब रक्षोपाय साधन को एक निश्चित अंतराल, न्यूनतम दो वर्षों के अंतराल के अध्यक्षीन, के पश्चात 'एक बार फिर' या 'नए सिरे से लागू' करना हो।

52.3. हितवद्ध पक्षकारों ने इस मामले में किए जा रहे रक्षोपाय समीक्षा जांच के विरुद्ध किए गए प्रस्तुतिकरणों में 'काटन यार्न (सिलाई वाले धागे के अलावा) के आयातों के संबंध में तुर्की रक्षोपाय साधन' ('तुर्कीकाटन यार्न') नामक डीएस 428 में तुर्की के विरुद्ध डब्ल्यू टी में भारत द्वारा की गई शिकायत पर भरोसा किया है। उपर्युक्त मामले में भारत ने तुर्की द्वारा काटन यार्न पर रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने को चुनौती दी थी। भारत ने तर्क दिया था कि तुर्की द्वारा, 14 जुलाई, 2011 को शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात दिनांक 28 जनवरी, 2012 को रक्षोपाय शुल्क में विस्तार करना रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत असंगत है क्योंकि तुर्की ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत अधिदेशित प्रतीतन अवधि (न्यूनतम 2 वर्ष) की प्रतीक्षा किए बिना इस साधन को लागू कर दिया।

52.4. चूंकि यह मामला डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य देश भारत से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि नोडल मंत्रालय अर्थात् वाणिज्य विभाग से टिप्पणियां मांगी जाएं। तदनुसार, वाणिज्य विभाग (व्यापार नीति अनुभाग) से सूचना प्राप्त की गई और उसकी जांच की गई। यह नोटिस किया गया कि तुर्की के साथ उक्त विवाद में भारत का मुख्य दावा यह था कि शुरुआती साधन दिनांक 14 जुलाई, 2011 को समाप्त हो गया था और भूतलक्षी प्रभाव से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है और यह कि इस साधन में वृद्धि अनुच्छेद 7.2 के अनुरूप समुचित निर्धारण करने के पश्चात ही की जाएगी। इस साधन में विस्तार करने से पहले ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया। तुर्की ने अपनी स्थिति को पुनः दोहराया और इसके दावे तथा किए गए साधन की रक्षा करने की मांग की। तुर्की द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के बावजूद भारत द्वारा प्रस्तुत किए प्रति तर्कों का सामना नहीं कर सके और तुर्की ने यह महसूस करते हुए कि काटन यार्न पर उनके द्वारा सतत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार से संगत नहीं है, एक परस्पर स्वीकार्य हल के जांच परिणाम की संभावनाओं का अन्वेषण करने का उल्लेख किया और पैनल तक जाने की जरूरत के बिना एक परस्पर सहमत करार का प्रस्ताव किया। तदनुसार भारत और तुर्की के बीच दिनांक 15 जून, 2012 को एक समझौता ज्ञापन, काटन यार्न पर दिनांक 1.1.2013 से रक्षोपाय शुल्क वापस लेने तथा यह कि रक्षोपाय शुल्क दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक लागू रहेगा, के लिए हस्ताक्षरित किया गया। अतः, भारत का डब्ल्यूटीओ के समक्ष शासकीय उदाहरण यह है कि एक बार रक्षोपाय शुल्क समाप्त हो जाने पर और पहले से ही अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त हो जाने से पहले रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश न करने पर, अधिरोपित शुल्क में विस्तार तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

52.5. इस स्थिति के विपरीत, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क से संबंधित कई मामलों/उद्धरणों का उल्लेख किया है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षोपाय शुल्क से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रक्षोपाय तथा पाटनरोधी दोनों ही व्यापार उपचारी उपाय हैं, फिर भी वे प्रकृति एवं समाधान दोनों रूपों में एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। इस संबंध में घरेलू उद्योग डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रक्रिया को समझने में असफल रहा है और तर्क दिया है कि भारत और तुर्की के बीच डीएस-428 विवाद कभी भी डब्ल्यूटीओ पैनल के पास नहीं पहुंचा। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश, एक परामर्श अनुरोध दायर करने के पश्चात द्विपक्षीय परामर्श कर सकते हैं और वे डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा हस्ताक्षेप करने का अनुरोध करने से पहले विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। इस मामले में विचार विमर्श प्रक्रिया ने तुर्की को रक्षोपाय साधन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया और डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा हस्ताक्षेप किए जाने की जरूरत नहीं पड़ी।

तुर्की ने भारत की स्थिति को स्वीकार किया और भारत के साथ एक करार किया जिसमें तुर्की रक्षोपाय साधन को वापस लेने पर सहमत हो गया।

52.6. इस मामले से संबंधित तथ्यों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क 29 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गया था। समीक्षा के लिए यह मामला दिनांक 29.8.2013 को प्रारंभ को प्रारंभ किया गया था। संबद्ध विचाराधीन उत्पाद पर पहले से ही प्रभावी रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति से पहले रक्षोपाय शुल्क, यदि किसी की सिफारिश की जानी थी, का अधिरोपण करने के लिए अंतिम सिफारिश किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। शुल्क के उदग्रहण में अंतराल हो जाता और चूंकि वर्तमान आवेदन शुल्क के सतत अधिरोपण की समीक्षा करने के लिए है इसलिए कोई सकारात्मक सिफारिश रक्षोपाय शुल्क के भूतलक्षी उदग्रहण की स्थिति के अनुरूप होगी। यह स्थिति, जैसा कि ऊपर उपपादित किया गया है, भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ के समक्ष दिए गए शासकीय आधार की संपुष्टि नहीं करेगा जिसके रक्षोपाय शुल्क (रक्षोपाय करार के अंतर्गत) से संबंधित उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क का उदग्रहण करने का प्रावधान नहीं करते हैं। शुल्क का भूतलक्षी उदग्रहण केवल तभी संभव है जब संविधि में इस तरह का अधिकार अभिव्यक्त रूप से प्रदान किया गया हो। अतः, इस समीक्षा के परिणामस्वरूप रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने से संबंधित निर्णय को उस 'पिछली तारीख से' लागू नहीं किया जा सकता है जिस तारीख को प्रभावी शुल्क समाप्त हुआ है। अतः, इस मामले में चूंकि शुल्क उस अवधि की समाप्ति के पश्चात पुनः प्रारंभ या लागू होगा जिसके लिए पूर्व में अधिरोपित शुल्क प्रभावी था, इसलिए यह शुल्क को 'एक बार पुनः' लागू करने अर्थात् रक्षोपाय शुल्क का नवीन उदग्रहण करने के अनुरूप होगा और इसलिए अनुच्छेद 7.5 में उल्लिखित निषेध लागू हो जाएगा।

53. निष्कर्ष एवं सिफारिश

53.1 उपर्युक्त जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग पीएक्स-13 पर 30 अगस्त, 2011 से प्रभावी विगत रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से उनके द्वारा की गई सकारात्मक समायोजन योजना के लिए किए गए प्रयासों का

अनुपालन करने में असफल रहा है और बिना किसी ठोस उपाय के विपश्चित भावी/प्रस्तावित समायोजन योजनाओं के आधार पर रक्षोपाय शुल्क में विस्तार किए जाने की मांग कर रहा है और उन दो वर्षों की अवधि के दौरान जब उसे रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्राप्त था तब किसी ठोस समायोजन प्रयास किए जाने में उसकी असफलता के कारण बिक्री /उत्पादन लागत तथा उपरिशीर्ष/लागतों को कम करने के ऐसे अन्य साधनों में कमी आई है। इस संबंध में की गई कोई अन्य कार्रवाई भारत सरकार द्वारा 'काटन यार्न (सिलाई वाले धागों के अलावा) के संबंध में तुर्की - रक्षोपाय साधन' ('तुर्की - काटन यार्न') डीएस-428 में तुर्की के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में डब्ल्यूटीओ में प्रस्तुत किए गए अपने आधार के विपरीत होगी।

53.2 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएक्स-13/6पीपीडी पर रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण करने से संबंधित रक्षोपाय जांच की वर्तमान समीक्षा प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है।

[फा. सं. डी-22011/1/2013/पीटी]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

**DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2014

Sub: Review of safeguard Duty on imports of PX-13 OR 6PPD (Rubber Chemicals) into India under provisions of Section 8B(4) of Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 16 and Rule 18 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 –Final Findings –regarding.

G.S.R. 293 (E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

Procedure

1. An application for review and extension of safeguard duty had been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (1) M/s. NOCIL Limited, Mumbai, for continuation/extension of Safeguard Duty on imports of Rubber Chemicals N-1, 3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine also known (and referred in the petition) as PX-13 or 6-PPD into India, after expiry of the existing safeguard duty, alleging that increased imports of PX-13 or 6PPD (Rubber Chemicals) was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of PX-13 or 6PPD (Rubber Chemicals) in India. The Notice of Initiation of Safeguard investigation for review of safeguard duty on imports of PX-13 or 6PPD (Rubber Chemicals) into India was issued on 29th August 2013 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day vide GSR 583 (E) dated 29th August, 2013 A copy of the Notice of Initiation dated 29th August, 2013 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other ministries concerned, Government's of exporting countries through their Embassies / High Commission in New Delhi and all known interested parties listed below in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty) Rules, 1997:

2A. EXPORTERS

1. China Sunsine Chemical Holdings Ltd.

China Business Address, Four Kilometres South-east of Shanxian Shandong Province,
Postal Code 274300, The People's Republic of China

2. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd., No.217, Qinghe West Road, Yanggu County,
Post Code: 252300

3. Dongying Bo Chen Chemical Co., Ltd.

Da wang, Dongying, Shandong Province Economic and Technological Development Zone

4. Nanjing Chemical Plant. (NCP) Address: 560 Heyan Road, Nanjing, China, Postcode: 210038

5. Henan Kailun Chemical Co., Ltd. 25 Jiefang Rd. North, Huaxian County, Henan, China.

6. Dalian Richon Chem Co.,Ltd., 1/10F, China Bank Plaza, No.15 Renmin Road, Dalian, China 116001

7. Hebei Haufeng Chemical Group 19, Changzing Road, Quing Liang Dian Town, Wuyi Country, Hebei Province, China

8. Yixing Dongfang Fince Chemical, 201Renmine Road, Fenshui Town, Yixing Jiangsu, China

9. Solutia Inc.,(World Headquarters), 575 Maryville Centre Dr, St Louis, MO 63141, United States

10. Duslo a.s, Administrativna budova ev. c. 1236, Sala, 927 03, Slovakia

11. Kumho Polychem Co., Ltd., 20th Fl., Kumho Asiana Main Tower, #115 Sinmunno 1-GA, Jongno-gu, Seoul, Korea

12. **Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.**, Shanghai Operation Center, 22 F, Yongda International Tower, No. 2277 Longyang Road, Pudong New Area, Shanghai, 201204, P. R. China
13. **Changde Dingyuan Chemical Industrial Limited**, Dongfeng Village, Nanping Township, Wuling District, Changde, Hunan, China.
14. **Jinan Runquan Chemical Co., Ltd.** Hengchang Building, No. 288 Jingsi Road, Jinan, Shandong, China.
15. **Zhejiang Yongjia chemical Plant**, Address: Dong-ou Industrial District (Oubei 3rd bridge) Wenzhou, China, Zip Code: 325105
16. **Rongcheng Chemical General Factory Co., Ltd.**, Rongan Road, Rongcheng City, Shandong Province, 264300 China.
17. **Zhenjiang No. 2 Chemical Factory**, Zhenjiang Chemical Development Area, Jianhi, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China.
18. **Shenzhen Huaren Industrial Co.**, Suit No. No.1103-1108 Dianjing Bldg, 2 Gujy Unn Road, Luohu Dist. Shenzhen City, China
19. **Zhejina Yueqing Ultrafine Powders & Chemicals Co Ltd.**, Shandgbutou Industrial Area, Qingjian, Yueqing, Zhejiang, China
20. LANXESS NV Germany, 51369 Leverkusen Germany
21. Flexsys NV **Belgium**, Parc Scientifique — Fleming Rue Laid Burniat, 3B - 1348 Louvain-la-Neuve Belgium.
22. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd., Exporter, republic of Korea.
23. M/S EASTMAN Chemical Company, P.O. Box- 511, Kingsport, Tennessee.

3B. IMPORTERS

1. **CEAT Limited**, RPG House, 463, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030
2. **Apollo Tyres Ltd**, VI Floor, Cherupushpam Building, Shanmugham Road Kochi 682031
3. **MRF Limited, Chennai**, 124, Greaves Road, Chennai - 600006.
4. **Poddar Tyres Ltd.**, G.T. Road, Jugiana, Ludhiana- 141420
5. **The Rubber Products Limited**, Plot No. C-44, Road No. 28, Wagle Industrial Estate, Thane (Mumbai)— 400 604
6. **J.K. Industries Ltd.**, 7, Council House Street, Kolkata — 700 001.
7. **Birla Tyres**, Birla Building, 7th Floor, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata, 700 001
8. **Metro Tyres Ltd.**, Metro Tower, C-49, Sector 62, Noida — 201 301, India
9. **Ralson Ind. Ltd.**, J-38, Udyog Nagar, Rohtak Road, New Delhi-41 (INDIA)
10. **M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.** 65 Atlanta, Nariman point, Mumbai

4C. INDIAN PRODUCERS

1. **M/s NOCIL Ltd. C-37, T.T.C. Industrial Area, Pawne Village, Navi Mumbai. (Domestic Industry)**
2. **LANXESS India Pvt. Ltd.** LANXESS House, Plot no: A 162-164, Road No 27, MIDC, Wagle Estate Thane (W)- 400 604, Maharashtra
3. **PMC Rubber Chemicals India Private Limited**
103 G T Road West, P.O: Rishra 712248, Dist : Hooghly West Bengal, India
4. **Merchem Limited**, Grove Centre, 44 Development Plot,
Kalamassery, Cochin -683109 Kerala, India.

5D. Known User Association

1. **Automotive Tyre Manufacturers 'Association**, PHD House, 4th floor, Siri Fort Institutional Area, Opp. Asian Games Village, New Delhi.
2. **The All India Rubber Association (AIRIA)**, 601, Pramukh Plaza, B Wing, 485 Cardinal Gracious Road, Opp. Proctor & Gamble, Chakala, Andheri (E) Mumbai - 400099

5E. EXPORTING NATIONS/DELEGATIONS/EMBASSIES

1. Delegation of the European Union to India
2. The Trade Representation of the Russian Federation in India.
3. The Embassy of People's Republic of China, 50-D, Shantipath, Chanakya Puri, New Delhi -21.
4. The Embassy of the Federal Republic of Germany, No. 6/50G, Shanti Path, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
5. The Embassy of Republic of Korea, 9. Chandragupta Marg., Chanakya Puri Extension, New Delhi - 21.

6. The Embassy of United States, Shanti Path, Chanakya Puri , New Delhi -21.
7. The Embassy of Slovakia, 50M, Niti Marg, Chanakya Puri , New Delhi -21.
8. The Embassy of Belgium, 50N, Shanti Path, Chanakya Puri , New Delhi -21.

5.1. Out of the above mentioned Exporters, there were 3 Exporters from where the notice of initiation could not be delivered and returned with a remark due to insufficient address which are as under:

- i. M/s **Nanjing Chemical Plant. (NCP)** Address: 560 Heyan Road, Nanjing, China
Postcode: 210038
- ii. M/s **Zhejiang Yongjia Chemical Plant** Address: Dong-ou Industrial District (Oubei 3rd bridge) Wenzhou, China, Zip Code: 325105
- iii. M/s **Zhenjiang No. 2 Chemical Factory** Zhenjiang Chemical Development Area
Jianhi, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China

6. The information presented by the applicants was verified by onsite visits to the plants of the domestic producer to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report was kept in the public file.

7. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

8. A public hearing was held on 19.12.2013, notice for which was sent on 03.12.2013. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. All the views expressed by the interested parties, during public hearing, either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

9. **Brief history:** An investigation was initiated by the DG (safeguards) earlier on the application filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s. NOCIL Limited, Mumbai, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Rubber Chemicals N-1, 3-dimethyl butyl-N-Phenylenediamine also known (and referred in the petition) as PX-13 or 6-PPD into India alleging that increased imports of PX-13 or 6PPD was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of PX-13 or 6PPD in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 of Safeguard Rules ibid were met, safeguard investigation against imports of PX-13 or 6PPD was initiated vide notice of initiation dated 27th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day. After expeditious conduct of investigation Final findings were issued on 6th June, 2011. Central Government levied definitive safeguard duty @ 30% minus Antidumping duty payable for a period of one year from 30-08-2011 to 29-08-2012 and @25% minus Antidumping duty payable for second year from 30-08-2012 to 29-08-2013 on the imports of Rubber Chemicals as mentioned above, vide Min of Finance Notification No 83/2011-Customs (SG) dated 30th Aug 2011 based on the recommendation of DG Safeguard. As mentioned above, the safeguard duty was in vogue till 29th August, 2013. However, the instant application has been filed by the domestic industry for continuation/extension of safeguard duty for a further period of two years with the purpose to enable the domestic industry to improve its competitiveness in order to survive.

10. Most of the issues raised by parties are similar to the submissions raised by other interested parties. These have accordingly been considered at appropriate places.

11. **Post-Initiation Submissions**, as follows, were received prior to the Public Hearing:

A. The Government of Mexico: The views expressed by Mexico that according to official data from their system of Tariff Information, there were no Mexican exports of the product to India during the period of time from January 2009 to June 2013. As the article 9.1 of the agreement on Safeguards of the World Trade Organization, Mexico is a developing country Member of WTO and requested to the Indian Govt. to consider the exclusion of Mexican product imports from the application of any safeguard measures derived from such proceeding.

B. The European Commission:

1. The Commission opposed the initiation of this review investigation which has serious procedural deficiencies and safeguard measures against imports of PX-13 would not be legally possible at this stage.

2. Under the provisions of Article 9.2 of the WTO agreement on safeguards, India would have the right to apply safeguard measure only after two years since the expiry of the original measure, i.e. not before August 2015 in this case. Accordingly, terminate this investigation and confirm that the measures have expired.

3. Petitioner claimed that imports continue to cause serious injury, in fact, after measures the sale of the domestic industry have only slightly increased and corresponding market shares were relatively stable while other Indian producers benefited and their market shares doubled during the period from 8% in 2009 to 16% in 2013 which indicated that domestic industry is facing problems caused by reasons other than imports.

4. As per Article 7.4 of the WTO agreement on safeguards, if measures extended, shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period and should continue to be liberalized.

C. The LANXESS:

LANXESS regarded as a domestic producer expressed that the Lanxess plant in Jhagadia, Gujarat is a multi-purpose plant and in absence of a safeguard duty, they would always be in the position to use it for the manufacture of the product offering the highest added value. Any safeguard duty would impede any such optimization, thereby diminishing the value created within India.

D. The Government of the Republic of Korea:

1. According to Article 7 of the WTO agreement on Safeguards (Duration and Review of Safeguard measures), the initiation of a review by the Indian Government should be regarded as a re-application rather than an extension of the measure.
2. There is no article that regulates provisional measures or retrospective effect of determination regarding a review under the WTO Agreement on safeguards because of the nature of safeguard measures that are exceptionally imposed against fair trade under strict conditions.
3. According to article 7.5 of the WTO Agreement on safeguards, the period of non-application is at least two years. Hence, the on-going investigation on review and extension by the Indian Government should be terminated either immediately or without imposing any safeguard measure.
4. Article 7.2 of the WTO safeguards Agreement states that safeguard measures “ may be extended provided that the competent authorities of the importing Member have determined, in conformity with the procedures set out in Article 2,3,4 and 5, that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting.... In this regard, Article 2.1 of the Agreement provides that there should be an increase of imports, absolute or relative to domestic production, as the basic condition for imposing safeguard measures. As per the data shown in the Notice of initiation of safeguard investigation in PX-13, the increase in imports of the product is not significant enough to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
5. It should also be noted that the spirit of the WTO Agreement on safeguards is to recognize “ the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit competition in international markets.” This aspect should be verified by the investigating authority whether sincere efforts were made by the domestic industry to make structural adjustments during the period when the safeguard measure was applied. As per the index of the capacity utilization and productivity per day shown in the Notice of initiation of safeguard investigation in PX-13, the efforts for structural adjustment, have continuously decreased even during the imposition of safeguard measure.
6. The imposition of safeguard measure in August 2011 caused arise in the price of the product in India and in turn had an adverse effect on the competitiveness of tire producers (end users) as they must buy at a higher price. If the safeguard measure is extended, it would cause a severe adverse affect on downstream industries and consumers.
7. There is no need to continue its investigation to review and extend its safeguard measure and terminate the investigation either immediately or without imposing additional safeguard measure.

E. M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea:

1. Under the framework for duration and review of safeguard measures envisaged under Article 7 of the AoS, a safeguard duty can be extended before the end of its term and not thereafter. Article 7.2 of the AoS applies when a safeguard measure is to continue without a gap and Article 7.5 of the AoS applies when a safeguard measure is to be applied "once again" or "applied afresh" after a gap, subject to a minimum gap of two years.
2. In the present case, the safeguard duty expired on 29th August 2013. The date of initiation of investigation is inconsequential in safeguard review. The legal provisions relating to safeguard duty and the AoS do not provide for retrospective levy of duty. Retrospective levy of duty is possible only if such power is expressly provided in the statute. Therefore, the decision to levy safeguard duty as a result of the review cannot ‘relate back’ to the date on which duty previously in force expired. Thus, in this case as the duty will recommence or apply after expiry of the period for which previously duty was in force, it would amount to applying duty "once again" i.e. a fresh levy of safeguard duty and therefore, prohibition contained in Article 7.5 is applicable. Further stated that for safeguard duty to continue in terms of Article 7.2 of the AoS, the DG Safeguards should have taken the decision to continue the safeguard duty on or before 29th August, 2013, which means the investigation and the decision to continue safeguard duty should have been completed on or before 29th August, 2013.

Incorrect information in the application of the Applicant Domestic Producer and consequently, initiation of review is bad.

3. The Applicant Domestic Producer in its application for original investigation submitted the following adjustment plan:

*“NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce ***MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX-13 as one of the product. This plant will have a capacity for production of ***MT PX-13 at an estimated expenditure of Rs. ***. The total project costs about Rs. *** Crs is under implementation stage. The company hopes to commence commercial production some times in FY 12-13. The company hopes that the Plant will be fully operational at optimum capacity in about three year's time. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the country after*

taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports.”

4. The Applicant Domestic Producer in its written submission post public hearing reiterated its aforementioned adjustment plan:

“The petitioner reiterates that NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce ***** **MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX-13 as one of the product.** This plant will have a capacity **for production of ***** MT PX-13** at an estimated expenditure of Rs *****Crs. The total project costs about Rs. *****Crs are under implementation stage. **The company hopes to commence commercial production sometime in FY 2013.** The company hopes that the Plant will be fully operational at optimum capacity in about three year’s time. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the Country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports.”

5. The DG Safeguards noted for the adjustment plan as follows in its Final Findings dated 6th June, 2011:
6. “34. The Indian Producers have laid down adjustment plan which focuses on a) cost reduction, b) Further utilization of existing production capacity, c) Capacity expansion to cater the growing demand.

35. The petitioner industry i.e. NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to **produce ***MT of PX-13** at an estimated expenditure of Rs. ***Crs... The project is slated to be commissioned from March 2012 and production from April 2012. A certificate from Chartered Engineer has been submitted giving detail of the work done and to be done and certifying that it is quite possible to commence production from April 2012.”

7. The Applicant Domestic Producer in its present application claims that in their application for original investigation they stated as follows for adjustment plan:

“NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce **10,000 MT of intermediaries used for production of PX-13.** This plant will have a capacity for production of 10,000 MT intermediates used for production of PX-13 at an estimated expenditure of Rs. 250 Crs... The company hopes to commence commercial production some time in FY 2013. The company hopes that the Plant will be fully operation at optimum capacity in about three year’s time.”

8. The Applicant Domestic Producer, further claims in its present application as follows:

“Since the company has already started manufacturing 4ADPA at Dahej Plant, the petitioner has taken adequate and appropriate measure for becoming import competitive.

2. the Petitioner has commenced production 4ADPA at Dahej. As per the plant, this is the only product that the petitioner shall be producing at Dahej. The plant is only for **PX-13 (sic....4ADPA)**, which shall be exclusively used for production of PX-13. ...

e. The Domestic Industry has already started production at Dahej Plant since November, 2012.”

9. The Applicant Domestic Producer notified the Bombay Stock Exchange under mandatory disclosure as follow:

07 Mar 2013

Commencement of Commercial Production at Dahej

Company Update

15:43

NOCIL Ltd has informed BSE that the Company after completion of successful trial runs of production at its new Greenfield Plant at Dahej, Dist. Bharuch in the state of Gujarat, has commenced commercial production of Rubber Chemicals effective from March 07, 2013.

10. The Applicant Domestic Producer has announced at its website as follows:

Board of
Directors
Financial results
Corporate
Governance
Share holding
pattern
Announcements

1. The name of the Company has been changed from National Organic Chemicals Industries Ltd. to NOCIL Ltd. with effect from 14th September, 2007.

2. The Company is pleased to inform that the Company after completion of successful trial runs of production at its new Greenfield Plant at Dahej, Dist. Bharuch in the state of Gujarat, has commenced commercial production of Rubber Chemicals effective from 7th March, 2013.

11. The DG Safeguards in the notice for initiation of review stated as follows:

Adjustment Plan: The petitioner has provided the information for setting up of a new plant at Dahej of about 10000 MTS for manufacturing the intermediaries of the PUC which as stated, have gone into production since Nov'12. As per records provided by the petitioner, they are manufacturing penultimate staged product/intermediaries of the PUC i.e. 4ADPA in a trial production and have cited this new plant as their adjustment plan for the purpose of review for continued imposition of duty.

12. Now the Applicant Domestic Producer claimed that it had made a different claim at the time of original investigation, i.e., the Applicant Domestic Producer will produce 4ADPA at its Dahej Plant (as seen from the portion extracted from the application). It is submitted that the DG Safeguards examine this fact and determine what was the claim of the Applicant Domestic Producer in its application for original investigation.
13. Secondly, the Applicant Domestic Producer claimed on its website and notified the Stock Exchange under the mandatory disclosure (under listing agreement with stock exchange) that the Dahej Plant commenced commercial production from 7th March, 2013. The Application has been filed on 31st July, 2013 (though that is incorrect, proved in elsewhere in this submission). On page 27 of the application, it is claimed that production commenced from November, 2012. The Initiation Notice also stated that Dahej Plant commenced production since November, 2012. when the Applicant Domestic Producer has claimed before other Statutory Authorities that the Dahej Plant has gone for production only on 7th March, 2013, then the contrary claim in the application and the initiation notice is a fraud played on the other interested parties. The DG Safeguards is requested to examine the issue.
14. Thirdly, it is not clarified whether the operation of Dahej Plant will also increase the capacity of production of PX-13. It may be noted the capacity to produce PX-13 is 8500 MT as stated in the initiation notice.

Non-compliance with adjustment plan

15. Rule 18(1)(i) of the Safeguard Rules requires the domestic industry to adduce evidence of adjusting positively, while applying for review of a safeguard measure. The Applicant Domestic Producer has provided inconsistent claims in application for original investigation and in application for present review. The initiation notice stated that the production capacity of the Applicant Domestic Producer is 8,500 MT. In the application, nowhere the Applicant Domestic Producer claimed that there is any increase in the capacity to produce PX-13.
16. There are major differences in the adjustment plan noted in the Final Findings of the original investigation and that relied upon in the Petition. These are outlined hereunder :

S. No.	Item	Per Adjustment Plan noted in Final Findings and earlier petition	Adjustment Plan relied on in the Petition
1	Product to be manufactured at Dahej plant	PX-13 or 6PPD	4 ADPA (actually manufactured)
2.	Timeline (Dahej plant)	Commissioning from March 2012 Production from April 2012	Commissioning sometime in FY 2013 (pg. 24 of the Petition) Commissioning by August 2012 (Annual Report 2011-2012) Trial Production since November 2012 (pg. 27 of the Petition) <u>Actual</u> Commissioning on 7th March 2013 (Annual Report 2012-2013)

17. The table above shows that the Applicant is misrepresenting data and presenting wrong facts before the DG Safeguards at different time. The Applicant has neither manufactured the subject product at its Dahej plant that it proposed in the original adjustment plan during original investigation. Further, the Applicant has already delayed taking positive steps for adjustment by 1 year, that cannot be alleged to be due to imports (cause is less supply of electricity).
18. Since, the Applicant has failed to take any positive steps for adjustment as proposed during original investigation; it cannot take refuge under Rule 18 of the Safeguard Rules. The DG Safeguards in its Final Findings in *Review of Safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride (PAN)* dated 7th June, 2013 has held that the request of the domestic industry to extend safeguard duty so they will get some time to get prepared to face the international competition implies thereby that they are yet to commence steps for positive adjustment. The DG Safeguards refused to extend safeguard duty in that case holding that the domestic industry had failed to provide any evidence that they had taken positive steps to adjust to competition. Similarly, in this case, the domestic industry is seeking extension of time to take positive steps for adjustment, which shows that they have failed to take any positive steps for adjustment as per the original adjustment plan. As per the jurisprudence set by the DG Safeguards in the aforementioned case, such requests for extension of safeguard duty that lack evidence of positive adjustment must be refused. Therefore, no extension of safeguard duty can be allowed in this case.
19. In view of the above, the DG Safeguards is requested to terminate the investigation as the domestic industry has failed to take positive steps for adjustment as proposed in original investigation in violation of Rule 18(1)(i) of the Safeguard Rules. Therefore, the domestic industry's application for extension of safeguard duty must be rejected and this investigation must be terminated forthwith.

Standard of investigation: Requirement to find serious injury due to imports

20. The rule 18(3) is not referring to Rule 8 because it would have resulted in excessive superfluous enactment of legal provisions. Rule 18(1)(i) provides for recommendation for continuation of safeguard duty only when safeguard duty is necessary to “**prevent or remedy serious injury**”. It is beyond imagination and also logically impossible to remedy or prevent a problem without its existence. Prevention or remedy of a thing is possible when first it is determined that such thing exists. Therefore, before making any determination that the continuation of safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury; it is required to determine that such serious injury exists.
21. Further, Rule 18 read with Rules 5 and 11 requires the DG Safeguards to determine existence of serious injury or threat of serious injury and establish a causal link between the increased imports and serious injury or threat thereof in its final findings. When Safeguard Rules clearly mandate determination of serious injury or threat of serious injury in a review and establish causal link, the Applicant's argument to the contrary fails to hold any legal ground.
22. Further, section 8B(1) of the Customs Tariff Act gives power to Central Government to impose safeguard duties, only in such cases where imports of subject goods cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
23. The continuation of duty in review is required to be in accordance with the Article 7.2 of the AoS, which provides that the determination by the Authority shall be in compliance with the procedure set out in Articles 2, 3, 4 and 5 of AoS. Articles 2, 3, 4 and 5 deals with original investigation as well.

The Applicant Domestic Producer is having intrinsic cause of injury

24. The Applicant Domestic Producer is an incapable and inefficient producer of PX-13 and is not capable to produce and supply the sufficient quantity even if protection is given of any level for any period. The causes of injury to domestic industry are intrinsic and not because of imports.

25. Unjustified increase in cost of production due to excess capacity to produce 4ADPA

1. The Applicant Domestic Producer was having capacity to produce 8,500 MT of 4ADPA before installation of new facility. During the Financial Year 2012-13, it started trial production in the new plant at Dahej which has capacity to produce 10,000 MT of 4ADPA. **Therefore, during Financial Year 2012-13, the Applicant Domestic Producer incurred cost on plants having the total capacity to produce 18,500 MT of 4ADPA whereas the limiting factor, i.e. the capacity to produce PX-13 was only 8,500 MT which was not changed at all.** In such a situation, when cost to produce the penultimate input was high in unjustified manner, it was certain that the Applicant Domestic Producers would incur loss or have reduced profit, but that cannot be attributed to imports at all.

2. The excess capacity for production of intermediate (10,000 MT) increased the cost of production in unjustified manner (atleast A BIG AMOUNT TOWARDS DEPRECIATION and other fixed/semi-fixed costs). The old plant is still producing 4ADPA, therefore, an unjustified high capital employed is used for determination of weighted average cost of sales at reasonable return on capital employed.

25. Unjustified comparison of cost of production for domestic sales

1. The Applicant Domestic Producer was exporting more than 50% of the total production during 2009-10 which is less than 22% of the total production during 2012-13. Therefore, more than 50% of cost of production for the product should not be allocated towards production for domestic market. It is illustrated by an example:

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Other Fixed and Semi Fixed Costs (A)	Rs.	200000	200000	200000	200000
Depreciation (B)	Rs.	100000	90000	80000	70000
Total installed capacity (C)	kg	8500	8500	8500	8500
Total production (D)	kg	7500	6500	5500	4800
Quantity exported (E)	kg	3750	3000	1800	1100
Quantity sold domestically (F)	kg	3750	3500	3700	3700
Justified manner of cost allocation (G)					
Allocation of Depreciation for domestic market (H) =50% of (B)	Rs.	100000	100000	100000	100000
Allocation of Other Fixed and Semi Fixed Costs on domestic market (I) =50% of (A)	Rs.	50000	45000	40000	35000
Cost per unit for Domestic market (J)=[(H)+(I)]/(F)	Rs./kg	40	41.42857	37.83784	36.48649
Unjustified manner of allocation of cost (K)					
Allocation of Other Fixed and Semi Fixed Costs (L)=(A)x((F)/(D))	Rs.	50000	48461.54	53818.18	53958.33
Allocation of Depreciation for Domestic market (M)=(B)x((F)/(D))	Rs.	100000	107692.3	134545.5	154166.7
Unit cost for Domestic market (N)=[(L)+(M)]/(F)	Rs./kg	40	44.61538	50.90909	56.25

2. It is evident from above since the exports of the Applicant Domestic Producer decreased very sharply after 2009-10, the allocation of cost component should be made proportionate to the base year 2009-10 to make comparison for costs and profits for subsequent years. If cost of production is allocated in any manner such as based on quantity sold in domestic and export market or turnover in domestic and export market or weighted average of both, it will be an unjustified comparison in increase in costs of production for domestic market from base year to other years. The only possible justified manner of allocation of costs is if 50%-50% of all components of cost (except which are specifically related to particular market, like packing, sales promotion, etc.) are allocated to domestic and export market.

26. Safeguard duty cannot be enhanced in review.

1. The Applicant has requested for enhancement of safeguard duty in their petition. That such plea cannot be allowed as it is prohibited to enhance safeguard duty if applied for more than one year. Further, progressive liberalization of

safeguard duty is provided for in case of continuation or extension of safeguard duty both in the Safeguard Rules and AoS. Rule 17 of the Safeguard Rules, which deals with liberalization of safeguard duty is reproduced below:

*“If the duration of the duty levied under rule 12 exceeds one year, the duty shall be **progressively liberalized at regular intervals** during the period of its imposition.”*

2. In view of the above, Indian law on safeguard measures expressly provides for progressive liberalization of safeguard duty when such measure is applied for more than one year. The mandate of Indian law cannot be deviated with and the plea to enhance safeguard duty in review must be rejected forthwith.
3. The requirement of progressive liberalization is also mandated in Article 7 of the AoS that deals with duration and review of safeguard measures. The relevant extract from Article 7.4 of the AoS is reproduced below:

*“...where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall **progressively liberalize it at regular intervals** during the period of application... A measure extended under paragraph 2 **shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period**, and should continue to be liberalized.”*

4. Under the terms of Article 7.4, member countries cannot apply safeguard measures that are more restrictive than they were at the end of the initial period. Member countries are obligated to progressively liberalize safeguard measures. The WTO Panel Report in *Argentina - Footwear*, WT/DS121/R (**Exhibit 7**), while interpreting Article 7.4 of the AoS has held that the only two modifications permissible in a review of safeguard measure are either to eliminate the measure or increase the pace of liberalization. Para 8.303 of the Panel Report provides as follows:

“...we note that the only modifications of safeguard measures that Article 7.4 contemplates are those that reduce its restrictiveness (i.e., to eliminate the measure or to increase their pace of its liberalisation pursuant to a mid-term review). The Agreement does not contemplate modifications that increase the restrictiveness of a measure...”

5. Further, Article 12.2 of the AoS also mandates progressive liberalization of a safeguard measure and the member country is required to notify the same to the WTO Committee on Safeguards. The relevant extract from Article 12 of the AoS is reproduced below:

“...the Member proposing to apply or extend a safeguard measure shall provide the Committee on Safeguards with all pertinent information, which shall include evidence of serious injury or threat thereof caused by increased imports,...expected duration and timetable for progressive liberalization.”

6. If the safeguard measure in this case is continued or applied again, it cannot be enhanced above the rates that were provided in the duty timetable in the original investigation. In view of the above, it is requested that the DG Safeguards may be pleased to reject the plea of the Applicant regarding enhancement of safeguard duty.

F. M/s Rishroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai:

The submissions are similar point-wise as reflected above by M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea.

G.. M/s Kumho Petrochemicals Company (KPC), Korea

a. Additional post-Initiation submissions were again made which is as below:

1. India's state practice vis-a-vis safeguard measures applied by other WTO member countries maintains at international arena that once safeguard measure/duty is not extended before its expiry, then the country cannot extend it subsequently. If an extension of the measure/duty is made after lapse of sometime (even if of one day) after expiry of a measure, that will be covered under Article 7.5 of the AoS and a cooling-off period is required to be observed.
2. India's state practice must reflect in its domestic administration of safeguard law as well, so as to maintain consistency and harmony with India's international stance. Any contrary practice by India in its domestic administration of safeguard law will undermine and frustrate the legitimate expectations of India's trade partners under the WTO framework and project that India is professing a dubious double standard so as to afford undue protection to its domestic industry.
3. Kind attention of DG Safeguards is brought to India's WTO complaint against Turkey in DS 428 titled ***"Turkey - Safeguards Measures on Imports of Cotton Yarn (Other Than Sewing Thread)"*** ("Turkey - Cotton Yarn"). In the aforesaid matter, India challenged Turkey's extension of safeguard measure on cotton yarn. India asserted that Turkey's extension of safeguard measure on 28th January, 2012 after expiry of the same measure on 14th July, 2011 was inconsistent under Article 7.5 of the AoS as Turkey had applied the measure without waiting for the mandatory cooling-off period (minimum 2 years) under Article 7.5 of the AoS. **Turkey accepted India's position and entered into an agreement with India, wherein, Turkey agreed to withdraw the safeguard measure.** The DG Safeguards to procure records of the aforesaid proceedings from the Ministry of Commerce to assess India's position on the issue.
4. The relevant excerpts from the consultation request are reproduced below for ready reference:

India considered that the measures in question were inconsistent with Turkey's obligations under the following provisions of the GATT 1994 and the AoS in, at least, the following aspects:

(c) With regard to the definitive **measures applied on 28 January 2012** retroactively with effect from 15 July 2011, **Turkey acted inconsistently with the provisions of-**

- (iii) **Article 7.5 of the AoS as the initial application period of safeguard measures expired on 14 July 2011** and Turkey made the fresh application of measures on the same product on 28 January 2012 **without waiting for the mandatory period as required under Article 7.5 of the AoS;**

5. India, by way of the subject review, is set to commit the same mistake that it vehemently objected to in Turkey - Cotton Yarn. This would lead to violation of Article 7.5 of the AoS and inconsistent with India's state practice as India is taking a position contrary to its stance in Turkey - Cotton Yarn. By already professing to the world that India supports extension of a safeguard measure only when it is done consistently with provisions of the AoS, India, now cannot go back and do the complete opposite in the subject review. India is proceeding to decide the extension of safeguard measure in the subject review post its expiry on 29th August 2013, without waiting for the mandatory waiting period of 2 years in this case. Such a proceeding is not only in violation of the AoS, but also inconsistent with India's state practice as well. Such review proceeding under the garb of a skewed interpretation of the AoS by domestic industry should not be allowed as it is not only inconsistent with the AoS but will certainly tarnish the image of India.

b. Violation of Article X of the GATT - Initiation is faulty as the notification initiating the subject investigation was neither officially published promptly, nor made available on 29th August 2013, which is the date of initiation of the subject investigation

1. A serious lapse in the initiation of the subject investigation and complete disregard of India's commitments under the aegis of the WTO framework with regard to transparency and due process requirements concerning publication and administration of its rules and regulations.
2. Article X of the GATT puts obligation on member countries and their authorities to promptly publish their rules, regulations and administrative decisions to enable governments and traders to become acquainted with them. KPC is concerned that the Authority's failure to publish the initiation notice on 29th August 2013, which is the date of initiation of the subject investigation, has not only jeopardised the trade relations between traders of India and Korea, but has also adversely affected Govt. of Korea's right to enable itself to acquaint with the initiation of the subject administrative procedure initiated by the DG Safeguards i.e. initiation of the subject investigation, under the terms of Article X of the GATT 1994 ("GATT"). Such a measure denies due process rights under international law and is a clear violation of principles of natural justice which is the bedrock of India's judicial system.
3. The initiation notice for the subject investigation was published via 'The Gazette of India, Extraordinary No. 437 dated 29 August 2013'. **The same was officially published only on 2 September 2013 and made available 24 hours later i.e. 3 September 2013** as is evident from reply to an RTI application as mentioned below.
4. Perusal here was made of the RTI application filed by Shri Arvind Kapoor, Managing Director of M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., an interested party in the subject investigation, dated 16 September 2013 with the Department of Publication, Government of India. The Reply dated 19 November 2013 at serial no. 11 clearly shows that Gazette No. 437 was sent for official publication on 2 September 2013 at 12 noon. The relevant extract is produced below :

11. G.No.436,437,438 are sent to publication 2.9.13 at 12 noon. The job no. Is 3754,3756,3761 GI/13.

5. The Reply at serial no. 10 stated that the normal time of distribution of the gazette publication of up to 8 pages is 24 hours from the time of receipt in the press. KPC submits that Gazette No. 437 is 6 pages long. The concerned Gazette No. 437 was sent for official publication to press only on 2 September 2013 and therefore, it was made available only 24 hours after it was sent to publication i.e. on 3 September 2013. Therefore, it is to be construed that review was initiated only on 2nd/3rd September, 2013 after expiry of the safeguard duty imposed initially. It appears that the Authority had already taken a decision to initiate the subject investigation on 29 August 2013, i.e. 5 days prior to informing the interested parties i.e. the exporters and the concerned governments, and in this case, KPC and the Govt. of Korea.
6. This is a serious violation of Article X of the GATT and shows the Authority's prejudice in not informing the concerned interested parties promptly. The notification initiating the subject investigation is therefore illegal under the terms of Article X of the GATT. Relevant extract of Article X is produced below:

"Article X: Publication and Administrative of Trade Regulations

(1) *Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any member...shall be published promptly in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them.*

(2) *No measure of general application taken by any member imposing a new or more burdensome requirement, restriction or prohibition on imports...shall be enforced before such measure has been officially published.*

H. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) and its member companies (JK Tyre, CEAT, Apollo Tyre and MRF Limited):

1. THE INVESTIGATION IS ULTRA VIRES OF INDIAN SAFEGUARD ACT AND RULES.

The Rule 18 clearly provides that a review investigation should be for *continued imposition* and the dictionary meaning of the word 'continued'. As per Oxford Dictionary, the word has been defined as '*existing in the same state **without change or interruption***'. The use of the word '*continued*' twice in Rule 18 clearly indicates that to comply with Rule 18, the final findings in a safeguard review investigation should be published before the expiry of the existing Safeguard duty, i.e. when the original SG duty is in existence so that the final findings if required can recommend the continuation of the existing SG duty and not when the original SG duty has expired as in such a scenario no SG duty exists which can be 'continued'. In this respect, neither the Central Government and nor the Hon'ble DG, Safeguards has been granted power under the SG Act and the SG Rules to extend a Safeguard duty pending a review investigation.

2. In view of the above, it should be noted that the present review investigation was initiated dated 29 August 2013. As per the custom notification, the SG duty was imposed for a period of two years, which expired on 29 August 2013. Thus at present no SG duty is in existence against imports of PX 13 into India.

3. The above proposition is also supported by the decision of the Hon'ble High Court of Bombay in the matter of *Thirumala Chemicals v. Director General of Safeguards*. The petitioners in this case had approached the Hon'ble High Court of Bombay after the expiry of the custom notification imposing the SG duty. In this respect, the Hon'ble High Court of Bombay observed as follows:

Apart from the above consideration, the petitioners were expected to approach this Court well within time from the Notification No. 75/2009-Customs dated 30th June, 2009. Once the Notification has expired and allowed to die its natural death, it is not possible to infuse life in the dead Notification by a judicial order, that too, at interim stage.

4. The above decision by the Hon'ble Bombay High Court clearly establishes that once a customs notification imposing SG duty expires, the same cannot be resurrected even by a judicial order.

5. In this respect, the importers would draw the kind attention of the Hon'ble DG, Safeguards towards its own past practice in SG review investigations.

TABLE 1

Product	Final Findings in the original investigation	Custom Notification & Duration of duty	Initiation Notification for review investigation	Final Findings in the review investigation
Phenol	11 June 1999	Custom Notification No. 82/99. The duration of the duty was from 30/06/1999 till 29/06/2001	1 January 2001 (1st Review Investigation)	16 May 2001
Phenol	16th May, 2001 [Date of Final Findings of the First Review]	Custom Notification No. 73/2001. The duration of the duty was from 30/6/2001 till 29/6/2003	22nd October, 2001 (2nd Review Investigation)	11 December 2001
Acetone	7 October 1999	Custom Notification No. 7/2000. The duration of the duty was from 27/1/2000 till 26/7/2002	21 November 2001	4 February 2002
Soda Ash	6 October 2009	Custom Notification No. 122 / 2009. The duration of the duty was from 20/4/2009 till 19/4/2010	19 February 2010	13 April 2010

6. In the present SG review investigation, if recommendation for continuation of the SG duty is made in the final findings, the recommendation would be after the expiry of the SG duty, thus going against the established practice of the Hon'ble DG, Safeguards.

2. NO AUTHORITY UNDER THE STATUTE TO EXTEND DUTY DURING PERIOD OF REVIEW INVESTIGATION

As per the WTO Appellate Body, the AD duty can be extended pending a review investigation only because the WTO Agreement on Anti Dumping provides for the same. There is no corresponding provision under the WTO Agreement on Safeguards which is similar to Article 11.3 of the WTO Agreement on Anti Dumping or Article 21.3 of the SCM. In view of the same, it has to be concluded that the WTO Agreement on Safeguards does not envisage a situation where in the SG duty is extended pending a review investigation.

The Hon'ble DG, Safeguards being a quasi judicial body is obligated to act within the purview of Section 8B of the Act and Rules therein. The same has also been emphasized by the Government of India through a circular, which states that the Government of India has advised the *Commissioner of Customs that it being a quasi judicial body it is required to work within the provisions of the Customs Act.*

3. THE REQUIREMENT OF ADJUSTMENT PLAN HAS NOT BEEN FULFILLED

1. Rule 18 of the SG Rules provides that Rule 5 of the SG Rules would be applicable in case of a review investigation. As per Rule 5(2) (b) of the SG Rules, a petition for initiation of SG investigation should contain a statement with respect to *the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.*

2. The DI had requested imposition of SG duty for three years and had provided details of its adjustment plan. As per the final finding in the original investigation, the Hon'ble DG, Safeguards highlighted the following aspect of the adjustment plan of the DI:

the restructuring plan submitted by the DI focuses on capacity expansion to cater the growing demand and cost reduction..... Further the DI is hopeful of cost reduction on account of overhead cost It is seen that the claim of DI is well supported by Chartered Engineer Certificate on expansion and expenditure for new plant and practicing Cost Accountant Certificate on the cost incurred and the claim of cost reduction.

3. The DG, Safeguards based upon the adjustment plan, concluded that two year time period was sufficient for the DI to adjust positively. The adjustment plan provided by the DI in the present review petition is same as it was in the original investigation, i.e. reduction of cost on account of production of 4ADPA at Dahej plant.

4. The DG, Safeguards in the original investigation has already concluded that based upon this adjustment plan, the DI required two year of SG duty protection which it already enjoyed from August 2011 to August 2013. Thus the same adjustment plan could not be the basis on which the DI can be granted additional duty protection as it would mean that the DI is seeking 4 years of duty protection based on the adjustment plan which the Hon'ble DGS already decided that 2 year of duty protection was sufficient.

5. In view of the fact that there has been no change in circumstances with respect to adjustment plan, the requirement of Rule 5(2) (b) of the SG Rules has not been fulfilled. In view of the same, the present investigation should be terminated.

4. THE REQUIREMENT OF INCREASED IMPORTS, SERIOUS INJURY AND CAUSAL LINK IS ALSO APPLICABLE IN A SAFEGUARD REVIEW INVESTIGATION

1. The DI has argued that there is no requirement of existence of increase in imports or serious injury in a safeguard review investigation.

2. It is clear that according to Article 7(2) of the WTO Agreement on Safeguards, Article 2, 3, 4 and 5 of the WTO Agreement on Safeguards are also applicable in a SG duty review investigation. Article 2 states that there should be a finding of increased imports, serious injury or threat of serious injury and causal link before imposition of a SG duty. Further Article 4 of the WTO Agreement on Safeguards provides for determination of serious injury or threat of serious injury.

3. The requirement of increased imports, serious injury or threat of serious injury and causal link between the two would also be applicable in a safeguard review investigation. The same requirements are also provided in the Indian Safeguard Rules.

4. Rule 18(3) of the SG Rules provides that '*provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall mutatis mutandis apply in the case of review.*' Rule 5(1) of the SG rules provides as follows:

Except as provided in sub-rule (4), The Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like article or directly competitive article, initiate an investigation to determine the existence of "serious injury" or "threat of serious injury" to the domestic industry, caused by the import of an article in such increased quantities, absolute or relative to domestic production

5. Thus initiation of a SG review investigation pursuant to Rule 5(1) of the SG rules has to be for the purpose of determination of the existence of serious injury or threat of serious injury caused due on increase in imports either in absolute terms or in relative terms.

5. EXCESS CONFIDENTIALITY CLAIMED BY THE DI

The DI in its petition has provided indexed figures for domestic sales though the initiation notification has disclosed the same.

6. DI CANNOT CATER TO THE DEMAND OF THE USER INDUSTRY

1. The DI in their petition has argued that there has been an increase in imports in spite of imposition of the Safeguard duty. However ATMA being the largest user industry of the rubber chemicals under investigation submitted that the user industry is forced to import as the DI cannot cater to the demand of the user industry in India. The same is established as per the data provided in the initiation notification which is as follows:

TABLE 2

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
PX 13 Capacity (MT)	8500	8500	8500	8500
Total Demand for PX	14705	15949	15954	18315

13 (MT)				
Shortfall between capacity and demand (MT)	6205	7449	7454	9815
Total Import of PX 13 (MT)	10090	10607	9735	11664

Based upon the above figures, there is a shortfall of 9815 MT between supply and demand of PX 13 in 2012-13. Thus the import figures of 11664 MT of PX 13 in 2012-13 though marginally more than the shortfall, bridges the gap between the demand and supply of PX 13 in India. In order to bridge this shortfall, the DI has commissioned a new plant in Dahej, Gujarat for manufacturing 4 ADPA and which became operating from 7 March 2013. However even after this plant, it is doubtful that NOCIL would be able to cater to the demand of the user industry in India as NOCIL has traditionally been exporting nearly 50% of its production. The user industry in India with respect to PX13 is left with no other option but to import.

2. If the DI produced at 100% of capacity utilization and supplied the entire production to the domestic product, the same would still cater to only 46% of the entire demand. Therefore it was inevitable that the user industry would resort to import of the PUC. The demand of the PUC increased by 25% in 2012-13 as compared to 2009-10 while the imports increased by 16% in 2012-13 in the same corresponding period. Thus the increase in imports was less than the significant increase in demand. At the same time, the installed capacity of the DI remained at the same level, i.e. 8500 MT. The DI has been under duty protection for the last 8 years. However it made no efforts to cater to the domestic demand under duty protection. In fact in spite of the installed capacity of the DI only able to cater to 46% of the total demand,

7. THERE IS NO SUDDEN, SHARP AND SIGNIFICANT INCREASE IN IMPORT OF THE PUC.

1. There has not been a *recent sudden, sharp or significant* increase in import of the PUC which is a requirement under the Safeguards Act and the Safeguard Rules. The same has also been affirmed by the WTO Appellate Body in the matter of *Argentina-Footwear Safeguard*, wherein it observed that “*the increase must necessarily be “recent enough”, “sharp enough”, “sudden enough” and “significant enough”, both quantitatively and qualitatively so as to cause serious injury to the domestic industry.*” The following table illustrates the same:

TABLE 3

Initiation Notification	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Import of PX 13 (MT)	10090	10607	9735	11664
Import of PX 13 (Indexed)	100	105	96	116

2. The imports have increased gradually over the last 4 years in consonance with the demand due to the fact that the DI is not able to cater to the increasing demand of the PUC in India. The share of the DI and the imports has remained the same. This therefore implied that the imports have not taken the market share from the DI.

8. THERE IS NO SERIOUS INJURY

1. As per the DI petition, export sales decreased by 24% in 2010-11 as compared to 2009-10 and consequently the DI production decreased by 26% in 2011-12 as compared to 2009-10. Further the export sales decreased by 43% in 2011-12 as compared to 2009-10 and consequently the DI production decreased by 35% in 2012-13 as compared to 2009-10. Thus it is clear that there is a direct correlation between decline in export sales and consequent a decline in production of the DI.

2. The DI has argued that it is currently suffering losses. While in absence of the actual figures, it is not possible to accurately analyze the claim of the DI. ATMA would like to state that the DI conveniently has not highlighted the substantial and significant increase in the interest paid by the DI for PX 13. The market share of the imports has traditionally been in the range of 61%-68% and in 2012-13 the market share of imports is 63%. Thus the loss in the market share of the DI cannot be attributed to import of PX 13. In such circumstances it has to be concluded that import of PX 13 has not impacted the market share of the DI. Though the DI has made a claim that imports are undercutting the DI prices, it is to be noted that the DI has not even provided indexed figures of price undercutting. In absence of the same, the importers are not in a position to examine the claim of the DI with respect to price undercutting. In view of the above facts, ATMA submits that there has not been a sharp, sudden and significant increase in imports.

9. BREAK IN OF CAUSAL LINK

1. It is clear that the DI has not suffered any serious injury on account of increase in imports. Further causal link between imports and serious injury (if any) to the DI is broken because injury suffered by the DI is on account of dumping from China PR and Korea RP.
2. The DGAD based on an application by the same DI, i.e. NOCIL has initiated a SSR investigation against import of certain rubber chemicals including PX 13 from China PR and Korea RP. The POI in the present SG review investigation is from April 2009- March 2013 as compared to the injury period in the SSR investigation which is 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI which is from January 2012-December 2012. Thus the injury period which are being examined in both the investigation overlap considerably.
3. Therefore the same DI for the same product, i.e. PX 13 and for the same period is contesting before the DGAD that it is suffering material injury on account of dumped imports from China PR and Korea RP. On the other hand, before DGS, the DI is contesting that it is suffering from serious injury due to increase in imports from all countries.
4. It is not the argument of the importers that the DI cannot file these two simultaneous applications. However the argument of the importers is that if these two applications have been filed, the DI then is obligated to provide a segregation of injury suffered on account of dumped imports from China PR and Korea RP and on account of increase in imports from all the countries.
5. Thus it is the submission of the importers that the injury suffered by the DI is on account of its export performance and the same leads to a break in of the causal link between import and the claim of serious injury to the DI.

10. THE IMPOSITION OF THE SG DUTY IS NOT IN PUBLIC INTEREST

Article 3(1) of the WTO Agreement on Safeguards provides that a SG measure should be in public interest. The extension of the SG duty would not be in the public interest. There is a huge demand supply gap and DI is not able to even supply 50% of the demand of the user industry. Even if the DI produces at 100% of capacity utilization and supplies the entire production to the domestic product, the same would still cater to only 46% of the entire demand. Thus the user industry has no option but to import the PUC.

I. M/s NOCIL Limited, (Domestic Industry)

1. The domestic industry is suffering serious injury despite safeguard duty in existence as is evident from the following factors:
 - a. The imports are entering into the Indian market at an increased rate despite safeguard duty in existence.
 - b. The production of the domestic industry declined during the injury period.
 - c. The capacity utilization of the domestic industry declined significantly over the injury period.
 - d. The market share of imports has increased in the most recent period whereas that of domestic industry has declined despite safeguard duty in existence.
 - e. The prices of imports are lower than not only the selling price of domestic industry but also cost. Resultantly the domestic industry is forced to reduce its prices below cost thereby suffering huge losses.
 - f. The domestic industry in order to sustain in the market is offering sub optimal prices. Resultantly, the domestic industry has suffered huge financial losses.
 - g. The profit before interest has declined to negative level and the domestic industry is suffering cash losses.
 - h. The return on investments have also declined to negative levels
 - i. The above clearly establishes that the domestic industry is suffering injury despite safeguard duty in existence. The situation would worsen if the safeguard duty is not continued.
2. There is no safeguard duty at present and the domestic industry is left with no protection against the continued increase imports. In the event of non continuation of safeguard duty, the domestic industry would be forced to further reduce its selling price in order to match the same with the import price. The import price would decline equal to the quantum of safeguard duty and therefore the domestic industry would suffer huge losses, cash losses and negative return on investment if the safeguard duty is not continued and injury to the domestic industry will further intensify.
3. No substantial argument has been raised by any of the responding party on facts and law. None of the submissions made by the interested parties establishes that the claims of the petitioners with regard to continued imposition of safeguard duty are untenable. At the same time, domestic industry has provided sufficient evidence that they have taken measures to adjust to injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed.
4. In the light of the above circumstances, the petitioner submits that any delay in the application of safeguard measures would cause grave damage to the domestic industry. Therefore, it is requested that the Director General may kindly expedite the investigation to prevent the domestic industry from suffering irreparable damage.

12. Public Hearing:

A Public Hearing was fixed on 19/12/2013 wherein several Interested Parties and the DI attended. Most of the Post-hearing replies of the Interested Parties are similar to the post-initiation submissions made earlier. However, the post hearing submissions are dealt with as below and for the sake of brevity, post-initiation submissions are not repeated.

13. M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea:**A. Standing of the domestic industry**

1. In the public hearing dated 19th December, 2013 before the DG Safeguards, the Applicant had claimed that the break-up of capacity among all the domestic producers was the following:
 - a) NOCIL : 8500 MT/ yr
 - b) Merchem : 8500 MT/yr
 - c) Lanxess : 2000 MT/yr
 - d) PMC : 1000 MT/yr.
2. It is submitted that Merchem is undergoing capacity additions in order to produce the penultimate intermediate raw material (4-ADPA) as well. In light of the significant capacity additions, the production break up in the domestic market has undergone a significant change. It is to be noted that Merchem Ltd. is manufacturing 4-ADPA at its new facilities, as stated in its Annual Report 2010-11 (material attached as **Annexure 3**). The Applicant is thus facing stiff competition from other domestic producers who are seeking to capture the market. The relevant extract is reproduced below:

“Your company’s new unit for manufacturing 6PPD [N-(1, 3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine], an antioxidant-antiozonant used in the tyre and other rubber Industry is expected to commence its operation by the end of this year. Your company is also proposed to manufacture 4ADPA (4-Aminodiphenylamine), a chemical intermediate used in the manufacture of 6PPD”
3. The Applicant no longer has 50% of the capacity to produce the subject good. Therefore, it is highly likely that it will not ultimately produce 50% of the subject good. In such a situation, the question of whether the Applicant produces a “major proportion” of the subject good arises for consideration.
4. It is also to be noted that none of the other domestic producers have supported the petition of the Applicant and it is already known that the Applicant is suffering losses due to its own inefficiencies and competition with other domestic producers. In light of the above, it is submitted that this raises serious doubts regarding the standing of the Applicant to fall within the definition of “domestic industry” under the AoS and the Safeguard Rules.
5. KPC wishes to emphasize on the importance of reviewing the changes in the make-up of the domestic market. The Authority may take note of the substantial changes among the production and capacity of domestic producers and investigate the standing of the Applicant accordingly.

B. Indian law supports the view that a period can only be extended before the expiry of original period

1. Indian law supports the view that once the decision to extend the time has not been taken before its expiry, continuity is broken and a subsequent decision is illegal. For a valid decision, not only a request for extension of time has to be made but also the order to extend has also to be passed before expiry of the period. Once the continuity is broken, it would not amount to extension but a fresh levy of duty.
2. It is submitted that Section 110(2) of the Customs Act, 1962 contains provision which is *pari materia* to the provision contained in Article 7.2 of AoS and Rule 18(1) of the Safeguard Rules. Section 110(2) reads as follows:

“Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Collector of customs for a period not extending six months”

3. In this case, the continuity has broken, as the decision to extend the safeguard duty has not been taken before expiry. Therefore, the decision to levy safeguards duty as a result of an investigation would be invalid as that decision would come after the expiry of safeguard duty on 29th August 2013. Such a levy would be contrary to the jurisprudence laid down by the Hon’ble Supreme Court of India and several High Courts.

C. Initiation of subject review is in breach of India's state practice and destroys legitimate expectations of India's trading partners under the WTO framework

1. KPC brings to the notice of DG Safeguards India's state practice vis-a-vis safeguard measures applied by other WTO member countries. KPC submits that India maintains at international arena that once safeguard measure is not extended before its expiry, then the country cannot extend it subsequently. If an extension of the measure is made after lapse of sometime (even if of one day) after expiry of a measure, that will be covered under Article 7.5 of the AoS and a cooling-off period is required to be observed.
2. Kind attention of DG Safeguards is brought to India's WTO complaint against Turkey in DS 428 titled “Turkey - Safeguards Measures on Imports of Cotton Yarn (Other Than Sewing Thread)” (“Turkey - Cotton Yarn”). In the aforesaid matter, India challenged Turkey's extension of safeguard measure on cotton yarn. India asserted that Turkey's extension of safeguard measure on 28th January, 2012 after expiry of the same measure on 14th July 2011 was inconsistent under Article 7.5 of the AoS as Turkey had applied the measure without waiting for the mandatory cooling-off period (minimum 2 years) under Article 7.5 of the AoS. Turkey accepted India's position and entered into an agreement with India, wherein, Turkey agreed to withdraw the safeguard measure.
3. Therefore, it is submitted that the DG Safeguards direct the Applicant to provide the basis/methodology of allocation of cost on domestic and export production, though it may not disclose the actual heads costs or figures.

D. Verification of Accurate Capacities

1. It is a commonly known fact that estimation of the correct capacities of an Applicant for safeguard duty investigation is an extremely important exercise to be carried out while conducting an investigation. The DG Safeguards is required to verify what proportion of the installed capacity of the subject good is earmarked for domestic production and exports. This is the basic requirement that one is required to fulfill while verifying the production capacities of a domestic producer. After the communication of the information that the Applicant is setting up a new plant at Dahej, it is imperative to gather and ascertain all information regarding the capacity of the plant, how much of the installed capacity will be utilised for the production of the subject good for domestic consumption, and the exact earmarking of capacity to be employed for that purpose.

E. Market Share of the Domestic Producers

1. It is to be noted that the market share of the domestic producers with regard to the subject good functioned in the following manner during the period of injury as well as in the POI :

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
NOCIL Sales	MT	3383	3443	3690	3991
Lanxess India P Ltd	MT		640	1188	1700
PMC Rubbchem P Ltd	MT	1100	1005	1390	1250
Total		4483	5088	6268	6941
Share of domestic producers among themselves					
NOCIL	%	75.46	67.67	58.87	57.5
	Index	100	90	78	76
Lanxess India P Ltd	%		12.58	18.95	24.49
PMC Rubbchem P Ltd	%	24.54	19.75	22.18	18.01
Share of Other Domestic Producers	%	24.54	32.33	41.13	42.5
	Index	100	132	168	173

2. It is evident from the above table that the share of other domestic producers with regard to domestic sales consistently increased from 100 in 2009-10, to 132 in 2010-11, 168 in 2011-12 to 173 in the POI. This was accompanied by a decline in Applicant's sales from 100 in 2009-10, 90 in 2010-11 and 78 in 2011-12 to 76 in the POI. That means whereas other domestic producers share increased 73 basis points, the share of the Applicant decreased by 24 basis points at the same time. This gives way to two implications:
 - i) First, that any decline in the sales of the Applicant is not attributable to imports.
 - ii) Second, the existence of inter se competition between the domestic producers is the real cause of injury.
 - iii) The other domestic producers are offering the subject goods at lower prices than the Applicant.

F. Duty Free Treatment of Imported Good : It is a fact that a substantial portion of the imports of the subject goods (50% or even more) is used in manufacturing the final goods which is subsequently exported out of India. For that portion of imported goods, these are exempted from all duties, (i) antidumping, (ii) safeguard, (iii) Basic Customs, (iv) CVD equal to central excise duties. As a consequence the landed value of that portion of imports of the subject goods is lower than the NIP because the BCD is exempted. Further, such imports were not affected by the duties imposed to give protection, such as safeguard and anti-dumping duty.

G. No Evidence of injury due to imports

1. Without prejudice to other submission, it is submitted that the domestic industry have failed to provide evidence of causal link in increased imports of the subject product and serious injury or threat of serious injury to the Applicant.
2. The table is prepared from the application of Applicant and from the initiation notice. It can be seen from the table that when the imports increased from 10090 MT in 2009-10 to 10607 MT in 2010-11, the sales of the domestic industry improved from 100 indexed points to 105 indexed points whereas when the imports decreased from 10607 MT in 2010-11 to 9735 MT in 2011-12, the sales of the domestic industry also declined to 103 indexed points from 105 indexed points. However, when the imports increased from 9735 MT in 2011-12 to 11664 MT in 2012-13, the sales of domestic industry again increased from 103 indexed points to 105 indexed points. That means with the increase in imports, sales of the Applicant increase, and decrease in imports results in decrease in sales of the Applicant. This proves that increase in imports does not result in decrease in sales of Applicant. Therefore, this proves that the causal link between imports and sales of domestic industry is clearly absent.

3. Further, market share of imports have gradually gone down from 2009-10 to 2012-13. Market share of imports stood at 68% in 2009-10, which decreased to 65% in 2010-11 and decreased further to 61% in 2011-12. In 2012-13, market share of imports have only increased marginally by 2% and was 63% despite the huge demand of 18315 MT of the subject product. The market share of imports is still lower than the base year by 5%. On the other hand, market share of domestic industry was stable at 24% both in 2009-10 and 2010-11, decreasing marginally by 1% in 2011-12 and 2% in 2012-13. The market share of the Applicant did not decrease due to imports but, its market share is eaten up by other domestic producers, whose share increased from 8% in base year to 16% in 2012-13. Clearly, there is no causal link between imports and market share of the Applicant.

4. After analyzing Applicant's adjustment plan submitted to DG Safeguards and its annual report of 2012 – 2013, KPC notices that the commissioning of its Dahej plant was delayed by one year. The Dahej plant was to commission in March 2012 as per the adjustment plan given to DG Safeguards, but it could commission only in March 2013. Applicant's Dahej plant was to produce the subject product as per the adjustment plan, but as per the petition, it only produces an intermediate product 4ADPA. The Applicant has clearly failed to take positive steps to adjust to competition as per the adjustment plan and as a result, cannot request the Authority to give it more time to take positive steps. Applicant's failure to take positive steps for adjustment breaks the causal link between the imports and the alleged serious injury or threat thereof.

H. DG Safeguards should not continue with illegal investigation

1. As explained above, because at the end of the investigation, neither safeguard duty can be extended nor applied again, therefore, the present investigation is illegal and continuation of it is an abuse of due process of law. Any submission that it is only a stage of investigation and a final decision will be taken only on completion of it is in support of abuse of due process of law.

I. Safeguard duty cannot be enhanced in review

1. The Applicant has requested for enhancement of safeguard duty in their petition. It is submitted that such plea cannot be allowed as it is prohibited to enhance safeguard duty if applied for more than one year. Further, progressive liberalization of safeguard duty is provided for in case of continuation or extension of safeguard duty both in the Safeguard Rules and AoS. Rule 17 of the Safeguard Rules, which deals with liberalization of safeguard duty is reproduced below:

"If the duration of the duty levied under rule 12 exceeds one year, the duty shall be progressively liberalized at regular intervals during the period of its imposition."

2. In view of the above, it is submitted that Indian law on safeguard measures expressly provides for progressive liberalization of safeguard duty when such measure is applied for more than one year. The mandate of Indian law cannot be deviated with and the plea to enhance safeguard duty in review must be rejected forthwith.

3. It is further submitted that the requirement of progressive liberalization is also mandated in Article 7 of the AoS that deals with duration and review of safeguard measures. The relevant extract from Article 7.4 of the AoS is reproduced below:

"...where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application... A measure extended under paragraph 2 shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period, and should continue to be liberalized."

4. It is submitted that under the terms of Article 7.4, member countries cannot apply safeguard measures that are more restrictive than they were at the end of the initial period. Member countries are obligated to progressively liberalize safeguard measures. The WTO Panel Report in Argentina - Footwear, WT/DS121/R (**Annexure 11**), while interpreting Article 7.4 of the AoS has held that the only two modifications permissible in a review of safeguard measure are either to eliminate the measure or increase the pace of liberalization.

5. In view of the above, it is requested that the DG Safeguards may be pleased to reject the plea of the Applicant regarding enhancement of safeguard duty.

J. Quantitative restrictions cannot be applied in a review

1. The Applicant seeks quantitative restrictions on the subject product in their petition. It is submitted that acceptance of such a plea would be a blatant violation of the scope of review provided under Safeguard Rules and the AoS. Further, provision for quantitative restrictions is separately provided for in **Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012**. Therefore, the Applicant's claim is essentially to levy a new form of duty in a review, which is a completely perverse understanding of scope of review of a safeguard duty.

14. M/s Rishroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai:

The submissions are similar point-wise as reflected above by M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea.

15. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) and its member companies (JK Tyre, CEAT, Apollo Tyre and MRF Limited):

1. Import of PX 13 is inevitable as DI has created a demand supply gap for PX 13

a. The DI in its petition as well as during the public hearing has claimed that there has been a substantial increase in import of PX 13 in the country and which has been in spite of imposition of the SG duty. While the import of PX 13 increased from 10090 MT in 2009-10 to 11,664 MT in 2012-13, the same has to be understood in the context of significant increase in demand of PX 13 which increased from 15,954 MT in 2011-12 to 18,315 MT in 2012-13 and the installed capacity of the DI which remained constant at 8500 MT during the same period.

b. Thus while there was an increase in the demand of PX 13 by 25% in 2012-13 as compared to 2009-10, the installed capacity of the DI remained constant at 8500 MT. Therefore even if the DI would have produced at 100% capacity utilization and supplied the entire production to the domestic market, the same would have still catered to only 46% of the entire domestic demand. Therefore it was inevitable that the user industry resorted to import of the PUC. This therefore explains the reason for the continued import of PX 13 in India.

c. The DI at the public hearing argued that there is no demand supply gap in the country for PX 13. The same is incorrect. The initiation notification for PX 13 safeguard investigation clearly states that the installed capacity of the DI for 2012-13 is 8500 MT. Thus if the installed capacity would have increased for PX 13 subsequent to the commissioning of the new plant the same would have reflected in the initiation notification published in August 2013 in the safeguard review investigation. Thus the capacity of the DI is only 8500 MT out of which 50% is exported and only the remaining is for the user industry in India. The following table and graph illustrates the same:

PX 13	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Installed Capacity (MT)	5500	5720	5720	5900	8024	8024	8500	8500	8500	8500
Indexed	100	104	104	107	146	146	155	155	155	155
Total Demand (MT)	5971	8007	7424	8753	11095	10053	14705	15949	15954	18315
Total Demand (Indexed)	100	134	124	147	186	168	246	267	267	307

d. It is quite clear from the above chart and table that there is a huge mismatch between the total demand of PX13 and supply by the DI. However in spite of such huge mismatch, the DI has till date not taken any steps to correct this anomaly. In fact the new plant at Dahej which has been commissioned by the DI is only intended for the manufacture of 4 ADPA and not PX 13. Thus the commissioning of the new plant would also not correct this anomaly.

2. The total capacity for PX 13 in India is less than the total demand for PX 13

a. The DI has further argued at the public hearing that in order to assess the demand supply gap in the country, the Indian demand needs to be compared with the total Indian capacity and not the capacity of the petitioner company alone and if the same would be done, no demand supply gap exists for PX 13. However this submission of the DI is incorrect as well as highly misleading and should be rejected. The following table illustrates the same:

TABLE 2

	2012-13 (as per initiation notification)
DI Installed Capacity	8500 MT
DI Market Share	61.60%
Market Share of other Indian producers	38.4%
Installed Capacity of the other Indian producers	5299 MT
Total installed capacity for PX 13 in India	13,799 MT
Total Demand for PX 13 in India	18,315 MT

b. Thus the initiation notification in the present investigation informed that the DI has a market share of 61.60% among the Indian producers for PX 13. Therefore even if the remaining 38.4% of the Indian producers would be taken into consideration, the total Indian production would still amount to around 13,799 MT and which would be still less than the total Indian demand of 18,315 MT by 4516 MT. Thus even if the argument of the DI is accepted, there still exists a demand supply gap for PX 13.

3. THE INVESTIGATION IS *ULTRA VIRES* OF INDIAN SAFEGUARD ACT AND RULES.

a. It is a settled position in view of the injury submission by the importers that a SG duty should be in existence before recommendation for continuation of SG duty is made by the Hon'ble DGS pursuant to a SG review investigation under Rule 18. Rule 18 is reproduced below:

18. Review

1. *The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that,*

i. *safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;*

b. Thus the obligation upon the Hon'ble DGS under Rule 18 is for recommendation to the Central Government for continued imposition of duty. It is to be noted that there is no requirement under Rule 18 that the custom notification for continuation of SG duty should be notified before expiry of the SG duty. Therefore as long as the recommendation in the form of final finding by the Hon'ble DGS is made before the expiry of the SG duty, the requirement under Rule 18 would be fulfilled.

c. The past practice of the Hon'ble DGS also clearly establishes that in all the past safeguard review investigations, the recommendation by the Hon'ble DGS in the form of final findings has been published before the expiry of the SG duty. The following table illustrates the same:

Product	Final Findings in the original investigation	Custom Notification & Duration of duty	Initiation Notification for review investigation	Final Findings in the review investigation
Phenol	11 June 1999	Custom Notification No.82/99. The duration of the duty was from 30/06/1999 till 29/06/2001	1 January 2001 (1st Review Investigation)	16 May 2001
Phenol	16th May, 2001 [Date of Final Findings of the First Review]	Custom Notification No. 73/2001. The duration of the duty was from 30/6/2001 till 29/6/2003	22nd October, 2001 (2nd Review Investigation)	11 December 2001
Acetone	7 October 1999	Custom Notification No. 7/2000. The duration of the duty was from 27/1/2000 till 26/7/2002	21 November 2001	4 February 2002
Soda Ash	6 October 2009	Custom Notification No. 122 / 2009. The duration of the duty was from 20/4/2009 till 19/4/2010	19 February 2010	13 April 2010

d. The DI at the public hearing had stated that a SG duty can be continued even 'with or without pause' and in this respect highlighted the *Soda Ash* investigation wherein the custom notification for continued imposition of SG duty was made after the expiry of the SG duty. However the *Soda Ash* investigation further supports the position of the importers.

e. The custom notification imposing SG duty against import of Soda ash into India was in effect till 19 April 2010. The final findings in the *Soda Ash review investigation* was published dated 13 April 2010. Thus the recommendation by the Hon'ble DGS in the form of final findings in the *Soda Ash review investigation* was made to the Central Government when the SG duty was in existence. Therefore the final findings in the *Soda Ash review investigation* was in compliance with Rule 18 and which supports the above submission of the importers that till date there has not been a single SG review investigation wherein the recommendation by the Hon'ble DGS in the form of final findings has been made after expiry of the SG duty.

f. In view of the above, it should be noted that the present review investigation was initiated dated 29 August 2013. As per the custom notification, the SG duty was imposed for a period of two years, which expired on 29 August 2013. Thus at present no SG duty is in existence against imports of PX 13 into India. Since no SG duty is currently in existence, the present review petition is not maintainable as the Central Government would not be able to 'continue' the existing SG duty pursuant to a final finding recommending 'continued imposition of duty'.

4. Intent of the Legislature

- a. The DI at the public hearing had argued that the use of the word 'continued imposition' in Rule 18 would imply 'with or without pause' and had cited the *Soda Ash* safeguard investigation. However as the importers have already established above, the final findings in the *Soda Ash* safeguard investigation was published before the expiry of the SG duty and thus the reliance of the DI on the *Soda Ash* safeguard investigation is misplaced.
- b. Further the importers would also point out that the Legislature has intentionally used the word 'continue' in Rule 18 of SG rules and has not used the word 'extend'. This is in contrast to Section 9A (5) of the Custom Tariff Act, 1975 wherein both the words are used but with different implications. Section 9A (5) of the Custom Tariff Act, 1975 is reproduced below:

Section 9A (5)

The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

- c. In the above provision, the word 'extend' in paragraph 2 clearly stipulates that the period of commencement of duty shall be from the date of order of commencement of such duty. Therefore the AD Act itself provides that there can be a gap between the previous AD duty and the AD duty which is being extended for another 5 years pursuant to a sunset review investigation.

- d. However if the Central Government intends to 'continue' the AD duty pending a sunset review investigation, the same has to be without any gap as long as the sunset review investigation has been initiated before the expiry of the AD duty. Thus the AD duty would continue to be in existence without any gap till the pending of the sunset review investigation.

Thus the intention of the legislature with respect to the use of the words 'extend' and 'continue' is clearly demarcated in the AD Act. The importers rely on this guidance and would draw the attention of the Hon'ble DGS that Rule 18 of the SG Rules uses the word 'continue'. This clearly demonstrates that the intention of the legislature by inserting the word 'continue' in Rule 18 was to ensure that the recommendation by the Hon'ble DGS should be published before the expiry of the SG duty.

- e. Lastly the Hon'ble DGS being a quasi judicial body cannot act beyond the mandate of the SG Act and the SG Rules. This position of the importers is supported by the ruling of the Hon'ble High Court of Bombay in the matter of *Thirumala Chemicals v. Director General of Safeguards*. The petitioners in this case had approached the Hon'ble High Court of Bombay after the expiry of the custom notification imposing the SG duty. In this respect, the Hon'ble High Court of Bombay observed as follows:

Apart from the above consideration, the petitioners were expected to approach this Court well within time from the Notification No. 75/2009-Customs dated 30th June, 2009. Once the Notification has expired and allowed to die its natural death, it is not possible to infuse life in the dead Notification by a judicial order, that too, at interim stage.

- f. The above decision by the Hon'ble Bombay High Court clearly establishes that once a customs notification imposing SG duty expires, the same cannot be resurrected by a judicial order. The Hon'ble DGS cannot recommend to the Central Government for continuation of the SG duty as the SG duty has already expired and the SG Act and the SG Rules does not provide the power to extend the SG duty pending the review investigation. In view of the same, this investigation should be terminated.

5. THE REQUIREMENT OF POSITIVE ADJUSTMENT HAS NOT BEEN FULFILLED

- a. The DI in its petition in the original investigation had stated as follows:

*NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce ****MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX 13 as one of the product.*

b. However this position of the DI suddenly changed in the review investigation wherein the DI states that it is manufacturing 4 ADPA at the new plant and as per the DI, this is the **only product which would be manufactured at Dahej.**

c. Further the final findings in the original investigation also stated that the production in the new plant would start from April 2012. However as per the available information, the production at the new plant has started in March 2013 and which is a delay of one year.

d. In view of the above, it is the submission of the importers that the DI has not implemented the adjustment plan outlined and approved by the Hon'ble DGS in the original investigation. In view of the same, it cannot be concluded that the DI has been adjusting positively as the adjustment plan itself has not been implemented.

6. The requirement of adjustment plan has not been fulfilled

a. In the original investigation, the DI had requested imposition of SG duty for three years and had provided details of its adjustment plan. As per the final finding in the original investigation, the Hon'ble DGS highlighted the following aspect of the adjustment plan of the DI:

the restructuring plan submitted by the DI focuses on capacity expansion to cater the growing demand and cost reduction..... Further the DI is hopeful of cost reduction on account of overhead cost..... It is seen that the claim of DI is well supported by Chartered Engineer Certificate on expansion and expenditure for new plant and practicing Cost Accountant Certificate on the cost incurred and the claim of cost reduction

b. Thus the DI had requested for imposition of SG duty for three years so that it could reduce its cost by commissioning a new plant at Dahej. However the Hon'ble DGS recommended imposition of SG duty for a period of two years. Thus the Hon'ble DGS based upon the adjustment plan provided by the DI concluded that two year time period was sufficient for the DI to adjust positively.

c. However the DI is now requesting for extension and enhancement of the SG duty. Since the DI is requesting for extension and enhancement of the SG duty beyond the period of two years which in the opinion of the Hon'ble DGS was sufficient to adjust positively, the DI is required to provide a fresh adjustment plan in order to fulfill the requirement of Rule 18 read with Rule 5(2) of the Indian SG Rules.

d. In this respect it should be noted that the adjustment plan provided by the DI in the present review petition is same as it was in the original investigation, i.e. reduction of cost on account of production of 4ADPA at Dahej plant. However the Hon'ble DGS in the original investigation has already concluded that based upon this adjustment plan, the DI requires two year of SG duty protection which it already enjoyed from August 2011 to August 2013. Thus the same adjustment plan cannot be the basis on which the DI can be granted additional duty protection as it would mean that the DI is seeking 4 years of duty protection based on the adjustment plan which the Hon'ble DGS already decided that 2 year of duty protection was sufficient. Thus the argument of the DI is in effect would lead to review of the decision of the Hon'ble DGS with respect to 2 years being sufficient based period of duty protection, even though the Indian SG Act and the Rules does not permit the same.

e. Therefore in view of the fact that there has been no change in circumstances with respect to adjustment plan, the importers submit before the Hon'ble DGS that the requirement of Rule 5(2) (b) of the SG Rules has not been fulfilled. In view of the same, the present investigation should be terminated.

7. THE REQUIREMENT OF INCREASED IMPORTS, SERIOUS INJURY AND CAUSAL LINK IS ALSO APPLICABLE IN A SAFEGUARD REVIEW INVESTIGATION

The DI in its petition as well as in the public hearing has stated that there is no requirement of existence of increase in imports or serious injury in a safeguard review investigation. However the arguments of the DI are not supported by the existing framework of the WTO Agreement on Safeguards, SG Act and the SG Rules and thus should not be accepted.

8. THERE IS NO SUDDEN, SHARP AND SIGNIFICANT INCREASE IN IMPORT OF THE PUC

The importers in the above paragraphs have clearly established that there is a huge demand supply gap for PX 13 in India and the DI is not interested to cater to the demand of the user industry in India. Thus in view of the fact that user industry in India has to resort to import to meet their demand, ATMA submits that there has not been a *recent sudden, sharp or significant* increase in import of the PUC which is a requirement under the SG Act and the SG Rules.

9. THERE IS NO SERIOUS INJURY

ATMA in its injury submission has clearly established that the claim of the DI with respect to serious injury is not established based upon the data provided in the petition. The DI in the public hearing has not presented any new arguments with respect to serious injury. Thus ATMA relies on its arguments made in the injury submission to rebut the claim of serious injury of the DI with a liberty to rebut any new claim of serious injury in the rejoinder if the DI advances any new claim with respect to serious injury in their Post PH WS.

10. NO SEGREGATION OF INJURY

a. The importers would first like to draw the attention of the Hon'ble DGS towards the statement of the DI made at the public hearing. The DI has stated that import of PX 13 is mainly from Korea RP, China PR and the European Union. Thus if imports are mainly from these countries, then it is logical to assume that injury to the DI is also taking place

against import of PX 13 from these countries. However DGAD has already imposed anti dumping duty against import of PX 13 from these countries.

- The DI initiated an anti dumping (“AD”) investigation against import of rubber chemicals PX 13 originating or imported from European Union and Chinese Taipei. An AD duty was imposed subsequently. In 2010 a SSR investigation was initiated against the above mentioned AD duty and pursuant to which the AD duty was continued against import of PX 13 from the European Union.
- In 2007, the same DI initiated an AD investigation against import of PX 13 (6PPD) from China PR and Korea RP and AD duty was imposed subsequently and which was increased against import of PX 13 from Korea RP in 2011.

b. Thus if the DI has been suffering injury against import of PX 13 from these countries, the same has already been taken care of by the DGAD by imposition of anti dumping duties. However if the DI still request for imposition of SG duty, the DI is obligated to segregate the injury suffered on account of dumping and injury suffered on account of increase in import of PX 13 from the above mentioned countries.

c. It should also be noted that the DGAD based on an application by the same DI, i.e. NOCIL has initiated a SSR investigation against import of certain rubber chemicals including PX 13 from China PR and Korea RP. The POI in the present SG review investigation is from April 2009- March 2013 as compared to the injury period in the SSR investigation which is 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI which is from January 2012-December 2012. Thus the injury period which are being examined in both the investigation overlap considerably.

d. Therefore the same DI for the same product, i.e. PX 13 and for the same period is contesting before the DGAD that it is suffering material injury on account of dumped imports from China PR and Korea RP. On the other hand, before DGS, the DI is contesting that it is suffering from serious injury due to increase in imports from all countries.

e. It is not the argument of the importers that the DI cannot file these two simultaneous applications. However the argument of the importers is that if these two applications have been filed, the DI then is obligated to provide a segregation of injury suffered on account of dumped imports from China PR and Korea RP and on account of increase in imports from all the countries.

11. INJURY ON ACCOUNT OF DECLINE IN EXPORTS

Further the importers would also highlight the fact that the DI has suffered injury on account of decline in demand in export markets which has affected the production and export sales.

12. THE IMPOSITION OF THE SG DUTY IS NOT IN PUBLIC INTEREST

a. In *Methyl Acetoacetate Safeguard investigation*, the DGS noted that the pharmaceutical industry was an important user of the subject product. In concluding that levy of duty would not be in public interest it was observed that “DI has not been able to give evidence as to how imposition of safeguard duty on the PUC will not affect these consumers, a few of whom are in sensitive pharma sector, and that the impact would be minimal so as to be in public interest.” The Hon’ble DGS refused to recommend imposition of duty as the requirement of public interest among other factors was not fulfilled by the DI.

b. As mention in the preceding paragraphs, the DI has been enjoying duty protection for the last 8 years and during this period has not taken any steps to increase its capacity so as to cater to the domestic demand of PX 13 in India. As of now, the DI can only cater to 46% of the total demand for PX 13 in India. Thus the user industry has to resort to imports. However for the last 8 years the user industry has been paying additional duties because of the inability of the DI to supply and it cannot be further penalized for the inability of the DI to become competitive even after 8 years of duty protection.

c. In view of the above ruling, the DI is under an obligation in the present SG review investigation to demonstrate that the continued imposition of safeguard duty after 8 years would not impact the user industry and would be in public interest. However till date the DI has not demonstrated the same. In view of this lacuna and the past practice of the Hon’ble DGS, the present investigation is liable to be terminated.

16. THE EUROPEAN COMMISSION:

The European Commission (the Commission) would like to thank the Indian authorities for the opportunity to present comments in this hearing with regard to the review of the safeguard measures on imports of the rubber chemical PX-13.

a. To begin with, and as raised in previous submissions, the Commission does not agree with the position of the Indian authorities that a safeguard duty can be imposed in addition to an ineffective anti-dumping. If anti-dumping measures prove to be ineffective through e.g. absorption or circumvention, the anti-dumping measures should be reviewed.

b. Therefore, the Commission also considers that the extension of the safeguard measures in this case is not warranted. The domestic industry is already protected by anti-dumping duties on imports from China, Korea and the EU (covering almost the totality of imports into India) imposed in 2005 and 2008.

c. The Commission trusts that the Indian authorities will reach the conclusion that penalising fairly traded imports, irrespective of their country of origin and whether or not they individually cause any injury to the domestic industry is not the solution.

d. Furthermore, we would like to raise the following issues that have attracted our attention when analysing the industry petition and the Notice of Initiation:

- i. As we have mentioned at the beginning, the SFG measures should not have been imposed on top of the AD measures in the first place. In addition, the initiation of this review investigation has serious procedural deficiencies and thus the extension of the safeguard measures in this proceeding would not be legally possible.
- ii. In particular, the measures under review expired on 29 August 2013 and therefore the only possibility to have a safeguard measure in place against the same product for an additional period would necessarily require the imposition of a new measure, following a new investigation.
- iii. However, according to Article 9.2 of the WTO Agreement on Safeguards, a safeguard measure can be applied again on a product which has been under measures, only two years after the expiry of the original measure, i.e. not before August 2015 in this case.
- iv. Therefore, India should immediately terminate this investigation and confirm that the measures have expired.
- v. This being said, should India nevertheless decide to go forward with the current procedure (which would be manifestly illegal), the Commission insists that any extension of the measures in this case would not be warranted, in particular:
- vi. It is recalled that the petitioner claimed in its application that imports continue to cause serious injury. Since measures have been imposed, the sales of the domestic industry have only slightly increased and the corresponding market shares were relatively stable. It seems however, that the only other (non-complaining) Indian producer benefited from the measures since its market shares doubled during the period considered (from 8% in 2009-10 to 16% in 2012-13). This clearly indicates that the domestic industry is facing problems caused by reasons other than imports.
- vii. In this context, the Commission would like to remind the Indian authorities that, according to the Article 7.4 of the WTO Agreement on Safeguards, a measure, if extended, shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period, and should continue to be liberalised. Extending a currently ineffective measure at an inevitably increased level would thus be impossible to justify.

e. To conclude, the Commission reiterates that, since the measures have expired, they cannot be extended via a review investigation, and a new imposition cannot take place for the next two years.

g. In any event, the measure proved to be ineffective and any injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to imports. Extending the measures is not justifiable from a legal and an economic point of view and the Commission therefore urges the Indian authorities to terminate the current procedure and confirm the expiry of the measures.

17. Domestic Industry

M/s NOCIL Limited, (Domestic Industry):

A. Previous history of increased imports causing serious injury leading to imposition of safeguard duty

1. An investigation was earlier initiated by the Director General (Safeguards) on an application filed by NOCIL under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"], seeking imposition of Safeguard Duty on imports of PX-13 into India establishing that increased imports of PX-13 was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of PX-13 in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, safeguard investigation against imports of PX-13 was initiated vide notice of initiation dated 27th December, 2011. The Director General issued final findings on 6th June, 2011, recommending imposition of definitive safeguard duty for a period of two years. Based on the recommendation of Director General Safeguard, the Central Government imposed definitive Safeguard duty for two years, @ 30% plus anti-dumping duty payable from 30-08-2011 to 29-08-2012 and @25% plus anti-dumping duty payable from 30-08-2012 to 29-08-2013.

B. Dumping of PX-13 causing injury to the domestic industry.

1. Imports of PX-13 are at present subject to anti dumping measures following an elaborate anti dumping investigation undertaken by the Designated Authority. The Hon'ble Authority earlier examined the nature and extent of dumping and its effect on the Domestic Industry with respect to imports of PX-13 from China and Korea RP; European Union and concluded that the producers in the subject countries were exporting the product under consideration at dumping prices and the same caused injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification dated December 12, 2008 on all imports of PX-13(6PPD) from China and Korea RP and vide finance notification No. 94/2005-Customs dated 20th October, 2005 on Imports of PX-13 from Chinese Taipei and EU. Subsequently, in the year 2010, the Designated Authority conducted a mid term review in order to examine whether there is a need to enhance the quantum of anti dumping duty with respect to PX-13 from Korea RP. Consequently, anti dumping duty earlier imposed on Korea RP were enhanced so as to provide relief to the Domestic Industry. The authority at present conducting sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of PX-13 from China and Korea RP. Further in the year 2010 the Authority conducted sunset review investigation of anti-dumping

duty on imports of PX-13 from EU and Chinese Taipei. Consequently, anti dumping duty earlier imposed on EU was continued and enhanced vide custom Notification No.67 /2011-Customs dated 28th July, 2011.

C. Legal Requirements for extension of period of imposition of safeguard duty

1. Section 8B(4) of Custom Tariff Act, 1975

“The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition”

2. Section 8B(4) prescribes following two conditions which needs to be fulfilled while extending the period of imposition of safeguard duty

a. Adjustment plan

- i. Domestic industry has initiated some steps
- ii. Some steps have already been taken
- iii. Some steps are being taken
- iv. Some steps will be taken to adjust itself

b. It is necessary to extend safeguard duty

3. There is no other requirement prescribed in the law for extension of period of imposition of safeguard duty. However, it has been argued by other interested parties that Rule 18 of the Safeguard Duty Rules provides for application of rules 5, 6, 7 and 11 and therefore the requirement of increased imports and serious injury are fully applicable in extension case as well. The petitioners submit that (a) existence of imports or increase in imports is not a pre-requisite at the time of extension of duty; (b) existence of injury is not a pre-requisite at the time of extension. Following is relevant in this regard:

a) Existence of imports or increase in imports not a pre-requisite at the time of extension of duty

i. The Act does not provide for a requirement of increased imports while extending the safeguard duty. This is clearly borne out by the wordings of section 8B(4) which is as follows

Section 8B(4) *“The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:*

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition”

ii. Further Rule 18 of Safeguard Duty Rules under the Customs Tariff Act, 1975 states as follows:

18 Review

1. The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that,

- i. *safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;*
- ii. *there is no justification for the continued imposition of such duty; recommend to the central Government for its withdrawal:*

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the midterm of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalization of duty.

2. Any review initiated under sub-rule (I) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.

3. The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall **mutatis mutandis** apply in the case of review.

iii. It would be seen that Rule 18 prescribes applicability of rules 5, 6, 7 and 11 on *mutatis mutandis* basis. It is important to understand the meaning of *mutatis mutandis* in this regard. The Hon'ble Supreme Court in the matter of *Ashok Service center and Ors v State of Orissa* has stated as follows in this regard

17. Before considering what provisions of the Principal Act should be read as part of the Act, we have to understand the meaning of the expression '*mutatis mutandis*'. Earl Jowitt's '*The Dictionary of English Law (1959)*' defines '*mutatis mutandis*' as '*with the necessary changes in points of detail*'. Black's Law Dictionary (Revised 4th Edn. 1968) defines '*mutatis mutandis*' as '*with the necessary changes in point of detail, meaning that matters or things are generally the same, but to be altered when necessary, as to names, offices, and the like*'. Houseman v. Water house, 191 App. Div. 850, 112 N.Y.S. 249. 251.' In Bouvier's Law Dictionary (3rd Revision, Vol.

II), the expression 'mutatis mutandis' is defined as '*The necessary changes. This is a phrase of frequent practical occurrence, meaning that matters or things are generally the same, but to be altered when necessary, as to names, offices, and the like. Extension of an earlier Act mutatis mutandis to a later Act brings in the idea of adaptation, but so far only as it is necessary for the purpose, making a change without altering the essential nature of the thing changed, subject of course to express provisions made in the later Act.*.....

- iv. It would be seen that the meaning of the expression Mutatis Mutandis is “necessary changes”, meaning thereby that matters or things are generally the same, but to be altered, when necessary”. Therefore, it does not imply applicability of provisions as it is; but the provision has to be applied with necessary changes. In the instant case, although Rule 18 provides for applicability of certain provisions; but the use of the expression mutatis mutandis clearly establishes that such provisions needs to be made applicable keeping in mind the express provision made in the Act i.e., Section 8B(4) of the Custom Tariff Act.
- v. The maximum duration of any safeguard measure is four years, unless it is extended consistent with the Agreement's provisions. In particular, a measure may be extended **only if** it is found, through a new investigation, that its continuation is necessary to prevent or remedy serious injury, and **only if** evidence shows that the industry is adjusting.
- vi. Increased import is not a pre-requisite for extension of safeguard duty investigation can be derived from the recent amendment (2012) in Section 8C of Customs Tariff Act, 1975. Section 8C (5) of the said act before amendment stated as follows:

5. *The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such impositions.*

Provided that if the Central Government is of the opinion that such articles continues to be imported into India, from People's Republic of China, in **such increased quantities** so as to cause or threatening to cause market disruption to domestic industry and the safeguard duty should continue to be imposed. It may extend the period of such imposition for a period not beyond the period of ten years from the date on which the safeguard duty was first imposed.

- vii. Whereas the Central Government in 2012 amended the said provision which states as follows now
“Provided that if the Central Government is of the opinion that such article continues to be imported into India from the People's Republic of China so as to cause or threatening to cause market disruption to domestic industry, the Central Government may, notwithstanding the measures taken by the domestic industry towards adjustment to such market disruption or any threat arising thereof, if considers necessary that such duty should continue, extend the period of imposition of such safeguard duty for a period not beyond the period of ten years from the date on which the safeguard duty was first imposed.”.

- viii. The memorandum for explanation to the amendment states as follows:

Section 8C empowers the Central Government to levy safeguard duty on imports from Peoples' Republic of China. It is being amended to provide that such duty may continue if the Central Government is of the opinion that such articles or goods continue to be imported into India so as to cause or threaten to cause market disruption to domestic industry even though the latter has taken measures to adjust to such disruption. The amendment would align the provisions of the section with the Transitional Product Specific Safeguard Mechanism under Chinese Accession Protocol signed with WTO in 2001.

- ix. It would be seen from the above that the Central Government has specifically deleted the requirement of increased imports from the proviso of Section 8C(5) to align it with the general safeguard mechanism. Hence increased imports in not a pre requirement for extension of safeguard duty investigation.
- x. The domestic industry refers and relies on Wheat Gluten: Extension of Action, wherein the USITC observed as follows:

Section 204(c)(1) of the Trade Act provides that the Commission, upon the request of the President or the concerned industry, is to “investigate to determine” –

*whether action under section 203 continues to be necessary to prevent or remedy serious injury
and*

whether there is evidence that the industry is making a positive adjustment to import competition.

Thus, in order to make an affirmative determination, section 203(c)(1) requires that the Commission make two affirmative findings – (1) whether the relief action continues to be necessary to prevent or remedy serious injury, and (2) whether there is evidence that the industry is making a positive adjustment to import competition. Neither the statute nor the legislative history of the URAA further describes the nature of the determination the Commission must make under section 204(c), or sets out factors to be considered in making that determination.

However, the term “positive adjustment” is defined in section 201(b) of the Trade Act. A positive adjustment to import competition is considered to have occurred when

(A) the domestic industry –

- (i) is able to compete successfully with imports after actions taken under section 204 terminate, or*

- (ii) the domestic industry experiences an orderly transfer of resources to other productive pursuits; and
(B) dislocated workers in the industry experience an orderly transition to productive pursuits.

The statute further provides that the domestic industry may be considered to have made a positive adjustment “even though the industry is not of the same size and composition” as the industry at the time the investigation was instituted under section 202(b).

b) Existence of serious injury not a pre-requisite at the time of extension of duty

- At the stage of extension of safeguard duty, as is evident from the legal provisions, there is no requirement of existence of either increased imports or serious injury to the domestic industry. The rules clearly provide for extension of safeguard duty in case the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed. Therefore, the Director General (Safeguards) is not required to find whether imports of PX-13 have increased in absolute terms or in relation to production and consumption in India. Nor the Director General (Safeguards) is required to find that the domestic industry has suffered serious injury within the meaning of the rules. This is also established by the language of Rule 18, which provides for “mutatis mutandis” application of Rule 5 and Rule 11. Further, this is established by the fact that Rule 8 is not even made applicable in case of such review. In fact, the domestic industry may not have been suffering injury because of the very imposition of safeguard duty and therefore existence or otherwise of injury to the domestic industry cannot be a pre-requisite for extension of safeguard duty.
- The circumstances which were prevalent at the time of imposition of previous safeguard duty are very much in existence even today. Further, the domestic industry is taking measures to become competitive and the process is underway. Under the circumstances, if the safeguard duty is not extended, the domestic industry would continue to suffer serious injury. It is therefore vital that the present safeguard duty may be extended further for a period of two years.
- Notwithstanding the above, it would be seen from the information provided hereinbelow that there is significant increase in imports of PX-13 in India and the injury to the domestic industry has intensified further in the most recent period.

D. Extension of duty after its expiry.

- It has been argued by interested parties that since there is no safeguard duty in existence and the present review is not maintainable. It is submitted that the review investigation was initiated on 29th August, 2013 i.e. before expiry of safeguard duty. Further the petitioner refers and relies on the following
 - Past precedence:** it is submitted that in the past as well the duty was extended after expiry of the existing safeguard duty. One such instance in safeguard duty investigation against imports of soda ash. Relevant dates and events are as follows:

SN	Date	Event
1	Findings by D.G.	6th October, 2009
2	Notification by Finance Ministry	5th November, 2009
3	Duty valid upto	19th April, 2010
4	Review recommendations by D.G.	13th April, 2010
5	Notification by Finance Ministry	28th June, 2010

a).i. It would be seen that the duty was extended after expiry of the duration of safeguard duty. Further, the Director General (Safeguards) specifically addressed the issue of extension of safeguard duty after expiry of existing duty. Relevant part of the decision are extracted below.

“The above decision of the Director General (Safeguards) was accepted by the Central Govt. Therefore, the issue raised by the interested parties is well settled”.

- Comparison of safeguard law and anti-dumping laws** – Numerous decisions of the Central Govt. in connection with anti dumping are directly relevant on this issue. Following is the comparison of relevant provisions of review in anti-dumping law and safeguard duty law :

Provision under safeguards law	Provision under dumping law
Section 8B (4): The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition: Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken	Section 9A (5): The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition: Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time

measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition : Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed	to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension: Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) i. It would be seen that there are two extensions in anti dumping law which are (1) extension for one year pending investigation (2) five year extension. There is only one extension in safeguard law. However, the obligations are the same and the issue involved is also the same, i.e., whether anti dumping duty or safeguard duty can be extended after the existing duty has completed its period and therefore the anti dumping proceedings are very much relevant in the present proceedings. It is settled position that the anti dumping duties have been extended even after the expiry of the existing duties. Such being the case, there is no bar in extension of safeguard duty after its expiry of existing duty, provided a review is initiated before its expiry. Following are some instances of one year extension and five year extension cases in anti-dumping investigation proceedings.

i. One year extension cases

SN	SSR cases initiated/ on-going	Country	Date of expiry of Original Duty	Extension by MOF (One Year Extension)
1	Diclofenac Sodium	China	9-Apr-13	13-Nov-13
2	Pentaerithrytol	Taiwan	27-Apr-13	25-Jun-13
3	Acetone	Korea	9-Jun-13	25-Jun-13
4	Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R and DVD-RW)	China, Hongkong, Taiwan	22-Jul-13	29-Aug-13
5	Cable ties	China, Taiwan	30-Oct-13	12-Nov-13
6	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	21-Aug-12	24-Aug-12
7	Phosphoric acid, technical or food grade	China PR	13-Sep-12	25-Sep-12
8	Phenol	South Africa	30-Oct-13	12-Nov-13
9	White Cement	UAE , Iran	11-Apr-12	21-May-12
10	Rubber chemical, namely, PX-13 (6PPD)	China PR	4-May-13	5-Jul-13
11	Pentaerithrytol	Chinese Taipei	27-Apr-13	25-Jun-13

ii. Five year extension cases

SN	SSR cases completed	Country	Date of expiry of Original Duty	Extension by MOF (Five Year Extension)
1	Bias Tyres for Bus and Lorries Trucks	China PR, Thailand	8-Oct-11	30-Mar-12
2	Caustic Soda	Saudi Arabia, Iran, Japan, USA, and France	12-Sep-11	6-Jan-12
3	Metronidazole	China PR	14-Jun-11	15-Jun-11
4	Peroxosulphates	China PR and Japan	18-Mar-12	4-Apr-12
5	Paracetamol	China PR	2-Sep-12	19-Sep-12
6	Sodium Hydrosulphite	China PR	14-Oct-11	20-Dec-11

7	Vitamin A Palmitate	China PR, Switzerland	27-Mar-12	13-Nov-12
8	Zinc Oxide	China PR	6-May-12	18-May-12

E. Ministry of Finance guidelines –

Further Ministry of Finance has issued guidelines in respect for such instances vide Circular No. 28/2011-Customs dated 8th July, 2011 wherein they accepted a situation where the final findings are issued after the lapse of parent notification. Relevant extracts are as follows

iii. '..... Where the findings in a review are notified after the lapse of the parent notification, the notification in such cases would be effective prospectively from the date of issue of such notification.....'

c. India-Turkey dispute – relevance and applicability – dictation

F. Dispute before WTO:

It was contended on behalf of interested parties that the India had raised a dispute before WTO on a similar issue and the issue was decided in favour of India. Reference to cotton yarn measures invoked by Turkey was made in this regard. Following are relevant in this regard.

- i. Even when India had sought and held consultations with Turkey in the matter of cotton yarn, WTO Dispute Settlement Body never considered the issue and no order has been passed on this issue. In fact, the issue never reached the stage of dispute. It should, therefore, be considered that there is no decision by WTO on the present matter.
- ii. In their own wisdom, and after holding consultations with India, Govt. of Turkey assured Govt. of India to withdraw the measures after sometime. Even when measures were not immediately withdrawn, Govt. of India did not proceed with a dispute before WTO.
- iii. The facts relating to this case were extremely different than the facts of the present case. The table below shows some pertinent difference between the two cases.

Turkish case	Indian case
The authorities applied interim duties. The Govt. of India contended that interim duties cannot be applied in a review case.	no interim duties have been recommended by the Director General in this case or such other cases
The Turkish authorities extended safeguard duty retroactively	In the soda ash case done by India where the safeguard duties were extended after expiry, the same were applied only prospectively.
The Government of India contended that the duties were recommended without adhering to the requirements of Article 2, 3, 4, and 5.	The Director General has complied and shall comply with all such requirements.
The Govt. of India contended that the duty was extended after the initial duty expired with retrospective effect from the date of its expiry.	The duty will be extended after the previous duties have expired and the same will be effective with effect from the date of notification by the Central Government. India is not extending such duties retroactively

iv. It would, thus, be seen that in the cotton yarn matter, Govt. of Turkey imposed interim safeguard measures in a review case and after initiation of expiry review. This could be a contestable issue as there appears no provision under the WTO Agreement on Safeguard permitting member countries to impose interim measures in a review proceeding. Further, Govt. of Turkey imposed definitive measures retrospectively, for which there appears no specific provision under the WTO Agreement on Safeguard.

v. In the present case, petitioner has not sought imposition of interim safeguard measures, nor petitioner has sought retrospective imposition of safeguard measures. In fact, petitioner is well aware of the circular issued by CBEC in the context of anti dumping, wherein it has been clarified by CBEC that such measures shall only be prospective in nature.

vi. In view of the above, while Turkish case do not establish that the extension of measures in the present case would be improper, vast experience from anti dumping cases clearly establish that it would be justified to extend the safeguard duties as a consequence of present review.

G. Whether demand supply gap indeed exist

1. It has been argued by the counsel of ATMA that user industry is forced to import as the domestic industry cannot cater to the demand. Following is relevant in this regards:

- a. The argument putforth by ATMA is without any factual basis.
- b. The counsel of ATMA is comparing the demand of India with the capacity of the petitioner company, ignoring completely the existence of other Indian producers. It is submitted that the Indian demand needs to be compared with the Indian capacity and not with the capacity of the petitioner company alone. The comparison methodology adopted by ATMA counsel is totally misleading.

- c. The petitioner has provided demand supply gap on gross demand (including duty free imports) and net demand (excluding duty free imports). Following is the demand supply situation of subject goods in India (all figures are in MT) which shows that there is no demand supply gap in India and the domestic producers are capable of meeting the entire demand of the country.

Product: PX-13

SN	Items	2009-10	2010-11	2011-12	Jan'12-Dec'12
A	Capacity				
1	NOCIL	***	***	***	***
2	Merchem	***	***	***	***
3	PMC	***	***	***	***
4	Lanxess	***	***	***	***
	Total Indian Producers Capacity	***	***	***	***
B	Duty free imports	***	***	***	***
C	Total availability	13,660	13,670	22,400	22,800
D	Demand	14,311	14,851	16,003	18,033
E	Surplus (+)/shortfall (-)	-651	-1,181	6,397	4,767

H. Whether demand-supply gap indeed forced consumers to import

i. Petitioner submits that the relevant issue is whether demand supply gap indeed forced consumers to import the product; or, it is a situation where the consumers are now framing a story that (a) they presumed existence of certain capacities in India, (b) presumed that the Indian producers would not be able to supply them the desired volumes and would instead be keen to export the material, and therefore the consumers presumed that they would not be able to get material from domestic sources and accordingly they aggressively resorted to import the product! The fact is that there is no evidence on record to show that during the relevant period of the present case, the consumers were forced to import the product because of regret from the Indian industry to supply material to the consumers. If indeed demand supply gap forced the consumers to import, they should be able to show that they placed orders for higher volumes on the domestic producers but domestic producers accepted the offers only for lower volumes, regretting lack of available capacities with the producers to supply the desired volumes. It should therefore be construed that the consumers are now trying to make a story of demand supply gap to justify their business action where they found that the imports were available at a price lower than domestic prices and therefore the consumers preferred to aggressively import the product instead of buying from domestic sources.

I. Export performance of the domestic industry.

i. It has been argued by the opposing interested parties that domestic industry is export centric (and that is why the consumers had to import). It is reiterated that exports are not a matter of choice for the domestic industry but a business compulsion for the domestic industry. The domestic industry is in a market where consumers order the procurement of the material. The domestic industry considers the orders placed by various buyers, accumulates the same and consider other supplies which the domestic industry is likely to make to other consumers who place either spot orders or who buy through traders. Further, petitioner considers the optimum production. If such production leads to accumulation of inventories, the petitioner undertakes plant shutdown. Further, the surplus production is offered by the petitioner to the foreign buyers. There is no reason for the petitioner to export the product when they are able to get better prices in the domestic industry. The reason for such exports is surplus production.

ii. It is also relevant to point out that the export price of the domestic industry is far higher than the import price from subject countries. This clearly shows that

- The domestic industry is faced with unfair competition in the international market from the exports from subject countries.
- The domestic industry has fetched much higher prices in the export market and has not reduced the prices to the level of import price in India from subject countries.
- However, the domestic industry has been constrained to export at a lower price as compared to its selling price in India. This is to fill the gap between the target production and actual domestic sales to the extent possible. The petitioner is incurring losses in the export market which clearly shows that the exports are compulsion to dispose off surplus production.

J. Plant shutdowns

- i. The fact that the petitioner has lost sales and production due to imports of PX-13 gets established by the plant shutdown undertaken by the petitioner. Details of plant shutdown are as follows.

Sr. No	Period of shutdown	No. of Hours	
		Actual	Indexed
1	2009-2010	***	100
2	2010-2011	***	424
3	2011-2012	***	909
4	2012-2013	***	1,002

- ii. It would be seen that there has been significant shutdown in the recent period. In fact, the number of hours of shutdown has increased over the period. Further, the shutdown has been because of lack of demand for the product of the company. The company has been faced with significant inventories of the product under consideration in the past and has been incurring cash losses on this product over the last two years. Therefore, the petitioner decided to align its production in line with the demand thereby regulating inventories and reducing the working capital requirement on this product. Petitioner is enclosing its production scheduling chart for each of the months of the investigation period, which clearly shows plant shutdown.

K. Losses suffered by KKPC

- i. It would be seen from the extracts of annual report of Korea Kumho enclosed with these submissions that the company incurred financial losses in their specialty chemical business in 2012. PX-13 de facto being the sole specialty chemical being produced and sold by the company, this clearly establishes that Korea Kumho is selling the product in the domestic as well as international market at loss. Further, comparison of export price of Korea Kumho to third countries and export price to India shows that the company is selling the product to India (and presumably, in domestic market) at much lower price as compared to third countries. So the losses suffered to the company are higher in its domestic sales and Indian exports.

L. Product under consideration:

- i. The product under consideration in the present case is **Rubber Chemical PX-13 (also known as 6-PPD)**. PX-13 is produced by hydrogenation of a mixture of 4-nitrodiphenylamine and methyl isobutyl ketone in an autoclave at moderately high pressure in the presence of a noble metal catalyst. The resulting reaction mass, which contains unreacted ketone, by-products, etc., is filtered to remove the catalyst, which is then recycled. The filtrate is distilled to remove low boilers and is then flaked to give the finished product. The low boilers are redistilled to recover the unreacted ketone. Catalyst is recycled until the activity is reduced. It is then removed from the system. PX-13 is extensively used in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, and Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber based compounds used for manufacture of various rubber products. There is no dedicated Customs Classification for the subject goods. Product under consideration is classified under various subheadings of customs classification heads 3810, 3812 as well as under 2921, 2934, 2925, and 2942 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act. However, the product is known by its trade name and chemical descriptions. Therefore, these customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

M. Like Article or directly competitive article

Rule 2(v) of **Safeguard Duty Rules, 1975** specifies that “like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation. Petitioner submits that the goods produced by them are like article to the goods imported in India. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product properties.

N. Domestic industry

- Petitioner company constitutes domestic industry. Followings are relevant in this regard.
 - Domestic industry is defined in Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B) as follows

6(b) “domestic industry” means the producers

 - as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
 - whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India ;
- The petition for safeguard duty investigation was filed by M/s NOCIL, Mumbai. There are three other producers of rubber chemicals in India viz. M/s. Lanxess India Pvt. Ltd., PMC Rubber Chemicals India Pvt. Ltd. and Merchem Ltd.

3. Petitioner submits that the production of the petitioner constitutes more than 50% of Indian production for the subject goods. The petitioner, therefore, constitutes the domestic industry under Section 8B sub-section 6(b). The Indian production and the share of the petitioner are shown in the table-below, which justifies the standing of the domestic industry.

Particular	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Total Indian Production	***	***	***	***
Share of NOCIL	Above 85%	Above 80%	Above 65%	Above 60%
Share of other Indian Producers	***	***	***	***

4. In view of the above, petitioners request the Director General (Safeguards) to consider petitioner as “domestic industry”.

O. Increase in Imports:

- As already established by the domestic industry that an increased import is not a prerequisite for extending the safeguard duty.
- Notwithstanding above, it is submitted that the imports of Px-13 constitute “increased imports” within the meaning of the Rules. Followings are relevant in this regard.

(a) The legal requirements

- Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 : Power of Central Government to Impose Safeguard Duty

If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article.

- Article 2 of Safeguard Agreement: Conditions

1. A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

- It would thus be seen that the conditions for imposition of safeguard duty are as (a) increased Imports – in absolute terms, relative to domestic production and relative to domestic consumption; (b) injury due to increased imports.

(b) Meaning of recent, sudden, sharp and significant increase.

1. Petitioners submit that the requirement under the law is that imports should have shown sudden and significant surge. WTO in the matter of *Argentina Footwear (EC)* has held that increased imports must be sudden and recent and therefore, the need for updated data:

*“[T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfil this requirement for applying a safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been **recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough**, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury’.”*

- Also, in *US — Wheat Gluten*, case, the panel observed that:

3. “...Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in *Argentina — Footwear Safeguard* that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”

- In view of the above, petitioner submits that imports of the product should be— (a) sudden; (b) significant; (c) most recent; (d) sharp.

(c) Absolute increase in imports

- Imports of PX-13 have “increased within the meaning of the rules” as can be seen from below :

SN	Year	Volume	Value in	Average price	Imports in relation to Production
		MT	Rs.Lacs	(Rs/Kg)	% (Indexed)

1	2009-10	10,090	16,197	160.53	100%
2	2010-11	10,607	16,936	159.67	106%
3	2011-12	9,735	15,888	163.20	101%
4	2012-13	11,664	18,396	157.72	126%

2.. It would be seen from the table above that:

- There is a sudden, significant, sharp and recent increase in imports of product under consideration in India.
- The imports have increased significantly in the most recent period with a slight decline during 2011-12.
- Imports of the product concerned have increased over the injury period, despite existing safeguard duty.
- It is pertinent to note that such increase in import is despite safeguard duty in existence. The volume of imports would further increase should safeguard duty be revoked.

Further imports have also increased since the base year of the original investigation clearly indicating “increased imports”

(d) Relative increase in imports

Imports of PX-13 have increased not only in absolute terms but also in relation to production in India

(e) Reasons for Increase in Imports:

1. The circumstances which were prevalent at the time of imposition of previous safeguard duty leading to increased imports are very much in existence even today. Under these circumstances, if the safeguard duty is not extended, the imports shall once again increase significantly. Following factors identified by the applicants at the time of previous application are very much in existence even today.

- surplus capacities with global producers and resultant low prices being offered by them, as would be seen from the following information (based on estimates and market intelligence of the petitioner):

All figures are in MT

SN	Country	Producer	Capacity	Domestic Demand	Surplus
1	Korea	Korea Kumho (KKPC)	70,000	8,000	62,000
2	China	Sinorgchem	120,000	-	-
		Nanjing Chemicals	30,000	-	-
		Tongling Xenda	10,000	-	-
		Northeast Aux	10,000	-	-
		Shangyu Lixing	2,000	-	-
		Jiangsu Donglong	8,000	-	-
		China Sunsine	15,000	-	-
	Total China		195,000	90,000	105,000
3	EU Region	Flexsys	65,000	-	-
		Lanxess	38,000	-	-
		Dusslo	18,000	-	-
	Total EU		123,000	32,000	91,000
4	Japan	Sumitomo	10,000	17,000	(7,000)
5	India		11,500	14,500	(3,000)
6	Rest of World		NIL	87,000	-
7	Total world		407,500	248,500	159,000
8	Indian demand				14,500
9	World surplus as a % of Indian demand				1097%

It would be seen that the current global surplus capacity in the product is significantly beyond the current demand for the product in India.

- some business arrangements between a Chinese producer of the product under consideration and its intermediate with a Korean producer, whereby the Korean producer is getting the intermediate at materially low prices.

c. Petitioner submits that Korea Kumho and Sinorgchem admittedly have special relationship have special relationship which is resulting in supply of 4-ADPA at special price to KKPC. This special relationship is in addition to the benefits of non market economy available to Sinorchem and being passed onto KKPC. Thus, KKPC and Sinorgchem are working in tandem. Further, petitioner submits that the following facts further establish existence of special relationship between the two parties.

- i. KKPC domestic sales have declined over the years;
- ii. KKPC exports to various countries, including US have increased;
- iii. KKPC continues to get 4-ADPA, the penultimate intermediate, at significantly concessional price from Sinorgchem;
- iv. The statement made by Korea Kumho in its annual report of 2009 wherein the exporter stated as follows.
"Our specialty chemical business- the industry leader in 6PPD production capacity- saw sales decline and prices fall as Chinese competitors pursued a low price strategy. Shortages in 4-ADPA feedstock market and restrictions on our ability to enter the Chinese market due to our special relationship with feedstock supplier Sinorchem resulted in low operating rate that further hurt profitability."
- v. The pattern of exports of the product under consideration from Korea to various countries globally and China shows that Korea Kumho has increased its exports significantly in the global market, barring the sole exception of China. If Korea Kumho has increased its exports so significantly in all the markets and if Korea Kumho is holding so significant capacities, there is no business and economic justification for not increasing exports to China, except for an understanding between Sinorchem and Korea Kumho, wherein Korea Kumho has agreed not to increase its exports to China in return for the low price at which 4-ADPA is being supplied by Sinorchem to Korea Kumho.

2. The above facts clearly show that transactions between Sinorgchem and KKPC are a part of some special arrangements between the two companies.

a. One of the major suppliers of the product under consideration in the Indian market, Korea Kumho Petrochemicals (KKPC), has expanded its capacity for production of the product under consideration from 44,000 MT/A to 80,000 MT/A. The current operating levels of the company are extremely low (in the region of 45-50 %). In fact, the surplus capacity available with this company alone is significantly higher than the entire demand in the Country. Resultantly, share of Korea in demand for the product in India, which was as low as 1% in 2003-04, increased to 33% in the period 2012-13. Further, whereas only 31% of the total imports were from Korea till 2005-06, despite imposition of anti-dumping duties and safeguard duty, 52% of imports are now being reported from Korea.

P. Injury to the Domestic Industry:

1) a. The Annexure to rules provide as follows –

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

b. As stated earlier at the stage of extension of safeguard duty, there is no requirement of existence of either increased imports or serious injury to the domestic industry. The rules clearly provide for extension of safeguard duty in case the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed. Therefore, the Director General (Safeguards) is not required to determine whether imports of PX-13 have increased in absolute terms or in relation to production and consumption in India. Nor the Director General (Safeguards) is required to determine whether the domestic industry has suffered serious injury within the meaning of the rules. This is also established by the language of Rule 18, which provides for "mutatis mutandis" application of Rule 5 and Rule 11. Further, this is established by the fact that Rule 8 is not even made applicable in case of such review. In fact, the domestic industry may not have been suffering injury because of the very imposition of safeguard duty and therefore existence or otherwise of injury to the domestic industry cannot be a pre-requisite for extension of safeguard duty.

c. Notwithstanding, petitioners have provided information with regard to performance of the domestic industry. The information clearly shows that the situation of the domestic industry continues to be quite adverse. In fact, the domestic industry continues to suffer serious injury. Under the circumstances, if the safeguard duty is not extended, the domestic industry will suffer aggravated injury.

d. The circumstances which were prevalent at the time of imposition of previous safeguard duty are very much in existence even today. Further, the domestic industry is taking measures to become competitive and the process is underway. Under the circumstances, if the safeguard duty is not extended, the domestic industry would once again suffer serious injury. It is therefore vital that the present safeguard duty may be extended further for a period of two years.

2) Demand

Petitioners have defined demand, for the purpose of the present petition, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of sales of the domestic producers and imports from all sources. Exports made by the Indian Producers have been excluded from the computation in order to ascertain apparent consumption. The overall demand for the product under consideration over the injury period has been positive

3) Market share

a. For the purposes of determining market share, the sales volume of the domestic industry considered is as per excise records maintained by the domestic industry. Market share has been determined considering despatches by the Indian industry and imports into India. Summarized position since 2009-10 is as under

SN	Year	Share of %			
		Petitioner	Other Indian producers	Indian producers	Imports
1	2009-10	***	***	31.39%	68.61%
2	2010-11	***	***	33.50%	66.50%
3	2011-12	***	***	38.98%	61.02%
4	2012-13	***	***	36.32%	63.68%

b. It would be seen that the market share of the petitioner has declined and that of other Indian producers has increased. With respect to imports, the market share of imports in total demand has declined till 2011-12 and thereafter increased during most recent period.

c. It is pertinent to note that the one of the Indian producers, M/s. Laxness is a multinational company having production facilities in India and outside India. The company has sometime produced the goods in India and sometime has resorted to imports. The company imported the product under consideration during 2009-10 when the company was in the process of shifting its plant from one location to another location. The company has commenced production at new site in the year 2009-10. Thus, production of other Indian producers was lower (about 1,000 MT) than normal in 2009-10 and consequently imports were higher (by about same quantum) than normal in the same period.

d. The petitioner submitted in the original investigation that M/s. Laxness had temporarily suspended its production and in order to meet out its customer's requirements it has resorted to supplies of the material from its production facilities outside India. If the production had not been suspended, the company would have produced the same quantities of subject goods domestically. Owing to the absence of permanence in the said arrangement, the imports should be excluded as the inclusion would have otherwise distorted the data.

e. In the light of the above, the petitioner has determined market share after showing separately imports and production by Laxness. The market share so determined is as follows:

Market Share in Demand	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
China	%	12.45	11.51	21.09	12.97
Korea	%	41.00	32.99	28.23	34.12
EU	%	3.92	6.14	5.11	16.61
Other Countries	%	3.01	10.68	5.47	2.01
Import by Lanxess	%	8.23	5.19	1.13	-
NOCIL	%	***	***	***	***
Lanxess India P Ltd	%	-	***	***	***
PMC Rubbchem P Ltd	%	***	***	***	***
Indian Industry	%	***	***	***	***
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

- c. It would be seen that the market share of laxness has increased whereas the market share of other Indian producer has declined. Clearly showing that the market share of other Indian producers as a whole, has increased as Lanxess once again started producing the rubber chemical instead of importing.

4). Production

The production of the domestic industry declined during the injury period:

Year	Production (MT) Indexed
2009-10	100
2010-11	92
2011-12	74
2012-13	65

5). Capacity utilization.

The capacity utilization of the domestic industry declined significantly over the injury period

Year	Capacity utilization (%) (Indexed)
2009-10	100
2010-11	90
2011-12	73
2012-13	64

6). Domestic Sales

The domestic sales volumes have been considered as per excise records wherein dispatches from factory are taken as sales. Even though sales of the domestic industry increased, the increase in sales was less than increase in demand. Further, the domestic industry should have gained much higher sales, given the safeguard duty imposed on the product and anti dumping duty enhanced on imports from Korea. However, despite these measures, imports increased further and even more than the increase in demand. This was because the landed price of imports after applicable anti dumping duty and safeguard duty was lower than selling price of the domestic industry.

	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of domestic industry	***	***	***	***
Imports	10,090	10,607	9,735	11,664
Changes vis-à-vis previous year				
➤ Sales of domestic industry		***	***	***
➤ Imports		517	(872)	1928

7) Inventories.

The closing stock of the domestic industry has declined throughout the period. This is due to the fact that the domestic industry, in order to sustain in the market and dispose off accumulated inventories, started regulating production and offering sub optimal prices. This has resulted on one hand in increase in sales but on the other hand the petitioner suffered huge losses. However, the stock as no of days sales have also remained significant in the recent period.

8) Price effect.

Imports of the products under consideration continue to be reported at prices significantly lower than not only domestic industry prices but also cost. Resultantly, the domestic industry is facing positive price undercutting despite safeguard duty.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Total Domestic Cost (Indexed)	Rs./KG	100	103	114	121
Selling Price	Rs./KG	100	101	103	98
Landed Price	Rs/ KG	172.93	172.00	175.81	169.91
Profit/loss (Indexed)	Rs./KG	100	76	(33)	(190)
Undercutting (Range)	%	35-45	35-45	35-45	35-45
Cost - Landed price (Indexed)	Rs/ MT	100	108	136	163

9) Profitability

Summarized position is as follows:

Particulars (Indexed)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Profit/loss	Rs./KG	100	76	(33)	(190)
Profit before interest	Rs. Lacs	100	80	(34)	(180)
Cash profit	Rs. Lacs	100	85	(8)	(150)
ROCE	%	100	70	(28)	(46)

a. It would be seen that

- The profitability of the domestic industry declined throughout the period to such an extent that the domestic industry suffered financial losses in the year 2011-12 and 2012-13. The losses suffered have significantly increased in the recent period.
- The PBIT and cash profits have shown the same trend as that of profitability. The domestic industry is suffering huge cash losses.
- The return on capital employed has also declined throughout the injury period. The domestic industry is suffering negative return since past two years.

10) Employment & productivity

The employment with the domestic industry has declined in the most recent period. Wages paid have shown a decline. Productivity per day has also declined. Petitioner submits that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the domestic industry. Hiring & firing of employees is the last resort situation of the domestic industry.

11) Plant Shutdown

a. The fact that the petitioner has lost sales and production due to imports of PX-13 gets established by the plant shutdown undertaken by the petitioner. Details of plant shutdown are as follows.

Sr. No	Period of shutdown	No.of Hours	
		Actual	Indexed
1	2009-2010	***	100
2	2010-2011	***	424
3	2011-2012	***	909
4	2012-2013	***	1,002

b. It would be seen that there has been significant shutdown in the recent period. In fact, the number of hours of shutdown has increased over the period. Further, the shutdown has been because of lack of demand for the product of the company. The company has been faced with significant inventories of the product under consideration in the past and has been incurring cash losses on this product over the last two years. Therefore, the petitioner decided to align its production in line with the demand thereby regulating inventories and reducing the working capital requirement on this product. Petitioner is enclosing its production scheduling chart for each of the months of the investigation period, which clearly shows plant shutdown.

c. This clearly shows that domestic industry is suffering to such an extent that they are compelled to take adverse measures like plant shut downs. The situation would worsene in the event of non extension of safeguard duty.

12). Conclusion on serious injury

1. Petitioner submits that the following factors establish that the imports are likely to cause serious injury, should the present safeguard duty not be extended further.

- (a) The imports are entering into the Indian market at an increased rate despite safeguard duty in existence.
 - (b) The market share of imports has increased in the most recent period whereas that of domestic industry has declined despite safeguard duty in existence.
 - (c) The prices of imports are lower than the selling price of domestic industry.
 - (d) The domestic industry in order to sustain in the market started offering sub optimal prices. Resultantly, the domestic industry has suffered huge financial losses, cash losses and negative returns.
 - (e) The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible.
 - (f) Production and capacity utilization of the domestic industry declined, which should have improved with imposition of anti dumping duty and safeguard duty.
2. The above clearly establishes that the domestic industry is suffering injury despite safeguard duty in existence. The situation would worsen if the safeguard duty is allowed to be revoked.
3. In the event safeguard duty is not extended further, the domestic industry would be forced to further reduce its selling price in order to match the same with the import price. The import price would decline equal to the quantum of safeguard duty and therefore the domestic industry would suffer huge losses, cash losses and negative return on investment. If the safeguard duty is not extended further, injury to the domestic industry will intensify.

Q. Other Factors of Injury

1. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than dumping and the low priced imports. Dumping of the product from China, Korea and EU caused injury to the domestic industry. However, anti-dumping duty has already being imposed by the Central Government after coming to a conclusion that the EU were dumping PX-13 in the Indian market. And the Designated Authority is undertaking sunset review investigation of anti-dumping duty on China and Korea at present. While there are no listed known other factors that are required to be examined by the Director General (Safeguards), petitioners examined possible injury due to some known other factors. Followings are relevant in this regard –

- a) Possible decline in demand of the product: Considering the information over the injury period, it would be seen that there is no contraction in demand of PX-13 in India. Thus, possible decline in the demand has not caused injury to the domestic industry.
 - b) Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.
 - c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - d) Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
 - e) Export performance: Petitioner has exported the product under consideration. However, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations. Claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.
2. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry: Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. Claimed injury to the domestic industry is not on account of other products being produced and sold by the domestic industry.

R. Causal Link

1. As demonstrated in the preceding paragraphs, some of the possible known factors have not caused injury to the domestic industry. Further, the dumping of the product under consideration and increased imports have caused injury to the domestic industry. Followings are relevant –

- c. Despite safeguard duty in existence, the imports are entering the Indian market at an increased rate.
- d. The product is largely sold in comparison/competition with imports. The landed price of imports is lower than the selling prices of the domestic industry.
- e. Due to presence of cheap imports in the market, the domestic industry in order to sustain in the market is forced to reduce its prices below cost.
- f. Resultantly, the domestic industry has suffered huge financial losses. The domestic industry is faced with negative cash profit and negative returns in the recent period.

2. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports and clearly establishes that the injury to the domestic industry is likely to intensify in the event the current safeguard duty is not extended. Further, such serious injury will be due to imports.

S. Duration of safeguard duty.

Petitioner requests extension of safeguard duty for a further period of two years.

T. Public interest

1. Extension of safeguard duty shall be in public interest. The Director General (Safeguards) earlier examined the issue in detail and held as follows –

283. It has been contended by the interested parties that the safeguard measure on PUI is not in public interest. However evidence to substantiate the same was not submitted by any of the interested parties.

284. The Applicants have submitted that the share of PX-13 in the tyre industry ranges between 0.71% to 1.11% and on non tyre segment is 0.5%. The fact has not been disputed by the ATMA, representing Tyre manufacturer in the current investigation and All India Rubber Manufacturer Association.

285. Considering the above share and the insignificant cost of PX-13 it is noted that there will be no or very minimal impact of Safeguard duty on price of tyre and on the non tyre segment.

*286. The applicant and one other domestic industry have undertaken expansion of their capacities and substantial progress has already been made as discussed in para 279 of this finding. The applicant alone will have an employment of more than *** persons. Further significant part of investment has come from financial institution. The employment and public finance are at risk if the Indian manufacturers are not given adequate protection from increased imports.*

*287. Further besides the applicant domestic industry, all other Indian producers are dependent on foreign producers for the penultimate intermediate 4ADPA for production of PUI. In the event of closing down of the applicant industry, there is no guarantee of timely getting 4ADPA at competitive price by other Indian producers. Hence the survival of applicant domestic producers is in the interest of the consumers. Further, the employment of more than *** persons presently working with the applicant is also at risk.*

288. The safeguard duty which would enable domestic industry to survive in the face of competition offered by increased imports is also in long term public interest of buyers of PUI as well as buyers of products manufactured therefrom. It is therefore considered that imposition of safeguard duty on PUI will be in Public interest.

2. In view of the above, petitioner submit that extension of safeguard duty shall be in public interest. The claim of opposing interested parties that extension of safeguard duty shall not be in public interest is without substance, wholly unsubstantiated and motivated. Mere argument that extension of duty would not be in public interest should be rejected for want of relevant evidence. Public interest has a much wider terminology as explained below.

3. Public interest – meaning thereof: It is submitted that the opposing interested parties have erroneously understood the public interest to mean the consumers' interest. As held by the Director General in a number of findings, the term public interest is a much wider term, covering in its ambit much larger general social welfare taking into account the larger community interest. The term public interest in this sense has to be understood so as to include the interests of the following:

- (a) producers' interests,
- (b) consumers' interests,
- (c) public at large interests

4. In the instant case, imposition of safeguard duty would be in public interests for the following reasons.

- (a) Product under consideration is a very critical, but low cost input for the consumers. There are no viable substitutes to the consumers. Substitutes for the product under consideration are either far more expensive or would result in a compromise in the quality of the tyres.
 - (b) Imposition of safeguard duty would result in survival and growth of the domestic industry in India.
 - (c) 6-PPD does not constitute a major cost element for the consumers. Majority consumption of 6-PPD is by tyre industry. Costs on account of 6-PPD constitutes below 1% of the price of tyre industry.
 - (d) 6-PPD constitutes even much lower cost item for non-tyre consumers. This gets established even from practically no response from non-tyre segment consumers and their association so far. Costs on account of 6-PPD will constitute hardly 0.5% of total costs for a consumer in non tyre segment.
 - (e) 6-PPD constitutes a major product for the producers of this product.
 - (f) Presence of domestic industry has kept the prices to reasonable levels. The intention of the Korean and in turn Chinese producer is to eliminate production of the product in India and then charge high prices. Should the domestic industry survive, benefit of the same will come to the consumers.
5. Further, the safeguard duty will be only to the extent to neutralize the injurious impact and thus the competition from import remains alive.
6. Moreover, if the injury to the domestic industry continued, it may lead to the closure of the domestic industry. As a result of which, 'PX-13' an important chemical would not be manufactured in India and thereby making the users of the 'PX-13' wholly dependent on the imports.
7. In view of the foregoing, it is submitted that extension of safeguard will be in public interest and especially the interests of end users are well protected.

U. Adjustment Plan

i. Adjustment plan provided in the original investigation: the petitioner stated as follows in its adjustment plan

“NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce 10,000 MT of intermediates used for production of PX-13. This plant will have a capacity for production of 10,000 MT intermediates used for production of PX-13 at an estimated expenditure of Rs 250 Crs. The total project costs about Rs. 250 Crs is under implementation stage. The company hopes to commence commercial production some times in FY 2013. The company hopes that the Plant will be fully operational at optimum capacity in about three year’s time. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the Country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports. Further, this expansion would enable the company to face fair competition from imports. Thus, the petitioner requests safeguard duty for a period of three years so that Petitioner is in a position to face the import competition.

ii. The rules provide as follows with regard to adjustment plan.

Rule 4(3)(ii) the duration of levy of safeguard duty and where the period so recommended is more than a year, to recommend progressive liberalization adequate to facilitate positive adjustment.

Rule 5(1)(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.

Rule 11 The Director General shall also give its recommendation regarding amount of duty which, if levied, would be adequate to prevent or remedy ‘serious injury’ and to facilitate positive adjustment.

iii. It would be seen that the rules provide that the domestic industry should take steps which will facilitate positive adjustment. In other words, the only relevant consideration is whether the adjustment plan **shall improve the competitiveness** of the domestic industry.

iv. Since the company has already started manufacturing 4 ADPA at Dahej Plant, the petitioner has taken adequate and appropriate measures for becoming import competitive. The rule does not prescribe that the full benefit of adjustment should have already accrued to the domestic industry before seeking extension of safeguard duty. In fact, if full benefit would have already accrued to the domestic industry, the need for extension of safeguard duty would not have arisen. The safeguard duty is required to be extended only because the adjustment plan undertaken earlier has not yet yielded full results and even though benefit has started flowing in, the company requires additional time to fully become competitive.

v. The petitioner has commenced production 4 ADPA at Dahej. As per the plan, this is the only product that the petitioner shall be producing at Dahej. The plant is only for PX-13, which shall be exclusively used for production of PX-13. The broad production process of production of PX-13 and various stages of manufacture are given below:-

Aniline,
Nitrobenzene
Hydrogen
MIBK
Catalyst

→ 4 NDPA → 4 ADPA → PX-13

vi. It would be seen that both 4 NDPA and 4 ADPA are stages in the production process of PX-13. However, 4 ADPA is the penultimate stage for production of PX-13 and is produced after production of 4 NDPA. In fact, only one penultimate stage of production process is left out after production of 4 NDPA. Only one product is being produced at present and is proposed to be produced in future at Dahej, i.e. 4 ADPA.

vii. Steps taken by the petitioner towards completion of the adjustment plan provided in original investigation: it is submitted that the petitioner has taken due steps to undertake the adjustment plan earlier envisaged. This is evident from the following:

a. The company has invested substantial amount of capital on the Dahej Plant. The capital work in progress (CWIP) at different point in time is as follows:

Period (Upto)	CWIP (Rs Lakhs)	Amount invested during the period (Rs. Lacs)	Remarks
March, 2011	***		
November, 2011	***	***	Between Apr to Nov., 2011
March, 2012	***	***	Between Dec., to March, 12
May, 2012	***	***	Between Apr. to May, 12
August, 2012	***	***	Between June to Aug., 12

It would be seen that the petitioner invested progressively in the Dahej Plant. The supporting documents in the form of CA certificate and extracts from balance sheet are provided with the petition.

- b. The petitioners have incurred substantial pre-operative expenses including employee cost, pre-marketing expenditure, trial run costs and other expenses. Details of pre-operative expenses are as follows:

Period (Upto)	Pre-operative expense (Rs Lakhs)
21st September, 2011	***
31st March, 2012	***

It is evident from above that the petitioner has already invested substantial amount of its resources towards implementation of the adjustment plan earlier envisaged.

- c. The relevant extracts from the annual reports for 2011-12 is as follows:

Project

As mentioned in our last annual report, the new Project at Dahej is nearing completion and is expected to go on-stream by August 2012. We are pleased to inform you that the total expenditure committed on this project is well within the original sanctioned amount of 250 crores. We are also proud to mention that the entire project, right from the conceptualization stage to execution, was executed by your company's own team with no foreign technical know-how. Further you would be happy to learn the debt component of the project will be less than the originally earmarked amount.

Preliminary discussions have already been initiated by the company's Management with Major Domestic and International tyre companies for the product approvals necessary for the new Dahej plant. We are pleased to inform you that the response from these customers has been very positive.

- c. The relevant extracts from the annual reports for 2012-13 is as follows:

PROJECT

Our Project at Dahej in Gujarat was commissioned for trial runs, from the second half of the year. Commercial Production at Dahej Site commenced on successful completion of a sustained and stable production run, and on receiving product approvals from all our major customers. It is noteworthy that the entire project was completed and commissioned by a dedicated in-house technical and engineering team. We are proud to mention that this was a project where no external technical collaboration was sought, particularly when such a complex and intricate chemical process was involved. Only a couple of producers in the world, have succeeded in using this chemical process.

The Project could have been commissioned a few months earlier, had timely and adequate power supply been made available by the Electricity Board. Production at the plant is expected to be optimized during the first half of the coming year. This project will enable the Company to improve its operational performance, through the technological innovations/improvements made in the new manufacturing process.

The total expenditure incurred for this project is well within the original sanctioned amount of `250 crore, and the debt component of the project will be less than the originally estimated amount.

- e. The domestic industry has already started trial production at Dahej plant since November, 2012 and commercial production from March, 2013. Petitioner apprehends that since the domestic industry is unable to sell its existing PX-13 production without suffering losses, it might be forced to suspend production at Dahej plant in the event the current safeguard duty is not extended further. The domestic industry is likely to suffer intensified injury not only at the existing capacities but also in the investments made at Dahej plant in the event the current safeguard duty is not extended further.

- f. Petitioner has already commenced commercial production at the Dahej plant and relevant evidence (excise records) are enclosed with the petition.

- viii. The above clearly established that the domestic industry is adjusting positively and there is need for continuation of duty.

V) Benefit that have already accrued from the adjustment plan

A statement showing the optimum cost of production of the petitioner at Dahej plant and the cost of production it would have incurred, had the petitioner continued production at old plant, was provided with the petition. It would be seen that the petitioner has already achieved significant cost savings by undertaking production at Dahej.

W) Significant increase in the raw material prices between previous investigation and current period

While considering the cost of production of the petitioner, it must be considered that the prices of various raw materials have very substantially increased in the current period, as compared to the prices that were prevailing at the time of original investigation. A statement showing comparison of the prices in two periods were enclosed with the petition. It is natural that the cost of production of the product under consideration would increase proportionately in view of increase in these raw materials costs. Therefore, any cost comparison between the previous period and current period must be considered by considering the same levels of raw materials prices. Petitioner has determined its cost of

production as it would have been, had the raw materials prices been the same as these were at the time of original investigation. The relevant statement was enclosed with the petition filed. Comparison of this cost of production with the cost of production at present shows that the cost of production in the current period is higher to a very significant extent because of increase in the raw materials prices. Petitioner requests the Director General to kindly consider this while examining the efforts already taken by the petitioner.

X) Conclusion

1. It would thus be seen that –

- There is continued significant imports;
- There is likelihood of significant increase in imports in the event safeguard duty is not extended;
- The performance of the domestic industry is fragile. In fact, the domestic industry is suffering serious injury;
- Further deterioration in performance of domestic industry likely if safeguard duty not extended;
- Domestic industry has taken and is taking measures to adjust. Extension of duty is vital to allow industry to take full measures.

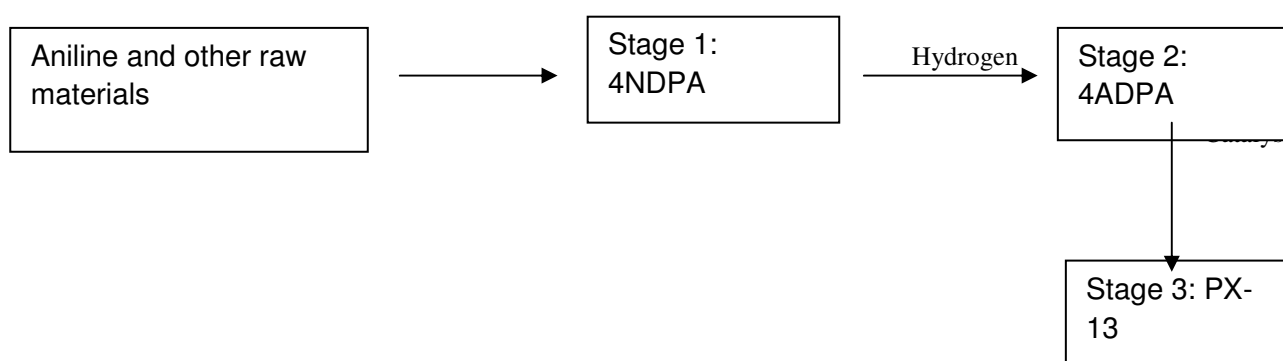
2. The interested parties are deliberately trying to create confusion with regard to installed capacities with the petitioner for the product under consideration. Further, the interested parties are deliberately creating confusion that investment in 4-ADPA does not mean investment in 6-PPD. We are enclosing herewith documents which were provided to the authority at the time previous investigations and present investigations. The table below shows the capacity with the petitioner for the intermediate and finished products over the period.

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
4 NDPA at Thane	***	***	***	***	***
4 ADPA (Dahej Plant)	***	***	***	***	***
PX-13 / 6 PPD at Thane	8,500	8,500	8,500	8,500	14,000

3. **Note:** Capacity of 4 ADPA in 2012-13 is only for one month (commercial production started on March'14 and trial production started on Nov'12) and annualized installed capacity of 4 ADPA at Dahej Plant is 14,000 MT.

It is also clarified that

- while the petitioner was earlier producing 4 NDPA at its Thane plant and the same was thereafter getting completed to 6 PPD; the petitioner has now setup facilities for production of 4 ADPA at Dahej and has enhanced capacities for production of 6 PPD at Thane.
- the production process for the product under consideration involves production of 4 NDPA and thereafter 4 ADPA and then 6 PPD. The process is shown below.



It may thus be seen that first 4 NDPA is produced, which gets converted into 4 ADPA and same is converted into 6 PPD. In the technology earlier adopted by the petitioner, the petitioner was carrying out Stage 1, Stage 2 and Stage 3 in the Thane plant. . The petitioner now is directly carrying out stage 2 at Dahej then transferred to Thane for producing 6 PPD in second step (stage 3).

4. The petitioner has continued with processing of 4 ADPA into 6 PPD in Thane itself for two additional reasons –

- the production facilities for production of 4 NDPA/4 ADPA available at Thane are now being utilized for production of 6 PPD and therefore these facilities would have remained under-utilized or unutilized/idle, had the petitioner undertaken production of 6 PPD as well at Dahej;
- production of 6PPD at Dahej would have implied an additional investment of Rs.*** crores at Dahej and idling of production facilities at Thane. This had no business prudence.

c. the petitioner cannot sell to tyre industry unless the tyre industry has approved not only the product but also the plant. The production process of tyre industry is highly matured and well established. The tyre company procures raw material after following a long drawn process of approval which involves not only approval of the product but also approval of the production plant. The process may take anywhere between *** years before tyre company can approve a new plant and a new product. Therefore for this additional reason, petitioner has continued to produce 6 PPD at Thane plant so that the changeover would not require a process of approval of the product by its purchasers. It is, however, clarified that all tyre consumers were made aware of the fact that the company is now producing 4 ADPA at Dahej and same is being processed further to 6 PPD at Mumbai. Few such emails sent by NOCIL to Customers and response from Customers are enclosed with this letter. From the said responses, it can be seen that tyre industry is very much aware of the exact situation of NOCIL in January 2013.

5. We hope that the above addresses to issue of capacity being repeatedly raised by interested parties with the initiation to create confusion in the matter. However, in view of deliberate attempt by the interested parties to create confusion in the matter and considering that this is a matter of capacity, we request you to kindly undertake another verification at our both plants so that we can demonstrate to the visiting team that the company has indeed undertaken an adjustment plan, as earlier informed to the Director General (Safeguards).

18. Rejoinder by the interested parties

19. M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea:

19.1 Rejoinder submission to the written submission dated 31st December 2013 made by the domestic industry is filed on behalf of M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd. ("Respondent"). It is to be noted that the domestic industry have raised **Grounds A-T** in its written submission and the rebuttal to many of the grounds are already covered in the written submission of the Respondent in its earlier submissions including the recent written submissions post public hearing filed on 31st December 2013. The submissions made earlier in preliminary injury submissions, additional injury submission and written submissions pursuant to public hearing are reiterated here and not reproduced for the sake of brevity. Herein below, all grounds raised by domestic industry are rebutted and only few issues are elaborated, merely to clarify them further.

Ground A – The Respondent submits that contents of Paragraph 1 of Ground A of the written submissions are factual and matter of record and need no reply.

Ground B – The Respondent submits that contents of Paragraph 2 of Ground B of the written submissions are facts related to anti-dumping investigation on the subject product and have no relevance whatsoever with the present proceedings. The contents of Paragraph 2 are irrelevant to the present proceeding and therefore need no reply.

Ground C – The Respondent submits that the contents of the Paragraphs 3-8 of Ground C are wholly denied and disputed. The Respondent has already made detailed submissions regarding the correct legal understanding of review in safeguard proceedings and reiterates the same here. The Respondent submits that the domestic industry is misleading the Authority by choosing to present only selective portions of the Safeguard Rules, mainly Rule 18, and indulging in purposive interpretation by reading Rule 18 in isolation to suit its needs. It is submitted that such an understanding and argument before a quasi-judicial forum like this Authority cannot be acceptable. It is submitted that a correct understanding of law in safeguard proceedings can only be arrived at by reading together Article XIX of the GATT, the WTO Agreement on Safeguards ("AoS") and Safeguard Duty Rules, 1997.

Ground D – i) The Respondent submits that the contents of the Paragraphs 9 and 9a-9e of Ground D are wholly denied and disputed. The Respondent fails to understand how instances of extension of anti-dumping duty mentioned on page 9 of the written submission would be helpful in this case. Article XIX of the GATT, AoS and Safeguard Duty Rules, 1997, squarely cover the present case. When there are specific laws governing review in safeguard proceedings, there is no need to seek aid of another law that deals with a different trade remedy measure unless the domestic industry concedes, and we submit the domestic industry has conceded, that anti-dumping law and not safeguard law covers this case. It is submitted that Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 read with Anti-dumping Rules specifically provide for continuation of an anti-dumping duty pending a review and further, it provides for extension of duty from the date of such notification. There are no corresponding rules like these in AoS and Safeguard Rules, which show the intention of the legislature that safeguard duty cannot continue pending the review and cannot be extended after expiry of the safeguard measure. It is submitted that the domestic industry has again indulged in selective understanding of law by providing only one instance where safeguard duty was extended after expiry. It is submitted that such an example is unacceptable when there have been numerous instances where the DG Safeguards has completed the review before expiry of safeguard measure in the past. These are as listed below:

Product	Final Findings in the Original investigation	Customs Notification & Duration of Duty	Initiation Notification of review Investigation	Final Findings in the Review investigation
Phenol	11 June 1999	Customs Notification No. 82/99. Duration of the duty was from 30 June 1999 till 29 June 2001.	1 January 2001 (1st review)	16 May 2001

Phenol	16 May 2001 (date of final finding in the first)	Customs Notification No. 73/2001. The duration of the duty was from 30 June 2001 till 29 June 2003	22nd October 2001 (2nd review)	11 December 2001
Acetone	7 October 1999	Customs Notification No. 7/2000. The duration of the duty was from 27 January 2000. The duration of the duty was from 27 January 2000 till 26 July 2002	21 November 2001	4 February 2002
Soda Ash	6 October 2009	Customs Notification No. 122/2009. The duration of the duty was from 20 April 2009 till 19 April 2010	19 February 2010	13 April 2010

ii. Further, the Respondent fails to understand why the domestic industry is placing reliance on Circular No. 28/2011 dated 8th July 2011, which is regarding “Collection of anti-dumping duty beyond the validity period. Again, it is submitted that if the domestic industry is conceding that their case relates to dumping of the subject product, there remedy lies before the DGAD and not DG Safeguards. It is completely incomprehensible why and how certain circulars related to collection of anti-dumping duty would be relevant to this case.

iii. Further, the domestic industry has failed to understand the WTO dispute settlement procedures and has naively argued that the dispute between India and Turkey in DS 428 never reached the WTO Panel. It is submitted that member countries of the WTO, after filing a consultation request, indulge in bilateral consultations and try to settle the dispute amicably between them before requesting a WTO Panel to intervene. In this case, the consultation process led Turkey to withdraw the safeguard measures, therefore there was no need for a WTO Panel to intervene. The Authority is requested to procure the documents regarding the settlement from the concerned department in the Ministry of Commerce to examine this. Further, the Respondent firmly reiterates that India’s stand in international arena is that safeguard duty cannot be extended after its expiry, and review of a safeguard measure has to be completed before expiry of that measure.

Grounds E and F – The Respondent submits that the contents of the Paragraph 10 of Ground E and contents of Paragraph 11 of Ground F are wholly denied and disputed. It is submitted that the surplus of the subject product in 2011-12 and in the period Jan 2012-Dec 2012 is incorrect. On the contrary, there is a sharp shortfall of the subject product in India, which led to imports of 11664 MT of subject product in 2012-2013. By arguing in Paragraph 11 that imports of the subject product were preferred because of low price of the subject product, the domestic industry has conceded that the present case is not fit for safeguard proceedings. The domestic industry is free to approach another appropriate forum if it is aggrieved with low priced imports of the subject product.

Ground G - The Respondent submits that the contents of the Paragraph 12-13 of Ground G show that the domestic industry is facing loss in export market. It is submitted that safeguard law does not provide for a remedy in such a situation. Whether the domestic industry is export-centric or not has nothing to do with the proposition seeking a safeguard measure on imports of the subject product. This ground is completely irrelevant in this case and should be rejected as such.

Ground H - The Respondent submits that the contents of the Paragraphs 14-15 of Ground H are wholly denied and disputed. It is submitted that the Authority may examine the veracity of the data regarding plant shut down and also examine the real reasons of such shut down. Plant shutdown cannot be attributed to imports if there have other reasons for it.

Ground I - The Respondent submits that the contents of the Paragraphs 16 of Ground I are wholly denied and disputed. Further, the Respondent fails to understand that why the domestic industry is raising such grounds that would have been pertinent in an anti-dumping proceeding. Assuming without conceding that KPC is suffering loss in sales, how would that information help in justifying levy of safeguard measure on the subject product? By raising such grounds, the domestic industry has repeatedly conceded that anti-dumping duty rather than safeguard duty is the appropriate remedy for them.

Ground J - The Respondent submits that contents of Paragraph 17 of Ground J of the written submissions are factual and matter of record and need no reply.

Ground K - The Respondent submits that insofar the contents of Paragraph 18 of Ground K of the written submissions are factual and matter of record they need no reply. It is submitted that the Authority may note that 4-ADPA produced by the domestic industry is neither like nor substitutable with the product under consideration or the subject product.

Ground L - The Respondent submits that the contents of Paragraphs 19-22 of Ground L of the written submissions are wholly denied and disputed. It is submitted that the Applicant does not constitute domestic industry in the present case, as the production of the domestic industry does not constitute a major proportion of the domestic production. In the public hearing dated 19th December 2013 before the DG Safeguards, the Applicant had claimed that the break-up of capacity among all the domestic producers was the following:

- a) NOCIL: 8500 MT/ yr
- b) Merchem: 8500 MT/yr
- c) Lanxess: 2000 MT/yr
- d) PMC: 1000 MT/yr.

The Applicant no longer has 50% of the capacity to produce the subject good. Therefore, it is highly likely that it will not ultimately produce 50% of the subject good. In such a situation, the question of whether the Applicant produces a "major proportion" of the subject good arises for consideration. It is submitted that the Authority must examine this important aspect to construe standing of the Applicant in the present proceedings.

Grounds M and N - The Respondent submits that the contents of Paragraphs 23-33 of Ground M and Paragraphs 34-36 of Ground N of the written submissions are wholly denied and disputed. It is submitted that the requirement under Article XIX of the GATT and AoS is not that there have been increased imports by just showing some data and figures related to the POI. The requirement is that the Applicant has to first identify how certain developments were unforeseen at the time of entering into commitments under GATT that led to increase of imports of the subject product. Secondly, the Applicant has to identify how due to specific obligations under the GATT with respect to the subject product led to increase of imports. It is submitted that till the present stage of the investigation, the Applicant has not made any submission or claim where it has established existence of unforeseen developments and any specific obligation that India incurred with respect to the subject product that led to increase of imports. Thirdly, even if the Applicant fails to establish the above two requirements, the burden still lies with the Authority to complete the above analysis and record the same in its findings. The Respondent fails to understand how mere figures from the POI in the written submissions establish the above requirements. Mere perusal of figures is not enough. The Authority is urged to complete the above analysis in its finding. Substantive submissions regarding the same have already been provided in our earlier submissions as well as our written submissions.

Ground O - The Respondent submits that the contents of Paragraphs 37-60 of Ground O of the written submissions are wholly denied and disputed. Substantial submissions in this regard have been dealt with in our earlier submissions. It has already been submitted in our earlier submissions that there is requirement of establishing serious injury to the domestic industry before extending safeguard duty in a review. The domestic industry has not only failed to establish serious injury, but has also failed to establish vital requirements of Article XIX of the GATT. It has already been submitted that the actual reason of domestic industry's depleting market share is due to other domestic producers, which are not supporting this petition, that are expanding their capacity, such as Merchem. By their admission, the domestic industry stated that Merchem has increased its capacity for the subject product to 8500 MT/year in the public hearing dated 19th December 2013. Further Merchem is adding facilities to produce 4-ADPA as is established from their annual report already provided with our written submissions dated 31st December 2013. Any further injury analysis based on factors such as production, capacity utilization, etc. is futile when the domestic industry has failed to establish the pre-requisites of Article XIX and AoS. As submitted earlier, mere perusal of figures and data is not enough. Analysis has to show a causal link to serious injury, otherwise it just becomes an exercise in statistics, in which the domestic industry has indulged. Such a hollow analysis is unacceptable and therefore, should be rejected.

Ground P - The Respondent submits that the contents of Paragraphs 61-62 of Ground P of the written submissions prove that the domestic industry has finally accepted that the reason of injury is dumping. A mere perusal of the first two sentences of Paragraph 61 of the written submissions that states

"There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than dumping and low priced imports. Dumping of the product from China, Korea and EU caused injury to the domestic industry."

indicates that the domestic industry has conceded that the appropriate remedy in this case should have been anti-dumping duty and not safeguard duty.

i) It is submitted that from the above admission of the domestic industry, the present case completely goes out of the purview of safeguard law. It is clearly a case of forum shopping and abuse of due process of law. The Authority may be pleased to terminate this investigation immediately.

Ground Q - The Respondent submits that the contents of Paragraphs 63-64 of Ground Q further strengthen that the present case should no have been initiated under safeguard law framework. A mere perusal of the second sentence of Paragraph 63 of the written submissions that states

"...the dumping of the product under consideration and increased imports have caused injury to the domestic industry." shows that the domestic industry has again conceded that the appropriate remedy in this case should have been anti-dumping duty and not safeguard duty. Further, the domestic industry has failed to prove how increased imports were the cause of injury, as it could not prove how certain unforeseen developments and due to certain specific obligation under GATT related to the subject product led to increase of imports. Therefore, there is no causal link established.

Ground R - The Respondent submits that the contents of Paragraph 65 of Ground R of the written submissions are wholly denied and disputed. Safeguard duty cannot be extended as a result of this investigation as has already been established in our earlier submissions.

Ground S - The Respondent submits that the contents of Paragraph 66-71 of Ground R of the written submissions are wholly denied and disputed. It is submitted that extension of safeguard duty in the present case shall not be in public interest. As has already been established in our earlier submissions, there is a sharp shortfall in the supply of the subject product in the domestic market. Further, the Applicant has only indulged in expansion of a facility that produces an intermediate 4-ADPA, which would not address the needs of consumers such as members of ATMA that heavily rely on the subject product. In fact, levying safeguard duty would be contrary to public interest and would only promote inefficient industries like the Applicant to abuse the due process of law. The Authority is, therefore, urged to terminate the subject investigation in public interest.

Ground T - The Respondent submits that the contents of Paragraph 72-82 of Ground R of the written submissions are wholly denied and disputed. It has been comprehensively established in our earlier submissions that the Applicant has not only failed to meet its adjustment plan but has also relied on a fraudulent adjustment plan in the present investigation. The initial adjustment plan submitted in the original investigation was for establishing a plant in Dahej that would produce PX-13 and the current plan is regarding establishment of a plant in Dahej that would produce an intermediate 4-ADPA, which is a completely different product than the subject product. The Applicant has not only provided a fraudulent adjustment plan, but has also failed to meet its initial adjustment plan and now argues that it requires extension of safeguard duty to realize full benefit of the adjustment plan. This cannot be allowed. If the Applicant had been complacent, that does not mean that other interested parties should suffer because of that. That is not the purpose of safeguard law.

i) The domestic industry has misrepresented facts in the present investigation by incorrectly stating about the previous adjustment plan provided during the original investigation. The statements made in the present investigation are completely different from the commitments made in the previous investigation. The domestic industry has also been unable to adhere to the commitment made in terms of previous adjustment plan and thereby take full benefit of the safeguard measures so imposed. In light of the above, the argument of the domestic industry of having met its adjustment plan has to be rejected outright. This investigation should, therefore, be terminated.

ii) The domestic industry has failed to prove existence of significant, sharp and sudden increase of imports, has failed to prove existence of unforeseen developments and any specific obligation under GATT with respect to the subject product that led to increase of imports. There is neither any serious injury to the domestic industry nor any such likelihood. The domestic industry has also failed to meet its adjustment plan. Further, there is no deterioration in performance of domestic industry due to the imports of the subject product.

iii) To conclude, there are no increasing imports due to existence of any unforeseen developments and India's obligation incurred during 1994, no causal link exists between assumed increase of imports and injury to domestic industry, which are the pre-requisites before any safeguard measure can be imposed. Also, imposition of safeguard measure will not be in public interest since domestic industry has no capability to cater to the demand of user industries. Further, having failed to meet its adjustment plan, the domestic industry has failed the mandate of Rule 18 of the Safeguard Rules, and therefore, safeguard duty cannot be extended. iv) As the domestic industry has accepted dumping as reason of injury, it is submitted that the Authority may direct the Applicant to seek remedy before the DGAD.

v) M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea ("KPC") is an interested party in the subject investigation. KPC refers to the Authority's e-mail dated 18 March 2014 inviting comments from interested parties on two letters filed by the applicant domestic industry with the Authority dated 14 March 2014 in the subject investigation.

vi) Without prejudice to the submissions contained in this letter, KPC submitted that the review of the safeguard duty on imports of PX-13(6 PPD) must be completed before expiry of such safeguard duty. Such an extension of safeguard duty on the completion of the review investigation, if it is so recommended, will only be done in this investigation after expiry of such duty which is untenable in law. As a result of the above, KPC submits that the DG Safeguards should terminate the investigation forthwith without inviting any more clarifications from the interested parties.

vii) KPC notes that the applicant has made certain claims therein regarding achievement of enhanced capacity for production of the subject product to 14000 MT from earlier capacity of 8500 MT in its Thane plant. The applicant's claims are based on:

- (a). Reduction in cycle time at Thane plant from 150 minutes to 90 minutes by change in raw material to 4ADPA from 4NDPA for production of the subject product;
- (b). Production of 4ADPA, an intermediate for manufacturing the subject product, at its Dahej plant that supplies the 4ADPA to Thane plant for production of the subject product;
- (c). Certification by a Chartered Engineer dated 14 March 2014 showing that the capacity at Thane plant has increased to 14000 MT.

viii) KPC notes that by the aforesaid letters, the applicant somehow wants to prove its argument related to enhanced capacity of the subject product that the applicant took up during the public hearing on 19 December 2013. It should be noted that the DG Safeguards provided till 31 December 2013 to all interested parties to submit written submissions to the Authority post public hearing. KPC fails to understand why the applicant has been allowed to file the aforesaid submissions concerning arguments taken up in public hearing dated 19 December 2013 after a considerable lapse of time of more than two months. By giving additional time to the applicant post public hearing to make submissions the Authority has shown bias towards the domestic industry. This is a violation of principles of natural justice and the applicant's aforesaid submissions should be rejected on this ground alone.

ix) Without prejudice to the above, KPC notes that the steps taken by the applicant at its Thane plant as per its aforementioned letters hardly comply with the applicant's adjustment plan that it submitted at the time of original investigation. As KPC has already established in its earlier submissions, the applicant has relied on a different version of adjustment plan in the present review than the one submitted in the original investigation. **While, as per the original adjustment plan mentioned in the Final Finding dated 6 June 2011, the applicant undertook to commence production of the subject product at its Dahej plant based on a certification from a 'Chartered Engineer' that it would accomplish the same by April 2012.** In the version submitted in the present investigation, the applicant argues that it had only proposed to commence manufacture of 10,000 MT intermediate 4ADPA at its Dahej plant from FY 2013. KPC submits that the applicant is playing fraud on the Authority by confusing the Authority with its adjustment

plans. Moreover, the applicant has miserably failed in complying with its adjustment plan by delaying its adjustment by almost 2 years even though the adjustment plan was considered feasible by the applicant as it was certified by a Chartered Engineer. The result of failure to comply with its adjustment plan is that fair trade between India and other nations concerning the subject product has been adversely affected.

x) Now, the applicant has again submitted a certificate given by a Chartered Engineer certifying enhanced production capacity for the subject product at its Thane plant. It is submitted that if the applicant could not achieve its adjustment plan of 2011 that was certified by a Chartered Engineer, then the applicant's present claims in the aforementioned letters regarding enhanced capacity at Thane plant based on a certificate by a Chartered Engineer again raise doubts about its feasibility and practicality. It is indeed possible that such claims are nothing but hollow statements made by the applicant to cover-up flaws and divert the Authority's attention from delays in implementing its original adjustment plan. The aforementioned letters and the accompanying certificate are mere theoretical assertions without any practical feasibility. Such assertions cannot be accepted by the Authority, and therefore, should be rejected forthwith.

xi) Further to the reasons given above, KPC submits that the aforesaid letters only indicate that due to reduction in cycle time, the applicant is able to achieve production of 14000 MT for the subject product. But it is not clear from the letters whether the applicant is able to manufacture sufficient quantities of intermediate 4ADPA at its Dahej plant that would allow it to manufacture 14000 MT of the subject product. It is submitted that mere assertions of enhanced capacity at Thane plant based on reduced cycle time is no indication of actual ability to manufacture 14000 MT of the subject product if there is inadequate supply of intermediate 4ADPA to Thane plant from Dahej plant. The applicant has to show that it is producing sufficient quantities of 4ADPA at Dahej plant that could be converted to 14000 MT of the subject product at Thane plant. Failure to do so renders the applicant's claims empty; therefore, these claims should be rejected. The applicant's aforementioned claims about enhanced capacity are devoid of any material support such as data of adequate production of intermediate 4ADPA from Dahej plant and its supply to its Thane plant. In fact, the applicant should have provided production log sheets of Dahej plant and any branch transfers of 4ADPA to Thane plant to buttress its claims of enhanced production at Thane plant, which it has failed to do so by the aforesaid letters.

xii) Without prejudice to the above, the applicant, by admitting through the aforesaid letter that it produces only 4ADPA at Dahej plant, which is supplied to its Thane plant for production of the subject product, has conceded that it has not complied with its adjustment plan submitted during the original investigation wherein it gave an undertaking that it would manufacture the subject product at its Dahej plant. It is submitted that in terms of Article 5.1 of the Agreement on Safeguards read with proviso to Rule 16(2) and Rule 18(1)(i) of the Indian Safeguard Rules, the applicant has failed to adjust positively and failed to take adequate steps to meet its own adjustment plan. Therefore, the present review should be terminated immediately because of the applicant's failure to adjust positively as per its adjustment plan.

xiii) Without prejudice to the above, it is submitted that for the purpose of this review, in terms of Rule 18(2)(i) of the Safeguard Rules, 1997, the applicant should have shown steps taken between the period from levy of safeguard duty till its expiry on 29 August 2013. That analysis would have been meaningful and would have helped all interested parties to assess the need of continuation of safeguard duty. Any steps taken post expiry of safeguard duty are irrelevant for the purpose of the present review. Since the applicant's aforementioned letters and accompanying data relate to steps taken post expiry of safeguard duty, such submissions should be rejected forthwith.

xiv) KPC submits that the applicant's aforementioned submissions should have no bearing on the present review and KPC reserves the right to challenge the aforementioned submissions at an appropriate forum.

xv) KPC submits that the present review should be terminated immediately in light of the reasons given above and its submissions made earlier during the present investigation and fair trade restored between India and other WTO member countries.

20. M/s Rishroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai:

The submissions are similar point-wise as reflected above by M/s Kumho Petrochemicals Company, Korea.

21. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) and its member companies (JK Tyre, CEAT, Apollo Tyre and MRF Limited):

1. THE REQUIREMENT UNDER RULE 18 WOULD BE APPLICABLE IN A SAFEGUARD REVIEW INVESTIGATION

a) The DI vide page 2 of their Post PH WS has argued that the requirements under Section 8B (4) of Custom Tariff Act, 1975 ('Indian SG Act') is applicable in the present SG review investigation. However this submission of DI is incorrect and should be rejected.

b) ATMA submits before the Hon'ble DGS that in SG review investigations wherein the duration of the SG duty is less than 4 years, the requirement of Rule 18 would be applicable and not Section 8B(4). The requirements under Section 8B(4) would be applicable in a scenario wherein the duration of the SG duty is 4 years and there is an application for extension of the SG beyond 4 years. Section 8B (4) is reproduced below:

Section 8B (4)

The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

c) Thus Section 8B(4) provides that a SG duty unless revoked earlier will expire after 4 years. Therefore this provision states the duration of a SG duty. Further 2 exceptions have been provided to this provision in the form of proviso. The first exception is that the Central Government may further extend the period of imposition of the SG duty beyond 4 years if the DI has fulfilled certain requirements mentioned therein and the second exception is that in no case the SG duty be continued after an expiry of 10 years from the date of first imposition.

d) The above submission of the importers is further strengthened by the fact that the initiation notification of this investigation also states that this investigation has been initiated under Section 8B(4) read with Rule 16 and Rule 18. Thus it is Rule 18 which specifically contemplates a scenario of SG review investigation when the duration of the SG duty is less than 4 years which would be applicable in the present investigation and not Section 8B(4).

e) The DI has also argued that Section 8B(4) uses the word 'continue' and which is similar to the word 'continue' as used in Section 9A(5) of the Custom Tariff Act, 1975 ('Indian AD Act'). Since AD duty can be extended even after the expiry of the existing AD duty, the same should also be applicable in a SG review investigation. However as submitted above the requirement under Section 8B(4) would not be applicable in the present investigation. Instead it is the requirement under Rule 18 which would be applicable. Thus this argument of the DI should be rejected.

f) In view of the same, the present investigation is liable to be terminated.

2. THE REQUIREMENT OF INCREASED IMPORTS, SERIOUS INJURY AND CAUSAL LINK IS ALSO APPLICABLE IN A SAFEGUARD REVIEW INVESTIGATION

a) The DI in its Post PH WS has argued that the requirement of increased imports and serious injury is not a pre-requisite at the time of initiation of a SG review investigation. This submission of the DI is incorrect and should be rejected. Firstly the importers in their Post PH WS has very clearly established that the Article 7.1 and Article 7.2 of the WTO Agreement on Safeguards clearly requires the investigating authority to examine requirements of increased imports, serious injury or threat of serious injury and causal link in a safeguard review investigation. It should be noted by the Hon'ble DGS that the DI has not rebutted this argument and has very conveniently ignored this submission of ATMA.

b) The above obligation under the WTO Agreement on Safeguards is also reflected within the Indian SG Act and Indian SG Rules which states the provisions under Rule 5, 6, 7 and 11 of the Indian SG Rules shall be applicable *mutatis mutandis*. The DI has tried to rebut the same by citing a decision by the Hon'ble Supreme Court in the matter *Ashok Service Center and Ors v. State of Orissa*. However the facts of the case and the decision of the Hon'ble Supreme Court in fact further supports the argument of the importers.

c) The Hon'ble Supreme Court rejected the contention of the Government of Orissa and observed as follows:

Section 3(2) of the Act shows that the State Legislature intended not to depart, substantially from the Principal Act except with regard to matters in respect of which express provision had been made in the Act. The Act only levied some extra sales tax in addition to what had been levied by the Principal Act. The nature of the taxes levied under the Act and under the Principal Act was the same and the Legislature expressly made the provisions of the Principal Act mutatis mutandis applicable to the levy under the Act. We are of the view that it is necessary to read and to construe the two Acts together as if the two Acts are one, and while doing so to give effect to the provisions of the Act which is a later one in preference to the provisions of the Principal Act wherever the Act has manifested an intention to modify the Principal Act.

d) Thus the Hon'ble Supreme Court rejected the argument of the Government of Orissa and clearly held that the act of the Principal act was applicable as the new Act used the word *mutatis mutandis*. Similarly Rule 18 of the Indian SG rules clearly states that Rule 5, 6, 7 and 11 shall be applicable *mutatis mutandis*. Therefore Rules 5, 6, 7 and 11 would be applicable in the present investigation. It is also to be noted that there is no other provision within the Indian SG Act and the Rules which states contrary to the applicability of Rule 5, 6, 7 and 11. In view of the same, the contention of the DI should be rejected and the Hon'ble DGS is required to examine the existence of increased imports, serious injury and causal link between the same.

3. THE INVESTIGATION IS ULTRA VIRES OF SG ACT AND RULES

a) The importers in their injury submission have very clearly established that this investigation is *ultra vires* of the Indian SG Act and the Rules. The importers for the sake of brevity would not repeat their arguments made in the injury submission and Post PH WS but would rely on the same. However the importers would herein highlight the incorrect submission made by the DI in its Post PH WS.

b) Firstly the DI has cited the *Soda Ash investigation* to support their argument that a SG duty can be continued even 'with or without pause'. However as established by the importers in their Post PH WS, in the *Soda Ash investigation* the final finding was issued by the Hon'ble DGS before the expiry of the SG duty and which therefore further supports the argument of the importers that a final finding by the Hon'ble DGS cannot be published after the expiry of the SG duty.

c) Secondly the DI has tried to draw an analogy between use of the word 'continue' and 'extend' in Section 9A(5) of the Indian AD Act and Section 8B(4) of the Indian SG Act. However the importers rely on their arguments made in this submission wherein it has been established that the requirements under Section 8B(4) of the Indian SG Act is not applicable in the present investigation and instead it is the requirement under Rule 18 of the SG Rules which is applicable in the present investigation.

d) Thirdly the DI has cited a custom circular issued by the CBEC and some AD investigations. However neither the circular nor the AD investigations cited by the DI are relevant in the present investigation as the same is enforced under Section 9A(5) of the Custom Tariff Act, 1975 and wherein the present investigation is initiated under Section 8B(4) of the Custom Tariff Act, 1975 read with Rule 16 and 18.

e) In conclusion, the importers state that it is clear that none of the arguments presented by the DI supports the conclusion that a final finding can be issued by the Hon'ble DGS in a SG review investigation after expiry of the SG duty. None of the precedents cited by the DI supports the position of the DI. In fact the *Soda Ash investigation* and the decision of the Hon'ble Supreme Court as discussed above further supports the position of the importers. In view of the same, it is the submission of the importers that continuation of this investigation is *ultra vires* of the Indian SG Act and the Rules and thus the present investigation should be terminated.

4. THERE IS A DEMAND SUPPLY GAP WITH RESPECT TO PX 13

a) The importers in their Post PH WS have clearly established that there exists a demand supply gap for PX 13 in the country and due to which the importers are forced to import PX 13.

b) Since the DI in their Post PH WS has not provided any new arguments, the importers stand by their arguments made in their Post PH WS. The importers further request the Hon'ble DGS to verify the installed capacity of the DI with respect to PX13 which would clearly establish the actual capacity of the DI.

5. THERE IS NO SUDDEN, SHARP AND SIGNIFICANT INCREASE IN IMPORT OF THE PUC

a) There is no sudden, sharp and significant increase in import of the PUC as claimed by the DI in its Post PH WS. The imports have increased gradually over the last 4 years in consonance with the demand due to the fact that the DI is not able to cater to the increasing demand of the PUC in India. Moreover during this time period, the market share of the imports in the total demand of the PUC has actually declined.

b) Since the DI has not presented any new arguments with respect to the same, the importers will not repeat their arguments for the sake of brevity but would rely on them.

6. THERE IS NO SERIOUS INJURY:

a) ATMA in its injury submission has clearly established that the claim of the DI with respect to serious injury is not established based upon the data provided in the petition.

b) The DI in its POST PH WS has not presented any new arguments with respect to serious injury. Thus ATMA relies on its arguments made in the injury submission to rebut the claim of serious injury of the DI.

7. BREAK IN OF CAUSAL LINK:

a) ATMA in their previous submission has clearly established that there is a break in of causal link and the same has not been rebutted effectively by the DI.

b) As the DI has not provided any new arguments with respect to this issue in their Post PH WS, the importers for the sake of brevity would not repeat their previous arguments and would rely on the same.

8. IMPOSITION OF SG DUTY IS NOT IN PUBLIC INTEREST

a) As established in the preceding submission of the importers, the levy of SG duty is not in public interest in the present investigation and also is not in consonance with the past practice of the Hon'ble DGS. It should be noted that the DI till its Post PH WS had not presented any argument with respect to SG duty being in public interest. However the DI in their Post PH WS has argued that the other parties have not presented any evidence to substantiate their claim on public interest and secondly since the share of PX 13 in the tyre manufacturing is miniscule, the same would not impact the user industry.

b) However the submission made by the DI is incorrect and contrary to the past practice of the Hon'ble DGS. In *Methyl Acetoacetate Safeguard investigation*, the DGS noted that the pharmaceutical industry was an important user of the subject product. In concluding that levy of duty would not be in public interest it was observed that "DI has not been able to give evidence as to how imposition of safeguard duty on the PUC will not affect these consumers". Thus the obligation is upon the DI to establish that the continuation of the SG duty would be in public interest and not the other way round. As noted above, the DI till its Post PH WS had not presented any arguments with respect to public interest.

c) Secondly with respect to the DI argument that since the share of PX 13 in tyre manufacturing is minimal, the same would have minimal impact on the user industry. Firstly the DI has not provided any documentary evidence for its conclusion that the share of PX 13 in the tyre manufacturing is minimal. In absence of the same, ATMA is not required to contest the same and therefore the argument of the DI should be rejected. Secondly it should be noted by the Hon'ble DGS that the user industry has been forced to bear the AD and/or SG duty for the last 8 years and which has clearly impacted the user industry even assuming the DI argument to be correct. Thus ATMA stands by its argument made in the Post PH WS that the continuation of the SG duty is not in public interest in the present investigation.

9. DI SUBMISSION ESTABLISHES THAT THE REQUIREMENT OF ADJUSTMENT PLAN HAS NOT BEEN FULFILLED

a) Rule 18 (1) of Indian Safeguard ('SG') Rules requires the DI to adjust positively before the Hon'ble DGS can make a recommendation for continued imposition of SG duty pursuant to a review investigation. In our previous submissions, the importers had drawn the kind attention of the Hon'ble DGS towards the submission of the DI in the original investigation with respect to its adjustment plan:

*NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce ****MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX 13 as one of the product.*

b) The above statement of the DI was also confirmed in the final findings of the original investigation. Thus the DI took a stand in the original investigation that it would produce PX 13 at the new plant. However this position of the DI has suddenly changed in the review investigation wherein the DI is now stating that it is manufacturing 4 ADPA at the new plant and as per the DI, this is the only product which would be manufactured at Dahej.

c) This aspect has now been further reconfirmed by the additional submission of the DI dated 14 March 2014 wherein the DI states as follows:

As far as PX13 is concerned, the same is produced at Thane. 4ADPA which is an intermediate for production of PX 13 is produced at Dahej.

d) Thus it is quite clear that the DI has not implemented the adjustment plan which was outlined in the original investigation. Rule 16(1) of the Indian SG Rules provides that "*The duty levied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.*" Thus the purpose of the safeguard duty is to allow the domestic producers to adjust positively so as to face the competition and an adjustment plan provides an outline of the steps to be taken by the domestic producers in order to adjust positively. However if the DI does not adjust positively, Rule 18(2) of the Indian SG Rules provides that that the Hon'ble DGS cannot make a recommendation for continued imposition of SG duty pursuant to a review investigation.

e) In this respect, the importers would draw the attention of the Hon'ble DGS towards the final findings in the *Review of Safeguard duty against import of Phthalic Anhydride* dated 07 June 2013 wherein the Hon'ble DGS concluded that the DI is required to produce documentary evidence for positive adjustment which has to be in line with the plan proposed in the original investigation for avilment of SG duty protection. Since the DI did not provide any such evidence, the Hon'ble DGS terminated the SG review investigation *against import of Phthalic Anhydride.*

f) Similarly in the present investigation, the DI till date has not provided any evidence that it has implemented the adjustment plan which it had proposed in the original investigation and accepted by the Hon'ble DGS. On the contrary, the evidence available in the present investigation establishes that the DI has not implemented the adjustment plan outlined in the original investigation. Thus it is the submission of importers that this petition of the DI for continuation and enhancement of the safeguard duty cannot be entertained and has to be rejected in view of Rule 18(2) of the Indian SG Rules.

10. DI SUBMISSION ESTABLISHES NO SERIOUS INJURY

The DI in its petition has claimed that it has suffered serious injury on account of import of PX 13. In support, it has argued that there has been a decline in production and capacity utilization among other parameters. In response, the importers in their previous submission had submitted that the DI has been an export centric company and the decline in production and capacity utilization is on account of decline in export sales of the DI. The additional submission of the DI dated 14 March 2014 supports the above submission of the importers.

a. Decline in production and capacity utilization is on account of decline in export sales.

i. The importers have submitted previously that the DI traditionally exports nearly 50% of its production and the decline in production of the DI is on account of decline in export sales. The argument is supported by the figures provided by the DI in its letter to the Hon'ble DGS dated 04 March 2014.

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Production (MT)	7264	6672	5408	4732
Production (Indexed)	100	92	74	65

Domestic Sales (MT)	3516	3697	3641	3701
Domestic Sales (Indexed)	100	105	104	105
Domestic Sales as % of production (%)	48	55	67	78
Export Sales (MT)	3656	2767	2040	1162
Export Sales (Indexed)	100	76	57	37
Export Sales as % of production (%)	50	41	38	25

ii. The importers have taken the figures from 2009-10 till 2012-13 as the application of the DI for initiation of the safeguard review investigation was based on the injury parameters from 2009-10 till 2012-13. These figures and the above chart clearly establishes that while the domestic sales has increased, there has been a simultaneous decline in the export sales which has resulted in the decline of production as the DI was exporting 50% of its production in 2009-10. For e.g. domestic sales in 2009-10 were 3516 MT and which constituted 48% of the total production. It however increased to 3701 MT in 2012-13 constituting 78% of the domestic sales.

Thus the significant increase of domestic sales in the overall share of production clearly establishes the huge decline in export sales. This decline is further put into perspective by the steep decline in the export value.

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Domestic Sales Value (Rs/Lacs)	10,125	10,709	10,772	10,418
Domestic Sales Value (Indexed)	100	106	106	103
Export Sales Value (Rs/Lacs)	7257	5139	4060	2399
Export Sales Value (Indexed)	100	71	56	33

iii. Thus value of export sales declined by 77% in 2012-13 as compared to 2009-10 as compared to the value of the domestic sales which increased by 3% during the same period.

b. Break in of the causal link.

i. Clause (2) of the Annexure to the Indian SG Rules provides that “*When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.*” This obligation is reflected in Article 4.2(b) of the Agreement on Safeguards which is also known as the ‘*non attribution analysis*’. The Appellate Body has interpreted Article 4.2(b) as follows:

Thus, to fulfill the requirement of Article 4.2(b), last sentence, the competent authorities must establish explicitly, through a reasoned and adequate explanation, that injury caused by factors other than increased imports is not attributed to increased imports. This explanation must be clear and unambiguous. It must not merely imply or suggest an explanation. It must be a straightforward explanation in express terms. In this case, the USITC acknowledged that there was injury to the DI on account of factors other than imports. However in its finding it simply stated that it has not attributed injury to the DI on account of such other factors. The Appellate Body found this explanation as not fulfilling the requirements of Article 4.2(b) of the Agreement on Safeguards as the “*USITC Report do not establish explicitly, with a reasoned and adequate explanation, that injury caused by factors other than the increased imports was not attributed to increased imports.*”

ii. Therefore injury to the DI on account of factors other than imports should not be attributed to imports as the same leads to break in of the causal link. However in the present investigation, it is quite clear that the DI has suffered injury on account of decline in exports. In addition, the importers in their previous submission have also provided other factors which leads to break in of the causal link and which are therefore required to be segregated. In view of the same, the causal link between serious injury to the DI on account of imports cannot be established unless injury to the DI on account of these other factors are segregated and removed. Further in view of the above ruling of the Appellate Body, the importers would kindly request that there should be a *reasoned and adequate explanation* with respect to the same.

In view of the above, there is break of the causal link between serious injury to the DI on account of imports unless serious injury on account of other factors is segregated with a reasoned and detailed explanation.

11. DI DOES NOT HAS THE CAPACITY TO CATER TO THE DOMESTIC DEMAND

a). As per the data provided by the DI, its installed capacity till 2012-13 was 8992 MT as compared to the overall demand of 18,315 MT in 2012-13. Thus the user industry had no other option but to import during the period from 2009-10 to 2012-13. Therefore imports made during this period were on account of the inability of the DI and the user industry should not be further penalized due to the inability of the DI.

b) The DI has tried to circumvent this inability by providing the capacity data for April 2013-January 2014 which puts the DI capacity at 12,000 MT and further the data for March 2014 at 14,500 MT. While this data has to be verified by the Hon'ble DGS, even assuming that this data is correct, it is the submission of the importers that this additional data cannot be taken into account for assessing the capacity of the DI.

22. Rejoinder by Domestic Industry

This has reference to the oral hearing conducted by the Designated Authority in the matter of extension of safeguard duty investigation on imports of PX-13(6PPD). We are grateful to the Authority for providing us the opportunity to present our views orally at the time of the oral hearing. The following interested parties have made Post-Hearing written submissions:

1. M/s Kumho Petrochemicals Co. Ltd.
2. M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.
3. Automotive Tyre Manufacturer Association(ATMA)
4. European Union

The domestic industry reiterates all the facts, contentions, averments and statements presented in the earlier submissions filed with the Designated Authority and requests that such submissions be deemed to be incorporated herein. Non-reproduction of these arguments in the present submissions on any issue raised by the domestic industry so far should not be held against the domestic industry. The submissions are being made below without prejudice to one another or to any other submissions on behalf of the domestic industry.

A. Standards of analysis at the time of review-

A major issue which arises for consideration and decision by the Director General is how increased imports and injury to the domestic industry must be determined in a review like the present. Followings are relevant in this regard.

(I) Legal requirement –It would be seen that the Director General is required to consider in a review whether safeguard duty should be continued further. For the purpose, the Director General is required to consider whether the product continues to be imported in India in “such increased quantities” so as to cause or threatening to cause serious injury to the domestic industry. Further, the Director General is required to consider and determine whether such continued imposition of safeguard duties is necessary to prevent or remedy serious injury. Petitioner submits that the rules clearly provides for a determination with regard to whether safeguard duty is necessary. The purpose of such continued imposition of safeguard duty has also been specified under the rules, i.e. to prevent or remedy serious injury as a result of revocation of safeguard duty. Petitioner submits that a determination relating to whether safeguard duty may be necessary to prevent or remedy serious injury implies (a) whether the domestic industry continues to suffer serious injury and such continued serious injury is required to be remedied; OR (b) in the alternate to (a), where there may not any longer be serious injury, whether such safeguard duty is necessary to prevent such serious injury upon revocation of safeguard duty. This later situation clearly implies that the domestic industry may no longer be suffering serious injury after imposition of safeguard duty (which could be a result of very imposition of safeguard duty), but such serious injury may be likely in the event of discontinuation of present safeguard duty and such likely serious injury should be prevented by further continuation of safeguard duty.

Safeguard rules at 18(3) clearly provide that the provisions of rule 5, 6 and 11 shall apply mutatis mutandis basis. In other words, provisions under 5, 6 and 11 cannot be read in the same manner in which they are required to be read and interpreted in a fresh investigation. Given that safeguard duty is already in place, it follows that the determination relating to increased imports and serious injury have to be made having regard to safeguard duty in place.

The interested parties have extensively argued at the time of both the hearing and also in their written submissions that no safeguard duty can be extended unless –

- Imports of the product show “increased imports”; and
- The performance of domestic industry shows serious injury.

(i) To put otherwise, these requirements must be read and applied as they are applied in original investigations. This would imply a determination of “increased imports” of the quality and quantity as is required in an original investigation. In other words, the director general must establish a sudden, significant, sharp & recent surge in imports.

The requirement under the law is that the imports of the product under consideration should pass the following tests –

- (a) the increase should be recent enough,
- (b) the increase should be sudden enough,
- (c) the increase should be sharp enough,
- (d) the increase should be significant enough

(ii) By no stretch of imagination, it can be argued that the legislator would have drafted the law with above prescription at the time of review to imply that the data in the most recent period should be compared with just the preceding period. The only possible situation in which such position (of recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough increase in the imports after imposition of safeguard duty) would exist is where the safeguard duty only is wrongly imposed or the quantum of safeguard duty is so grossly inadequate that the imports of the product continued to remain highly lucrative despite imposition of safeguard duty and resultantly, the imports of the product showed **further** surge, that too a surge within the meaning of safeguard law) and performance of the domestic industry further deteriorated. In other words, it implies a situation where safeguard duty of just & adequate amount was imposed, but the same had no impact at all and the situation continued with surge in imports and injury to the domestic industry. This also implies that there is no mechanism under the safeguard law which permits extension of safeguard duty in a situation where the safeguard duty has had the desired impact, partial or full, but the safeguard duty imposed earlier is required to be extended further in order prevent or remedy injury. It is settled principle of law that nullity in law cannot be permitted.

(iii) Contrary to what the interested parties have argued, and as the above makes it evident, what the Director General is required to determine in a review is whether the imports of the product have continue to remain so significant inspite of imposition of safeguard duty that the same constitutes “increased imports”, when compared with pre-surge period and whether the revocation of safeguard duty at this stage would lead to a situation where such imports cause or threaten to cause injury. Further, the Director General is required to determine whether the safeguard duty should be continued further to prevent or remedy injury. The above makes it very clear that while the imports must be considered for the recent period, the same does not mean the volume of imports must show increased imports at the time of passing the judgment. Nor the comparison need be restricted with the immediately period.

II. Practice of other investigating Authorities – in view of the fact that the present investigation is the first case of an expiry review and in view of the argument by interested parties, petitioner reviewed the determinations made by other countries. Following cases are referred to and relied upon:

- (a) GLASS MIRRORS [WTO report no G/SG/N/11/PHL/3/Suppl.2 and G/SG/N/14/PHL/4] - On 12 May 2006, the Department of Trade and Industry (DTI), Philippines received **a letter** from Asahi Glass Philippines, Inc. (AGP) requesting for the extension of the definitive general safeguard measures against imported glass mirrors (copper-based) classified under AHTN Nos. 7009.9100 and 7009.9200 from various countries. AGP claimed that the industry needed more time to complete the implementation of its adjustment plan and become import competitive. Moreover, external factors such as rise in power and fuel prices, overall transport costs and China’s massive import demand which pushed up prices of most commodities, adversely affected their cost competitiveness. The Authority held as follows –

On 5 October 2006, DTI received a copy of the Commission’s report on the petition of AGP. The Commission concluded that “as the sole manufacturer of glass mirrors, petitioner Asahi accounted for all domestic production of subject articles. The domestic industry made serious efforts to comply with its adjustment plan and there is evidence that the industry is making positive adjustment to import competition. The current safeguard measure is effective. The volume of imports decreased below the pre-surge level. The domestic industry showed improvements in its production, sales, market shares, productivity, capacity utilization and profitability. Without a safeguard duty, domestic selling prices will fall below levels not enough to recover cost to produce and sell. There is a substantial threat of serious injury if safeguard duty is not extended. Current overcapacity in China’s domestic market, more furnaces being built and import trends in the Philippines indicate that the resumption of substantial increased imports is very likely once the safeguard measure is discontinued. The proximity of China to the Philippines and their sufficient freely disposable production capacities indicate the likelihood of substantially increased exports to the Philippines if the safeguard measure is terminated. Factors outside the control of Asahi negated the gains resulting from its stalled adjustment plan. Asahi needs more time to fully put it in place to effectively face import competition. Non-extension of the safeguard measure will likely lead to increased imports of glass mirror which will cause serious injury to the domestic industry.”

- (b) **White Sugar** (G/SG/N/13/MDA/1), where duty was imposed in 2004, and in review investigation held in 2006, data for 2002 to 2006 was investigated. The Analysis showed as follows:

		2002	2003	2004	2005	2006
Domestic production	1000 tons	114	83	111	133	148
Import sugar	1000 tons	72	74	0	8	0
Export	1000 tons	38	26	5	13	30
Sales to domestic market	1000 tons	150	105	101	114	86
Incl.						

Domestically produced sugar	1000 tons	111	40	101	106	86
Import sugar	1000 tons	39	65	0	8	0
Market share of the domestic product		74%	38%	100%	93%	100%
Market share of imports		26%	62%	0%	7%	0%
Domestic producers stocks at the year end	1000 tons	63	73	71	83	111

Thus the Authority reached to the conclusion that despite the signs of recovery of the domestic industry and its successful efforts to fulfill the compromise, the safeguard measure was still necessary to allow further recovery of the sector.

(c) **Desiccated Peeled Coconut** (G/SG/N/13/BRA/3): where original duty was imposed in 2002 and for the purposes of review investigation held in 2004, data for the period 2002 and 2003 was analyzed. The Authority observed that a fall in volume and a rise in f.o.b. prices of imports were detected. Nevertheless, the volume of imports for the years 2002 and 2003, respectively 4,782.6 tons and 4,519.9 tons, was higher than the quota for the first three years of the measure – respectively, 3,957 tons, 4,154 tons and 4,353.7 tons. Hence the authority reached to the conclusion that the safeguard measure was still necessary to ensure the full recovery of the sector.

(d) **Crown Corks** (G/SG/N/13/BGR/1), where original duty was imposed in 2002 and for the purposes of review investigation held in 2004, data for the period 2002, 2003 and 2004 was analyzed. Here, after the analysis of the domestic industry, Authority reached to the conclusion that the safeguard measure is still necessary to ensure the recovery of the sector as though not all of the expected results have been achieved during the period under review.

It is evident from the above that even if imports have completely dried up after imposition of safeguard duty and performance of the domestic industry has substantially improved, the same is insufficient justification of termination of safeguard duty or not extending it further. What is relevant at this stage is whether continued imposition of safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury. The objective of safeguard duty was to remedy serious injury to enable the domestic industry to recover from the injury earlier caused by increased imports. In other words, recovery in the performance of the domestic industry is pre-supposed and expected and is in fact the objective of imposition of safeguard duty. Such being the case, the fact that the performance of the domestic industry has improved after imposition of safeguard duty cannot be a factor for non-existence of safeguard duty. On the contrary, safeguard duty is required to be imposed to enable the domestic industry to improve its performance.

III. Jurisprudence emerging from dumping law – in view of the fact that a very large number of expiry/sunset reviews have been conducted on antidumping front, it would be relevant and useful to understand how the Designated Authority on antidumping examines the performance of the domestic industry at the time of sunset review and how the authority comes to a conclusion whether the anti-dumping duties should be extended further. However, to be fair to all, before referring to the determinations made by the authority on anti-dumping and emerging jurisprudence, it is necessary to consider the law itself.

Section 9 A (5) of the customs tariff act provides as follows:

The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition: provided that if the central government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

Rule 23 of the dumping rules provide as follows:

(IV) Review: (1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that

the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

It would be seen that whereas anti-dumping law requires a determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury at the stage of sunset review, the safeguard rules requires a determination whether continued imposition of safeguard duty is required to prevent or remedy serious injury.

What does the Designated Authority considers at sunset review – from the vast number of decisions/determinations on anti dumping, the jurisprudence which clearly emerges is as follows:

- (a) whether the dumping continued; and if so, whether the dumping is likely to continue;
- (b) whether the injury to the domestic industry continued; and if, whether injury is likely to continue;
- (c) if dumping has not continued, whether dumping is likely to recur in the event of revocation of duty;
- (d) if injury has not continued, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of duty;

It would thus be seen that existence of dumping or injury is not even a pre-requisite for extension of anti-dumping duties. The Designated Authority must examine whether dumping and injury is likely in the event of revocation of anti-dumping duties.

In the light of the above jurisprudence, the petitioner submits that what the Director General is required to determine at this stage is -

- (a) Whether imports of the product continue to constitute increased imports – The Director General is first require to consider imports of the product and determine whether the imports of the product have continued to such an extent that the same constitute increased imports. Petitioner submits that such a determination can only be made considering imports in the most recent period and comparing the same with pre-surge period of the original investigations. By no stretch of imagination, imports in the most recent period can be compared with the period of surge in import earlier established and the conclusion drawn with regard to increased imports. Had this been the requirement and understanding, other WTO members would not extended safeguard duty when the imports had declined or even dried up after imposition of safeguard duty.
- (b) With regard to serious injury, the Director General is required to establish whether the domestic industry continues to suffer serious injury or threat of serious injury, i.e., serious injury to the domestic industry is likely i.e. whether imports would cause or threaten serious injury in event of revocation of Safeguard duty.

(VI) Replies to the issues raised by ATMA

1. **Despite 8 years of duty protection, the domestic industry has not taken steps to become competitive in the domestic market. This is evidenced by the demand supply gap in the domestic market. The domestic industry exports 50% of its production which further reduces the option of the user industry.**

Petition, written submissions and previous findings issued by the Director General (Safeguards) are relied upon which clearly deals with steps taken by domestic industry to become competitive in the domestic market. There is no demand supply gap for the product in the Country. The domestic industry does not export its product out of choice/preference. The exports are a matter of compulsion, as is clearly established by lower price at which exports are being made. The imports by consumers have been made because of price considerations and not because of non availability of the product in the Country. Elaborate written submissions are referred to and relied upon.

2. **The increase in imports has to be seen in the context of increase in demand and the installed capacity of the domestic industry remaining constant. Commissioning of the new plant at Dahej is only for production of 4 ADPA.**

Written submissions are referred to and relied upon. The increase in import is not justified by the increase in demand for the reason that the domestic industry has lost production. The domestic industry should have gained production and its capacity utilisation should have been optimum had the imports being made because of demand supply gap in the country. The new plant at Dahej is clearly for product under consideration, given that 4 ADPA is only a penultimate intermediate in production of PX-13 and does not have any use other than for production of PX-13.

3. **Total installed capacity in India for PX-13 is 13,799 MT (calculated from market share), while total demand is 18,315 MT.**

The calculations are flawed. Capacities cannot be calculated from market share. Market share is determined from sales, whereas capacities are determined based on ability of a company to produce the goods. The installed capacity for the product under consideration during period of investigation was 20,500MT which was sufficient to meet the demand for the product in the Country. Further, in any case, some imports would have been made in the country given the duty exemption scheme of the Government of India. Thus, net demand available to the domestic industry, in any case, is lower than the consumption figures determined by the domestic industry. Further, as stated in the written submissions, demand in the country cannot be compared with the capacity of the domestic industry. Demand

for the product in the country needs to be compared with the installed capacities of the domestic producer as a whole.

4. **As long as recommendation in the form of final findings by the DG Safeguards is made before the expiry of the duty, the requirement under Rule 18 is fulfilled. This has been done in all past cases, including Soda Ash, cited by the domestic industry in the hearing.**

Following are relevant rule 18 is extracted below.

18. Review

- a. *The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that,*
 - i. *safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;*
 - ii. *there is no justification for the continued imposition of such duty; recommend to the central Government for its withdrawal:*

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the midterm of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalization of duty.

- b. *Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.*
- c. *The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall mutatis mutandis apply in the case of review.*
 - a. Further, extension of safeguard duty is governed by Section 8B(4) which is extracted below.
 - b. *Section 8B(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:*

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

- c. It would be seen that the fact whether Director General (Safeguards) made recommendations before or after expiry of duty is entirely immaterial. What is relevant is the notification by the Central Government. Further, as stated in written submission, petitioner has referred to several cases in the context of anti dumping where duties have been extended after expiry.
5. **The Legislature has intentionally used the word ‘continue’ in Rule 18 of SG rules and not ‘extend’. In Section 9A (5) of the Custom Tariff Act, the word ‘extend’ in paragraph 2 clearly stipulates that the period of commencement of duty shall be from the date of order of commencement of such duty. Therefore the AD Act itself provides that there can be a gap between the previous AD duty and the AD duty which is being extended for another 5 years pursuant to a sunset review investigation. However if the Central Government intends to ‘continue’ the AD duty pending a sunset review investigation, the same has to be without any gap as long as the sunset review investigation has been initiated before the expiry of the AD duty.**

Following are relevant in this regard.

- a. Rule 18 alone is not the relevant legal provision. In fact, Rule 18 deals only with review procedure and midterm/interim review. Rule 16 deals with expiry review or duration of duty.

Further, Section 8B(4) deals with extension of duty. The relevant rules are reproduced below.

Section 8B(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed

16. Duration

The duty levied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of this rule duty levied under rule 12 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of its imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition;

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

It would be seen that in the present case, Rule 16 is relevant, as it deals with extension of duty at the time of expiry of existing duties. Both Rule 16 and Rule 18 have to be considered alongwith Section 8B(4). In fact, the Director General (Safeguards) has clearly referred to Section 8B(4) with Rule 16 and 18 of the Rules in the notice of initiation. Further, Rule 18 is relevant only with regard to the procedure to be followed in conducting a midterm or expiry review.

Rule 16 clearly states “extend” duty and does not state “continue” the duty. A question of review of existing duty shall arise when there is a duty in force and the Director General conducts a review to decide whether the duty should “continue” or should be withdrawn. The question of “extension” shall arise when the duty is completing its period and the question is that of its further extension. Thus, clearly the word “continue” in Rule 18 is entirely immaterial in the present circumstances. The word “extend” in Rule 16 is a relevant legal provision at this stage.

Above all, extension of duty is governed by Section 8C(4) which clearly states “extend” and not “continue”.

d. Arguendo, whether word “continue” or “extend” are considered in the present context, both word have to be considered in the context of “continuation with or without pause”. Thus, even if the word continuation is considered, such continuation may be with or without a pause/interruption. The mere fact that duty has already come to an end does not mean it cannot be continued further.

e. Anti dumping Rule also refers to two kinds of review – (a) a review to decide whether duty should continue or should be withdrawn and (b) a review to consider further extension of duty. The two legal provisions are reproduced below.

Section 9A(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition :

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension :

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

23(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

f. It would thus be seen that even under anti dumping, there are two reviews (a) review for duration of duty and; (b) review for existence of duty. While review for duration of duty shall result in extension, review for existence of duty shall result in continuation or premature withdrawal. The review of duty under Rule 23(1A) is a review to decide whether the duty should continue to remain force during pendency of its duration or the duty should be withdrawn at a premature stage on finding no further justification. This is typically called midterm review or changed circumstances review in anti dumping parlance. Safeguard law clearly provides that a mandatory interim review if such duty was originally imposed for a period exceeding three years whereas anti dumping law provides for a need based interim review.

g. Section 9A(5) second proviso further supports the argument of the domestic industry. The rule is reproduced above. It would be seen that the second proviso permits continuation of duty for a period not exceeding one year, pending outcome of review. The word used here is “may continue to remain in force...”. This has been interpreted extensively by Designated Authority and Ministry of Finance to mean that this duty can be extended even after expiry. Thus, if interpretation drawn by Designated Authority and Ministry of Finance with regard to extension of

duty for one year period is to be accepted, it follows that the safeguard duty can be continued further even after expiry of existing duties. The interested parties indeed have admitted that anti dumping law permits such continuation of anti dumping duty after expiry of existing duty. Such being the case, going by the arguments of interested parties, it is evident that the Government is justified in continuing the duty even after its expiry.

h. While first proviso to Section 9A(5) has used the word “extend”, the second proviso to this section has used the word “continue”. In both the situations, the Ministry of Finance has extended anti dumping duty after the existing duty has come to an end. Thus, Ministry of Finance has not distinguished and differentiated between “extend” and “continue”.

6. Once a customs notification imposing SG duty expires, the same cannot be resurrected by a judicial order (Bombay High Court in *Thirumala Chemicals vs. Director General of Safeguards*)

The issue decided by the Hon’ble High Court in the stated case is entirely irrelevant to the present issue. The issue before Hon’ble High Court was whether High Court has powers to direct continuation of the duties after its expiry, whereas the issue in the present case is whether Central Government has powers to extend the duty after its expiry based on an investigation and recommendation by the Director General (Safeguards). High Court obviously could not have extended safeguard duty beyond the period for which duties was originally imposed by the Central Government, as an extension of duty is permissible only after following the legal provisions in this regard.

7. In the petition in the original case, the domestic industry stated that the Dahej plant was being set up for the manufacture of rubber chemicals and intermediates, including PX-13. In the review investigation, it has stated that it would only manufacture 4 ADPA. The final findings in the original investigation stated that production at Dahej would start in April 2012 while production actually started in March 2013. The domestic industry is not adjusting positively.

The domestic industry provided evidence to the Designated Authority at the time of original investigations which clearly showed that the domestic industry was setting up a plant for production of 4-ADPA and that such 4-ADPA was to be used for production of PX-13. Further, the evidences on record of previous investigation will clearly established that the 4-ADPA plant was being set up at Dahej was for production of 4-ADPA, which was to be used exclusively/solely for production of PX-13. The petitioner has fulfilled the very same obligation as it had incurred earlier. There is no difference between the claims made by the petitioner between previous investigation and present investigation. In fact, following documents were provided to the Director General (Safeguards) at the time of original investigations, a copy of which is enclosed with these submissions for ready reference:

- a. copy of project report
- b. certificate from Chartered Engineer
- c. Project cost certificate

These documents clearly established that the petitioner was setting up a plant for production of PX-13. Thus, it was very well known to the Director General (Safeguards) at the time of original investigations that the petitioner was setting up a plant for production of PX-13. The Director General (Safeguards) is requested to kindly examine original case record in this regard.

The petitioner had targeted commercial production in April 2012. The commercial production has actually started on Mar 2013. While admitting that there was a delay in commencing commercial production, the same, in any case, does not establish that the domestic industry is not adjusting positively. All investments are based on some projection and it is not necessary that all achievements will fall in line as projected. All projects are made with a number of estimates and assumptions with regard to a number of steps that are required to be undertaken for completing the project. A large number of these steps are normally beyond the control of the company undertaking the implementation of the project. Some of the actions that need to be taken by other parties are clearly beyond the control of the company implementing the project. Thus, even when all business enterprises make efforts to chase the targets, it is not necessary that all targets are fulfilled as originally envisaged. However, as far as consumers are concerned, no prejudice has been caused to these consumers on this account. The petitioner continued to produce and sell the product from its existing plant and, in fact, in view of insufficient orders received by the petitioner, even the existing plant remained highly unutilised. Thus, when the petitioner was not in a position to fully utilise its existing manufacturing facilities, injury would have, at the least, aggravated had the petitioner commenced commercial production in April 2012. It may be noted in this regard that the capacities of the petitioner were targeted to increase from *** to *** MT. As against this, the production in period of investigation was only *** MT, even when petitioner had already produced to the extent of *** MT in 2009-10. Leave aside targeting a capacity of *** MT, the petitioner was prevented to achieve utilisation of the existing production capacities even to the extent it had achieved in 2009-10 in view of surge in imports. Thus, the fact that commencement of commercial production at the new plant has got delayed does not in any way vitiate the factual position in the present case.

8. In a review, the DI is required to produce documentary evidence for positive adjustment which has to be in line with the plan proposed in the original investigation. (DGS in *Phthalic Anhydride* Safeguard Review)

The petitioner has provided substantial documentary evidences for the positive adjustments undertaken by the company. Following are the relevant documents which the petitioner had enclosed with the petition.

- a) documents in the form of CA certificate and extracts from balance sheet to show that the company has invested substantial amount of capital on the Dahej Plant and incurred substantial pre-operative expenses including employee cost, pre-marketing expenditure, trial run costs and other expenses
- b) relevant extracts of Annual report on status of Dahej Plant
- c) excise records to show that the company has commenced commercial production at Dahej plant
- d) a statement showing the optimum cost of production of the petitioner at Dahej plant and the cost of production it would have incurred, had the petitioner continued production at old plant to show that the petitioner has already achieved significant cost savings by undertaking production at Dahej.

If the Director General requires any further documentary evidences. The petitioner will provide the same.

9. **In the original investigation, the DGS found that two years was sufficient time for the DI to positively adjust. The DI is requesting extension and enhancement of duty. Therefore the DI has to provide a fresh adjustment plan as per Rule 18 read with Rule 5(2). It cannot claim 4 years protection on the basis of the same adjustment plan that the DGS held required only 2 years for implementation.**

The fact that Director General earlier considered two year as sufficient period does not imply that the Director General cannot now review and consider whether further extension of duty is necessary. Even if the Director General had originally considered that the duty is necessary for 4 or 6 years, the Director General would have always been in a position to recommend duty only for a shorter period and thereafter consider the need for further extension. In fact, the Director General has actually taken a conservative view in the interests of consumers and exporters by recommending duty for shorter period; and therefore this now cannot become a ground to deny further protection to the domestic industry. In fact, even while considering that the safeguard duties can be in force for 10 years, the rule specifies that the duty should be proposed only for 4 years and thereafter extended further if considered it necessary. This clearly establishes that duty need not be imposed at the first place for the full period which appears necessary for the purpose.

10. **In view of the fact that user industry in India has to resort to import to meet their demand, there has not been a recent sudden, sharp or significant increase in imports. Imports have increased gradually over the last four years due to the inability of the domestic industry to cater to domestic demand. Market share of imports has actually declined.**

It is not a fact that user industry in India has to resort to import to meet their demand. On the contrary, imports have been made because of the lower price at which imports were available. This gets clearly established by (i) decline in production and capacity utilisation of the domestic industry, (ii) lower price that the domestic industry is getting in its exports as compared to domestic market, (iii) comparison of landed price of imports and selling price of the domestic industry, (iv) increase in imports despite existing safeguard duties. As a result of increase in safeguard duty, imports should have showed a decline and not an increase.

11. **The domestic industry has stated that imports are mainly entering from China, Korea and the EU, on which anti-dumping duties have been imposed. Injury by dumping is to be segregated from injury by increased imports.**

There are two ways to address the simultaneous imposition of safeguard duty and anti dumping – (a) determine the total quantum of injury and thereafter reduce the existing quantum of anti dumping duty, a methodology followed at present; and (b) determine injury margin after adding anti dumping duties to landed price of import. The petitioner has done calculations on this alternate basis as well which are enclosed with these submissions. It would be seen that the injury margin is still significant. However, if this alternate procedure is followed, the injury margin so determined shall become the safeguard duty and shall have to be applied on all imports without adjusting the same for anti dumping duty. This would thus imply charging safeguard duty even on imports from those sources whether the domestic industry is protected by dumping duties and undercharging safeguard duty on those sources where the domestic industry is grossly under protected by dumping duties. The methodology would have been thus been unfair to all parties – the domestic industry, the consumers and the foreign producers. This would have meant additional duties on imports from some sources (such as China) and under protection to the domestic industry on imports from Korea.

12. **DI has suffered injury on account of decline in demand in export markets which has affected the production and export sales, as per Annual Reports.**

ATMA has on one hand contended that there is a demand supply gap for the product in the country and has at the same time referred to decline in exports of the domestic industry because of decline in demand in export markets. The petitioners fails to understand why it should suffer injury in the form of decline in production and capacity utilisation in a situation where there is increase in demand for the product in the country and where the consumers are repeatedly stating demand supply gap in the country. Given sufficient demand for the product in the country, these decline in demand in the export market in any case would not have impacted the domestic industry had the consumers placed orders on the domestic industry. In any case, the petitioner has segregated its performance with regard to exports and the claimed injury is only on account of domestic market.

13. **The requirement of public interest has not been fulfilled. (DGS in Methyl Acetoacetate)**

The present case is a review case and the requirement of public interest has already been fulfilled in the original investigation. ATMA and other parties are required to provide information and evidence establishing that the

previous determination by the Director General (Safeguards) was inappropriate. No information/evidence has been provided by these interested parties to establish incorrectness of the determination earlier made by the Director General (Safeguards). Such being the case, the previous determination of the Director General (Safeguards) continues to hold field and the Director General (Safeguards) is not required to review the issue. Notwithstanding, the petitioner has established in their submissions that the extension of safeguard duty shall continue to be in public interest. The product under consideration forms quite insignificant proportion of the cost of production of the consumer industry. Proposed quantum of safeguard duty shall have insignificant impact on the consumers. At the same time, extension of safeguard duty would ensure continued existence of domestic industry and would enable it to adjust itself positively.

(VII) Replies to the issues raised by European Union

- 1. Safeguard measures cannot be imposed in addition to an ineffective anti-dumping measure. If an anti-dumping measure is ineffective due to circumvention or absorption, the same should be reviewed.**

Elaborate written submissions are referred to and relied upon, which adequately addressed the issue. As rightly admitted by the counsel for Korea Kumho, the word “continue” means *persist in an activity or process; remain in existence or operation; remain in a specified position or state; recommence or resume after interruption*. In the context of extension of safeguard duties (or anti dumping duty), the meaning of extension has to be seen as *recommence or resume after interruption*.

- 2. The Indian industry is already protected with ADD on imports from China, Korea and the EU.**

The domestic industry has sought extension of safeguard duty because the existing anti dumping duty has not addressed the injury suffered by the domestic industry. It is well established legal position that the protection under anti dumping law cannot exceed dumping margin. Thus, if injury to the domestic industry is higher than dumping margin and consequently quantum of anti dumping duty, the unaddressed injury can only be addressed through imposition of safeguard duties. This is clearly established by the previous imposition of safeguard duty on this product and on other products such as carbon black and caustic soda. In any case, the way anti dumping and safeguard duty has been applied in India, it is very clear that the domestic industry has not been protected beyond the injury margin.

- 3. The measures under review expired on 29.08.2013 and so for safeguard duty to be imposed, a new measure, following a new investigation is required. However, according to Article 9.2 of the Agreement on Safeguards, this can only occur 2 years after expiry of the measure.**

The present petition is for extension of safeguard duty. The mere fact that safeguard duty has come to an end on 29th Aug. 2013 does not imply that it cannot be extended thereafter. Petition by the domestic industry is for extension of anti dumping duty. It is not for fresh levy of safeguard duty. Therefore, the requirements of cooling period prescribed under article 7.5 or 9.2 are not attracted in a situation where the anti dumping duty is being extended. The mere fact that the anti dumping duty is proposed to be extended after a pause/interruption does not mean it becomes a fresh levy.

- 4. Since measures have been imposed, sales of the domestic industry have only slightly increased and market shares were stable. However, the non-complaining Indian producer benefited from the measure with its market share doubling.**

By their own admission, sales of the domestic industry have only slightly increased and market share remained stable. On facts, in fact, market share of the domestic industry has declined. Further, sales and market share of the domestic industry should have significantly improved with imposition of safeguard duty given significant unutilised capacities with the domestic industry on one hand and sufficient demand for the product on the other hand. Inability of the domestic industry to improve its production beyond the earlier levels and instead a deterioration in production of the domestic industry despite extension of safeguard duty clearly establishes increased injury caused to the domestic industry.

As regards increase in market share of other domestic producers, as established in the written submissions, indeed there is no significant increase in the market share of other domestic producers. There is a mere re-alignment of sales made by Lanxess. Whereas the company had earlier sold the product by importing the product, the company has earlier sold the product subsequently by producing in India. The table below clearly demonstrates. Thus, switching of sales by Lanxess between imports and supply from domestic market cannot be viewed as increase in sales by domestic industry.

Market Share in Demand	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
China	%	12.45	11.51	21.09	12.97
Korea	%	41.00	32.99	28.23	34.12
EU	%	3.92	6.14	5.11	16.61
Other Countries	%	3.01	10.68	5.47	2.01
Import by Lanxess	%	8.23	5.19	1.13	-
NOCIL	%	***	***	***	***

Lanxess India P Ltd	%	-	***	***	***
PMC Rubberchem	%	***	***	***	***
Indian Industry	%	***	***	***	***
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

Note – Supplies made by Lanxess through imports considered as supplies by the domestic industry

It is also relevant to point out that sales of other domestic producers should have materially increased, given that Merchem has set up significant facilities for production of product under consideration.

5. **Article 7.4 of the Agreement states that a measure if extended cannot be more restrictive than it was at the end of the original period. Therefore extending an ineffective measure at an inevitably increased level cannot be justified.**

The request for enhancement of safeguard duty by the domestic industry is based on injury margin in the present period.

(VIII) Replies to the issues raised by M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea + Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.

1. **Authority's failure to publish the initiation notice on 29th August 2013 (the date of initiation) jeopardized trade relations with Korean traders and adversely affected the Govt. of Korea's right under Art X of the GATT 1994.**

Following are relevant

- a. There are a number of different dates relevant in this regard. These are :
- the dates on which investigation was initiated by the Director General i.e. the date on which Director General decided on the file for initiating the investigation,
 - the date on which public notice for initiation was signed by the Director General,
 - the date on which the public notice of initiation was sent to Govt. of India Press for publication,
 - the date on which the initiation was received by the Govt. of India for publication,
 - the date on which Govt. of India Press received the job in registry,
 - the date on which the notification was printed by Govt. of India Press
 - the date on which Govt. of India Press sent the notification for circulation to public at large.

In fact, there may be more activities involved within Govt. of India Press.

The actual date of initiation of the investigation is the date on which Director General signs the notice of initiation and the same is sent to Govt. of India Press for printing and publication. The date on which the notification is printed or the date on which the notification is circulated for publication are entirely immaterial.

- b. The petitioner refers to the decision of Hon'ble Supreme Court in the matter of Union Of India vs Ganesh Das Bhojraj wherein the Hon'ble Supreme Court held as follows:-

Facts: Respondent admittedly imported a consignment of Green Beans (Pulses) weighing 505-505 M.T. vide Invoice No. 14/099, dated 31-12-1986. They have filed bill of entry for the same on 5-2-1987. The importer claimed clearance of the said goods free of duty on the basis of Exemption Notification No. 129/76-Cus., dated 2-8-1976. However, it was pointed out that on 4-2-1987 the said notification was amended vide Notification No. 40/87-Cus., whereby basic duty @ 25% was levied. As the duty was levied @ 25%, importer filed Writ Petition No. 535 of 1987 in the High Court of Bombay contending inter alia that the said notification was not duly published and that it was not in force on the date. A Division Bench of the High Court of Bombay accepting the said contention on the basis of Full Bench decision of the said Court in the case of Apar (P) Ltd. v. Union of India and Others [1985 (22) E.L.T. 644] allowed the writ petition. Hence the present appeal by the State.

Decision: 20. The learned counsel for the respondent, however, submitted that there is nothing on record to establish that Notification dated 4-2-1987 withdrawing full exemption from the levy of customs duty was published on the same day. For this purpose, original copy of the Notification dated 4-2-1987 published in the Extraordinary Gazette on the said date has been produced before us. The Gazette is admissible being official record evidencing public affairs and the Court is required to presume its contents as genuine under Sections 35 and 38 read with Section 81 of the Evidence Act, unless contrary is proved. Hence, there is no substance in the contention that notification dated 4-2-1987 was published in the Gazette on the same day. In our view, said notification came into force on the same date.

21. Lastly, at this stage, we would mention that Parliament has added sub-sections (4) and (5) to Section 25 of the Customs Act by Act No. 21 of 1998 w.e.f. 1-6-1998 which prescribe the method and mode of publication of the Notification and the date on which it comes into force. Newly inserted sub-sections (4) and (5) to Section 25 are as under :-

“(4) Every notification issued under sub-section (1) shall, -

(a) unless otherwise provided, come into force on the date of its issue by the Ceernment for publication in the Official Gazette;

(b) also be published and offered for sale on the date of its issue by the Directorate of Publicity and Public Relations of the Board, New Delhi.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where a notification comes into force on a date later than the date of its issue, the same shall be published and offered for sale by the said Directorate of Publicity and Public Relations on a date on or before the date on which the said notification comes into force."

22. In the result, the appeal is allowed. The impugned judgment and order passed by the High Court is set aside and quashed. The respondent is held liable to pay customs duty @ 25% under Notification No. 40/87-Cus., dated 4-2-1987. There shall be no order as to costs.

It would, thus, be seen that the relevant date for the present purpose is the date of its issue by the Central Government for publication in the Official Gazette. Since it was received by Govt. of India Press on 29th Aug.2013, it should be held that the investigation was initiated on 29.08.2013.

c. The investigation was initiated before the present duties came to an end. The interested parties have selectively referred to the reply received by them under RTI. The letter clearly states as follows.

i) Received Job in Register on dated:

G.No.436 & G.No.437 on dated 29.08.2013. And G.No.438 received on 30.08.2013.

ii) The date of receipt of G.No.436 & 437 is 29.08.2013 and for G.No.438 is 30.08.2013. All are sent to Kitab Mahal on 2.9.2013.

iii) G.No. 436, 437, 438 are sent to publication on 2.9.13 at 12 noon. The Job No.3754, 3756, 3761 GI/13.

iv) It would thus be seen that the Gazette Notification was received by Government of India Press on 29.08.2013. Thus, admittedly the initiation was done on 29.08.2013 and the notification was also issued on 29.08.2013 for publication. The fact that the notification was printed on 2.9.2013 and became available to public at large thereafter is entirely immaterial.

v) It is relevant to point out in this regard that a number of sunset review initiation and final findings are issued by the Designated Authority on Ant dumping on the last day of the time limits. The table below demonstrates cases where initiation was on the date of expiry of duty.

Table: Where date of expiry is the same as date of initiation

Product	Country	Original Expiry date	Date of Initiation
Diclofenac Sodium	China	9-Apr-13	9-Apr-13
Sodium Hydrosulphite	China PR	14-Oct-11	14-Oct-11

The table below demonstrates cases where final findings were on the last date of completion.

Product	Country	Original Expiry date	One Year Extension Granted till	Date of Initiation	Date of Final Findings
Bias Tyres for Bus and Lorries Trucks	China PR, Thailand	8-Oct-11	N/A	3-Aug-11	2-Aug-12
Caustic Soda	Saudi Arabia, Iran, Japan, USA, and France	12-Sep-11	N/A	2-Sep-11	31-Aug-12 (1-Sept-12 was a Saturday)
Partially Oriented Yarn (POY)	China PR	1-Aug-11	N/A	11-Feb-11	10-Feb-12
Peroxosulphates	China PR and Japan	18-Mar-12	N/A	13-Mar-12	12-Mar-13
Viscose Filament Yarn	China PR	23-May-11	N/A	25-Feb-11	24-Feb-12
Caustic Soda	Saudi Arabia, Iran, Japan, USA, and France	12-Sep-11	1-Sep-12	2-Sep-11	31-Aug-12
Partially Oriented Yarn (POY)	China PR	1-Aug-11	10-Feb-12	11-Feb-11	10-Feb-12
Viscose Filament Yarn	China PR	23-May-11	24-Feb-12	25-Feb-11	24-Feb-12

vi) It would, thus, be seen that the anti dumping cases have been initiated before its expiry. Further, final findings have been issued in a large number of cases just before the last date of issuance of final findings. It is obvious that the notification would not have been printed and made available by Govt. of India Press in all these cases before the time limits, particularly when the Government of India Press has confirmed that the time required for printing the notification is significant and the date of circulation of the Gazette copy depend upon the load of the press.

d. While initiation notification in the present case was clearly before the present duty came to an end, it is relevant to point out that, in any case, the rules does not specify that the initiation of investigation must be before expiry of duty. The difference in Anti dumping law and Safeguard law makes it obvious as would be seen from the relevant provisions extracted below.

Section 9A(5), Customs Tariff Act, 1975, which deals with a sunset review in an anti-dumping case, states in relevant part:

*“Provided further that where a **review initiated before the expiry** of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”*

The corresponding section for safeguard duty extension is Section 8B (4), reproduced below.

“4. The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.”

It would, thus, be seen that the anti dumping sunset review should be **initiated before expiry** of anti dumping duty. However, the safeguard duty law does not have any such obligation. Thus, in any case, it cannot be said that the Director General (Safeguards) is obliged to initiate the investigations before expiry of existing safeguard duty.

IX) The initiation notification was dated 29 August 2013 but was officially published only on 2 September 2013 and made available 24 hours later i.e. 3 September 2013.

Initiation of investigations and making the same available to the interested parties are two different actions. There is nothing in the law which says that the initiation notification should be made available to the interested parties on the date of initiation. Rule 6 is relevant in this regard which clearly implies that these activities falls subsequent to initiation of investigations. Further, it would be seen that the only time limit laid down in Rule 6 is the time limit to the interested parties to provide relevant information. However, there is no time limit specified under Rule 6 for the Director General (Safeguards) to inform interested parties about initiation of investigations or for seeking relevant information or for informing the interested parties about the initiation of investigations.

a) Publication and printing are two different aspects as clearly stated in the ‘instructions for printing and distribution of Gazette of India’. The instructions also state that in the case of notifications which are to be published by a particular date, they should be sent giving sufficient time to the Press concerned. The understanding of the Central Government is that a publication completes when the printed gazette is made available to public.

Initiation, printing and publication are three different actions. While initiation has been done before the present duty came to an end, printing and publication of the same has happened after the duties have come to an end. However, the rules merely refer to initiation of investigation and not about printing and publication of initiation. The obligation of initiation cannot be read into obligation for printing and publication of initiation or final findings.

b) The measure is actually an initiation of a fresh investigation which cannot happen within two years of expiry (Art. 7.5).

The petition and the notice of initiation make it evident that the investigation is for extension of present duty and not for levy of fresh duty. Extension of duty cannot be read as fresh levy merely because of interruption in duty.

c) There have been significant capacity additions by other domestic producers and the applicant is facing stiff domestic competition. It no longer has 50% of the capacity to produce the subject good. None of the other producers have supported the petition.

The argument is without any basis. The table below shows market share of various domestic producers. It would be seen that other domestic producer enhancing capacity has also lost market share. As regards support to the petition, since the production of petitioner constitutes a major share in Indian production, the petitioner is entitled to seek protection under the law regardless of whether or not other domestic producers support the petition.

d) “Remain in existence or operation” is the only meaning that can be adopted for interpreting Art. 7.2 since if “recommence or resume after interruption” is adopted, then the prohibition in Art. 7.5 will be meaningless.

The contention is flawed. Article 7.5 clearly comes in play when a product was suffering a safeguard duty and the safeguard duty is proposed to be imposed again after sometime. Imposition of safeguard duty again is different from extension of safeguard duty. This is clearly borne out by Article 7 of the Agreement which clearly differentiates

between extension of existing duty and fresh imposition of anti dumping duty. A review of duty during the period of duty for its extension and application of duty again on the same product are two distinctly different processes. In fact, in the context of extension of duty, the word “extend” has to be interpreted to imply “recommence or resume with or without pause”.

e) Determination of extension has to be made before the previous period is over. In the present case, if the DGS recommends continuation of the measure, the measure will recommence or apply again after a gap. The law does not provide for retrospective levy of safeguard duty and it is only possible where expressly provided. Submissions made before are relied upon. The issue of extension of duty before expiry of existing duty can only be relevant in context of notification by Ministry of Finance. The recommendation made by the Director General (Safeguards) is entirely irrelevant on the issue. Further, the petitioner has not sought retrospective imposition of safeguard duty. The petitioner hereby clearly submits that it has not sought imposition of duty with retrospective effect and the petitioner is seeking extension only with prospective effect. Petitioner is aware that it will not get relief for the intervening period between the date of expiry of previous duty and the date on which fresh duty shall be imposed by the government.

It is also relevant to point out in this regard that the petitioner had in fact filed its application for extension of safeguard duty on 1st Jan., 2013. The Director General (Safeguards) however initiated the investigations only on 29th Aug., 2013.

f) Punjab & Haryana High Court (Tarsem Kumar v. Collector of Central Excise, Chandigarh) and Kerala High Court (Ambali Karthikeyan v. Collector of Customs and Central Excise) held that a decision to extend period of seizure after expiry of original period of seizure of goods was illegal. Section 110(2), Customs Act proviso is pari material to safeguard provision.

The stated decisions are entirely irrelevant to the present case as is clearly established by the context of the two situations. The issue before Punjab and Haryana Court or Kerala High Court was in the context of extension of period of seizure after expiry of original period of seizure of goods, while the issue in the present case is an extension of safeguard duty on imports. The two certainly cannot be equated.

g) Supreme Court (Babu Verghese v. Bar Council of Kerala) held the decision to extend the term of Kerala Bar Council after its term expired was illegal.

The decision of Supreme Court is not applicable to the present case, as the decision of Hon'ble Supreme Court was in the context of extension of the term of Kerala Bar Council. The present situation is entirely different

h) Art XIX of GATT requires the Authority to a) identify the specific obligation including tariff concessions incurred by India concerning the subject product under GATT and b) establish that specific obligation's link with increase of imports of the subject product in India. (Korea – Certain Dairy Products, Argentina – Footwear, US – Lamb, Dominican Republic – Polypropylene Bags and Tubular Fabric) The bound rate for the product for India is 40% and present Customs Duty Rate is 7.5%. Therefore, any increase in import due to reduction of Customs Duty below 40% cannot be attributable to the obligation and tariff concession incurred by India in 1994.

i) The responding party has, in its submissions, stated:

“55. In this context, the DG Safeguards may note that India along with other countries agreed to lower the Customs Duties on imports and provided a fixed rate more than that it will not charge Basic Customs Duty. The maximum rate that is agreed is known as “Bound Rate” and that is the rate for which only India has incurred an obligation. Any further reduction in Customs Duties below that Bound Rate is not in terms of any obligation incurred by India. The Bound Rate is 40% and present Customs Duty Rate on import of the subject goods is 10% as per Customs Tariff of India 2013-14. Therefore, any increase in import due to reduction of Customs Duty below 40% cannot be attributable to the obligation and tariff concession incurred by India in 1994.”

ii) However, this is not the interpretation taken by the Appellate Body in *Korea – Dairy*, a case cited by the responding party. In *Korea – Dairy*, the Appellate Body found that the phrase “of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions” simply meant ‘that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions’.

In *Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric*, another case relied on by the responding party, the Panel held:

“[A]s a matter of fact the importing Member must have incurred obligations under the GATT 1994, for example, tariff concessions, with respect to the product in question. It then falls to the importing Member to identify those obligations incurred under the GATT 1994 that are linked with the increase in imports causing serious injury to its domestic industry.”

iii) The Panel held that since the Dominican Republic granted a tariff concession of 40% ad valorem on the product, it had incurred an obligation with respect of the product under the GATT 1994. However, the **Dominican Republic had not identified these obligations** (or other obligations under GATT 1994) ‘as obligations linked with the increase in imports said to have caused serious injury to its domestic industry’ **in its report**. Since it found that the report of the authority did not contain any findings or reasoned conclusions with respect to how the Dominican Republic incurred obligations which lead to increased imports causing serious injury, the Panel did not further

examine the issue. Therefore, the Panel did not take the view taken by the responding party when it stated “any increase in import due to reduction of Customs Duty below 40% cannot be attributable to the obligation and tariff concession incurred by India in 1994”.

i) **The domestic industry in the public hearing admitted that tariff reduction was not an unforeseen development and the special relationship between KPC and Sinorgchem was an unforeseen development. WTO Panels have never interpreted unforeseen developments in such a manner. Developments should have been unforeseen by negotiators at the time of granting relevant concessions. (Argentina – Preserved Peaches, Korea – Certain Dairy Products, Argentina – Footwear, Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric)**

a) The requirements of Article XIX:1(a), GATT 1994 have been incorrectly understood by the interested parties. The provision is extracted below:-

“If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that Member in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the Member shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.” (Emphasis added.)

b) It would be seen that there are two conditions for imposition of safeguard measures. These are (a) existence of unforeseen developments and (b) Government of India incurring obligations, including tariff concessions. In *Dominican Republic - Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric* (a case relied on by the responding party), the Panel looked at these two requirements separately. In the present case, the requirement of tariff concession is clearly met, as Government of India has reduced customs duties on the product under consideration. Further, such reduction in customs duties is not only on the product under consideration, but also on the raw materials.

c) It would, thus, be seen that the reduction in tariff and unforeseen developments are not interchangeable requirements. These are two distinctly different requirements. Mere fulfillment of one is insufficient. Thus, the mere fact that Govt. of India has reduced customs duties is insufficient to invoke safeguard measures. Similarly, had the Govt. of India not undertaken tariff reduction or such other measure as committed before, mere existence of unforeseen development would have been insufficient to invoke the safeguard measures. The interested party seems to have interchangeably read the two requirements. It is in this context that the petitioner made a statement at the time of oral hearing that tariff reduction by the Govt. of India was not the unforeseen development relied upon by the domestic industry. A reduction in tariff can only be an ‘obligation incurred’.

d) Petitioner has not referred to tariff reduction for the reason that the product is already suffering safeguard duties and the issue has already been considered by the Government of India. The Govt. of India would not have imposed safeguard duties earlier without satisfying itself that the requirement under WTO was met. Neither Govt. of Korea nor any other country has raised any concern before WTO in this regard. Thus, it is well known to all parties that the safeguard measures in the present case were invoked only after satisfying with the requirements with regard to obligations of Govt. of India which were met. The present case being only a case of review, the obligation was not required to be stated again by the petitioner.

e) In the present case, the responding party in its submissions has stated that the special relationship between KPC and Sinorgchem cannot constitute an unforeseen development, as neither the WTO Panel nor the Appellate Body has considered such an event as an unforeseen development (page 20, paragraph 48 of the KPC submissions). However, it may be noted that none of the WTO decisions quoted by the responding party lay down a limitation on the **nature of event** that may constitute an unforeseen development.

f) The Appellate Body in *Argentina – Footwear (EC case)* held that the phrase unforeseen developments means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’.

g) The Appellate Body in *Korea-Dairy case* held that unforeseen developments are **developments not foreseen or expected when member incurred that obligation**. The Appellate Body in *Argentina — Footwear (EC)* noted a GATT Panel Report, which confirmed that the **development must have been unforeseen at the time of the tariff negotiation**:

“In addition, we note that our reading of the clause — ‘as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ...’ — in Article XIX:1(a) is also consistent with the one GATT 1947 case that involved Article XIX, the so-called ‘Hatters’ Fur’ case. Members of the Working Party in that case, in 1951, stated:

... ‘unforeseen developments’ should be interpreted to mean developments occurring after the negotiation of the relevant tariff concession which it would not be reasonable to expect that the negotiators of the country making the concession could and should have foreseen at the time when the concession was negotiated.”

‘Unforeseen Developments’ and ‘Obligation Incurred’ in the Present Case:

h) The unforeseen developments giving rise to increased imports causing serious injury in this case, as mentioned in the petition and elsewhere in these submissions, are the surplus capacities with global producers, the special arrangement between KPC and Sinorgchem and the significant expansion of capacities by KPC.

These developments could not have been foreseen by the negotiators when setting down India's obligations with respect to the product under consideration. The 'obligation incurred' in the present case is the tariff concession granted by India with respect to the product.

j) In India's complaint against Turkey in Turkey – Cotton Yarn, India stated Turkey's extension of safeguard measure on 28th January 2012 after expiry of measure on 14th July 2011 inconsistent with Art. 7.5. Turkey agreed to withdraw. India's state practice must be followed domestically also.

Written submissions are relied upon which deals with the issue. The facts of the Turkey case are entirely different. The Govt. in the present case has not imposed an interim duty upon expiry of existing duty, nor the petitioner has sought retrospective imposition of anti dumping duty. In any case, the issue was never decided by WTO.

k) In its adjustment plan in the application (and written submissions) for the original investigation, NOCIL stated that the Dahej plant was intended to produce PX-13 as one of its products, and commence commercial production in FY 2012-13. This was noted by the DG in its Final Findings. However, in the present application, NOCIL has stated that it intends to produce 10,000MT of intermediaries used for the production of PX-13 at Dahej. The applicant in present application claimed that they had stated in their application for original investigation that the Dahej plant was for 'intermediaries used for production of PX-13'.

The petitioner has undertaken adjustment plan as stated in the previous petition leading to imposition of safeguard duty. Submissions made before are relied upon. The petitioner commenced trial production in Nov., 2012 and commercial production in March 2013.

l) It is not clarified whether the operation of the Dahej plant will increase the capacity of production of PX-13, noted as 8500 MT in the Initiation Notice.

It is clarified that the operation of the Dahej plant will increase the capacity of petitioner for PX-13 to 14,000 MT.

Adequate information has been provided to the Director General (Safeguards) in this regard.

m) Authorisation letter was dated 23rd August 2013 but date of filing application is 31st July 2013 in initiation notification.

The petition was filed on 31st July. Letter from NOCIL requesting Director General (Safeguards) to undertake review and extension of safeguard duty is dated 26th July, 2013. However, NOCIL did not authorise TPM to represent them in this letter. Therefore, the Director General (Safeguards) demanded a specific authorisation from NOCIL, which was signed on 23rd Aug. A copy of this authorisation has also been enclosed with the non confidential version of the petition.

n) There are major differences in the adjustment plan in the Final Findings of the original investigation and relied upon in the petition.

There is no difference in the adjustment plan informed to the Director General (Safeguards) at the time of original investigation and informed to the Director General (Safeguards) now.

o) Not realizing the full benefit of the adjustment plan is no excuse for the extension of safeguard duty. (In PAN Review duty was not extended since the domestic industry had failed to provide evidence that they had taken positive steps.)

Reference to PAN review case is entirely irrelevant, as the Director General held in that case that the domestic industry has not taken positive steps. The relevant part of the order is reproduced below.

"The applicants were categorically asked to submit detailed evidence of the positive adjustment steps undertaken by them since the imposition of safeguard duty on the subject product with effect from 17th Jan, 2012, prior to initiation of this investigation. However, the consultants, vide their reply dated 26th Sep, 2012, merely furnished the details of the adjustment plans proposed by the Domestic Industry in near future. Meanwhile, during onsite verification of the three units of the domestic industry, conducted as per orders by the competent authority, the domestic industry were especially asked to furnish documentary evidence of positive adjustment steps undertaken by the unit as per the provisions of Rule 18(1)(i) of Safeguard Duty Rules, 1997. However, none of the units verified, furnished any such evidence. Initiation of safeguard investigations were ordered ruling that the question of adjustment plan will be considered at the time of passing the review order.

Now, since the question of submitting evidence of positive adjustment plan is of vital importance in this case, In fact, the written submissions post PH by the domestic industry talk of "Some steps have already been taken" without adducing any evidence as to what specific steps they have already undertaken. Further, the domestic industry has not been able to control/contain their cost of sales as a first step towards making themselves competitive. The cost of sales(indexed) has continuously risen from 100 per MT in 2009-10 to 110 per MT in 2010-11, to 148 per MT in 2011-12 and further to 172 per MT in 2012-13. Therefore, the domestic industry seem to have failed in this very important aspect towards making themselves competitive. The consultant for domestic industry have themselves emphasized in their written submissions post PH that as per Section 8B(4) of CTA, 1975 there are only two conditions which need to be fulfilled while extending the period of imposition of safeguard duty – (a) Adjustment Plan (b) It is necessary to extend safeguard duty. According to them, there are no other requirements prescribed in

the law for extension of period of imposition of safeguard duty. This submission makes the question of producing evidence of positive adjustment all the more important, which the domestic industry have failed to comply."

i) It would be seen that the Director General found in that case that the domestic industry has not taken positive steps to adjust itself. In the present case, however, the domestic industry has taken positive steps to adjust itself. The petitioner has already commenced commercial production at the new plant and the capacity is remaining largely unutilized for want of orders from the customers.

p) The applicant is an inefficient producer and the causes of injury are intrinsic. After safeguard duty was imposed, the price at which PX-13 was available to the user industry increased by 30% but the applicant was unable to increase its selling price or sales volume, and kept losing its export market.

i) There is no basis for the argument that the price of imported products to users increased by 30% or the petitioner is an inefficient producer. Further, even after charging anti dumping duty and safeguard duty, the landed price of imports remained lower than selling price of the domestic industry. It is seen in this regard that whereas cost of production increased by Rs. *** per kg due to increase in the input prices, the import price declined by about Rs. *** per kg.

The table below shows increases in major input prices over the period.

SN	Raw Material	Unit	Actual Consumption per unit of Production			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	ANILINE	Rs/Kg	100	119	132	164
2	PNCB	Rs/Kg	100	112	114	119
3	XYLENE	Rs/Kg	100	115	136	182
4	M I B K	Rs/Kg	100	121	147	156

The table below shows increases in the cost of PX-13 on account of the above inputs.

Unit in Rs/Kg

SN	Particular	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	Raw Material Cost	100	104	115	129
	Increase compared to previous year		4	11	14
	Increase compared to base year				29
2	Other Conversion Cost	100	101	112	111
	Increase compared to previous year		1	11	(1)
	Increase compared to base year				11
3	Cost of Sales	100	103	114	121
	Increase compared to previous year		3	11	7
	Increase compared to base year				21
4	Selling Price	100	101	103	98
	Increase compared to previous year		1	2	(5)
	Increase compared to base year				(2)
5	Import Assessable Price	160.53	159.67	163.2	157.72
	Increase compared to previous year		-0.86	3.53	-5.48
	Increase compared to base year				-2.81

ii) It would, thus, be seen that whereas raw material cost increased by Rs.*** per kg, the import price declined by Rs. *** per Kg. Further, if import price is considered in terms of US\$, it would be seen that the import price in fact declined. Thus, whereas the input costs were rising globally, the subject exporters effectively reduced their prices for exports to India.

Table of import price in US\$

SN	Particular	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	Import Assessable Price (US\$/Kg)	3.32	3.46	3.39	2.88
	Increase compared to previous year		0.13	-0.07	-0.51

	<i>Increase compared to base year</i>				-0.44
2	Raw Material Cost	100	109	115	114
	<i>Increase compared to previous year</i>		9	7	(2)
	<i>Increase compared to base year</i>				14

iii) Further, comparison of landed price of imports with selling price of the domestic industry after including anti dumping duty and safeguard duty shows that the landed price of imports remained significantly below the selling price of the domestic industry.

SN	Particular	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	Selling Price (Indexed)	100	101	103	98
2	Landed Price of Imports including ADD/Safeguard duty (Rs/Kg)	184.18	165.94	224.74	212.59

q) Unjustified increase in the cost of production was due to excess capacity to produce 4ADPA since in FY 2012-13 the applicant incurred cost on plants having the capacity to produce 18,500 MT of 4ADPA whereas capacity to produce PX-13 (8,500 MT) was not changed at all.

There is no increase in the cost of production on account of any expense incurred in the 4ADPA plant. In fact, the expense considered by the petitioner does not include any expense incurred at Dahej plant. The petitioner maintains separate record of expense incurred at Dahej and Thane plants. The profit/loss and cost of production determined for the product under consideration is based on expense incurred at Thane plant only. No expenditure incurred at Dahej plant has been included in the information provided. Petitioner is separately providing a certificate from the Cost Accountant in this regard which clearly shows that the petitioner follows accounting practice wherein the expense are booked to respective locations and the expenses incurred at Dahej have not been included in the expenses incurred in Thane.

(r) When imports increased, sales increased and vice versa. Market share of the applicant was taken up by other Indian producers and not imports. (Where other producers share increased by 73 basis points, applicant's decreased by 24 basis points.)

(i) The table below shows sales of the domestic industry, demand and imports into India. It would be seen that the increase in the sales of the domestic industry is far lower than the increase in demand and increase in imports. This is despite the fact that safeguard duty was imposed on 29th August, 2011 and therefore petitioner expected significant increase in sales and significant decline in imports with imposition of safeguard duty.

Particular	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Demand	14,705	15,949	15,954	17,753
Imports	10,090	10,607	9,735	11,664
Sales of NOCIL (Indexed)	100	105	104	105
Increase as compared to 2009-10				
Demand		1,244	5	1,799
Imports		517	-872	1,929
Sales of NOCIL		5	-2	2

(ii) As regards increase in sales and market share of other domestic producers, as the table below clearly demonstrates, other domestic producers have also lost market share. It is only re-alignment between production and imports by Lanxess from its affiliates that its production and market share shows an increase. In fact, since Lanxess has switched between production and imports from its own affiliates during the period of shifting its plant from one location to other location in India, the entire situation should be seen after excluding imports made by Lanxess and treating the same as supplies by domestic competitor, as shown in the table hereinabove.

It would be seen that in fact there is a significant increase in imports and all domestic producers lost market share.

(s) Other domestic producers are offering the subject goods at lower prices than the applicant. (Egypt – Steel Rebar from Turkey; US – Hot Rolled Steel Products from Japan)

The argument is without any factual basis. In fact, landed price of import is materially below the domestic price. Thus, if the safeguard duty is not extended, none of the domestic producer would be able to compete with imports and would suffer aggravated injury.

(t) 50% or more of imports are used to manufacture goods that are exported. These are exempted from ADD, SGD, Basic Customs Duty and CVD equal to central excise duties. Landed value of that portion is lower than NIP.

By their own admission, almost 50% of the imports are on duty paid basis which clearly shows that the imports have not been made because of duty exemption scheme of the Govt. of India. Further, if 50% of the imports have been made on payment of anti dumping duty and safeguard duty, if safeguard duty is not extended further, the landed price of import shall decline substantially which shall imply that the domestic industry should either reduce its prices or face further loss of volumes. If the domestic industry does not reduce the prices, nothing prevents the consumers from further meeting their requirements from imports, given significant difference between the domestic and imported product price and significant un-utilized capacities with the foreign producers. In fact, even two of the largest producer of the product, Korea Kumho and Sinorgchem individually are capable of meeting entire Indian demand.

(u) Safeguard duty cannot be enhanced in review since Rule 17 of Safeguard Rules provides that if duty is applied for more than one year, it should be progressively liberalized.

Submissions made before are relied upon. The previous duty was not imposed to the extent of injury margin and the petitioner has sought duty upto the injury margin.

(v) Quantitative restrictions cannot be applied in review since Rule 18 allows the DG to either recommend continued imposition of the duty or withdrawal of the same in a review. Quantitative restrictions would be more restrictive than the measure in the original investigation.

Imposition of quantitative restriction and safeguard duties are two different reliefs provided under Agreement on Safeguards. The two can be imposed at the same time or one after. The fact that safeguard duty is already imposed on the product does not mean quantitative restrictions cannot be imposed. If the two measures can be imposed at the same time, these can certainly be imposed one after other. The petitioner request the Director General (Safeguards) to conclude that imports have surged despite existing duties and there is a need for imposition of quantitative restrictions. The request for imposition of quantitative restriction may thereafter be transmitted to the Authority on Quantitative Restriction.

(IX) Reply to issues by Kumho Petrochemicals

(a) Completion of investigations before expiry of duty

(i) The issue has been adequately addressed by us in the previous submissions. Further to our previous submissions wherein we reported that (i) the Director General (Safeguards) decision in soda ash case is binding on the present case. The fact that the final findings in that case were issued before last date is entirely immaterial in deciding the issue raised by these interested parties, (ii) the anti dumping duties have been extended in a number of cases after six years of the date of initial imposition. We are enclosing a statement showing all various relevant dates in these cases (we had earlier given only few dates in these cases. We are however now giving all other dates as well in order to establish that the anti dumping duties have been extended in these cases after expiry of six years).

(ii) With regard to the **Turkey case** referred by the interested parties, petitioner submits that the facts relating to this case were extremely different than the facts of the present case. The table below shows some pertinent difference between the two cases (petitioner has made these submissions in their post hearing written submissions).

Turkish case	Indian case
The authorities applied interim duties. The Govt. of India contended that interim duties cannot be applied in a review case.	no interim duties have been recommended by the Director General in this case or such other cases
The Turkish authorities extended safeguard duty retroactively	In the soda ash case done by India where the safeguard duties were extended after expiry, the same were applied only prospectively.
The Government of India contended that the duties were recommended without adhering to the requirements of Article 2, 3, 4, and 5.	The Director General has complied and shall comply with all such requirements.
The Govt. of India contended that the duty was extended after the initial duty expired with retrospective effect from the date of its expiry.	The duty will be extended after the previous duties have expired and the same will be effective with effect from the date of notification by the Central Government. India is not extending such duties retroactively

(iii) It would be seen that the entire submission of the interested parties in this regard is grossly misplaced. Above all, when the Govt. of India is extending anti dumping duties routinely after expiry of extended duties, petitioner fails to understand why this issue should be relevant in the present case. There can be no difference between anti dumping and safeguard law in this regard.

We are enclosing a writ petition filed before Delhi High Court in connection with anti dumping matter. The exporter involved is the same as has been involved in the present matter. It would be seen that they have now raised the same issue with regard to anti dumping duty extension. This clearly establishes that such interested parties consider the legal provisions under anti dumping and safeguards as “similar”, but contended before the Director General (Safeguards) that the provisions/situations were “different”. Further, this further shows comparability of the issue between anti dumping and safeguards.

(b) Opportunities given to petitioners for further submissions after hearing

The Director General (Safeguards) has given opportunities to the domestic industry to provide relevant information after conducting the hearing and the same is in violation of principles of natural justice. There is absolutely no basis for such an argument in an investigation such as safeguard investigation or anti dumping investigation. In fact, the Director General (Safeguards) has directed the domestic industry to clarify the issue only because of the argument raised by the interested parties. It is important to note in this regard that the entire submissions of the domestic industry now made was directed in establishing correctness of the submissions earlier made by the domestic industry with regard to capacity of the plant. The domestic industry had earlier contended that it has a capacity of 14000 MT. The contention of the petitioner was contested by interested parties and therefore the Director General rightly decided to direct the domestic industry to establish the correctness of the contention made by the domestic industry. The domestic industry has not brought new facts on records. The domestic industry has merely provided evidence/justification/argument in support of its earlier contention that the capacity of the company for the product under consideration is 14,000 MT.

(c) Adjustment plan informed to the Director General at the time of original investigation was different

The adjustment plan now given by the domestic industry is different from the adjustment plan that the domestic industry had earlier informed the Director General (Safeguards) at the time of original investigation. Petitioner submits that there is no truth in this contention. It is totally misleading statement. The Director General stated as follows in previous final findings

278. The restructuring plan submitted by the DI focuses on capacity expansion to cater the growing demand and cost reduction.

279. *The petitioner has submitted that they are expanding the capacity of production to face fair competition from imports. The expanded capacity of DI along with the capacity of other Indian producers will be enough to meet the growing demand of the product along with imports. The applicant DI is expanding capacity by ***MT at a cost of Rs. ***Crores An amount of Rs. ***Crore has been committed as on 30.04.2011. Out of the said amount Rs. ***Crore has already been spent. The expansion work is likely to be submitted in March 2012 and production is likely to be started from April 2012.*

280. *The applicant has claimed that the expansion would result in minimum cost saving of Rs. ***/Kg. Further the DI is hopeful of cost reduction on account of overhead cost once it is able to sell more in the market.*

281. *The details of the restructuring plan were called. It is seen that the **claim of DI is well supported by Chartered Engineer Certificate on expansion** and expenditure for new plant and practicing Cost Accountant Certificate on the cost incurred and the claim of cost reduction. It is noted that the Adjustment plan of company is reasonable and feasible.*

282. *The adjustment plan has been taken into account for gradual liberalisation of duties.*

The petitioner has carried out a very same adjustment plan as was informed to the Director General (Safeguards). It is relevant to point out in this regard that the adjustment plan envisaged an investment on about Rs.250 crores in these facilities. This investment is too significant in the overall operations of the company and there is absolutely no way the company could have planned something different earlier and done something different now.

(d) Capacity vs. capability

KPC has now contended that it is not clear whether the applicant is able to (i.e., capable) produce sufficient quantities of 4ADPA to allow it to produce 14000 MT of subject goods and there is no indication of actual ability to manufacture 14000 MT product under consideration. Petitioner submits that capacity and capability are two different parameters. The issue disputed by the interested parties was with regard to capacity of the plant. The issue was never with regard to actual production of 14000 MT by the petitioner. When the petitioner has not been able to produce and supply material even to the extent of old capacities, question of having achieved 14000 MT production of PX-13 or having produced full volumes of 4ADPA does not arise. Petitioner can produce only to the extent it can sell. Further, petitioners will produce 4ADPA only to the extent it can produce and sell PX-13. Petitioner cannot produce and store the material to such a large extent. The fact is that the import of the product continues in large volume to such an extent that the petitioner was never able to produce to the extent it could have produced.

Notwithstanding, the fact that petitioner was earlier producing PX-13 by taking 160 minutes per cycle and the fact that the petitioner is now producing PX-13 by taking 90 minutes per cycle is clearly established by the copies of log sheet earlier provided by the petitioner. Thus, the petitioner has established its capability to produce PX-13 to the extent of 14,000 MT by establishing that its alkylolation cycle time is now 90 minutes whereas it was earlier 160 minutes. Such being the case, it is established that petitioner will be able to produce 14000 MT of the product if it is able to sell the same.

(e) Steps for adjustment plan taken during the period of safeguard duty

KPC has contended that the applicant should have taken steps (towards positive adjustments) during the period of safeguard duty and any steps taken thereafter are irrelevant. Following are relevant in this regard.

(i) First and foremost, there is no legal basis for the argument. The rule nowhere states that the petitioner should have taken steps during the period of safeguard duty. On the contrary, the WTO Panel in Korea- Dairy case has rejected the view that Article 5.1 of the Agreement on Safeguards imposes obligation to consider the adjustment plan. The panel stated as follows –

“..... We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the authorities ... The Panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply. Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a safeguard measure, would be strong evidence that the authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.....”

(ii) Thus, the only requirement under the Rules is that where the period of safeguard duty is more than a year, the Director General (Safeguards) shall recommend progressive liberalization adequate of the safeguard duty to facilitate positive adjustment.

(iii) Secondly, the petitioner stated that it is taking steps to expand the capacities of the product under consideration for which the petitioner was to set up another plant for changing its raw material from 4 NDPA to 4ADPA. The 4ADPA plant was to be set up in Dahej. The petitioner has taken all these steps till the expiry of duty on 29.08.2013. In fact, petitioner commenced trial production in Dec., 2012 and commercial production in March, 2013 which clearly establishes that the petitioner has taken steps during the period of safeguard duty.

(X) Reply to issues by ATMA

(a) Petitioner has not enhanced capacity

Submissions made before are relied upon. The evidence that the alkylation cycle time has been reduced to 90 minutes from 160 minutes in itself establishes that the petitioner has enhanced the capacity. Whereas the petitioner was earlier taking about 160 minutes in alkylation using 4NDPA as a raw material, the petitioner is now taking 90 minutes in alkylation using 4ADPA as the raw material. Thus, capacity of the petitioner has enhanced from 8500 MT to 14000 MT.

(b) Decline in export volumes has led to decline in production.

i) The issue addressed by the domestic industry in the letters under reference concerned enhanced capacity by the domestic industry. The domestic industry has not addressed any other issue in these letters. Further, the issue of decline in exports has already been addressed by the domestic industry.

(ii) Extension of anti dumping duty after five years may be addressed by the extension provision under Section 9A(5), extension of anti dumping duty after six years is an issue identical to the issue raised by the interested parties in the present case. It would be seen that the view of the Govt. of India is clearly that the duties can be extended after six years. Such being the case on anti dumping side, petitioner hopes that the situation cannot be different on safeguard side.

(iii) With regard to capacity of PX-13 with the DI, DI submitted a letter from an independent Chartered Engineer certifying that the capacity of the company was earlier 8500 MT and the same at present is 14000 MT per annum. The certificate deals in detail how the capacity has been determined and where the capacity is bottlenecked in the plant. The Chartered Engineer has also certified the present alkylation time involved in the process.

(c) With regard to the **Turkey case** referred by the interested parties, petitioner submits that the facts relating to this case were extremely different than the facts of the present case. The table below shows some pertinent difference between the two cases (petitioner has made these submissions in their post hearing written submissions).

Turkish case	Indian case
The authorities applied interim duties. The Govt. of India contended that interim duties cannot be applied in a review case.	no interim duties have been recommended by the Director General in this case or such other cases
The Turkish authorities extended safeguard duty retroactively	In the soda ash case done by India where the safeguard duties were extended after expiry, the same were applied only prospectively.
The Government of India contended that the duties were recommended without adhering to the requirements of Article 2, 3, 4, and 5.	The Director General has complied and shall comply with all such requirements.
The Govt. of India contended that the duty was extended after the initial duty expired with retrospective effect from the date of its expiry.	The duty will be extended after the previous duties have expired and the same will be effective with effect from the date of notification by the Central Government. India is not extending such duties retroactively

(d) It would be seen that the entire submission of the interested parties in this regard is grossly misplaced. Above all, when the Govt. of India is extending anti dumping duties routinely after expiry of extended duties, petitioner fails to understand why this issue should be relevant in the present case. There can be no difference between anti dumping and safeguard law in this regard.

23. Findings of the DG:

24. I have carefully gone through the case records of this review proceedings and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting government. Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for continued imposition of safeguard duty on the import of product under consideration has been examined with reference to the domestic law as well as international law. The findings have been given accordingly.

24.1 Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

24.2 The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in terms of law.

24.3 The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at appropriate places below. The investigation has been conducted in accordance with the said Rules and the Final Findings are recorded through this notification.

25. Brief History: An investigation was initiated by the Director General (Safeguards) earlier on the application filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s NOCIL Ltd, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of PX-13 into India alleging that increased imports of PX 13 were causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of PX 13 in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 of Safeguard Rules ibid were met, safeguard investigation against imports of PX 13 was initiated vide notice of initiation dated 27th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.

25.1 After investigation in the case, Director General (Safeguards) issued Final Findings in the case on 6th June, 2011 which were accepted by the Standing Board on Safeguards and consequently Safeguard duty for two years was levied vide Notification No 83/2011-Cus(SG) dated 30 Aug 2011. The safeguard duty is in force till 29th Aug, 2013. The instant application has been filed by the domestic industry for continuation/extension of safeguard duty for a further period of two years from the date of expiry of existing duty, with the purpose to enable the domestic industry to improve its competitiveness in order to survive. The review safeguard investigation for continued imposition of safeguard duty under provisions of Section 8B(4) of Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 16 and Rule 18 of Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty)Rules, 1997was Initiated on 29th August, 2013.

26. Domestic Industry: M/s NOCIL Ltd, Navi Mumbai is a domestic industry in India who manufacture rubber chemicals i.e. PX-13 or 6PPD. the applicant producer constituted a major share of 61.60% of the total production of PX-13 in India. Further no claim has been made by the interested parties against the applicants being the domestic industry. Therefore, it is held that the applicant domestic producer constitute and represent the domestic industry (DI) within the meaning of required and defined under Sec 8B(6)(b)(iii) of the Safeguard Duty Rules 1997.

27. The product under investigation: The product under consideration is rubber chemical called PX-13 or 6 PPD, falling under heading 3812,3810 as well as under 2921,2925,2934 and 2942 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act 1975 under section 8B of the Customs Tariff Act and Rule 18 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. It is a produced by hydrogenation of a mixture of 4-nitrodiphenylamine (4NDPA) and methyl isobutyl ketone (MIBK) in an autoclave at moderately high pressure in the presence of a noble metal catalyst. The resulting reaction mass, which contains un-reacted ketone, by-products, etc., is filtered to remove the catalyst, which is then recycled. The filtrate is distilled to remove low boilers and is then flaked to give the finished product. The low boilers are redistilled to recover the un-reacted ketone. Catalyst is recycled until the activity is reduced. It is then removed from the system. PX-13 is extensively used in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, and Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber based compounds used for manufacture of various rubber products. The main raw materials of PX-13 are a) 4-nitrodiphenylamine (4NDPA) b) Methyl isobutyl ketone (MIBK) c) Catalyst and d) Hydrogen. No interested party raised any issue with regard to the product under investigation. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is rubber chemical called PX-13 or 6 PPD, falling under heading 3812,3810 as well as under 2921,2925,2934 and 2942 (at six digit levels) of the schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. Further, no differences in the production process, characteristics or end-uses between imported PX-13 and domestically produced PX-13 were raised by any of the interested parties during the course of this investigation. Therefore, it is also held that domestically produced PX-13 falls under the ambit of like or directly competitive in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced PX-13 is a like article to the imported PX-13 within the meaning of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules, 1997.

28. The application dated 31/7/2013 has been filed by M/s NOCIL Ltd, Pawne Village, Navi Mumbai for continuation/extension of Safeguard Duty on imports of Rubber Chemicals N-1, 3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine also known as PX-13 or 6-PPD.

29. Period of Investigation (POI): The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Art. XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury. In the notice of initiation, import data from 2009-10 to 2012-13 had been considered. The period of investigation has, therefore, been taken from 2009-10 to 2012-13. Further, a reasonably longer period has been considered to even out the effect of temporary fluctuations and seasonal effects, if any.

30. Source of data: The import data for the period from 2009-10 to 2012-13 has been taken from IBIS, as furnished by the applicant. The data on various economic parameters submitted by the domestic industry in their petition March 2013 has been verified by this directorate to the extent possible and the verified data has been taken into consideration for injury analysis. The data from 2009-10 to 2012-2013 has been compiled and taken from the copies of the ERIs of the applicant unit furnished by the consultant to the Directorate.

Continued imposition of safeguard duty under Review :

31. I find that several interested parties have contended that the review proceedings for continued imposition of safeguard duty must be completed before the expiry of the said safeguard duty itself, in tune with the provisions of Rule 18 of the Safeguard Duty Rules' 1997; as against the arguments of the domestic industry that such requirement is not explicitly or otherwise exist under the said provision.

31.1 In view of the above, the relevant legal position/requirements related to review is being extracted below:

82. Section 8B(4) of Custom Tariff Act, 1975

"The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition"

83. Section 8B(4) prescribes following two conditions which need to be fulfilled while extending the period of imposition of safeguard duty

- a. Measures taken by the DI to adjust itself ;
- b. It is necessary that the safeguard duty should continue, to extend the safeguard duty.

31.2 Further, Rule 18 of Safeguard Duty Rules under the Customs Tariff Act, 1975 states as follows

18. Review

1. *The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that,*
 - i. *safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;*
 - ii. *there is no justification for the continued imposition of such duty; recommend to the central Government for its withdrawal:*

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the midterm of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalization of duty.

2. *Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.*

*3. The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall **mutatis mutandis** apply in the case of review.*

32. The DI in their post-hearing written submissions have contended that since Rule 18 prescribes applicability of rules 5, 6, 7 and 11 on *mutatis mutandis* basis, it is important to understand the meaning of *mutatis mutandis* in this regard. They have cited the case of Hon'ble Supreme Court in the matter of *Ashok Service center and Ors v State of Orissa* whereby they claim that in the instant case, although Rule 18 provides for applicability of certain provisions; but the use of the expression *mutatis mutandis* clearly establishes that such provisions need to be made applicable keeping in mind the express provision made in the Act i.e., Section 8B(4) of the Custom Tariff Act. They have also contended that a measure may be extended **only if** it is found, through a new investigation, that its continuation is necessary to prevent or remedy serious injury, and **only if** evidence shows that the industry is adjusting. Increased import is also not a pre-requisite for extension of safeguard duty investigation.

33. The matter has been examined, accordingly, I am of the view that in order to fulfill the requirements of law, a determination of existence of serious injury or threat of serious injury is imperative. The analysis for determining the injury to the DI constitutes one of the important factors for determining whether the existing safeguard duty may be continued or otherwise during this review safeguard investigation. Secondly, evidence regarding positive adjustments

made by the DI has to be tangible in nature. A close study of the provision reveals that the incumbent domestic industry has to produce evidence of adjusting positively to enable him/her to recommend for the continued imposition of duty. Further, Rule 16(1) of Safeguard Duty Rules *ibid*, states that the duty levied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment. This means that the domestic industry has to commence positive adjustment in line with availment of protection through safeguard duty. Lastly, whether this determination is in sync with the past cases and/or consistent with the position of India at the WTO level under International Law/AoS.

34. Whether Serious Injury or Threat of Serious Injury due to Increased imports:

I find that the period 2011-12 and 2012-13 are the period when the safeguard duty was in vogue. However, the injury analysis for the product under consideration during the POI is as follow:

35. Increased Imports (absolute and relative terms): PX-13 or 6PPD is imported into India from a number of countries, and primarily from the Republic of Korea. The quantum of imports of PX-13 during 2009-10 to 2012-13 remained as under :

Financial Year	Total Imports (MT)	Domestic Production (MT)	Import in relation to Production %
2009-10	10090	7264	139
2010-11	10607	6672	159
2011-12	9735	5408	180
2012-13	11664	4732	246

It appears that Imports have increased to 11664 MT in 2012-13 from 9735MT in the preceding year 2011-12 as well as from the base year, i.e., 10090 MT in 2009-10 in absolute terms. Imports have also surged sharply in relation to Production, by about 66% in 2012-13 over 2011-12 as well as surged by about 107 % from the base year. Therefore, it is clear that the imports have surged during the period of safeguard duty applicable on the PUC.

36. Injury Analysis: The details of performance of the DI is shown below in the table, as follow:

Rubber Chemicals N-1, 3-dimethyl butyl - N'Phenylenediamine also known as PX-13 or 6-PPD				
Financial Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Total Import (MT)	10090	10607	9735	11664
Trend	100	105	96	116
Production of DI(MT)	7264	6672	5408	4732
Trend	100	92	74	65
Import in relation to Production(%)	139	159	180	246
Import in relation to Demand(%)	69	67	61	66
Production of others(MT)	1100	1645	2578	2388
Trend	100	150	234	217
Export (MT)	3656	2768	2079	1359
Trend	100	76	57	37
Sale of DI(MT)	3516	3697	3641	3701
Trend	100	105	104	105
Sale of others(MT)	1100	1645	2578	2388
Total consumption (MT)	14706	15949	15954	17753
Market Share of DI(%)	24	23	23	21
Market Share of Import(%)	69	67	61	66
Installed Capacity (MT)	8500	8500	8500	8500
Capacity utilisation (%)	87	79	64	56
Employment (Nos)	18	18	18	16
Productivity Per Day (MT)	21	19	15	14

INVENTORY (MT)	328	532	257	238
Profit/Loss (Rs. In Lacs)	753	605	(260)	(1507)
Trend	100	(80)	(35)	(200)

37. Market Share: The market share of the domestic industry in total production and domestic consumption of the product in question is analyzed in the table above. Market share of imports has increased to 66% in 2012-13 from 61% in 2011-12. The market share of the DI has decreased to 21% in 2012-13 from 23% in 2011-12. Domestic sales of the DI have also risen to 3701 MT in 2012-13 from 3641 MT in 2011-12.

38. Production: The statistics relating to the production pertaining to the domestic industry is shown in the table above. Domestic production has decreased to 4732 MT in 2012-13 from 5408 MT in 2011-12.

39. Capacity Utilisation: Capacity utilization of the domestic industry has shown decline trend from 2009-10 to 2012-13. The statistics relating to capacity utilization pertaining to the domestic industry is shown below.

YEAR	PRODUCTION (MT)	INSTALLED CAPACITY(MT)	CAPACITY UTILISATION(%)	Inventory (MT)
2009-10	7264	8500	87%	328
2010-11	6672	8500	79%	532
2011-12	5408	8500	64%	257
2012-13	4732	8500	56%	238

40. Inventories: The table above depicts the inventory position which has improved to 238 MT in 2012-13 from 257 MT in 2011-12.

41. Domestic Sale: The table above shows that the domestic sales have increased to 3701 MT in 2012-13 from 2079 MT in the preceding year. The exports have decreased to 1359 MT in 2012-13 from 2079 MT in the preceding year.

42. Employment: There is no significant change in the level of employment and in productivity over the injury period, but has deteriorated in 2012-13 from 2011-12.

43. Profit & Loss(Cash Profit): The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses as shown in the table above. There has been a increase in loss suffered in 2012-13 which has come down to -200(indexed) when compared to the preceding year 2011-12, when there has been a loss of -35 (indexed).

44. Productivity: The DI has suffered in its productivity in 2012-13 both from the preceding year 2011-12 and sharply from the base year 2009-10.

Other Factors:

45. Import in relation to demand: The share of imports in relation to demand has also risen in 2012-13 by about 5% over the preceding year 2011-12.

46. Exports: The performance of the DI in the export segment has witnessed sharp decline in the most recent period of 2012-13 both when compared from the preceding year as well as from the base year.

47. Overall Position of the DI:

From the entire analysis made as above, it is seen that the performance of the domestic industry in the area of production, export, capacity utilisation, employment and productivity has deteriorated since 2010-11 till 2012-13. However, the sale of 'domestic industry' in 2012-13 marginally increased as compared to the year 2011-12. The inventory position has also shown improvement. Profitability has declined drastically in the recent period of 2012-13 from the base year as well as when compared in 2012-13 from the preceding year of 2011-12. It is further seen that the market share of the domestic industry has further declined in 2012-13 to 21% from 23 % in 2011-12 with a corresponding rise in the market share of imports from 61% to 66% during the same period.

47.1 Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of almost all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows a significant overall impairment. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration and in view of the declining production and market share of DI with corresponding sharp surge in imports both in absolute and relative terms, there is also a serious threat of serious injury to the DI.

48. Adjustment Plan: As this is a review case seeking extension/continuation of safeguard duty, the question of adjustment plan is of vital importance in this case. I find that the domestic Industry have submitted details of the positive steps taken during the investigation, which is as follow:

48.1 The DI in its application for original investigation submitted the following adjustment plan:

"NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce *****MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX-13 as one of the product. This plant will have a capacity for production of ***MT PX-13** at an estimated expenditure of Rs. ***. The total project costs about Rs. *** Crs is under implementation stage. **The company hopes to commence commercial production some times in FY 12-13.** The company hopes that the Plant will be fully operational at optimum capacity in about three year's time. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports."

48.2 The DG Safeguards mentioned for the adjustment plan as follows in its Final Findings dated 6th June, 2011:

"34. The Indian Producers have laid down adjustment plan which focuses on a) cost reduction, b) Further utilization of existing production capacity, c) Capacity expansion to cater the growing demand.

35. The petitioner industry i.e. NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce *****MT of PX-13** at an estimated expenditure of Rs. ***Crs... The project is slated to be commissioned from March 2012 and production from April 2012. A certificate from Chartered Engineer has been submitted giving detail of the work done and to be done and certifying that it is quite possible to commence production from April 2012."

48.3 The DI in its written submission post public hearing reiterated its aforementioned adjustment plan:

"The petitioner reiterates that NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce ******* MT of rubber chemicals and intermediates which includes PX-13 as one of the product. This plant will have a capacity for production of ***** MT PX-13** at an estimated expenditure of Rs *****Crs. The total project costs about Rs. *****Crs are under implementation stage. **The company hopes to commence commercial production sometime in FY 2013.** The company hopes that the Plant will be fully operational at optimum capacity in about three year's time. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the Country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports."

48.4. The DI in its present application claimed that in their application for original investigation they stated as follows for adjustment plan:

"NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends to produce **10,000 MT of intermediaries used for production of PX-13.** This plant will have a capacity for production of 10,000 MT intermediates used for production of PX-13 at an estimated expenditure of Rs. 250 Crs... The company hopes to commence commercial production some time in FY 2013. The company hopes that the Plant will be fully operation at optimum capacity in about three year's time."

48.5. The Applicant Domestic Producer, further claimed in its present application as follows:

"Since the company has already started manufacturing 4ADPA at Dahej Plant, the petitioner has taken adequate and appropriate measure for becoming import competitive.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. the Petitioner has commenced production 4ADPA at Dahej. As per the plant, this is the only product that the petitioner shall be producing at Dahej. The plant is only for **PX-13 (sic....4ADPA)**, which shall be exclusively used for production of PX-13. ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e. The Domestic Industry has already started production at Dahej Plant since November, 2012.

48.6. On the above facts, in the present review investigation, the adjustment plan in the notice for initiation of review stated as follows:

48.7. Adjustment Plan: The petitioner has provided the information for setting up of a new plant at Dahej of about 10000 MTS for manufacturing the intermediaries of the PUC which as stated, **have gone into production since Nov'12.** As per records provided by the petitioner, they are manufacturing penultimate staged product/intermediaries of the PUC i.e. 4ADPA in a trial production and have cited this new plant as their adjustment plan for the purpose of review for continued imposition of duty.

48.8. Prima facie, there appears to be discrepancy in the claim of the DI so far as adjustment plan for the production of the PUC i.e., PX-13 or 6 PPD is concerned. First, at the time of original investigation, the claim by the DI was that the Applicant Domestic Industry has set up a new production facilities at Dahej, which will produce rubber chemicals including PUC and intermediaries at their Dahej plant. However, in the chartered Engineer certificate referred to and relied upon by the DG(Safeguards) in the original investigation, mentioned that the Applicant will produce intermediaries of the rubber chemical (PUC) at its Dahej Plant. Thereafter, in the application filed for review, they have cited the enhanced production facilities at new Dahej plant as the adjustment plan which has improved their capacity in their Thane plant.

48.9. I find that the petitioner has not made any physical changes regarding increased capacity from 8500 MT to 14000 MT as claimed. They have also not submitted any evidence / any document regarding changes or modifications in plant, nor informed to the central Excise Deptt. or any other Govt. Agencies. They have claimed that they have made some technical changes by reducing cycle timing for production of PX-13 directly using 4ADPA instead of using 4NDPA

which however, as per records available, never brought to the notice of Safeguard office by the petitioner during on-site verification of the unit at Thane & Dahej from 13/3/2013 to 18/3/2013. However, it is another issue, whether the DI has been able to clearly demonstrate that the operation of Dahej Plant would also increase the capacity of production of PX-13 because the capacity to produce PX-13 is still 8500 MTS only as found during on-site verification and stated in verification report, in order to fulfill the requirements of adjustment plan in this investigation.

48.10. Accordingly, when asked by this office regarding the exact methodology of this increase in capacity by the DI, they submitted a chartered Engineer certificate vide their letter dated 14-03-2014 which shows that the achievement of increased capacity of 14000 MTs is on account of change in the cycle of production. The DI submitted a detailed inspection report of a chartered Engineer, R. Soori, enclosed with their letter dated 14-03-2014, which was circulated amongst all Interested Parties on 18-03-2014 for comments. After the Comments were received by the due date 26-03-2014 from various Interested Parties, the DI was extended an opportunity to respond with a rejoinder till 31-03-2014.

48.11. I find that the applicant domestic industry in their arguments have relied upon the report of the said CE as per whose report it appears that in their Thane Plant, the production of the PUC is such that first 4 NDPA is produced, which gets converted into 4 ADPA and same is converted into 6 PPD/PX-13. In this there are 'constrained and un-constrained capacities'. In the technology earlier adopted by the DI, the DI was carrying out Stage 1, Stage 2 and Stage 3 in the Thane plant. The DI now is directly carrying out stage 2 at Dahej then same is transferred to Thane for producing 6 PPD/PX-13 in second step (stage 3). Thus, by improving upon the unconstrained capacity, they have, as stated by the CE, the DI has been able to enhance its capacity to 14,000 MTs. Further, the reason cited by the DI in their post-hearing written submission for their continued processing of 4 ADPA into 6 PPD/PX-13 in Thane itself is that:

- a. "the production facilities for production of 4 NDPA/4 ADPA available at Thane are now being utilized for production of 6 PPD and therefore these facilities would have remained under-utilized or unutilized/idle, had the petitioner undertaken production of 6 PPD as well at Dahej;
- b. production of 6PPD at Dahej would have implied an additional investment of Rs.*** crores at Dahej and idling of production facilities at Thane. This had no business prudence.
- c. the petitioner cannot sell to tyre industry unless the tyre industry has approved not only the product but also the plant. The production process of tyre industry is highly mature and well established. The tyre company procures raw material after following a long drawn process of approval which involves not only approval of the product but also approval of the production plant. The process may take anywhere between *** years before tyre company can approve a new plant and a new product. Therefore for this additional reason, petitioner has continued to produce 6 PPD at Thane plant so that the changeover would not require a process of approval of the product by its purchasers. It is, however, clarified that all tyre consumers were made aware of the fact that the company is now producing 4 ADPA at Dahej and same is being processed further to 6 PPD at Mumbai. Few such emails sent by NOCIL to Customers and response from Customers are enclosed with this letter. From the said responses, it can be seen that tyre industry is very much aware of the exact situation of NOCIL in January 2013".

48.12. Interested Parties have responded to this letter of the DI on adjustment plan with the submission that the applicant has relied on a different version of adjustment plan in the present review than the one submitted in the original investigation. While, as per the original adjustment plan mentioned in the Final Finding dated 6 June 2011, the applicant undertook to commence production of the subject product at its Dahej plant based on a certification from a 'Chartered Engineer' that it would accomplish the same by April 2012. In the version submitted in the present investigation, the applicant argues that it had only proposed to commence manufacture of 10,000 MT intermediate 4ADPA at its Dahej plant from FY 2013. It is further submitted that the applicant is confusing the Authority with its adjustment plans. Moreover, the applicant has miserably failed in complying with its adjustment plan by delaying its adjustment by almost 2 years even though the adjustment plan was considered feasible by the applicant as it was certified by a Chartered Engineer.

48.13. It appears that if the applicant could not achieve its adjustment plan of 2011 that was certified by a Chartered Engineer, then the applicant's present claims in the aforementioned letters regarding enhanced capacity at Thane plant based on a certificate by a Chartered Engineer again raise doubts about its feasibility and practicality. It is indeed possible that such claims are nothing but hollow statements made by the applicant to cover-up flaws and divert the attention from delays in implementing its original adjustment plan. Further, it is not clear from the letters whether the applicant is able to manufacture sufficient quantities of intermediate 4ADPA at its Dahej plant that would allow it to manufacture 14000 MT of the subject product. It is noticed that mere assertions of enhanced capacity at Thane plant based on reduced cycle time is no indication of actual ability to manufacture 14000 MT of the subject product if there is inadequate supply of intermediate 4ADPA to Thane plant from Dahej plant. The applicant has to show that it is producing sufficient quantities of 4ADPA at Dahej plant that could be converted to 14000 MT of the subject product at Thane plant. I find that the applicant's aforementioned claims about enhanced capacity are devoid of any material support such as data of adequate production of intermediate 4ADPA from Dahej plant and its supply to its Thane plant.

48.14. Accordingly, I find that the adjustment plan given by the DI during the course of the investigation has not been fully justified by the DI towards becoming more competitive to imports. I also find that this aspect is also clearly visible in the rising cost of sales of the DI in the most recent period even though, as claimed, they have changed the cycling process to manufacture the PUC. The DI has also not been able to conclusively prove that during the period of protection of the safeguard duty, they have been able to reduce their cost of production to become cost competitive to increased

imports. As such, their contention that the production of the PUC has therefore increased, is not convincing. Therefore, the requirement of the adjustment plan has not been met as per the Safeguard Rules.

49. Issuance of Final Findings After Expiry of Duty—Anti Dumping Cases:

49.1. I find that the DI has contended in their post-hearing written submissions and rejoinders that as compared to the anti dumping sunset review where case should be initiated before expiry of the anti dumping duty, the safeguard duty law does not have any such obligation. In support, the DI has submitted a list of cases pertaining to anti dumping directorate. On examination it appears that though the initiation of review of anti dumping duty was initiated before the expiry of the existing anti dumping duty, while in some cases the initiation was done on the last date of the expiry of the existing duty, in no circumstances, the Final Findings was issued after the stipulated period permissible under the rules. The interested parties have also provided a table of some safeguard cases whereby the final findings under review were issued well before the expiry of the safeguard duty applicable, including soda ash case. The fact that the notification levying the safeguard duty in case of soda ash was issued after the expiry of the safeguard duty is therefore irrelevant for this directorate.

49.2. On the basis of facts made available before me in the instant case, I find that in no case of review, whether anti dumping or safeguard, the concerned authority has issued its final findings/recommendations beyond the prescribed time period as per respective anti dumping/safeguard rules. I therefore, do not agree with the contention of the DI in this regard.

50. Unforeseen Circumstances:

I find that several Interested Parties have raised the issue of non-existence of unforeseen circumstances in the instant review petition. In this regard, I agree with the submissions made by the DI that since the present investigation is a review investigation, unforeseen developments are not required to be established again. Unforeseen developments were established at the time of imposition of the measure. The present petition is only for extension of the measure. However, the data provided by the DI regarding continued surge of imports from Korea and China even after imposition of safeguard duty fully supports their contention and also satisfies the condition of unforeseen circumstances.

51. Public Interest: Several Interested Parties has argued that continued imposition of safeguard duty on PX-13 would not be in Public Interest. As against these submissions, the DI has argued that since the present case is for review for continued imposition of duty and that the issue of Public Interest had already been discussed at the time of original investigation, any further analysis of the same, as claimed by opposing interested parties, may not be considered. I find that the DI in their post-hearing written submissions and rejoinders has submitted that the impact of the safeguard duty on PX-13/6-PPD would be minimal as it does not constitute a major cost element for the consumers and that majority consumption of PX-13/6-PPD is by tyre industry. The DI has stated that costs on account of PX-13/6-PPD constitutes below 1% of the price of tyre industry and constitutes even much lower cost item (hardly 0.5% of total costs) for non-tyre consumers which gets established from the fact no response from non-tyre segment consumers and their association so far. I find that the contention of the DI, that there would be a minimal impact on the consumers due to continued imposition of safeguard duty on the PUC and thus would be in Public Interest, has not been countered with any substantiated evidence by any Interested Party. In view of the foregoing and the fact that its impact would be minimal & there is a surge in imports causing serious injury to the DI, it is found that the continued imposition of safeguard duty, if any, will be in public interest.

52. WTO-Turkey Issue:

52.1. Another important issue that has been raised by the Interested Parties is whether the positive recommendation in this case by the DG(Safeguards) would be in compliant to the provisions of Agreement on Safeguards under the WTO.

52.2. Under the framework for duration and review of safeguard measures envisaged under Article 7 of the AoS, a safeguard duty can be extended before the end of its term and not thereafter. Article 7.2 of the AoS applies when a safeguard measure is to continue without a gap and Article 7.5 of the AoS applies when a safeguard measure is to be applied "once again" or "applied afresh" after a gap, subject to a minimum gap of two years.

52.3. The Interested Parties have relied upon India's WTO complaint against Turkey in DS 428 titled "*Turkey - Safeguards Measures on Imports of Cotton Yarn (Other Than Sewing Thread)*" ("Turkey - Cotton Yarn") in their submissions against the review safeguard investigation being undertaken in this case. In the aforesaid matter, India challenged Turkey's extension of safeguard measure on cotton yarn. India asserted that Turkey's extension of safeguard measure on 28th January, 2012 after expiry of the same measure on 14th July, 2011 was inconsistent under Article 7.5 of the AoS as Turkey had applied the measure without waiting for the mandatory cooling-off period (minimum 2 years) under Article 7.5 of the AoS.

52.4. As the matter pertained to a stand taken by the member Country India at the WTO, it was thought prudent to call for comments from the nodal Ministry, i.e., Deptt. of Commerce. Accordingly, information was obtained from the Deptt. of Commerce (Trade policy Division) and examined. It was noticed that in the said dispute with Turkey, India's main claim was that initial measures had expired on 14th July 2011 and there was no provision to impose safeguard measures retrospectively and that the measures could be extended only after making a proper determination as per the Article 7.2. No such determination was made before extending the measures. Turkey reiterated its position and sought to defend its claim and measures taken. In spite of arguments put-forth by Turkey, they could not sustain the counter arguments put-

forth by India and Turkey stated it would explore the possibilities of finding a mutual acceptable solution, realizing that their continued safeguard measures on cotton yarn was not consistent with WTO Safeguard Agreement and proposed a mutual agreement without the need to go to panel. Accordingly an MOU was signed between India and Turkey on 15th June 2012 for withdrawal of the safeguard duty on the cotton yarn w.e.f 01/01/2013 and the Safeguard duty would be valid till 31st December 2012. Therefore, the official stance of India before the WTO is that once a duty has expired, and a recommendation of safeguard duty has not been made before the expiry of the duty already expired, duty imposed cannot be extended unless the requirements of Article 7.5 of AoS is met.

52.5. As against this position, the DI has submitted several citations/cases pertaining to anti dumping. However, there appears to be no case related to safeguard. Going by the fact that both safeguard and anti dumping are trade remedy measures, they are clearly distinct in their nature and treatment. In this regard, the domestic industry has failed to understand the WTO dispute settlement procedures and has argued that the dispute between India and Turkey in DS 428 never reached the WTO Panel. The member countries of the WTO, after filing a consultation request, may indulge in bilateral consultations and try to settle the dispute amicably between them before requesting a WTO Panel to intervene. In this case, the consultation process led Turkey to withdraw the safeguard measures, therefore there was no need for a WTO Panel to intervene

Turkey accepted India's position and entered into an agreement with India, wherein, Turkey agreed to withdraw the safeguard measure.

52.6. As per the facts in this case, the safeguard duty expired on 29th August 2013. The case for review was Initiated on 29-08-2013. In no circumstances, the final recommendation for imposition of any safeguard duty, if at all the same is to be recommended, can be made before the expiry of the already effective safeguard duty on the subject PUC. There will be a break in the levy of the duty and since the present application under review is for continued imposition of duty, any positive recommendation would tantamount to a situation of retrospective levy of safeguard duty. This situation, as found above will not be in conformity to the official stand taken by India before the WTO whose legal provisions relating to safeguard duty (under AoS) do not provide for retrospective levy of duty. Therefore, the decision to levy safeguard duty as a result of the review cannot 'relate back' to the date on which duty previously in force has expired. Thus, in this case as the duty will recommence or apply after expiry of the period for which previously duty was in force, it would amount to applying duty "once again" i.e. a fresh levy of safeguard duty and therefore, prohibition contained in Article 7.5 will become applicable.

53. Conclusion and recommendation:

53.1. In view of the findings above, it is concluded that the domestic industry have failed to adduce positive adjustment steps undertaken by them since the imposition of the previous safeguard duty on PX-13 with effect from 30th August, 2011 and are merely seeking extension of safeguard duty on the basis of deviated futuristic/proposed adjustment plans without any concrete measure in place. The DI has also failed to take any concrete adjustment steps towards reduction of cost of sales/production and similar other measures to cut overheads/costs, during the period of two years when they were protected by safeguard duty. Any further action in this regard will also be against the stand taken by Government of India at the WTO, in its complaint against Turkey in DS 428 titled "**Turkey - Safeguards Measures on Imports of Cotton Yarn (Other Than Sewing Thread)**" ("Turkey - Cotton Yarn").

53.2. In view of the above, the instant review proceedings of the safeguard investigation related to continued imposition of safeguard duty on PX-13/6PPD are, therefore, terminated.

[F. No. D-22011/1/2013/PE]

R. K. SINGLA, Director General